



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941

No. 346]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सं.1सीए(5)/70/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

70वीं वार्षिक रिपोर्ट

आईसीएआई की परिषद् को 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी 70वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम द्वारा आईसीएआई के प्रारंभ से लेखांकन वृत्ति का अत्यधिक विकास हुआ है। संस्थान, जिसे केवल 1700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, 31 मार्च, 2019 को उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 291698 हो गई है। यह रिपोर्ट, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2018-2019 के दौरान की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही संस्थान के 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की विशिष्टियों को उपदर्शित करती है। परिषद् इस अवसर पर इस रिपोर्ट में, इस अवधि के और जुलाई, 2019 के शुरूआती दिनों तक की अवधि के दौरान, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय रूपरेखाओं, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यौरों को भी समाविष्ट करती है। परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के समाज में विद्यमान वर्तमान सम्मान के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति सदस्यों और छात्रों द्वारा एक साथ मिलकर उपदर्शित की गई उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और ईमानदारी के द्वारा हुई है।

1. परिषद्

चौबीसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2019 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वर्तमान में, परिषद् 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए 8 सदस्यों से मिलकर बनी है। 24वीं परिषद् की संरचना पृथक रूप से

दर्शित की गई है।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार 12 फरवरी, 2019 को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति से संबंधित विषयों के बारे में स्थायी और विभिन्न गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों का गठन किया था। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न स्थायी और अस्थायी समितियों और बोर्डों और समूहों की 236 बैठकें आयोजित की गई थीं।

3. संपरीक्षक

मैसर्स शाह गुप्ता एंड कं. और मैसर्स खन्ना और अन्नाधानम वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे।

4. स्थायी समिति

4.1 कार्यपालक समिति

कार्यपालक समिति आईसीएआई की परिषद् की स्थायी समितियों में से एक है। इस समिति के कृत्यों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 175 में विहित किया गया है। समिति के कुछ कृत्य, आर्टिकल्ड और संपरीक्षा सहायकों तथा सदस्यों के नामों का रजिस्टर में नामांकन करने, हटाए जाने, नामों की पुनः प्रविष्टि करने, व्यवसाय प्रमाणपत्र को रद्द करने, लेखांकन वृत्ति से भिन्न किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में नियोजित होने के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित है। कार्यपालक समिति आईसीएआई की संपत्तियों, आस्तियों और निधियों की अभिरक्षक भी है और साथ ही आईसीएआई के कार्यालय के अनुरक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति, जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा स्थापित किया गया था, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है।

4.3 परीक्षा समिति

परीक्षा समिति, परीक्षाओं से संबंधित परिषद् के सभी कृत्यों का निर्वहन करती है। समिति ने, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (विद्यमान और पुनरीक्षित) परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कराई गई परीक्षाओं के व्यौरे नीचे दिए गए हैं।

मई, 2018 की परीक्षाओं – का संचालन 2 मई से 17 मई, 2018 के दौरान 475 केन्द्रों पर किया गया। उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (विद्यमान और पुनरीक्षित) परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		दोनों समूहों/किसी एक समूह की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसी)	53149	5392	72146	10861	32878	6671
मध्यवर्ती	13135	3026	445	18	19108	8369
फाइनल (विद्यमान)	38696	6195	37350	5075	27727	6871
फाइनल (पुनरीक्षित)	2289	260	1208	96	936	266

नवंबर, 2018 की परीक्षाओं – का संचालन पूरे देश भर में और विदेशों में 1 नवंबर से 18 नवंबर, 2018 के दौरान 470 केन्द्रों पर किया गया। उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (विद्यमान और पुनरीक्षित) परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		दोनों समूहों/किसी एक समूह की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसी)	40157	5051	68888	21708	25375	5577
मध्यवर्ती	24411	4525	8652	3724	21909	8095
फाइनल (विद्यमान)	32633	9934	35655	8348	22514	9466
फाइनल (पुनरीक्षित)	6181	884	3307	894	4075	1505

	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
फाउंडेशन परीक्षा मई, 2018	6315	1215
फाउंडेशन परीक्षा नवंबर, 2018	48702	21488

उपरोक्त के अलावा, सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) संबंधी परीक्षाओं को 17 जून, 2018 और 16 दिसम्बर, 2018 को, देश भर और विदेशों में क्रमशः 332 और 248 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। उक्त सीपीटी परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थी	उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी
17 जून, 2018 को आयोजित सीपीटी	54474	15284
16 दिसम्बर, 2018 को आयोजित सीपीटी	25037	9038

वर्ष के दौरान, सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापत्र पाठ्यक्रम – निर्धारण परीक्षा (आईएसए-एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन 23 जून, 2018 को देश भर में 54 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था। एक अन्य सूचना प्रणाली संपरीक्षा – निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 22 दिसम्बर, 2018 को देश भर में 62 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था।

इन परीक्षाओं को देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
23 जून, 2018 को आयोजित आईएसए-एटी	2768	1020
22 दिसम्बर, 2018 को आयोजित आईएसए-एटी	3211	1160

बीमा और जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन नवंबर, 2018 के दौरान देश भर में कराया गया था। इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षा देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
आईआरएम - तकनीकी परीक्षा	47	25

सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन मई और नवंबर, 2018 के दौरान किया गया था। इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :

	परीक्षा देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मई, 2018 में आयोजित आईएनटीटी – एटी	176	13
नवंबर, 2018 में आयोजित आईएनटीटी – एटी	193	51

नवंबर, 2018 में प्रबंध अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम (एमएसी) (भाग 1), निगम प्रबंध पाठ्यक्रम (सीएमसी) (भाग 1), कर प्रबंध पाठ्यक्रम (टीएमसी) (भाग 1) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल एंड डब्ल्यूटीओ) (भाग 1) में अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का भी आयोजन किया गया था।

संस्थान अपनी परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में, प्रश्नपत्र निर्धारित करने के प्रक्रम से आरंभ करते हुए परिणामों की घोषणा तक की प्रक्रियाओं में निरंतर रूप से सुधार करता रहा है, जिससे परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और संतता, जो कि पिछले सात दशकों से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक मजबूत तथा विकसित किया जा सके।

संस्थान की परीक्षाएं सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में अवधारणात्मक समझ और साथ ही व्यावहारिक प्रयोग की जांच करती हैं, जिससे छात्र वृत्ति के विभिन्न पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें। प्रश्नों की पूर्व अनुमानता की संभावनाओं को यथासंभव रूप से दूर रखते हुए छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए संस्थान की परीक्षाएं लगातार यह सुनिश्चित करती रहीं हैं कि अर्हित छात्र सुयोग्य वृत्तिक बन सकें।

विशेष परीक्षा : निम्नलिखित विदेशी वृत्तिक लेखांकन निकायों के साथ किए गए परस्पर मान्यता करार/समझौता ज्ञापनों से उद्भूत होने वाली विशेष परीक्षाओं का, जिनमें आईसीएआई की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए इच्छुक इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स इन आस्ट्रेलिया (सीपीए आस्ट्रेलिया) के सदस्य बैठना चाहते थे, सफलतापूर्वक आयोजन 18 से 20 जून, 2018 के दौरान नई दिल्ली में किया गया था।

ई-मूल्यांकन प्रणाली : हमारी परीक्षा प्रणाली के उन्नयन और इसे और अधिक पारदर्शी बनाने के मद्दे इस वर्ष एक अन्य प्रमुख पहल के रूप में उत्तर-पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन संबंधी परियोजना (जिसे नवंबर, 2017 में एक अग्रणी परियोजना के रूप में आरंभ किया गया था) को वस्तुतः मई, 2018 की परीक्षाओं के दो प्रश्न-पत्रों के संबंध में आरंभ किया गया और तत्पश्चात् नवंबर, 2018 की परीक्षाओं में इसे 5 प्रश्न-पत्रों के लिए आरंभ किया गया था।

केंद्रीकृत मूल्यांकन : नवंबर 2018 की परीक्षाओं में एक पेपर के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केंद्रीकृत मूल्यांकन। दिसंबर 2018 / जनवरी 2019 में हैदराबाद और नोएडा में आयोजित पेपर 6, फाइनल (मौजूदा योजना) के लिए समान मूल्यांकन।

खुली किताब पद्धति: मई 2018 में मौजूदा स्कीम के तहत परीक्षा के साथ संशोधित योजना के तहत परीक्षा आयोजित की गई। मई 2018 में पहली बार फाउंडेशन परीक्षा आयोजित की गई। फाइनल (संशोधित योजना) के पेपर 6 (वैकल्पिक पेपर) पहली बार ओपन बुकोलॉजी पर आयोजित किए गए। मई 2018. इन सभी को नवंबर 2018 की परीक्षाओं में भी जारी रखा गया था।

छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध संबंधी वेब इंटरफेस :-

आईसीएआई ने एक छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध परियोजना नामक एकीकृत वेब इंटरफेस प्रारंभ किया था, जहां सीए के छात्र एकल उपयोक्ता पहचान और पासवर्ड का उपयोग करते हुए विभिन्न परीक्षा संबंधी सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय अंक सूचियां/ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/प्रतिलिपियों, केंद्र/ माध्यम/समूह में परिवर्तन के लिए आवेदन, परीक्षा-दर-परीक्षा प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड करना, परिणामों की जांच करना और परिणाम के पश्चात् उत्तर-पुस्तिकाओं के सत्यापन/उनकी प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आदि भी हैं।

नए परीक्षा केन्द्र : छात्रों द्वारा उनके आवास/आर्टिकलड प्रशिक्षण के स्थान से निकटतम संभव स्थानों पर परीक्षाएं देने को सुकर बनाने के विचार से निम्नानुसार नए परीक्षा केंद्र खोले गए थे :

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (विद्यमान और पुनरीक्षित) परीक्षाओं के लिए खोले गए नए परीक्षा केंद्र :

मई, 2018 की परीक्षाओं से : जूनागढ़, बदलापुर, चंद्रपुर, पालघर, रतनागिरी, गोंदिया, यवतमाल, जालना, परभनी, हल्द्वानी, बांसवाड़ा, मंदसौर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना और सिरौही।

नवंबर 2018 की परीक्षाओं से : दोहा (कतर)।

सीपीटी के लिए खोले गए नए केंद्र : जून, 2018 से : अंबिकापुर, रायगढ़, बलोतरा, पोर्ट ब्लेयर और कालाबुर्गी।

4.4 अनुशासन समिति

अनुशासन निदेशालय, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार किसी औपचारिक शिकायत के रूप में या किसी “सूचना” के माध्यम से प्राप्त उसके सदस्यों के विरुद्ध वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के मामलों के संबंध में कार्यवाही करता है।

भारत में लेखांकन वृत्ति की साख, ईमानदारी और छवि को सर्वोपरि बनाए रखने के अपने सतत अभियान के भागरूप में आईसीएआई के विनियामक ढांचे ने, एक सुदृढ़ और सक्रिय अनुशासन तंत्र की स्थापना की है, जिसमें एक सुपरिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से कार्यवाहियों को आरंभ किया जाता है और उनका संचालन किया जाता है, जिसके दौरान सतत रूप से यह प्रयास किया जाता है कि कदाचार के दोषी व्यक्तियों को दंडित करके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया जा सके।

आईसीएआई न केवल भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वृत्ति के विनियामक के रूप में अपने कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपितु साथ ही उसने नैतिक संहिता में यथा परिकल्पित नैतिक मूल्यों को भी प्रवर्तनीय बनाया है और साथ ही वह सक्रिय रूप से अपने वृत्ति करने वाले ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई भी करता है, जिन्हें वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया जाता है और यह कार्रवाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन विरचित नियमों के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार एक सुपरिभाषित अनुशासन तंत्र के माध्यम से की जाती है।

अनुशासन तंत्र और उसमें अंतर्बलित प्रक्रियाओं की विरचना ऐसी रीति में की जाती है, जो वृत्ति के पणधारियों और साधारण जनता में उसके प्रति विश्वास में वृद्धि करे और साथ ही वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के आरोपों में संलिप्त सदस्यों को निष्पक्ष और साम्यापूर्ण न्याय भी उपलब्ध कराए।

(I) चालू वर्ष के दौरान प्रमुख पहलें/उपलब्धियां

- ऐसे लंबित अनुशासन संबंधी मामलों के, जो जांच के अधीन हैं, शीघ्र निपटारे के लिए पांच न्यायपीठों, अर्थात् अनुशासन बोर्ड की दो न्यायपीठों और अनुशासन समिति की तीन न्यायपीठों का गठन किया गया है।
- लोक हित के मामलों और साथ ही विभिन्न विनियामकों, अर्थात् सेबी, आरबीआई, एसएफआईओ, सीबीआई द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक् और अनन्य खंडपीठ का भी गठन किया गया है। इस खंडपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा की जाती है और सरकार द्वारा, विनिर्दिष्ट रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए दो व्यक्ति भी इस वर्ष इसके सदस्य थे। नैसर्गिक न्याय के और निष्पक्षता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठों ने मामलों के निपटारे के संबंध में अपनी गति को बनाए रखा। पीएनबी और आईएल एंड एफएस के मामलों में शीघ्रतापूर्वक और स्वविवेकानुसार अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ की गई थी। वस्तुतः, पीएनबी और आईएल एंड एफएस के मामले में, निदेशक (अनुशासन) के प्रारंभिक निष्कर्ष उन आधारों में से एक आधार बने थे, जिनका उपयोग कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एनसीएलटी के समक्ष, आईएल एंड एफएस और साथ ही इसकी अन्य दो समूह कंपनियों की लेखाबहियों को पुनः तैयार करने का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया था।
- पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच करने और साथ ही तथाकथित रूप से उसके दोषी सदस्यों की भूमिका के बारे में जांच करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समूह का गठन किया गया था। तत्पश्चात्, समूह ने पीएनबी में हुई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक सुग्राह्य गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसके अतिरिक्त, अन्य विनियामक अभिकरणों को भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे।
- आईएल एंड एफएस के मामले में प्रणालीगत मुद्दों का अध्ययन करने और उसके संबंध में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए भी एक उच्च शक्ति प्राप्त समूह का गठन किया गया था।
- अनुशासन समिति/अनुशासन बोर्ड के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने को सुकर बनाए जाने के संबंध में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 में दो संशोधन किए गए थे। इस प्रभाव की पद्धतियों की विरचना की जा रही है।
- आईसीएआई की शासकीय वेबसाइट www.icai.org पर आनलाइन पद्धति से अनुशासन संबंधी किसी शिकायत को फाइल किए जाने को सुकर बनाया गया है। यह लिंक <https://icai.org/disciplinarydirectoriate/> पर उपलब्ध है।

- संपूर्ण अनुशासन प्रक्रिया के स्वचालन हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई और यह आशा की जाती है कि इस कार्य को आने वाले चार से पांच मास के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 में संशोधनों का सुझाव दिए जाने संबंधी प्रारूप संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए एक समूह का गठन किया गया है, जिससे अनुशासन संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर किया जा सके।
- पुराने अनुशासन तंत्र के अधीन लंबित बचे हुए मामलों का निपटारा करने के विचार से, अनुशासन समिति ने (धारा 21घ के अधीन) बार-बार बैठकें की। जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान सभी लंबित मामलों की सुनवाई की गई थी और उनका निपटारा किया गया था, जिनमें वित्तीय वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 से संबंधित ई-जीटीबी की संपरीक्षा से संबंधित मामले भी सम्मिलित थे।
- ई-जीटीबी से संबंधित रिपोर्टों पर परिषद् द्वारा मई, 2019 में विचार किया गया था। यह विचार किए जाने के पश्चात्, परिषद् ने अनुशासन समिति की रिपोर्टों को स्वीकार करने का विनिश्चय किया था और साथ ही यह विनिश्चय भी किया था कि उन रिपोर्टों के संबंध में संबंधित माननीय उच्च न्यायालय को सिफारिश की जाए।

(II) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (की धारा 21क) के अधीन अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद् द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक और अन्य कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथमदृष्टया रूप से किसी कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, अनुशासन बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर **20 बैठकें** (खंडपीठ I : 6 बैठकें और खंडपीठ II : 14 बैठकें) की थी। इन बैठकों में, बोर्ड ने **88 मामलों**, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी। ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) – 1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 की अवधि के दौरान

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन बोर्ड द्वारा की गई बैठकों की संख्या	20
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय प्राप्त की गई थी*।	292
ग)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामलों) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा जांच पूरी कर ली गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	88
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	32

*इसके अंतर्गत ऐसे मामले भी हैं, जिनके संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों का अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 6/12 के अधीन कार्यवाही की गई थी।

(III) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन)

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद् द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची या पहली तथा दूसरी अनुसूची, दोनों के अंतर्गत आते हैं।

वर्ष 2018-2019 के दौरान, अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) की तीन खंडपीठों, अर्थात् खंडपीठ I और खंडपीठ II तथा खंडपीठ III का गठन किया गया था, जहां खंडपीठ 3 अनन्य रूप से सरकारी/विनियामकों/लोक हित, आदि के मामलों पर विचार कर रही है।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित स्थानों पर **39 बैठकें (खंडपीठ-I : 6 बैठकें, खंडपीठ-II : 14 बैठकें और खंडपीठ III : 19 बैठकें)** की थी। पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने **153 मामलों** में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे। ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) – 1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 की अवधि के दौरान

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा की गई बैठकों की संख्या	39
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय प्राप्त की गई थी।	274
ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन्हें आगे और जांच के लिए अनुशासन समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था) * ऐसे मामलों सहित, जो निर्दिष्ट किए गए हैं	153
ङ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था) * ऐसे मामलों सहित, जो निर्दिष्ट किए गए हैं	49

(IV) धारा (21घ) के अधीन अनुशासन समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के उपबंधों के अधीन कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में पूर्वोक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसे सदस्यों के, जिनके मामले उसे परिषद् द्वारा प्रथमदृष्टया राय बनाए जाने पर निर्दिष्ट किए गए हैं, विरुद्ध अनुशासन संबंधी जांच करने के अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस समिति ने पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान 04 बैठकों का आयोजन किया था। ऐसे मामले, जिन पर पुराने अनुशासन तंत्र के अधीन कार्यवाही की गई थी [धारा 21(घ)]

1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 तक की अवधि के दौरान परिषद् और अनुशासन समिति के समक्ष रखे गए मामलों से संबंधित आंकड़े :

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
1.	(i) पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या (ii) पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा धारा 21घ के अधीन की गई बैठकों की संख्या	05 04
2.	अनुशासन समिति की ऐसी रिपोर्टों की संख्या, जिन पर परिषद् द्वारा विचार किया गया था (इनके अंतर्गत उन मामलों की रिपोर्टें भी हैं, जिन पर पूर्व वर्षों के दौरान सुनवाई की गई थी) उपरोक्त में से	03
3.	(क) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया है किंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(4) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व परिषद् के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। (ख) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दूसरी अनुसूची और/या अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है किंतु जिनके मामले को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालयों को निर्दिष्ट किया जाना है।	शून्य 02

	(ग) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची/ अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है (घ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें मामला आगे और जांच हेतु अनुशासन समिति को वापस निर्दिष्ट किया गया है (ङ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को किसी कदाचार के लिए दोषी नहीं पाया गया है	शून्य शून्य 01
4.	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें ऐसे प्रत्यर्थियों के संबंध में धारा 21(4) के अधीन आदेश पारित किया गया था, जिन्हें पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया था	शून्य
5.	उच्च न्यायालय द्वारा धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की संख्या	04

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी)

(I) वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का उन्नयन :

- मार्च, 2019 में, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2019 द्वारा इंडिएस 17 को प्रतिस्थापित करते हुए इंडिएस 116, पट्टों, को अधिसूचित किया गया था तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2019 द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित इंडिएस में कतिपय संशोधन किए गए थे :
 - परिशिष्ट ख, इंडिएस 12 में आय-कर के संबंध में व्यवहार के बारे में अनिश्चितता
 - इंडिएस (2018) में वार्षिक सुधार (आईएसएसबी द्वारा जारी किए गए 2015-2017 चक्र द्वारा आईएफआरएस मानकों में किए गए वार्षिक सुधारों के तत्समान)
 - योजनाबद्ध संशोधन, संक्षेपण या समाधान (इंडिएस 19, कर्मचारियों को फायदे, में संशोधन)
 - ऋणात्मक प्रतिकर के साथ पूर्व संदाय विशिष्टियां (इंडिएस 109, वित्तीय लिखतें, में संशोधन)
 - सहबद्धों और संयुक्त उद्यमों में दीर्घकालिक हित (इंडिएस 28 में संशोधन)
- कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2018 को 20 सितंबर, 2018 को अधिसूचित किया गया था। इन नियमों में इंडिएस 20 में सीमित संशोधन अंतर्विष्ट थे, जिससे अस्तित्वों को नाममात्र रकम पर गैर-घनीय शासकीय अनुदानों के विकल्प को अनुज्ञात किया जा सके और आस्ति की अग्रणी रकम से अनुदान की रकम को घटाकर आस्तियों से संबंधित शासकीय अनुदानों को प्रस्तुत किया जा सके।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग 3 - अनुसूची 3, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2018 में अधिसूचित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण हेतु।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, परिषद्, आईसीएआई द्वारा निम्नलिखित संशोधनों को मंजूरी दी गई थी :
 - कारबार की परिभाषा (इंडिएस 103 में संशोधन)
 - सामग्री की परिभाषा (इंडिएस 1 और इंडिएस 8 में संशोधन)
 - इंडिएस 40, निवेश संपत्ति में संशोधन

विद्यमान लेखांकन मानकों का उन्नयन करने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा, जिससे उन्हें इंडिएस के समरूप बनाया जा सके और इस संबंध में एएसबी द्वारा समुन्नत लेखांकन मानकों के निम्नलिखित उद्भासन प्रारूपों को जारी किया गया था :

- लेखांकन मानक (एएस) 34, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी उद्भासन प्रारूप
- लेखांकन मानक (एएस) 17, पट्टे संबंधी उद्भासन प्रारूप
- लेखांकन मानक (एएस) 41, कृषि संबंधी उद्भासन प्रारूप
- लेखांकन मानक (एएस) 11, संनिर्माण संविदाओं संबंधी उद्भासन प्रारूप
- लेखांकन मानक (एएस) 18, राजस्व संबंधी उद्भासन प्रारूप
- लेखांकन मानक (एएस) 01, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण संबंधी उद्भासन प्रारूप

- लेखांकन मानक (एएस) 37, प्रावधान, आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक आस्तियों संबंधी उदभासन प्रारूप
- लेखांकन मानक (एएस) 40, निवेश संपत्ति संबंधी उदभासन प्रारूप
- लेखांकन मानक (एएस) 19, कर्मचारी फायदों संबंधी उदभासन प्रारूप
- लेखांकन मानक (एएस) 109, वित्तीय लिखतों संबंधी उदभासन प्रारूप

(II) कार्यान्वयन संबंधी समर्थन

निम्नलिखित मार्गदर्शक टिप्पण/बहुधा पुछे जाने वाले प्रश्न/उदघोषणाएं जारी की गई थी :

- उपदान की अधिकतम सीमा में वृद्धि के कारण दायित्व में हुई वृद्धि के संबंध में लेखांकन व्यवहार संबंधी बहुधा पुछे जाने वाले प्रश्न
- भू-संपदा संव्यवहारों के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण को वापस लिए जाने के लिए उदघोषणा (ऐसे अस्तित्वों के लिए, जिन्हें इंडएएस लागू हैं)

(III) अंतर्राष्ट्रीय पहलें : दीर्घकालिक भागीदारियां स्थापित करना

अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी निम्नलिखित उदभासन प्रारूपों/परामर्श पत्रों के संबंध में टिप्पणियों को आईएएसबी को प्रस्तुत किया गया था :

- लेखांकन नीति परिवर्तनों, आईएएस 8 में प्रस्तावित संशोधनों संबंधी उदभासन प्रारूप
- 'साम्या की विशिष्टियों वाली वित्तीय लिखतों' संबंधी आईएएसबी के परामर्श पत्र
- 'दुर्वह संविदाओं – किसी संविदा को पूरा करने संबंधी लागत' संबंधी उदभासन प्रारूप – आईएएस 37 में प्रस्तावित संशोधन
- 'व्याज दर बैंचमार्क सुधार (आईएफआरएस 9 और आईएएस 39 में प्रस्तावित संशोधन)' संबंधी उदभासन प्रारूप
- आईएफआरएस निर्वचन समिति द्वारा जारी अंतरिम कार्यसूची निर्णय (टीएडी)

⇒ **वैश्विक सहयोग/एमओयू/एमआरए :** भारत को, एओएसएसजी वित्तीय लिखतों संबंधी कार्यकारी समूह का एक सदस्य होने के कारण, सामान्य शेषों से भिन्न लिखतों के माध्यम से धारित किसी सहबद्ध में हितों के संबंध में एक लेखांकन संबंधी मुद्दा प्राप्त हुआ था और इस संबंध में आईसीएआई के सुझावों को कार्यकारी समूह को उपलब्ध कराया गया था ।

⇒ 2 अक्तूबर, 2018 के ऐतिहासिक दिवस पर, जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सालगिरह भी थी, आईसीएआई ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार की ओर से लंदन में आईएफआरएस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) और अनुज्ञप्ति करारों पर हस्ताक्षर किए थे। यह एमओयू आईएफआरएस मानकों और भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) में पक्षकारों में से प्रत्येक के प्रतिलिप्याधिकारों से संबंधित अधिकारों को परस्पर रूप से समझने और स्वीकार करने को औपचारिक रूप प्रदान करता है ।

⇒ वैश्विक भागीदारी का सप्ताह :

- भारतीय पणधारियों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को एकसाथ लाने के लिए परस्पर क्रियाशील बैठकों और सम्मेलनों की एक शृंखला का आयोजन किया गया था । 10 अप्रैल, 2018 को "आईएएसबी पदधारियों की राष्ट्रीय विनियामकों के साथ परस्पर क्रिया" संबंधी एक आयोजन भी किया गया था ।
- 11 अप्रैल, 2018 को "आईएफआरएस-17 (इंडएएस 117, बीमा संविदाएं) बीमा उद्योग आउटरीच" और आईसीएआई-आईएएसबी संयुक्त पणधारियों की संगोष्ठी "आईएफआरएस 9 (इंडएएस 109) बैंककारी उद्योग में ईसीएल आदर्श चुनौतियां" का आयोजन किया गया था, जिसमें सुसंगत पणधारियों ने भाग लिया था ।
- 12-13 अप्रैल, 2018 के दौरान मुंबई में लेखांकन मानक निर्धारकों के अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफएएसएस) की एक बैठक का आयोजन किया गया था । 25 से अधिक अधिकारिताओं से, जिनके अंतर्गत यूएस, यूरोप, जापान, आस्ट्रेलिया आदि जैसी प्रमुख अधिकारिताएं भी थी, साठ से अधिक प्रतिनिधियों ने एक ऐसे आयोजन में भाग लिया था, जिसमें भारत द्वारा 'आईएफआरएस 10 के अधीन लाभ न कमाने वाले अस्तित्वों के समेकन' से संबंधित एक मुद्दे को प्रस्तुत किया गया था ।

⇒ सीए एस.बी. जवारे, पूर्व अध्यक्ष, एएसबी (2016-19), जो एशियाई ओशनियन मानक निर्धारक समूह (एओएसएसजी) के उपाध्यक्ष हैं, को लेखांकन मानक सलाहकार मंच (एएसएएफ) द्वारा 1.12.2018 से 30.11.2021 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए एओएसएसजी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया था। एएसएएफ, आईएसबी और आईएफआरएस फाउंडेशन का एक प्रमुख परामर्शी निकाय है।

⇒ आईएफआरएस फाउंडेशन के न्यासियों ने सीए एम.पी. विजय कुमार, अध्यक्ष, एएसबी को 1 जनवरी, 2019 से साफा का प्रतिनिधित्व करने वाली आईएफआरएस सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। आईएफआरएस सलाहकार परिषद्, आईएफआरएस फाउंडेशन न्यासियों और आईएसबी को नीतिगत और तकनीकी, दोनों प्रकार के विषयों के संबंध में सलाह प्रदान करती है।

एएसबी ने उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के साथ अपने सहयोग और सहायता को जारी रखा। आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों, अर्थात् विश्व मानक निर्धारकों (डब्ल्यूएसएस), एशियाई ओशनियन मानक निर्धारक समूह (एओएसएसजी), उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह (ईईजी) और अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारक मंच (आईएफएसएस) की बैठकों में निम्नानुसार भाग लिया था :

⇒ 25-27 मार्च, 2019 के दौरान हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह (ईईजी) की 17वीं बैठक और ब्यूनस ऐरिस, अर्जन्टीना में 28-29 मार्च, 2019 के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारक मंच (आईएफएसएस) की बैठक। आईसीएआई ने इन बैठकों में विचार-विमर्श के लिए निम्नलिखित दो विषयों के संबंध में अपने प्रपत्र भेजे थे :

- ईईजी में – आईएस 20 : प्राप्य सरकारी अनुदानों के संबंध में प्रपत्र
- आईएफएसएस में, वित्तीय लागतों – आईएस 1, आईएफआरएस 7 और आईएस 23 से संबंधित एक मद का प्रस्तुतीकरण

⇒ 29 जनवरी, 2019 को क्वालालम्पुर, मलेशिया में आयोजित खंडपीठ की सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक

⇒ 30 जनवरी, 2019 को क्वालालम्पुर, मलेशिया में आयोजित एओएसएसजी के सीएसी सदस्यों और आईएफआरएस के न्यासियों की संयुक्त बैठक

⇒ 30 सितंबर, 2018 को लंदन में और 20 नवंबर, 2018 को सिंगापुर में आईएफआरएस फाउंडेशन के न्यासियों के साथ खंडपीठ और सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक

⇒ 19 जुलाई, 2018 और 14 सितंबर, 2018 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (सीवीसी) की टेलीकांफ्रेंस बैठक तथा 26 जुलाई, 2018 को खंडपीठ की सलाहकार समिति (सीएसी) की टेलीकांफ्रेंस बैठक

⇒ 2-3 अक्तूबर, 2018 को लंदन, यूके में आईएफएसएस की बैठक, जहां "कारबार संयोजनों में संपत्ति के अर्जन पर स्टॉप शुल्क के संबंध में व्यवहार" विषय पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था।

⇒ 22-24 नवंबर, 2018 के दौरान सिंगापुर में आयोजित एओएसएसजी की दसवीं वार्षिक बैठक, जिसमें 'बुलियन (स्वर्ण) उधार देने और उधार लेने में अंतर्वर्तित लेखांकन संबंधी मुद्दों' पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था और 30 सितंबर, 2018 को लंदन में एओएसएसजी की अंतरिम बैठक

⇒ 29-31 अक्तूबर, 2018 के दौरान सियोल, दक्षिण कोरिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह (ईईजी) की 16वीं बैठक, जहां विभिन्न तकनीकी विषयों, उदाहरणार्थ आईएसबी द्वारा जारी साम्या की विशिष्टियों वाली वित्तीय लिखतों (एफआईसीई), साख और हानिकरण, आदि के संबंध में विचार-विमर्श पत्र के संबंध में विचार किया गया था।

⇒ 1-2 अक्तूबर, 2018 के दौरान लंदन में आयोजित विश्व मानक निर्धारकों (डब्ल्यूएसएस) का सम्मेलन

⇒ 17-18 मई, 2018 के दौरान क्वालालम्पुर, मलेशिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह (ईईजी) की 15वीं बैठक, जिसमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित दो प्रपत्र प्रस्तुत किए गए थे :

- लाभ न कमाने वाले अस्तित्वों का समेकन

- चालू/गैर चालू आस्तियों का प्रस्तुतीकरण
- ⇒ 1-2 अप्रैल, 2019 के दौरान लंदन में एसएसएफ की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें एसबी ने निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर एओएसएसजी सचिवालय, चीन को अपने मत प्रस्तुत किए थे, जिसके पश्चात् कार्यकारी समूह के नेताओं ने टिप्पणियों का समेकन किया था और उन्हें मंच के साथ साझा किया था :
- एसएमई, जो समनुषंगी हैं
 - लेखांकन संबंधी नीति में परिवर्तन (आईएस 8 में प्रस्तावित संशोधन)
 - दुर्वह संविदाएं – किसी संविदा को पूरा करने की लागत
- ⇒ आईएफआरएस सलाहकार परिषद् (आईएफआरएस एसी) : आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने 19-20 मार्च, 2019 के दौरान लंदन, यूके में आयोजित आईएफआरएस एसी की बैठक में भाग लिया था, जिसमें संवेदनशील जानकारी का प्रकटन, एसएमई मानक के संबंध में आईएफआरएस का व्यापक पुनर्विलोकन – एसएमई मानक के संबंध में आईएफआरएस का विस्तार क्षेत्र आदि जैसे मुद्दों के संबंध कार्यवाही की गई थी। आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने संवेदनशील जानकारी के प्रकटन संबंधी ब्रेकआउट सत्र में भाग लिया था।

(IV) विनियामक निकायों के साथ सुदृढ़ संबंध बनाना :

विभिन्न विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मुद्दों पर मत प्रस्तुत किए गए थे और जहां कहीं उपयुक्त समझा गया था, सुसंगत विनियामकों के साथ विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों को उठाया गया था, उदाहरणार्थ :

⇒ कारपोरेट कार्य मंत्रालय :

- 14 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की पहली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आईसीएआई के पदधारियों ने भाग लिया था। उक्त बैठक में इंडएस 116, पट्टे और आईसीएआई द्वारा इंडएस में सिफारिश किए गए अन्य संशोधनों के संबंध में एनएफआरए को प्रस्तुतीकरण किया गया था।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुरोध पर, एसबी ने विद्यमान कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 की रूपरेखा के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नए नियमों के प्रारूपण को सुकर बनाने का कार्य आरंभ किया था जिससे उन्हें एनएफआरए को प्रस्तुत किया जा सके।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय के कोर समूह – इंडएस कार्यान्वयन समूह की बैठक का आयोजन 24 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में किया गया था, जहां बैंकारी सेक्टर और बीमा सेक्टर में इंडएस के कार्यान्वयन संबंधी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें समादत शेयर पूंजी, शुद्ध मूल्य, आवर्त और कर के पश्चात् लाभ (पीएटी), आदि जैसे प्रमुख पैरामीटरों के आधार पर सभी अस्तित्वों के लिए इंडएस के कार्यान्वयन संबंधी बहुमुखी अवसीमा मानदंडों की विरचना जैसे विषय सम्मिलित थे।
- 25 मई, 2018 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय में इंडएस के कोर समूह की बैठक का आयोजन किया गया था। एस 8 द्वारा भू-संपदा क्षेत्र के प्रतिनिर्देश से राजस्व को मान्यता दिए जाने संबंधी उपबंधों का वर्णन किया गया था। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी के इंडएस को अप्रैल, 2019 तक आस्थगित करने के अनुरोध पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

⇒ इंडएस के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के विचार से विनियामकों, उद्योग संगमों और अन्य पणधारियों के साथ विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था और गत वर्ष नए इंडएस को अंतिम रूप प्रदान किए जाने से पूर्व एक सक्रिय उपाय के रूप में भारत के विभिन्न अवस्थानों पर, अर्थात् नई दिल्ली, मुंबई और पुणे में, कुछ मानकों, जैसे कि इंडएस 109, वित्तीय लिखतें, इंडएस 115, ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व, इंडएस 116, पट्टे और इंडएस 117, बीमा संविदाओं के संबंध में अनेक आउटरीच बैठकों का आयोजन किया गया था।

(V) अन्य पहलें

जारी किए गए प्रकाशन : बोर्ड ने साधारण रूप से संस्थान के सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए थे :

- ⇒ आईएफआरएस भाग ख (दृष्टांत उदाहरण और कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश) और आईएफआरएस भाग ग (निष्कर्षों के लिए आधार) को अंतर्विष्ट करने वाली आईएफआरएस मानकों संबंधी इंडएएस मार्गदर्शक सामग्री के ई-पाठ के साथ 1 अप्रैल, 2018 को प्रभावी होने वाले भारतीय लेखांकन मानकों के सार संग्रह के पहले सेट का विमोचन किया गया
- ⇒ भारतीय लेखांकन मानक (आईएफआरएस अभिसरित) – सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के प्रभाव का विश्लेषण और उद्योग का अनुभव
- ⇒ भारतीय लेखांकन मानक : प्रकटन जांच सूची
- ⇒ 1 अप्रैल, 2019 को प्रभावी होने वाले भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) के सार संग्रह के दूसरे सेट के ई-पाठ का विमोचन 1 मई, 2019 को किया गया। इसके तुरंत पश्चात्, आईएफआरएस भाग ख (दृष्टांत उदाहरण और कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश) और आईएफआरएस भाग ग (निष्कर्षों के लिए आधार) को अंतर्विष्ट करने वाली आईएफआरएस मानकों संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री को भी 7 मई, 2019 को जारी किया गया था।
- ⇒ इंडएएस कार्यान्वयन समिति के साथ संयुक्त रूप से जुलाई, 2018 में भारतीय लेखांकन मानकों : एक पर्यावलोकन के तीसरे संस्करण का विमोचन 1 जुलाई, 2018 को किया गया, जिसमें मार्च, 2018 तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इंडएएस में किए गए हाल ही के सभी संशोधनों को समाविष्ट किया गया था, विशेष रूप से राजस्व संबंधी मानक (इंडएएस 115) को जारी किए जाने और उससे संबंधित अन्य पारिणामिक संशोधनों को भी सम्मिलित किया गया था।
- ⇒ 1 जुलाई, 2019 को प्लेटिनम जयंती समारोहों के अवसर पर निम्नलिखित प्रकाशनों का विमोचन किया गया था :
 - लेखांकन मानक : क्लिक रेफरेंसर
 - लेखांकन मानकों का सार संग्रह
 - आईएफआरएस 09, वित्तीय लिखतें, एक अध्ययन : विश्व भर में बैंकों पर संपरिवर्तन संबंधी प्रभाव
 - बुलियन (स्वर्ण) को उधार देने और उधार लेने संबंधी व्यवहारों के संबंध में लेखांकन व्यवहार संबंधी तकनीकी गाइड
 - इंडएएस का सार संग्रह (मुद्रण पाठ)
 - भारतीय लेखांकन मानक : एक पर्यावलोकन का चौथा संस्करण, इंडएएस कार्यान्वयन समिति के साथ संयुक्त रूप से, जिसमें मार्च, 2019 तक कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इंडएएस में किए गए हाल ही के सभी संशोधनों को समाविष्ट किया गया था।

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति (सीएसएलबी)

आईसीएआई की तत्कालीन स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति (सीएसएलबी) ने वर्ष 2005 से, सतत रूप से सरकार के तीसरे टियर (स्थानीय – स्वशासन), अर्थात् स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) हेतु उच्च गुणवत्ता वाले प्रोद्भव लेखांकन ढांचे को विहित करने की दिशा में अथक कार्य किया था। सीएसएलबी शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएलबी)/अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएसबी) को दस्तावेजों/प्रारूपों संबंधी तकनीकी अंतःनिवेश भी उपलब्ध कराती रही है। सीएसएलबी स्थानीय निकायों और विभिन्न पणधारियों जैसे कि अंतःउपयोक्ताओं और नागरिकों को सरकारी और स्थानीय निकायों में लेखांकन संबंधी सुधार प्रक्रिया के फायदों के बारे में भी प्रशिक्षण प्रदान कर रही थी।

वर्ष 2019 के दौरान, स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों संबंधी समिति को वर्ष 2019-20 में लोक वित्त और स्थानीय निकायों के लेखांकन मानकों संबंधी समिति के रूप में पुनः नामित किया गया था और उसे निष्पादन हेतु उन कार्यों को सौंपा गया था जिनका निष्पादन वर्ष 2018 में लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति द्वारा किया जा रहा था।

1 अप्रैल, 2018 से 11 फरवरी, 2019 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप :

(I) स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) तैयार करना और अन्य परियोजनाएं :

- जारी किए गए एसएलबी : एसएलबी 2, 'नकद प्रवाह विवरण' और एसएलबी 20, 'संबंधित पक्षकार प्रकटन'
- स्थानीय निकायों द्वारा साधारण प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित अवधारणात्मक ढांचे को, उसके अंतिम अनुमोदन हेतु परिषद् को प्रस्तुत किया गया था।

(II) संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम :

- 19 मई, 2018 को जोधपुर (राजस्थान) में प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी) के साथ संयुक्त रूप से 'प्रत्यक्ष करों के अधीन विभिन्न मुद्दे (न्यास और स्थानीय निकाय)' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की जोधपुर शाखा द्वारा की गई थी।
- 24-25 अगस्त, 2018 को जयपुर (राजस्थान) में निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति (सीएलएंडसीजीसी) के साथ संयुक्त रूप से 'प्रवाह' विषय पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, जिसकी मेजबानी जयपुर, डीसीओ द्वारा की गई थी।
- 1 सितंबर, 2018 को भिलाई में 'आय-कर' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की भिलाई शाखा द्वारा की गई थी।
- 17-18 नवंबर, 2018 के दौरान रांची में 'सृजन : विकास की ओर' विषय पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की रांची शाखा द्वारा की गई थी।
- 24-26 नवंबर, 2018 के दौरान सालासर बालाजी (चुरू, राजस्थान) में बैंककारी, वित्तीय सेवाओं और बीमा संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से एक तीन दिवसीय आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की सीकर शाखा द्वारा की गई थी।
- 5-6 जनवरी, 2019 के दौरान उदयपुर में बैंककारी, वित्तीय सेवाओं और बीमा संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से, 'ज्ञानोदय – वृत्तिक उत्कृष्टता का परिदृश्य' विषय पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की उदयपुर शाखा द्वारा की गई थी।

(III) प्रस्तुत की गई तकनीकी टिप्पणियां

- अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएसबी) को दस्तावेजों/परामर्श पत्रों/ उद्भासन प्रारूपों : 'रणनीति और कार्ययोजना 2019-23' संबंधी दस्तावेज और आईपीएसएसबी के उद्भासन प्रारूप 64 'पट्टे' के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थी।
- 17 मई, 2018 को आयोजित जीएएसबी की 32वीं बोर्ड बैठक की कार्यसूची संबंधी दस्तावेजों, जीएएसबी की "सम्यक् प्रक्रिया" और "भारतीय शासकीय लेखांकन मानक और भारतीय शासकीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का पूर्व कथन", उपांतरित भारतीय शासकीय लेखांकन मानक (आईजीएस) 2, 'लेखा अनुदान संबंधी लेखांकन', उपांतरित आईजीएस 3, 'ऋणों और अग्रिमों का लेखांकन', और 30 अक्तूबर, 2018 को आयोजित जीएएसबी की 33वीं बोर्ड बैठक की कार्यसूची के संबंध में शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसबी) को टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थी।
- 16 और 18 अगस्त, 2018 के दौरान वियतनाम में आयोजित सीएपीए की पब्लिक सेक्टर वित्तीय प्रबंध समिति (पीएसएफएमसी) की बैठक की कार्यसूची संबंधी पत्रों पर अंतःनिवेश प्रस्तुत किए गए थे।

5.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएसबी)**(I) अभ्यावेदन/सुझाव**

रिपोर्टाईन अवधि के दौरान बोर्ड ने विभिन्न मंत्रालयों और विनियामकों को निम्नलिखित अभ्यावेदन/सुझाव प्रस्तुत किए थे :

- बोर्ड ने श्री वार्ड.एच. मालेगम, अध्यक्ष, आरबीआई द्वारा गठित एनपीए और कपटों संबंधी विशेषज्ञ समिति को "आरबीआई के कपटों संबंधी आदर्श निदेशों – वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई द्वारा रिपोर्टिंग, में सम्मिलित किए जाने के लिए पूर्व चेतावनी संकेतों संबंधी नए संकेतकों के लिए सुझाव" प्रस्तुत किए थे।
- अध्यक्ष, एएसबी ने 26 अक्तूबर, 2018 को एनएफआरए कार्यालय, नई दिल्ली में एनएफआरए के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ एक बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में अध्यक्ष, एएसबी ने, एएसबी के क्रियाकलापों और एएसबी द्वारा संपरीक्षा मानकों को तैयार तथा उन्हें जारी करने के लिए अनुसरित की जाने वाली मानक निर्धारक प्रक्रिया के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया था।

- सेबी ने, सेबी के 2015 के यथा संशोधित विनियमों के नए विनियम 33(8) संबंधी दिशा-निर्देशों (एलओडीआर) के संबंध में पुनरीक्षित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समूह का गठन किया गया था। समूह द्वारा तैयार किए गए प्रारूप दिशानिर्देशों के संबंध में आईसीएआई के अंतःनिवेशों की ईप्सा की गई थी। बोर्ड ने प्रारूप दिशानिर्देशों पर विचार किया था और उनके संबंध में सेबी को अपने मत प्रस्तुत किए थे।

(II) जारी किए गए प्रकाशन

बोर्ड ने साधारण रूप से संस्थान के सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले थे :

- संपरीक्षा उदघोषणाओं संबंधी हैंडबुक, 2019 संस्करण
- बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण, 2019 संस्करण
- कंपनी विवरणिकाओं में रिपोर्टों संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण (पुनरीक्षित 2019 संस्करण)
- एसए 230 संपरीक्षा संबंधी दस्तावेजीकरण संबंधी कार्यान्वयन गाइड (पुनरीक्षित 2018 संस्करण)
- वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा करने के लिए किसी नियोजन से त्यागपत्र देने/हटने संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- एसए 610 (पुनरीक्षित), आंतरिक संपरीक्षकों के कार्य का उपयोग संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- शहरी सुधार न्यासों और विकास प्राधिकरणों की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

(III) अन्य तकनीकी उपलब्धियां

- बोर्ड ने भू-संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश न्यासों (आईएनवीआईटी) संबंधी संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्रारूप को तैयार किया था और उसे आगे सेबी को प्रस्तुत किए जाने हेतु लेखांकन मानक बोर्ड को प्रस्तुत किया था।
- बोर्ड ने यथा संशोधित कंपनी (निक्षेपों को स्वीकार करना) नियम, 2014 के नियम 16 के अनुसरण में निक्षेपों की वापसी संबंधी दृष्टांतमक संपरीक्षक के प्रमाणपत्र को जारी किया था।
- बोर्ड ने, अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन बोर्ड द्वारा जनता की टिप्पणियों हेतु जारी आईएसए 315 (पुनरीक्षित), "सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान और उनका निर्धारण करना" के उद्भासन प्रारूप के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की थी।

(IV) सदस्यों के लिए पहले

- बोर्ड ने, सदस्यों की जागरुकता और वृत्तिक ज्ञानवर्धन के लिए संपरीक्षा मानकों, बैंक संपरीक्षा और अन्य संपरीक्षा संबंधी पहलुओं पर विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन कार्यक्रमों का आयोजन वर्ष के दौरान कोलकाता, इंदौर, मुंबई, जयपुर, बंगलौर, चेन्नई, कोयंबटूर, विशाखापट्टनम, बिलासपुर, भोपाल, सिलिगुड़ी, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, आसनसोल, भिलाई और रायपुर में किया गया था।
- बोर्ड ने, आईसीएआई की वृत्तिक विकास समिति के साथ संयुक्त रूप से जनवरी और फरवरी, 2019 के दौरान कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में बैंकों के केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों के लिए परस्पर क्रियाशील संगोष्ठियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया था।
- बोर्ड ने, नवंबर, 2018 में जयपुर में "संपरीक्षा और उससे परे" विषय पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें 2000 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था।
- बोर्ड ने मार्च, 2019 में भोपाल में बैंक संपरीक्षा, कंपनी अधिनियम और जीएसटी विषयों पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 500 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था।
- बोर्ड ने 4 सितंबर, 2018 को मुंबई में "सामान्य रूप से पाए जाने वाला एसए का अननुपालन और पुनरीक्षित रिपोर्टिंग मानकों" संबंधी विषय पर एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था।

- बोर्ड ने 8 अप्रैल, 2019 और 11 अप्रैल, 2019 को मुंबई में एसए 701, "स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख संपरीक्षा संबंधी विषयों की संसूचना" विषय पर एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था।
- पूर्व वर्षों की भांति बोर्ड ने, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षाओं के संबंध में सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विशेषज्ञों के आनलाइन पैनल का गठन किया था। इस पैनल ने 1 अप्रैल, 2019 से 15 अप्रैल, 2019 तक सदस्यों की शंकाओं का समाधान किया था।
- बोर्ड ने निम्नलिखित के संबंध में सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु उदघोषणाओं/ स्पष्टीकरणों को जारी किया था :
 - कंपनी (निक्षेपों को स्वीकार करना) नियम, 2014 के नियम 16 के अनुसरण में निक्षेपों की विवरणी संबंधी संपरीक्षक के प्रमाणपत्र के बारे में स्पष्टीकरण।
 - संपरीक्षा रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करते समय यूडीआईएन का उल्लेख करने संबंधी अपेक्षा।
 - बाह्य पुष्टिकरणों के लिए सूचना उपयोगिता (आईयू) मंच पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग करना।
- बोर्ड ने, संपरीक्षा पहलुओं के संबंध में सदस्यों से समय-समय पर प्राप्त विभिन्न प्रश्नों के उत्तर/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए थे।

(V) अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग

- अध्यक्ष, एएएसबी ने, सितंबर, 2018 में न्यूयार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड की बैठक में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था।
- अध्यक्ष, एएएसबी और उपाध्यक्ष, एएएसबी ने, दिसंबर, 2018 में न्यूयार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड की बैठक में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था।
- अध्यक्ष, एएएसबी ने, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के संपरीक्षा और आश्वासन संबंधी एक दल के साथ सितंबर, 2018 में लंदन में हुई बैठक में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था।
- अध्यक्ष, एएएसबी ने, नवंबर, 2018 में सिडनी में हुई आईएएसबी – एनएसएस बैठक में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था।
- उपाध्यक्ष, एएएसबी ने, मई, 2019 में पेरिस में हुई आईएएसबी – एनएसएस बैठक में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था।

5.4 बैंककारी, वित्तीय सेवा और बीमा समिति

समिति ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया था :

समिति ने 14 मई, 2018 को आयोजित एफआरडीआई विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में "वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा (एफआरडीआई) विधेयक, 2017" के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए।

- समिति ने 22-23 जून, 2019 के दौरान मुंबई में वित्तीय जगत के लिए ब्लॉक चेन संबंधी एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था।
- समिति ने 14 जून, 2019 को मुंबई में "भारत 2030 तक एक दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था : बैंकों की भूमिका" विषय पर दसवें बैंककारी और वित्तीय सम्मेलन का आयोजन करने के लिए आईएमसी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का सहयोग किया था।
- सदस्यों और साधारण जनता के फायदे हेतु, समिति के सहयोग से बैंककारी और वित्तीय सेवाओं से संबंधित 8 कार्यक्रमों का आयोजन आईसीएआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा किया गया था।

- समिति ने इस अवधि के दौरान वृत्तिक संगतता और हित वाले विषयों पर दो वेबकास्टों का भी आयोजन किया था।
- इस अवधि के दौरान, आईसीएआई की डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले सदस्यों के लिए अनुकूलन कार्यक्रमों के तीन बैचों का आयोजन किया गया था।

30 जून, 2019 तक डीआईआरएम पाठ्यक्रम के लिए 5244 रजिस्ट्रीकरण प्राप्त हुए थे।

5.5 व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीएमपी)

व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीएमपी) का सृजन फरवरी 2010 में एक अस्थायी समिति के रूप में किया गया था। इस समिति के प्रमुख उद्देश्य सीए फर्मों और साथ ही लघु तथा मध्यम व्यवसायियों के व्यवसाय पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाना है। समिति, प्रबंध परामर्शी सेवा फर्मों की नेटवर्किंग, विलयन और स्थापना के माध्यम से समेकन करके सीए फर्मों के बीच सक्षमता निर्माण के संबंध में जागरूकता का सृजन करने और बेहतर लेखांकन, संपरीक्षा और नैतिक मानकों के समेकन और स्थायित्व के फायदों के संबंध में कार्यशालाओं, सभाओं और शिखर सम्मेलनों का आयोजन करके संघ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाए जाने संबंधी कार्य करती है। समिति लघु और मध्यम व्यवसायियों को, कारबार समुदाय के बीच उनकी दृश्यता में सुधार लाने में सहायता करती है और साथ ही उनके लिए अतिरिक्त वृत्तिक अवसरों का सृजन भी करती है।

वर्ष के दौरान व्यवसाय में लगे सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीएमपी) ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए :

(I) कार्यालय प्रबंध

- समिति ने, आईसीएआई के व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों और सीए फर्मों हेतु वेब आधारित आईटीआर और टीडीएस विवरणी तैयार करने के लिए एक 'टैक्स क्लाउड' नामक साफ्टवेयर की व्यवस्था की है। पूर्वोक्त साफ्टवेयर व्यवसायियों और सीए फर्मों हेतु दो वित्तीय वर्षों के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। पूर्वोक्त साफ्टवेयर आय-कर विवरणी और टीडीएस विवरणी को तैयार करने में समर्थ बनाता है, सभी प्रकार की निर्धारण संबंधी सहायता उपलब्ध कराता है, जिसके अंतर्गत व्यष्टियों, एचयूएफ, फर्मों और कंपनियों का आय-कर निर्धारण भी है, सभी शीर्षों जैसे कि वेतन, गृह संपत्ति, पूंजी अभिलाभ, कारबार और वृत्ति, अन्य और छूट प्राप्त आय शीर्षों के अधीन आय-कर की संगणना करता है, आय-कर विवरणियों की ब्यौरेवार संगणना का सृजन करता है। कागज-पत्र फाइल करने हेतु पीडीएफ तथा ई-फाइलिंग हेतु एक्सएमएल तैयार करता है तथा सीए के लिए प्रत्येक रात्रि में क्लाउड सर्वरों में स्वतः डाटा बैकअप की व्यवस्था करता है।
- सदस्यों की एक उत्तम एंटी वायरस साफ्टवेयर तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए एक प्रमुख एंटी वायरस साफ्टवेयर प्रदाता के साथ करार किया गया है, जिसके अधीन उसने मार्च, 2018 से मार्च, 2020 के दौरान आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए एकल उपयोक्ता हेतु विशेष बट्टा प्राप्त कीमत पर एंटी वायरस साफ्टवेयर तक पहुंच बना सकेंगे। उपरोक्त साफ्टवेयर से संबंधित ब्यौरे www.icai.org/post.html?post_id=11505 पर उपलब्ध हैं।
- समिति ने, प्रभावी रूप से वृत्तिक व्यवसाय का प्रबंध करने के लिए, सेवारत सदस्यों/फर्मों हेतु क्लाउड साफ्टवेयर के रूप में डिजाइन किए गए व्यवसाय प्रबंध साफ्टवेयर की व्यवस्था की है। पूर्वोक्त साफ्टवेयर समनुदेशन प्रबंध के विस्तार क्षेत्र और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं – दीर्घकालिक, समनुदेशन प्रबंध – अल्पकालिक, कार्य आबंटन और उसकी ट्रेकिंग, टाइमशीट रिकार्डिंग, अंतरों और लाभ संबंधी विश्लेषण, छुट्टी प्रबंध, व्यय प्रबंध, बैठक संबंधी प्रबंध, मोबाइल आधारित जीपीआरएस आधारित उपस्थिति प्रबंध, मोबाइल ऐप और पोर्टल आधारित प्रणाली, ग्राहक के साथ संबंधों का प्रबंध (सीआरएम), बीजक तैयार करना, संग्रहण प्रबंध, बीआई और विश्लेषणात्मक उपकरण।

https://www.icai.org/new_post.html?post_id=15286

(II) बीमा स्कीमें

- एलआईसी समूह टर्म बीमा : आईसीएआई के सदस्यों के लिए एलआईसी के माध्यम से एक विशेष रूप से तैयार किए गए समूह टर्म बीमा। यह टर्म बीमा पालिसी किसी भी कारण से हुई मृत्यु के संबंध में कवर प्रदान करेगी।

इसके ब्यौरे https://www.icai.org/new_post.html?post_id=15416 पर उपलब्ध हैं।

- आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों के लिए मोटर यान बीमा : न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मोटर यान बीमा की व्यवस्था करने के लिए समिति द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह मोटर यान बीमा आधारीक रूप से सदस्यों के लिए तैयार किया गया है किंतु इसे आईसीएआई के छात्रों और कर्मचारियों को भी विस्तारित किया गया है। इस मोटर यान बीमा, जिसके लिए समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया जा रहा है, में अनेक मूल्यवर्धित विशिष्टियां हैं, जैसे कि निजी कार और दोहपिया वाहन, दोनों के लिए 65% छूट (तत्कालीन टैरिफ दर पर) का विशिष्ट प्रस्ताव आदि। सदस्य और छात्र इस मोटर यान बीमा पालिसी का आनलाइन रूप से <http://icai.newindia.co.in> वेबसाइट पर क्रय कर सकते हैं।
- व्यवसायरत सदस्यों/सीए फर्मों के लिए विशेष प्रीमियम पर आफिस प्रोटेक्शन शील्ड बीमा के लिए व्यवस्था : आईसीएआई की समिति ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए विशेष प्रीमियम पर आफिस प्रोटेक्शन शील्ड बीमा की व्यवस्था की है। पूर्वोक्त स्कीम के फायदों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक सदस्य और सीए फर्म पूर्वोक्त स्कीम के बारे में <http://icai.newindia.co.in> और आनलाइन सल्यूशन पर जानकारी ले सकती हैं।
- आईसीएआई के सदस्यों/सीए फर्मों के लिए वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा : समिति ने आईसीएआई के व्यवसायरत सदस्यों/फर्मों के लिए युक्तियुक्त प्रीमियम, अर्थात् बाजार दर से 85% तक की छूट सहित, पर विशेष रूप से तैयार किए गए वृत्तिक क्षतिपूर्ति बीमा की व्यवस्था की है। यह स्कीम आईसीएआई के व्यवसायरत सदस्यों/फर्मों के लिए उपलब्ध है। पूर्वोक्त स्कीम के फायदों का लाभ उठाने के इच्छुक सदस्य और सीए फर्म इस स्कीम के बारे में <http://icai.newindia.co.in> और आनलाइन सल्यूशन पर जानकारी ले सकती हैं।
- आईसीएआई के सदस्यों के लिए निजी दुर्घटना बीमा : समिति ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए निजी दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की है। निजी दुर्घटना बीमा पालिसी में मृत्यु/स्थायी सकल निःशक्तता, अंगों का कट जाना और स्थायी आंशिक निःशक्तता सम्मिलित हैं और इस पालिसी के अंतर्गत अस्पताल में दाखिल होने संबंधी व्ययों का प्रतिदाय भी सम्मिलित होगा। पूर्वोक्त स्कीम के फायदों का लाभ उठाने के इच्छुक सदस्य इस स्कीम के बारे में <http://icai.newindia.co.in> और आनलाइन सल्यूशन पर जानकारी ले सकते हैं।
- आईसीएआई के सदस्यों के लिए घरेलू बीमा : समिति ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के माध्यम से आईसीएआई के सदस्यों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए घरेलू बीमा की व्यवस्था की है। यह घरेलू बीमा पालिसी, भवन और उसमें रखे गए सामान के लिए अग्नि और अन्य समान प्रकार के जोखिमों, जिसके अंतर्गत एसटीएफआई और ईक्यू भी है, घर में संध लगाने, जिसके अंतर्गत चोरी और डकैती भी है, जेवरात और अन्य मूल्यवान वस्तुओं, नियोजक की वार्षिक मजदूरियों आदि संबंधी दायित्व के प्रति बीमा कवर उपलब्ध कराती है। पूर्वोक्त स्कीम के फायदों का लाभ उठाने के इच्छुक सदस्य इस स्कीम के बारे में <http://icai.newindia.co.in> और आनलाइन सल्यूशन पर जानकारी ले सकते हैं।

(III) सक्षमता निर्माण संबंधी उपाय

- उपापन संपरीक्षा के संबंध में विश्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन : समिति ने, उपापन संपरीक्षा और उससे संबंधित विषयों में आईसीएआई के सदस्यों के ज्ञान में अभिवृद्धि की व्यवस्था करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक के साथ किया गया ठहराव, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों हेतु संयुक्त प्रमाणन आधार पर उपापन प्रशिक्षण की प्रस्थापना करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य आईसीएआई के सदस्यों की बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में उपापन संबंधी अवसरों में भागीदारी को समर्थ बनाने के लिए उनकी सक्षमता में वृद्धि करके उन्हें विभिन्न समनुदेशनों हेतु तैयार करना है, जिसके अंतर्गत आईसीएआई की फर्मों और व्यक्ति सदस्यों के लिए बाह्य/आंतरिक संपरीक्षाएं ; उपापन संपरीक्षाएं/पश्च पुनर्विलोकन और अन्य परामर्श संबंधी समनुदेशन भी हैं।
- अपील प्राधिकरणों और कानूनी निकायों के समक्ष अपीलों को तैयार करने, विलेखों और दस्तावेजों तथा अभ्यावेदनों का प्रारूपण करने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : अपील प्राधिकरणों और कानूनी निकायों के समक्ष अपीलों को तैयार करने, विलेखों और दस्तावेजों तथा अभ्यावेदनों का प्रारूपण करने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को, सदस्यों के प्रभावी प्रारूपण कौशलों संबंधी ज्ञान में अभिवृद्धि करने और साथ ही सदस्यों को विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने से संबंधित विधिक उपबंधों से अवगत

कराने के लिए विकसित किया गया है। चूंकि, चार्टर्ड अकाउंटेंटों को विभिन्न अधिनियमों के अधीन इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई है कि वे विभिन्न अधिकरणों/अर्ध-न्यायिक निकायों के समक्ष एक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे अधिकरणों और अन्य अर्ध-न्यायिक निकायों के समक्ष उपस्थित होते हुए और साथ ही निगम जगत में अपनी वृत्तिक और दक्ष छवि को बनाए रखें। इस सकल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया गया है जिससे सदस्यों में दस्तावेजों का प्रारूपण करने और कानूनी निकायों के समक्ष उपस्थित होने संबंधी आवश्यक बुद्धिमत्ता में अभिवृद्धि को सुकर बनाया जा सके।

- धन प्रबंध और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (डब्ल्यूएमएफपी) : इस पाठ्यक्रम को सदस्यों हेतु नए कैरियर संबंधी अवसरों में वृद्धि करने के विचार से आरंभ किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य सदस्यों को, उन्हें प्रभावी निवेश रणनीति के माध्यम से निवेशों और सेवानिवृत्ति संबंधी फायदों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करके वित्तीय योजना और धन प्रबंध के क्षेत्र के सिद्धांतों के संबंध में जानकारी से सुसज्जित करना है। यह पाठ्यक्रम, वित्तीय सेवाओं में सदस्यों की, उनके कैरियर संबंधी अवसरों में वृद्धि करने के लिए मूल सक्षमता का निर्माण करने हेतु धन प्रबंध के व्यावहारिक प्रक्रियात्मक पहलुओं को विस्तृत रूप से सम्मिलित करता है। पाठ्यक्रम के व्यौरों हेतु <https://resource.cdn.icai.org/35876ccbcac25359-wmf-details.pdf> वेबसाइट देखें।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' नगरों में किए जाने वाले वृत्तिक समनुदेशनों हेतु सिफारिश की गई पुनरीक्षित न्यूनतम फीस का मान : समिति ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' नगरों में किए जाने वाले वृत्तिक समनुदेशनों हेतु सिफारिश की गई न्यूनतम फीस का पुनरीक्षण किया है। पूर्वोक्त ब्रोशर को संदर्भ हेतु भारत में सीए फर्मों के बीच परिचालित किया जाएगा।
- क्लिक इन साइट 2018 : समिति ने सीए भ्रातृसंघ के लिए, वृत्ति में हुई नवीनतम घटनाओं को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए क्लिक इन साइट 2018 को जारी किया है। इस क्लिक इन साइट में कर, लेखांकन और संपरीक्षा मानकों, सीमित दायित्व भागीदारी, प्रबंध परामर्श सेवाओं, विवरणों और मानकों, संपरीक्षा संबंधी मानकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही सीए छात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्ररूप अंतर्विष्ट हैं। यह https://www.icai.org/post.html?post_id=14719 पर उपलब्ध है।
- "सदस्यों और सीए फर्मों के लिए आईसीएआई के विनियामक पहलुओं संबंधी सुगम संदर्भिका" नामक ई-पुस्तक का प्रकाशन : "सदस्यों और सीए फर्मों के लिए आईसीएआई के विनियामक पहलुओं संबंधी सुगम संदर्भिका" नामक ई-पुस्तक एक संदर्भ पुस्तक है, जो व्यवसायियों को, आईसीएआई के विभिन्न विनियामक पहलुओं का अनुपालन करने संबंधी सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगी। यह, सदस्यों और सीए फर्मों के नामांकन, रजिस्ट्रीकरण और आईसीएआई के अन्य विनियामक पहलुओं जैसे वृत्ति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित जानकारी को अंतर्विष्ट करती है और यह व्यवसायियों के लिए अत्यंत फायदाप्रद सिद्ध होगी। यह https://www.icai.org/post.html?post_id=14807 पर उपलब्ध है।
- "आर्टिकलड/संपरीक्षा सहायकों के लिए विनियामक पहलुओं संबंधी सुगम संदर्भिका : यह पुस्तक एक संदर्भ पुस्तक है, जो व्यवसायियों और सीए फर्मों को ऐसी सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगी, जो आर्टिकलड/संपरीक्षा सहायकों के विभिन्न विनियामक पहलुओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक है। यह पुस्तक आर्टिकलड/संपरीक्षा सहायकों को उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे नियोजन, वृत्तिका/पारिश्रमिक, कार्य घंटों और सीए फर्मों/व्यवसायियों से संबंधित विभिन्न विनियामक पहलुओं का अनुपालन करने संबंधी सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगी। यह https://www.icai.org/post.html?post_id=15063&c_id=240 पर उपलब्ध है।
- सीए फर्मों की नेटवर्किंग : फर्मों की नेटवर्किंग ऐसी सुविधा है, जिसे सीए फर्मों को, उनके द्वारा बेहतर वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संगृहित संसाधनों का आदान-प्रदान करने हेतु सामुहिक संगम को तैयार किया जा सके तथा उन्हें बहु स्थानों पर उपलब्ध कराया जा सके। समिति ने, सीए फर्मों के समेकन – नेटवर्किंग की विरचना में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों पर विचार किया है। इस संबंध में, आने वाली विभिन्न बाधाओं की समीक्षा की गई है और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए समिति ने सदस्यों और फर्मों को नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी पुनरीक्षित मार्गदर्शनों को उपयुक्त रूप से अंतिम रूप प्रदान किया है, जिससे इसे सुगमता से अंगीकृत किया जा सके।

(IV) ज्ञान का आदान-प्रदान और उसमें अभिवृद्धि

- आईसीएआई लर्निंग कर्व – बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों द्वारा शंकाओं का समेकन करने और शंकाओं के लिए समाधान उपलब्ध कराना और लाइव वेबकास्ट : समिति ने विभिन्न वृत्तिक मुद्दों पर शंकाओं का समेकन करने और शंकाओं के लिए समाधान उपलब्ध कराने के लिए आईसीएआई के पोर्टल आईसीएआई लर्निंग कर्व का शुभारंभ किया था, जो बहु-प्रक्रमों में इन शंकाओं के उत्तर प्रदान करता है ताकि व्यवसाय पोर्टफोलियो और अन्य पहलुओं के संबंध में अभिवृद्धि को सुकर बनाया जा सके। समिति, पूर्वोक्त पोर्टल के माध्यम से व्यवसायरत सदस्यों, महिला सदस्यों और वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न वृत्तिक मुद्दों से संबंधित शंकाओं को प्राप्त करती है। इन शंकाओं को बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है। शंकाओं के उत्तरों को समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले लाइव वेबकास्ट में अन्य वृत्तिक पहलुओं के साथ सम्मिलित किया जाता है।
- पोर्टल <http://kb.icai.org/> : आईसीएआई ज्ञान बैंक का द्वार : आईसीएआई के प्रकाशनों का समेकन : समिति ने आईसीएआई के सभी प्रकाशनों के समेकन हेतु पोर्टल <http://kb.icai.org/> : आईसीएआई ज्ञान बैंक के द्वार की व्यवस्था की थी। इस पोर्टल को खोज/समस्त खोज प्रसुविधा के लिए तथा प्रकाशनों के प्रबंध हेतु उन्नत रीति में तैयार किया गया है और उपयोक्ता किसी कुंजी शब्द के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की खोज करने में सक्षम हो सकेगा। प्रणाली ऐसे दस्तावेजों की एक सूची उपदर्शित करेगी, जिसमें प्रत्येक परिणाम को पृष्ठ संख्या, कुंजी वाक्य और पीडीएफ दस्तावेज को डाउनलोड और देखने के लिंक सहित दर्शित किया जाएगा। उपयोक्ता के पास इस दस्तावेज के लिंक को ई-मेल के माध्यम से साझा करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। अग्रिम खोज इंटरफेस, उपयोक्ता को प्रवर्ग, खंड, प्रकाशन की तारीख और परिणामों को पंक्तिबद्ध करने तक सीमित रहते हुए खोज तक पहुंच उपलब्ध कराएगा और ऐसे कुंजी शब्दों के लिए संबंधित अन्य खोजों को भी उपदर्शित किया जाएगा, जिनकी खोज अन्य उपयोक्ताओं द्वारा पूर्व में की गई है। उक्त पोर्टल में आईसीएआई के प्रकाशन, आईसीएआई के जर्नल और समितियों, शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों के न्यूज़ लैटर सम्मिलित होंगे और इसके अतिरिक्त अन्य प्रकाशनों को भी इस पोर्टल पर समेकित किया जाएगा।
- आईसीएआई के सदस्यों के लिए आईसीएआई कनेक्ट - सदस्यों के लिए एक स्व सेवा पोर्टल (<http://ssp.icai.org/>): समिति ने आईसीएआई कनेक्ट, आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक स्व सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। पूर्वोक्त एकल पटल स्व सेवा पोर्टल की विशिष्टियों में निजी प्रोफाइल और फर्म के संविधान, आईसीएआई की उदघोषणाओं, आईसीएआई को संदत्त फीसों और विनियामक प्रभारों के ब्यौरों, माई आर्टिकल्स के ब्यौरों को देखना, विनियामक प्ररूपों और आवेदननों की प्रास्थिति को ट्रेक करना, ई-सेवाओं, माई फर्मों, माई साफ्टवेयर, लेटर्स और प्रमाणपत्रों, प्रत्यय किए गए सीपीई घंटों, नेटवर्क करने, विलयन और निर्विलयन संबंधी दिशा-निर्देशों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना सम्मिलित है।
- समिति की अनन्य वेबसाइट www.icai.org.in : यह वेबसाइट सीए फर्मों के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध कराती है, जहां वे अपनी फर्मों के ब्यौरे अपलोड कर सकती हैं और इस प्रकार उन्हें सदस्यों और विश्व भर में व्यवसायरत सीए फर्मों तक पहुंच बनाने का अवसर प्राप्त होता है। यह वेबसाइट आईसीएआई के सदस्यों और सीए फर्मों के सुदृढीकरण के लिए भी एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करती है, जो नेटवर्किंग, विलयन और व्यवसाय के निगम रूप जैसे सुदृढीकरण उपायों को उपलब्ध कराती है।
- आईसीएआई के वरिष्ठ सदस्यों के लिए पोर्टल www.seniormembers.icai.org : समिति ने एक वेबसाइट अर्थात् www.seniormembers.icai.org को विकसित किया है, जो आईसीएआई के वरिष्ठ सदस्यों को, उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् नमनीय कार्य घंटों के समनुदेशन और साथ ही पूर्णकालिक कार्य प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है। साथ ही यह पोर्टल उद्योग की, ऐसे अनुभव प्राप्त योग्य पूल तक पहुंच स्थापित करने में सहायता करेगा, जिस तक सामान्य अनुक्रम में अन्यथा पहुंच संभव नहीं हो सकती थी। उक्त पोर्टल आईसीएआई के सभी वरिष्ठ सदस्यों के लिए उपयोगी और सुगम सिद्ध होगा।
- <https://www.cpeicai.org/cpe-qna/> के माध्यम से लीड - महिला सीए के लिए एक विविध समर्थन : व्यवसायरत सदस्यों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीएमपी) और सीपीई समिति द्वारा एक पहल : व्यवसायरत सदस्यों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीएमपी) और सतत वृत्तिक शिक्षा समिति (सीपीईसी) लीड - महिला सीए के लिए एक विविध समर्थन को प्रस्तुत करती हैं, जहां महिला सीए किसी भी क्षेत्र के संबंध में निजी विकास, वृत्तिक अभिवृद्धि और सशक्त बने रहने

की रणनीतियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकती हैं तथा अगुवाई कर सकती हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कुछ दिवसों के समय के भीतर विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा दिया जाएगा। शंकाओं के उठाए जाने को एक मंच, अर्थात् समाधान लिंक <https://www.cpeicai.org/cpe-qna/> के माध्यम से समर्थ बनाया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :

- प्रश्नकर्ता केवल निजी विकास, वृत्तिक अभिवृद्धि और सशक्त बने रहने की रणनीतियों और इस प्रकार अगुवाई करने से संबंधित प्रश्न पूछ सकती है, जो प्रश्नोत्तर सत्र के लिए खुले हैं।
 - सत्र से संबंधित विषयों से बाहर के प्रश्नों को विचार में नहीं लिया जाएगा।
 - आईसीएआई का यह प्रयास होगा कि पूछे गए प्रश्नों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सुसंगत समय-सीमा के भीतर प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराया जा सके।
 - वर्तमान सत्र में किसी प्रश्नकर्ता द्वारा केवल एक ही प्रश्न पूछे जाने की अनुमति है।
- सेतु – महिला सदस्यों और सीए फर्मों के बीच की खाई को भरना : समिति महिला सशक्तिकरण के संबंध में अपने सेतु कार्यक्रम, अर्थात् पूरे राष्ट्र में महिला सदस्यों और व्यवसायरत सीए फर्मों के बीच की खाई को भरने संबंधी कार्यक्रम के संचालन के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित नियमित कार्यक्रमों/संगोष्ठियों का भी आयोजन करती है।
- एसए से संबंधित नमूना जांच सूची संबंधी ई-पुस्तिका : व्यवसायियों और सीए फर्मों के लिए सुगम संदर्भिका : समिति ने, एसए से संबंधित नमूना जांच सूची संबंधी ई-पुस्तिका : व्यवसायियों और सीए फर्मों के लिए सुगम संदर्भिका नामक एक प्रकाशन निकाला है। इसका उपयोग व्यवसायियों और सीए फर्मों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए किया जाता है।

(V) समिति के प्रकाशन

- आय-कर व्यवसाय की कार्ययोजना : एक व्यवसायी के परिप्रेक्ष्य से, संबंधी ई-पुस्तक का प्रकाशन
- “पैक्टीकुअर” - चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु एक त्रैमासिक ई-न्यूज़ लैटर
- कंपनी अधिनियम, 2013 : एक व्यवसायी के परिप्रेक्ष्य से, संबंधी ई-पुस्तक का प्रकाशन
- जीएसटी की कार्ययोजना : एक व्यवसायी के परिप्रेक्ष्य से, संबंधी ई-पुस्तक का प्रकाशन

(VI) लाइव वेबकास्ट, सम्मेलन, संगोष्ठियां और आवासीय कार्यक्रम

सीसीबीएमपी ने, व्यवसाय प्रबंध, आय-कर के अधीन अपील संबंधी प्रक्रियाओं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों और रेरा में वृत्तिक अवसरों, बेनामी विधि तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, जीएसटी विवरणियों और संपरीक्षा में सामान्य त्रुटियों, प्रारूपण अभिवाक् और हस्तांतरण, कर संपरीक्षा, जीएसटी संपरीक्षा, आईटीआर प्ररूपों में हाल ही में हुए परिवर्तनों के विशेष संदर्भ से और इंड एएस के अधीन उचित मूल्य मापमान के संबंध में व्यवसायियों की सक्षमता निर्माण संबंधी उपायों हेतु आईसीएआई भवन, मुंबई, दिल्ली, इंदौर और बंगलौर में 11 लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया था। समिति ने वर्ष के दौरान, ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार समान विषयों पर भुवनेश्वर, मुन्नार, कोल्लम, शिरडी, मसूरी, तिरुपति, रांची, गोड, जोधपुर, एर्नाकुलम आदि में 56 राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों और आवासीय कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिनमें अनेक सदस्यों ने अति उत्साह से भाग लिया था।

5.6 सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति (सीपीई समिति)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) अपनी सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति (सीपीई समिति) (जो परिषद् वर्ष 2019-20 से अब सीपीई निदेशालय बन गया है) के माध्यम से कठोर परिश्रम कर रहा है और वह अपने सदस्यों की जानकारी को विद्यमान और उभरते क्षेत्रों में होने वाली हाल ही की घटनाओं से अद्यतन बनाने के लिए अनेकों पहलें आरंभ कर रहा है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति को सदैव शिक्षा की गुणवत्ता, उत्तम प्रशिक्षण और तकनीकी मानकों के संबंध में सुदृढ़ पकड़ के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार न केवल चार्टर्ड अकाउंटेंटों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं को अद्यतन बनाए रखें अपितु यह भी आवश्यक है कि वे नई कारबार संबंधी अपेक्षाओं और वृत्तिक परिस्थितियों की चुनौतियों का उत्तर देने के लिए नए ज्ञान को अर्जित करते रहें। सतत वृत्तिक शिक्षा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यह वृत्तिक अपने ज्ञान और कौशल को बनाए रखते हैं, उसमें सुधार करते हैं तथा उसे व्यापक बनाते हैं और साथ ही उनके वृत्तिक जीवनो के लिए अपेक्षित अंतः व्यक्तिगत गुणों को भी विकसित करते हैं।

(I) सदस्यों के पठन और विकास के लिए ठोस तंत्र

विभिन्न पीओयू के कार्यक्रम की मानीटरी, पर्यवेक्षण और पर्यावलोकन करना और सीपीई निदेशालय/परिषद् के निदेशों का उनके द्वारा अनुपालन किए जाने को सुनिश्चित करना। साथ ही सीपीई दिशानिर्देशों को भी समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

वैश्विक अपेक्षाओं और व्यवहारों के अनुरूप सीपीई प्रत्यय घंटों की अपेक्षाएं, जो सदस्यों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए (1 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2019) के तीन वर्षों के चालू ब्लॉक के दौरान लागू होंगी, निम्नानुसार हैं :

सदस्यों का प्रवर्ग	सीपीई घंटों संबंधी अपेक्षा
व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है) (सिवाय उनके, जो विदेश में रह रहे हैं)	120 (जिसमें से न्यूनतम 60 सीपीई घंटे संरचित पठन के होने चाहिए) - प्रत्येक कलेंडर वर्ष में संरचित पठन के न्यूनतम 20 सीपीई प्रत्यय घंटे
व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है)	90 (या तो संरचित अथवा असंरचित पठन) - प्रत्येक कलेंडर वर्ष में या तो संरचित या असंरचित पठन के न्यूनतम 20 सीपीई प्रत्यय घंटे
व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण न करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है) ; और ऐसे सभी सदस्य, जो विदेश में रह रहे हैं (चाहे वे व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं अथवा नहीं)	60 (या तो संरचित अथवा असंरचित पठन) - प्रत्येक कलेंडर वर्ष में या तो संरचित या असंरचित पठन के न्यूनतम 15 सीपीई प्रत्यय घंटे

सदस्यों को छूट :

- किसी सदस्य को केवल ऐसे विशिष्ट कलेंडर वर्ष के लिए ही छूट प्राप्त है, जिसके दौरान वह पहली बार सदस्यता प्राप्त करता है।
- निम्नलिखित वर्ग के सदस्यों को सीपीई प्रत्यय घंटों की अपेक्षा से छूट प्राप्त है :
 - व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण न करने वाले सभी सदस्य (जिनकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है)
 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अधिकरणों के न्यायाधीश
 - संसद् सदस्य/एमएलए/एमएलसी
 - राज्यों के राज्यपाल
 - केंद्र और राज्य सिविल सेवाएं
 - उद्यमी [वृत्तिक सेवाओं से भिन्न कारबार (विनिर्माण) संगठनों के स्वामी]
 - न्यायिक अधिकारी
 - सैन्य सेवा के सदस्य

अस्थायी छूट**(II) आईटी संबंधी पहलें**

- ई पठन मंच – डिजिटल पठन हब (<https://icai.org/elearning>) : समिति ने ई पठन मंच – डिजिटल पठन हब को विकसित किया है। इस हब तक सदस्य अपनी एसएसपी लॉगिन अंतर्वस्तु के साथ (<https://icai.org/elearning>) लिंक के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं। सदस्य इस मंच के माध्यम से अपने वृत्तिक पठन संबंधी प्रत्यय (असंरचित सीपीई घंटों) को अर्जित कर सकते हैं, जहां पठन को वीडियो, प्रस्तुतीकरणों, संदर्भ सामग्री, मार्गदर्शक टिप्पणों आदि के माध्यम से डेस्कटाप और मोबाइल डिवाइस मोड, दोनों रूपों में सुकर बनाया जाता है। आने वाले समय में, यह पोर्टल संरचित पठन के माध्यम से सीपीई प्रत्यय घंटों के अर्जन को भी सुकर बनाएगा।

- समाधान : सीपीई – प्रश्नोत्तर ई-समाधान मंच : समाधान एक सीपीई – प्रश्नोत्तर ई-समाधान मंच है, जिसके माध्यम से सदस्य विशेषज्ञों तक पहुंच बना सकते हैं और सतत जानकारी के लिए तथा व्यवसाय के चुने गए क्षेत्रों में शंकाओं के समाधान संबंधी अनुभवों हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
- मेरा सीपीई – आपकी मर्जी का सीपीई कार्यक्रम – यह अवधारणा सदस्यों के लिए एक ऐसा विकल्प उपलब्ध कराती है, जिसके द्वारा वे मेरे सीपीई – सीपीई कार्यक्रमों के लिए अपनी मर्जी की कार्यक्रम संबंधी अधिमानताओं को गूगल फोरम पर उस कार्यक्रम को चुनकर, जिसमें वे दिलचस्पी रखते हैं, अद्यतन कर सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार प्राप्त हुई अधिमानताओं का सकल योग लगाया जा सके और संबंधित कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) को वर्ष के अनुक्रम के दौरान इन कार्यक्रमों को आयोजित करने की संसूचना दी जा सकती है।
- आईसीएआई – आईसीई : आईसीएआई परस्पर क्रियाशील सीपीई संबल (www.ice.icaai.org) : इस कार्यक्रम को सीपीई कार्यक्रमों से पूर्व और उसके दौरान प्रश्न पूछे जाने तथा मतदान कराए जाने के लिए सीपीई समिति द्वारा विकसित किया गया है। सीपीई – ई-पहल प्रयासों के भाग रूप में अब आईसीएआई – आईसीई के एक संपूर्ण पाठ को, विभिन्न पीओयू द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी सीपीई कार्यक्रमों के लिए समर्थ बनाया गया है, जिसके माध्यम से वक्ताओं से कार्यक्रम से पूर्व और कार्यक्रम के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनमें से अनेक का उत्तर वक्ताओं द्वारा समय की उपलब्धता के अनुसार दिया जाता है।
- आनलाइन फीडबैक तंत्रों का विकास और कार्यान्वयन (www.ice.icaai.org) : समिति ने फीड बैक तंत्र और सकल सीपीई मानीटरी ढांचे के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न आनलाइन फीडबैक प्रारूपों को विकसित किया है, अर्थात् क्लिक फीड बैक प्रारूप, ब्यौरेवार फीडबैक प्रारूप तथा मानीटर फीड बैक प्रारूप।
- सीपीई पोर्टल को नई विशिष्टियों के साथ मजबूत बनाना तथा उसका अद्यतन करना : एक समर्पित सीपीई पोर्टल (www.ice.icaai.org) को, सदस्यों और पीओयू की सुविधा हेतु स्थापित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सदस्य होने वाले सीपीई आयोजनों के संबंध में पीओयू-वार, नगर-वार और विषयवार खोज कर सकते हैं तथा उनके संबंध में सूचनाओं को प्राप्त किए जाने संबंधी अपनी अधिमानताओं का प्रबंध कर सकते हैं। इस पोर्टल में कार्यक्रम से पूर्व और सीपीई घंटों के प्रत्यय के पश्चात् ई-मेल के माध्यम से सूचनाओं की सुविधा उपलब्ध है।
- उपरोक्त क्रियाकलापों तक, एंड्रायड और आईओएस, दोनों मंचों पर उपलब्ध आईसीएआई की मोबाइल ऐप पर “सीपीई कार्यक्रम” खंड के माध्यम से केवल एक बटन दबाकर पहुंच बनाई जा सकती है।

(III) अन्य क्रियाकलाप

- ई-न्यूज़ लैटर : त्रैमासिक ई-न्यूज़ लैटर के 20वें संस्करण को निकाला गया था, जिससे सीपीई निदेशालय द्वारा हाल ही में की गई पहलों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके।
- वैश्विक सत्ता बनना : सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से 14 सीपीई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरों का आयोजन आस्ट्रेलिया, कैंडी और कोलंबो (श्रीलंका), बाली (इंडोनेशिया), बैंकाक (थाइलैंड), लंकावी (मलेशिया), कजाकिस्तान, बीजिंग (चीन), सिंगापुर, फुकेट (थाइलैंड), दुबई, मस्कट (ओमान) में किया गया था।
- ब्रांड और क्षमता निर्माण : आईसीएआई, अपने सदस्यों को ऐसे वृत्तिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों, जो पूरे विश्व में हो रहे हैं, के संबंध में, कक्षा पठन, ई पठन पद्धति, घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रमों, वेबकास्टों, जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के माध्यम से निरंतर उनके कौशलों में सुधार करने की प्रक्रिया को अपनाते हुए उन्हें जागरूक बनाने और उन्हें उससे अवगत कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। उसकी कुछ उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :
 - आईसीएआई के सीपीई निदेशालय/केंद्रीय समितियों/बोर्डों द्वारा वृत्तिक हितों के उभरते विषयों से संबंधित विभिन्न विषयों पर 66 वेबकास्टों का आयोजन किया गया था। वेबकास्टों की रिकार्डिंग www.icaaitv.com पर उपलब्ध है।
 - सीपीई समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 41 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और उनकी मेजबानी देश के विभिन्न भागों में आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं द्वारा की गई थी।

- आईसीएआई की विभिन्न कार्यक्रम आयोजक ईकाईयों (पीओयू) के द्वारा वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों पर देश भर में सदस्यों के लिए 9109 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- आईसीएआई की केंद्रीय समितियों के माध्यम से सदस्यों के लिए आईसीएआई के जीएसटी, धन शोधन निवारण विधियों, धन प्रबंध और वित्तीय योजना, बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा, इंड एस, न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने, आदि संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, अपीलों को तैयार करने, अपील प्राधिकरणों और कानूनी निकायों आदि के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु विलेखों और दस्तावेजों तथा अभ्यावेदनों के प्रारूपण से संबंधित 224 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- आईसीएआई – आरबीओ द्वारा आयोजित रजिस्ट्रीकरण पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रमों के 26 बैच।
- आईआईआईपीआई द्वारा आयोजित रजिस्ट्रीकरण पूर्व शिक्षा पाठ्यक्रमों के 18 बैच।
- आईसीएआई की केंद्रीय समितियों के माध्यम से 133 सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) संबंधी अर्हता-पश्चात् पाठ्यक्रम, बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा (डीआईआरएम और अंतर्राष्ट्रीय कराधान आदि) का आयोजन किया गया था।
- देश के मुफसिल/दूरस्थ स्थानों में अवस्थित सदस्यों को उनके निकट स्थित स्थानों पर सीपीई क्रियाकलापों में भाग लेने में सहायता करने के लिए 30 और सीपीई पीओयू आरंभ किए गए थे, जिससे भारत और विदेशों में 610 सीपीई पीओयू का एक सुदृढ़ नेटवर्क स्थापित हो गया है।

(IV) समाज की सहायता करना – राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

आईसीएआई, देश के विभिन्न भागों में, सरकार की नई पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए अपनी सीपीई कार्यक्रम आयोजक ईकाईयों के सुदृढ़ नेटवर्क आधार के माध्यम से निम्नलिखित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है :

- सीपीई पीओयू द्वारा विमुद्रीकरण, काला धन, बेनामी संव्यवहार और अप्रकटित आय संबंधी 113 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
- सीपीई पीओयू द्वारा देश के विभिन्न भागों में जीएसटी संबंधी 2703 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें जीएसटी संपरीक्षा से संबंधित 657 विनिर्दिष्ट कार्यक्रम सम्मिलित थे, जिनका आयोजन सीपीई पीओयू द्वारा देश के विभिन्न भागों में किया गया था।
- रेरा (भू-संपदा विनियामक अधिनियम) संबंधी 291 कार्यक्रम।
- आईसीडीएस (आय की संगणना और प्रकटन मानक) संबंधी 129 कार्यक्रम।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी 203 कार्यक्रम।
- कंपनी अधिनियम संबंधी 256 कार्यक्रम।
- निवेशक जागरूकता संबंधी 35 कार्यक्रम।
- वृत्तिक नैतिकता संबंधी 21 कार्यक्रम।
- 21 जून को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तनाव प्रबंध, जीवन शैली प्रबंध, जहां योग जीवन का सही मार्ग है, कार्य जीवन संतुलन आदि विषयों पर 52 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- सीपीई पीओयू द्वारा देश के विभिन्न भागों में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी 9 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

5.7 निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति (सीएल एंड सीजीसी) तथा सीएल एंड सीजीसी का दिवाला और शोधन अक्षमता विधियों संबंधी समूह

अ. निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति

निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति का उद्देश्य सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ एक उचित निगम व्यवस्था की स्थापना को सुकर बनाना है और ऐसा सरकार के साथ सहायक प्रयासों के माध्यम से किया जाता है जिससे विनियामक ढांचे, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 की नियम बनाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा सके और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ नियमित रूप से परस्पर क्रियाकलाप

किए जाते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में उन्हें नियमित रूप से प्रतिवेदन/सुझाव/अंतःनिवेश उपलब्ध कराए जाते हैं।

(I) कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रतिवेदन

समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 के सुचारु कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ परस्पर क्रिया करती है। उसने मंत्रालय को निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे :

वर्ष 2019-2020 के दौरान

- आईसीएआई की इस संबंध में सिफारिशों को, कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के अधीन कौन सी बातें प्रबंध सेवाओं का गठन करेंगी/नहीं करेंगी, जून, 2019 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।
- आईसीएआई के, श्री उदय कोटक समिति के अधीन निगम शासन से संबंधित समिति की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों पर सुझावों को जून, 2019 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था :
 - आईसीएआई की सुदृढीकरण संबंधी भूमिका – आईसीएआई की प्रवर्तन/अनुशासन संबंधी प्रक्रिया के संबंध में सिफारिशें।
 - आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्टिंग को मजबूत करने।
 - संपरीक्षा क्वालिटी सूचकों के संबंध में बेहतर पारदर्शिता।
 - क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी) के स्वतंत्र कार्यकरण को मजबूत करना, वर्तमान विनियामक उपबंध।
- यूके, यूएस, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर द्वारा बाह्य संपरीक्षकों को, उनके कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् आंतरिक संपरीक्षकों के रूप में नियुक्त करना तथा विलोमतः हेतु अनुसरित किए जाने वाले व्यवहारों के संबंध में आईसीएआई के सुझावों को जून, 2019 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।
- कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और सीएसआर से संबंधित जारी किए गए परिपत्रों में सीएसआर से संबंधित उपबंधों के बारे में आईसीएआई की टीका-टिप्पणियों/सुझावों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित सीएसआर संबंधी उच्चस्तरीय समिति को मई, 2019 में प्रस्तुत किया गया था।
- एक्टिव प्ररूप को फाइल किए जाने के संबंध में, जहां कंपनियों द्वारा 1 अप्रैल, 2014 से 19 अक्तूबर, 2014 की अवधि के लिए प्ररूप जीएनएल – 2 को पहले ही फाइल कर दिया गया है, वहां एडीटी-1 को फाइल करने हेतु अतिरिक्त फीस को वापस लेने से संबंधित अनुरोध को अप्रैल, 2019 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 15.06.2019 तक प्ररूप एडीटी-1 को फाइल करने हेतु अतिरिक्त फीस के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है तथा उसे माफ कर दिया है।

वर्ष 2018-2019 के दौरान

- कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में सुझाव।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन संपरीक्षा चक्रानुक्रम और कुछ सीए फर्मों द्वारा कानूनी संपरीक्षक के रूप में आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति और विलोमतः हेतु अपनाए जाने वाले व्यवहार के संबंध में आईसीएआई के सुझाव।
- डीआईआर-3 केवाईसी को फाइल करने की अंतिम तारीख को 15 दिनों के लिए अर्थात् 30 सितंबर, 2018 तक विस्तारित करने हेतु अनुरोध।
- कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अहंताएं) तीसरा संशोधन नियम, 2018 की प्रारूप अधिसूचना से संबंधित टिप्पणियों/सुझावों के संबंध में आईसीएआई के सुझाव जुलाई, 2018 में प्रस्तुत किए गए थे।
- प्रारूप राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, जून 2018 में अंतर्बलित प्रमुख मुद्दों को 18 जुलाई, 2018 को प्रस्तुत किया गया था।
- प्रारूप एनएफआरए नियम, जून, 2018 से संबंधित आईसीएआई की चिंताओं को जुलाई, 2018 में प्रस्तुत किया गया था।

- कंपनी (संपरीक्षा और संपरीक्षक) संशोधन नियम, 2018 के संबंध में सुझावों को मई, 2018 में प्रस्तुत किया गया था।
- प्रादेशिक निदेशकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 के अधीन संपरीक्षकों को हटाए जाने के लिए आवेदनों के संबंध में की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित प्रस्तुतीकरण मई, 2018 में किया गया था।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनता की टिप्पणियों के लिए 2013 में जारी प्रारूप राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियमों के संबंध में आईसीएआई के सुझावों को मई, 2018 में प्रस्तुत किया गया था।
- प्रारूप कंपनी (फायदाग्राही हित और महत्वपूर्ण फायदाप्रद हित) नियम, 2018 के संबंध में आईसीएआई के सुझावों को अप्रैल, 2018 में प्रस्तुत किया गया था।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में 20 नवंबर, 2018 तक टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना जारी की थी। इस संबंध में आईसीएआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में अपने सुझावों को नवंबर, 2018 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया था।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने आईसीएआई से, प्रारूप कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के संबंध में टिप्पणियां/सुझाव देने का अनुरोध किया था। निगम विधि और निगम शासन समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक को बनाए रखने और स्वतंत्र निदेशकों की अर्हताओं के संबंध में कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 की प्रारूप अधिसूचना पर विचार-विमर्श किया था। इस संबंध में आईसीएआई ने निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए जुलाई, 2018 में अपने सुझाव कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किए थे :
 - चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के अधीन डाटा बैंक को वर्ष 2014 में पहले ही तीन संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में विकसित कर लिया गया था, इसलिए, नए पोर्टल का विकास करने की बजाए उसे अपनाया जाए और विचार में लिया जाए।
 - प्रारूप नियम, स्वतंत्र निदेशक बनने के लिए आईसीएआई द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के बारे में उल्लेख करता है और साथ ही छूट के लिए मानदंडों को अधिकथित करता है। आईसीएआई का सुझाव यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंटों को, उनकी वृत्तिक अर्हता के कारण यह प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा करने से छूट प्रदान की जानी चाहिए।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 के अधीन संपरीक्षकों को हटाए जाने से संबंधित मामलों में कार्यवाही करने हेतु प्रादेशिक निदेशकों के लिए ब्यौरेवार दिशानिर्देशों की विरचना करके उन्हें जारी करे। एक बार नियुक्त किए गए संपरीक्षकों को शेयर धारकों द्वारा हटाए जाने को सामान्यतः उसी समय अनुज्ञात किया जाना चाहिए जब उपयुक्त कारणों सहित पूर्ण औचित्य साबित हो जाए। इस संबंध में, समिति ने एक ब्यौरेवार जांच सूची तैयार की है, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(II) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को प्रतिवेदन

वर्ष 2018-2019 के दौरान

प्रस्तावित सेबी (प्रतिभूति बाजार में प्रत्ययी) (संशोधन) विनियमों के संबंध में परामर्शी पत्र पर आईसीएआई के सुझावों को जुलाई, 2018 में प्रस्तुत किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, मूल्यांकक और लागत लेखापाल जैसे पूंजी बाजार के 'प्रत्ययी', जो कंपनियों द्वारा निधियों को जुटाने, परस्पर निधियों और संबंधित अन्य प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रमाणपत्रों को जारी करते हैं, का विनियमन करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप नियमों से संबंधित एक परामर्शी पत्र जारी किया था। सेबी ने इन प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से टिप्पणियों को आमंत्रित किया था। इस संबंध में, आईसीएआई के परामर्शी पत्र से संबंधित सुझावों/परिवर्तनों को अगस्त, 2018 में सेबी को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उक्त परामर्शी पत्र के संबंध में आक्षेप किए गए थे।

(III) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के गठन के संबंध में

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अनुसार 13 नवंबर, 2018 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), 2018 को अधिसूचित किया है।

- आईसीएआई ने एनएफआरए के गठन और एनएफआरए से संबंधित प्रारूप नियमों के बारे में अपनी चिंताओं को नियमित रूप से प्रस्तुत किया है।

1 मार्च, 2018 से, जब संघ के मंत्रिमंडल ने एनएफआरए की स्थापना का विनिश्चय किया था, आईसीएआई द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- 14 मार्च, 2018 – धारा 132 को अधिसूचित करने संबंधी विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
- 17 मार्च, 2018 – प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा एनएफआरए की स्थापना से संबंधित मंत्रिमंडल के तारीख 1 मार्च, 2018 के निर्णय के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए समय मांगा गया था।
- 8 मई, 2018 – कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव से प्राप्त अनुरोध के आधार पर प्रारूप नियम, 2018 के संबंध में आईसीएआई की चिंताओं को प्रस्तुत किया।
- 5 जून, 2018 – प्रारूप नियम, 2018 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा टिप्पणियों/सुझावों हेतु आईसीएआई को अग्रेषित किया गया था।
- 18 जून, 2018 – कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव को एक पत्र, जिसके द्वारा यह सूचना दी गई थी कि प्रारूप एनएफआरए नियम, 2018 का विस्तार क्षेत्र उससे परे है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के सारवान उपबंधों में अंतर्विष्ट है।
- 5 जुलाई, 2018 - प्रारूप नियम, 2018 के संबंध में आईसीएआई के सुझावों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया।
- 18 जुलाई, 2018 - प्रारूप एनएफआरए नियम, 2018 के संबंध में चिंताओं से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष किया गया।
- 30 जुलाई, 2018 – एनएफआरए को अधिसूचित न करने के संबंध में विचार करने हेतु अनुरोध करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री को अपील।
- 30 सितंबर, 2018 – कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव को एक पत्र, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रारूप नियमों को आईसीएआई के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए।
- अक्तूबर, 2018 में, मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देते हुए दो रिट याचिकाएं फाइल की गई हैं। दोनों रिट याचिकाओं में आईसीएआई को प्रत्यर्थी बनाया गया है।
- आईसीएआई ने मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व महा अटार्नी से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की सांविधानिक विधिमान्यता के संबंध में राय की ईप्सा की थी।

अपनी विधिक राय में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह राय दी है कि “राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन सांविधानिक रूप से विधिमान्य नहीं है और वह आईसीएआई की शक्तियों का अतिक्रमण करता है और सीए अधिनियम के उपबंध, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों पर अभिभावी नहीं हैं”। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे और यह राय दी कि “मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकचाहट नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 द्वारा ईप्सित निर्बंधनों का प्रयोग अनुच्छेद 19(6) के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। यह निर्बंधन अवैध तथा मनमाना है और साथ ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है।”

उन्होंने यह भी कथन किया कि “कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के विभिन्न उपबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाएं पहले ही मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं। मुझे यह सूचना दी गई है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 को तारीख 03.10.2018 तक इस आधार पर आस्थगित रखने का आदेश पारित किया है कि आप सीए अधिनियम के अधीन विद्यमान प्राधिकरण के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक अनुशासन प्राधिकरण स्थापित नहीं कर सकते और वह भी किसी पृथक् अधिनियम द्वारा जहां इस प्रकार गठित प्राधिकरण में गैर-वृत्तिक व्यक्ति

सम्मिलित हैं। यह प्रश्न उठाने वाला व्यक्ति पहले ही उक्त याचिका में एक पक्षकार है और वह इसका समर्थन कर सकता है तथा उसमें इस प्रकार का कथन कर सकेगा।”

- 3 अक्तूबर, 2018 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फाइल की गई याचिका पर सुनवाई की और निम्नलिखित आदेश पारित किया :

“रिट याचिका संख्या डब्ल्यू.पी.(सी)10537/2018 और सीएम संख्या 41116/2018 में डब्ल्यू.पी.(सी)10537/2018 और सीएम संख्या 41116/2018 (आस्थगन के लिए) समाविष्ट हैं, इस संबंध में कारण बताओ सूचना जारी करें कि अंतिम निर्णय क्यों न जारी कर दिया जाए, जिसका उत्तर 16 जनवरी, 2019 तक दिया जाना था।

आज से 4 सप्ताह के भीतर शपथ पत्रों को फाइल किया जाए।

इस दौरान याचियों के संगमों के सदस्यों और प्रत्यर्थी सं. 3/संस्थान के विरुद्ध, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132(2) और 132(4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के कारण कोई अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ न की जाए। 16 जनवरी, 2019 को सूचीबद्ध किया जाए।”

- 12 अक्तूबर, 2018 – कारपोरेट कार्य मंत्रालय को एक पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संस्थान की परिषद् ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन के विषय पर विचार किया है और उसकी प्रथमदृष्टया राय यह थी कि वह असांविधानिक है तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के उपबंधों के विरुद्ध है और इसलिए उसने उसके सदस्यों के एक समूह का गठन करने का विनिश्चय किया, जो इस विषय की वृहत्तर पणधारियों के परामर्श से आगे और समीक्षा करेगा।
- 13 नवंबर, 2018 को केंद्रीय सरकार ने एनएफआरए नियम, 2018 को अधिसूचित किया।

(IV) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से परस्पर क्रिया

आईसीएआई नियमित रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय से परस्पर क्रिया करता रहा है और कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्बलित मुद्दों का समाधान करने और उसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए विधेयक के प्रक्रम से ही विभिन्न मुद्दों पर उसके संबंध में विभिन्न प्रतिवेदन/सुझाव/अंतःनिवेश नियमित रूप से प्रस्तुत करता रहा है।

आईसीएआई, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रमुख संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए गठित कंपनी विधि समिति द्वारा अपनाई गई परामर्शी प्रक्रिया का भाग था। साथ ही आईसीएआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 के मुद्दों पर वित्त संबंधी माननीय संसदीय स्थायी समिति के समक्ष भी प्रस्तुतीकरण किया था।

(V) कंपनी अधिनियम, 2013 में विधि बनाने की प्रक्रिया को सुकर बनाना

- आईसीएआई कारबार करने की सुगमता संबंधी सूचकों, “किसी कारबार को आरंभ करने”, “दिवाला का समाधान करने” और “अल्पसंख्यक निवेशकों की संरक्षा करने” संबंधी कार्यबल का एक सदस्य है।
- आईसीएआई, एमसीए-21 भाग 3 को तैयार करने वाले कारपोरेट कार्य मंत्रालय के नीतिगत सलाहकार समूह का एक सदस्य है।
- आईसीएआई कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने संबंधी कार्यकरण समिति का सदस्य है।
- आईसीएआई कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने से संबंधित सुझावों की समीक्षा करने वाले उप समूह (2) का सदस्य है।
- आईसीएआई, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वयन में सामने आने वाले मुद्दों की पहचान करने और उनके संबंध में उपायों का और समाधान का सुझाव देने वाली दिवाला विधि समिति के सदस्य के रूप में योगदान कर रहा है।

- आईसीएआई कंपनी (निक्षेपों को स्वीकार करना) नियम, 2014 की समीक्षा करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सृजित समूह का सदस्य है।
- आईसीएआई वाणिज्य और उद्योग के पीएचडी चैम्बर की कंपनी विधि और निगम शासन समिति का एक सदस्य है।
- आईसीएआई गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के अन्वेषण संबंधी मैनुअल के परिशिष्ट के प्रारूपण संबंधी समिति का एक सदस्य है।
- आईसीएआई निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन की शासी परिषद् का एक सदस्य है।

(VI) इस संबंध में कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के अनुसार कौन सी बातें प्रबंध सेवाओं का गठन करेंगी/नहीं करेंगी, आईसीएआई के सुझाव जून, 2019 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए थे

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 144(ज) के अनुसार, किसी संपरीक्षक द्वारा कंपनी को प्रबंध सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं। तथापि, अधिनियम “प्रबंध सेवाओं” पद को परिभाषित नहीं करता है। दूसरी ओर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आईसीएआई नैतिक संहिता, 2009 और आईसीएआई पुनरीक्षित नैतिक संहिता, 2019 में ऐसी सेवाओं से संबंधित सिद्धांत अंतर्विष्ट हैं, जिन्हें किसी व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रदान किया जा सकेगा।

तदनुसार, आईसीएआई द्वारा एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया है, जिसमें आईसीएआई नैतिक संहिता, 2009 और आईसीएआई पुनरीक्षित नैतिक संहिता, 2019, आईईएसबीए पुनरीक्षित नैतिक संहिता, 2018 के उपबंधों और यूएसए, आस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में विद्यमान व्यवहारों पर विचार किया गया है।

आईसीएआई की उन सेवाओं से संबंधित सिफारिशों को, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144(ज) के अधीन प्रबंध सेवाओं के रूप में विचार में लिया जा सकता है और साथ ही ऐसी विस्तृत सेवाओं से, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144(ज) के अधीन प्रबंध सेवाओं के रूप में नहीं माना जा सकेगा, संबंधित सिफारिशों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

(VII) प्रभाग 1 – गैर इंडएस – कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण (पुनरीक्षित जुलाई, 2019 संस्करण)

ऐसी कंपनियों द्वारा, जिनसे लेखांकन मानकों के अनुसार उनके वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाना अपेक्षित नहीं है, वित्तीय विवरणों के तैयार किए जाने को सुकर बनाने के लिए, समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 प्रभाग 1 – गैर इंड एस संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणों का पुनरीक्षण किया है। पुनरीक्षित मार्गदर्शक टिप्पण जारी कर दिए गए हैं।

(VIII) प्रभाग 2 – इंडएस – कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण (पुनरीक्षित जुलाई, 2019 संस्करण)

ऐसी कंपनियों द्वारा, जिनसे इंड एस अनुसूची 3 के अनुसार उनके वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाना अपेक्षित है, वित्तीय विवरणों के तैयार किए जाने को सुकर बनाने के लिए, समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 प्रभाग 2 – इंड एस संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणों का पुनरीक्षण किया है। पुनरीक्षित मार्गदर्शक टिप्पण जारी कर दिए गए हैं।

(IX) कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न – पुनरीक्षित जुलाई, 2019 संस्करण

पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, जिसके अंतर्गत कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 संबंधी अधिसूचना भी है, जिसमें अनेक प्रमुख संशोधन किए गए थे, समिति ने “कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न” नामक प्रकाशन के पुनरीक्षण का कार्य आरंभ किया था। पुनरीक्षित प्रकाशन को हाल ही में जारी किया गया है।

(X) एनबीएफसी, जिनसे भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएस) का अनुपालन अपेक्षित है, के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के प्रभाग 3 के मार्गदर्शक टिप्पण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने “ऐसी किसी गैर वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), जिसके वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाना है, के लिए प्रभाग 3 वित्तीय विवरणों” को अधिसूचित किया है।

इस संबंध में समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के प्रभाग 3 के मार्गदर्शक टिप्पणों को तैयार करने हेतु कार्यवाही कर रही है।

(XI) अन्य पहलें

- समिति द्वारा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार किया गया था। ऐसे प्रश्नों को, वेबकास्ट के दौरान उनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त प्रश्नों के आधार पर तैयार किया गया था, जिससे उनमें अंतर्वलित मुद्दों को और अधिक स्पष्ट किया जा सके तथा उन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने समिति द्वारा प्रस्तुत एफएक्यू के आधार पर तैयार किए गए ई-प्ररूप आईएनसी 22 ए संबंधी एफएक्यू जारी किए हैं। ये एफएक्यू कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अधीन रखे गए हैं : <http://mca.gov.in/MinistryV2/active.html>
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को उसके द्वारा ली जाने वाली पहलों में सहायता उपलब्ध कराने के लिए समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय का ई-प्ररूप डीपीटी-3-अनुपालन और अन्य पहलुओं, विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया था। इस वेबकास्ट को मंत्रालय के पदधारियों द्वारा संबोधित किया गया था। इस वेबकास्ट को 800 से अधिक सदस्यों द्वारा देखा गया था और इसके संबंध में लगभग 550 प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनका उत्तर वक्ताओं द्वारा दिया गया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस वेबकास्ट की साराहना की थी।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को उसके द्वारा ली जाने वाली पहलों में सहायता उपलब्ध कराने के लिए तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा की गई वांछा के अनुसार, समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय का ई-प्ररूप एक्टिव (एक्टिव कंपनी टेगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन) आईएनसी-22ए-अनुपालन और अन्य पहलुओं, विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया था। इस वेबकास्ट को मंत्रालय के पदधारियों द्वारा संबोधित किया गया था। इस वेबकास्ट को 25000 से अधिक सदस्यों द्वारा देखा गया था और इसके संबंध में लगभग 500 प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनका उत्तर वक्ताओं द्वारा दिया गया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस वेबकास्ट की साराहना की है।

(XII) सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम

- समिति ने वर्ष के दौरान, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न विधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में तमिलनाडु सरकार के आईएस पदधारियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल, ओडिशा के माननीय राज्यपाल द्वारा संबोधित किया गया था।
- भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने सरकार की, उसकी रजिस्ट्री को अद्यतन बनाए जाने संबंधी पहलों का समर्थन किया है, जिसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय का एक नया ई-प्ररूप, अर्थात् डीआईआर-3 केवाईसी के माध्यम से वार्षिक रूप से सभी कंपनियों के सभी निदेशकों के केवाईसी को पूरा करेगा। इस संबंध में जागरूकता का सृजन करने और इस पहल को लोकप्रिय बनाने के लिए आईसीएआई ने विभिन्न संगोष्ठियों, वेबकास्टों का आयोजन किया है, साथ ही उसने अपने सदस्यों को बड़ी संख्या में ई-मेल भी भेजी थी तथा आईसीएआई की वेबसाइट और साथ ही आईसीएआई जर्नल में भी उससे संबंधित उदघोषणा को रखा था। इस संबंध में जानकारी का प्रसार ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से भी किया गया था।

(XIII) निगम विधियों से संबंधित सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए अद्यतन जानकारी

समिति, वृत्तिक विकास के मद्दे सदस्यों के लिए नियमित रूप से अद्यतन जानकारी की श्रृंखला जारी करती है, जिसके अंतर्गत निगम विधियों से संबंधित अद्यतन जानकारी भी होती है। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा निम्नलिखित विषयों के संबंध में आईसीएआई की वेबसाइट पर विभिन्न उदघोषणाएं/विश्लेषण भी अपलोड किए गए हैं :

- प्रत्येक वर्ष 30 जून तक ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी को फाइल किए जाने संबंधी कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना का विश्लेषण
- 29 जून, 2019 तक डीपीटी-3 प्ररूप – एक ही विवरणी, को फाइल किए जाने संबंधी कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना का विश्लेषण

- ई-एक्टिव प्ररूप को फाइल किए जाने की तारीख को 15 जून, 2019 तक बढ़ाने संबंधी उदघोषणा
- कंपनी (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2019 के उपबंधों का संक्षिप्त विवरण
- कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के उपबंधों के संबंध में तारीख 2 नवंबर, 2018 की अधिसूचना का संक्षिप्त विवरण

(XIV) आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा हेतु तैयारी करने के लिए पठन प्रबंध प्रणाली

संस्थान ने, वृत्तिकों को आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा हेतु तैयारी करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक पठन प्रबंध प्रणाली को आरंभ किया है। यह ज्ञान संबंधी पहल एक सुगम मंच है, जो प्रस्तुतीकरणों के रूप में संपूर्ण पाठ्यचर्या संबंधी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है और इसे पाठ्यचर्या के प्रत्येक संघटक से संबंधित मोक परीक्षाओं द्वारा अनुपूरित किया गया है। इसकी एक अद्वितीय विशिष्टि यह है कि यह प्रणाली वृत्तिकों को मोड्यूलर स्तर पर अभ्यास करने और इस प्रकार परीक्षा हेतु तैयार करने में समर्थ बनाती है। इस माड्यूल में तीन भाग अंतर्विष्ट हैं – संपूर्ण पाठ्यचर्या संबंधी साहित्य, उपरोक्त अंतर्वस्तु संबंधी वीडियो व्याख्यान और लघु अंतरालों पर प्रश्न बैंक के अतिरिक्त 500 से अधिक बहु विकल्प प्रश्नों से युक्त मोक परीक्षा। लागू पाठ्यचर्या के अनुसार प्रस्तुतीकरणों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और नई मामला विधियों को अपलोड किया जाता है। एलएमएस पर 1 नवंबर, 2018 से लागू होने वाली पाठ्यचर्या के अनुसार एलएमएस से संबंधित 42 पीपीटी को अद्यतन बनाया गया था और नई मामला विधियों (संख्या में 37), बेयर अधिनियमों, नियमों और विनियमों (संख्या में 17), आईबीबीआई नमूना प्रश्न पत्रों को अपलोड किया गया था।

(XV) विख्यात व्यक्तियों से बैठकें

- 15 मार्च, 2019 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय का ई-प्ररूप एक्टिव (एक्टिव कंपनी टेगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन) आईएनसी-22ए की प्रमुख विशिष्टियों के प्रसार के संबंध में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें इस बात पर विचार-विमर्श किया गया था कि उत्तम निगम शासन के लिए यह अपेक्षित है कि इस प्रकार की स्कीमों को आज्ञापक बनाया जाए। सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने आईसीएआई द्वारा वेबकास्टों, जिन्हें अत्यधिक उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी, के आयोजन के लिए उसके प्रयासों की सराहना की थी।
- 28 जून, 2018 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अपर सचिव के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह ऐसे युवा वृत्तिकों (चार्टर्ड अकाउंटेंटों) की पहचान करे, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न उपबंधों के अधीन संविदा के आधार पर पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण, अन्वेषण जैसे कार्यों को कर सकते हैं। इस संबंध में, आईसीएआई ने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों (सीए) से आवेदन आमंत्रित किए थे, जिनके पास विभिन्न अवस्थानों पर दो वर्ष से अधिक का अर्हता-पश्च अनुभव है।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 'कारबार की सुगमता' संबंधी एक कार्यबल का सृजन किया है, जो "कारबार आरंभ करने", "दिवाला का समाधान करने" और "अल्पसंख्यक निवेशकों की संरक्षा करने" जैसे सूचकों के संबंध में कार्य करता है। इस समूह की तीसरी बैठक का आयोजन 11 अप्रैल, 2018 को किया गया था। इस बैठक में इस बात पर विचार-विमर्श किया गया था कि 'कारबार की सुगमता', विशेष रूप से कारबार आरंभ करने और दिवाला का समाधान करने के क्षेत्रों में सरकार द्वारा की गई पहलों के संबंध में किस प्रकार जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। इस संबंध में, समिति ने मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में तीन कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :
 - इस कार्यक्रम में सीए मनमोहन जुनेजा, प्रादेशिक निदेशक (पश्चिमी जोन) एमसीए, सीए आर.के. डालमिया, उप प्रादेशिक निदेशक (पश्चिमी जोन) कारपोरेट कार्य मंत्रालय और श्री विनोद शर्मा, कंपनी रजिस्ट्रार, एमसीए, मुंबई द्वारा अतिथि वक्ताओं के रूप में भाग लिया गया था। हमें इस कार्यक्रम के संबंध में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी और इसमें 70 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था।
 - इस कार्यक्रम में श्री आलोक सामंत राय, प्रादेशिक निदेशक, एमसीए, पूर्वी क्षेत्र, श्री के.जी. जोसफ जैक्सन (आरओसी कोलकाता), कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अतिथि वक्ताओं के रूप में भाग लिया गया था।

- 20 अप्रैल, 2018 को आईसीएआई, दिल्ली में एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया गया था, जहां श्री बंधोपाध्याय, प्रादेशिक निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (उत्तर), आईसीएआई के सरकारी नामनिर्देशिती के साथ अतिथि वक्ता थे।

आ. सीएल एंड सीजीसी का दिवाला और शोधन अक्षमता विधियों संबंधी समूह – वर्ष 2018-19 के दौरान

(I) प्रकाशन

वर्ष के दौरान, सीएल एंड सीजीसी के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता विधियों संबंधी समूह ने, आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) के साथ संयुक्त रूप से “दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन न्यायिक उदघोषणाएं” नामक एक प्रकाशन की दो श्रृंखलाओं, अर्थात् श्रृंखला 1 और श्रृंखला 2 को जारी किया है। इस प्रकाशन में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत आने वाले मुद्दों के संबंध में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, एनसीएलएटी और एनसीएलटी द्वारा सुनाए गए निर्णयों के संबंध में विश्लेषण आधारित महत्वपूर्ण मामलों को सम्मिलित किया जाता है।

(II) कार्यक्रम

- दिवाला और शोधन अक्षमता विधियों संबंधी समूह, सीएल एंड सीजीसी, आईसीएआई ने, 21 जुलाई, 2018 को दिल्ली में और 11 अगस्त, 2018 को मुंबई में एक वृहत् आईबीसी सभा का आयोजन किया था। 10 नवंबर, 2018 को कोलकाता में भी एक वृहत् आईबीसी सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा/आयोजन में विभिन्न वृत्तियों से संबंध रखने वाले देश भर से अनेकों प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डा. एम.एस. साहू, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने दिल्ली और साथ ही कोलकाता में आयोजित इन सभाओं के उद्घाटन सत्रों में इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया था और साथ ही पैनल परिचर्चा के दौरान प्रश्नों के उत्तर भी दिए थे। डा. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य, आईबीबीआई ने मुंबई सभा में प्रतिनिधियों को संबोधित किया था।
- आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा की तैयारी करने हेतु एक तीन दिवसीय गहन प्रशिक्षण का आयोजन 9 स्थानों पर किया गया था, अर्थात् ओंगोले, गुंटूर, कांचीपुरम, हुबली, तिरुपति, शिवाकाशी, वाराणासी, कोलकाता और बेलगाम।
- आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा की तैयारी करने और आईबीसी से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन पुणे, नागपुर, नासिक, कोटा, भिलाई, अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर में किया गया था।
- आईबीसी से संबंधित विभिन्न संगोष्ठियों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन 4 स्थानों – भिलाई, अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर में किया गया था।

5.8 प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी)

(I) सीबीडीटी को प्रतिवेदन/परस्पर क्रिया

- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि आयकर नियम, 1962 के नियम 115 और 115क को लागू करने के संबंध में निर्धारितियों के सामने आने वाले मुद्दों पर विचार किया जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में सीआईटी (छूट) की न्यायपीठों की संख्या में वृद्धि की जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि सीआईटी (ए) द्वारा जारी किए जा रहे आदेशों की निगरानी करने के लिए सीसीआईटी की शक्ति के संबंध में सीबीडीटी अनुदेश (फा.सं. डीजीआईटी(सतर्कता)/मुख्यालय/एसआई/ अपील/2017-18/9959), तारीख 8 मार्च, 2018 में संशोधन किया जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्ररूप 3गक/3गख/3गघ के संबंध में सुझावों संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को, ऐसी विवरणियों, जिन्हें सीपीसी द्वारा निर्धारण अधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है, के संबंध में कार्यवाही किए जाने के बारे में पत्र फा.सं. 225/53/2018/आईटीए.II, तारीख 28.3.2018 का प्रस्तुत किया गया।

- अध्यक्ष, सीबीडीटी को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर उपयोगिताओं को शीघ्र जारी किया जाए (अभी तक केवल आईटीआर 1 और 4 के संबंध में ही उन्हें जारी किया गया है)।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए नए कर संपरीक्षा प्रारूपों (3गक/3गख/3गघ) और उनकी उपयोगिताओं को शीघ्र जारी किया जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को अधिसूचना सं. 23/2018, तारीख 24 मई, 2019, जिसके द्वारा नियम 11पक में “अकाउंटेंट” पद के प्रतिनिर्देश का लोप किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप चार्टर्ड अकाउंटेंट बट्टा प्राप्त मुक्त नकद प्रवाह पद्धति के अनुसार कोट न किए गए सामान्य शेयरों के एफएमवी का निर्धारण करने के लिए अपात्र हो गए हैं, के संबंध में विभिन्न प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया गया।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के साथ उपाबद्ध स्पष्टीकरण में “अकाउंटेंट” की परिभाषा में संशोधन करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा आईसीएमएआई पत्र सं. जी: 142: 05: 2018, तारीख 23.05.2018 के प्रतिनिर्देश से आईसीएमएआई की चिंताओं से संबंधित प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया।
- यह अनुरोध करते हुए प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया कि भविष्य निधि अतिशेष पर व्याज के कराधान – विसंगतियों को दूर करने संबंधी स्पष्टीकरणों को जारी किया जाए।
- यह अनुरोध करते हुए प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर प्रारूप फाइल करते समय करदाताओं के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान किया जाए।
- यह अनुरोध करते हुए प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया कि करदाताओं को, धारा 139(4) के अधीन अनुज्ञात समय के अवसान के पश्चात् ही समय द्वारा वर्जित विवरणियों को फाइल करने की अनुज्ञा दी जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि तारीख 19 जुलाई, 2018 के द इकोनॉमिक टाइम्स समाचार-पत्र में प्रकाशित लेख के संबंध में सुसंगत ब्यौरे उपलब्ध कराएं जाएं और इस संबंध में आईसीएमएआई के सुझाव।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर विवरणियों को फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित किया जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधिसूचना संख्या 33/2018, तारीख 20 जुलाई, 2018 द्वारा पुनरीक्षित प्रारूप सं. 3गघ के संबंध में सुझावों को प्रस्तुत किया गया।
- यह अनुरोध करते हुए प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया कि कटौतीकर्ता द्वारा टीडीएस विवरणी फाइल किए जाने के पश्चात् प्रारूप सं. 26एस में टीडीएस डाटा को अद्यतन करने में होने वाले विलंब और अन्य संबद्ध मुद्दों से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि केरल में स्थित पूर्त और धार्मिक संस्थाओं के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क(1)(खक) के लागू होने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए और साथ ही केरल में रहने वाले निर्धारितियों के लिए वहां आई अभूतपूर्व बाढ़ और जन जीवन के अस्त व्यस्त हो जाने के कारण आयकर विवरणियों और कर संपरीक्षा रिपोर्टों को फाइल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को विभिन्न प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया गया, जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि कर संपरीक्षा रिपोर्टों और संबद्ध रिपोर्टों को फाइल करने के समय को आगे और बढ़ाया जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को, प्रारूप सं. 13 और आयकर नियम, 1962 के नियम 28, 28कक, 28कख, 37छ और 37ज में प्रस्तावित संशोधनों की प्रारूप अधिसूचना के संबंध में सुझाव देते हुए प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया गया।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को, सीबीडीटी द्वारा सीआईटी (अपील) को, केंद्रीय कार्य योजना 2018-19 के मुकदमेबाजी के प्रबंध से संबंधित अध्याय 3 के भाग क - ‘सीआईटी (अपील) के लक्ष्य’ के अधीन “क्वालिटी आदेशों के लिए प्रोत्साहन” से संबंधित कार्य मर्दों के पैरा (3) के द्वारा जारी अनुदेशों के संबंध में करदाताओं की चिंताओं से संबंधित प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया।

- अध्यक्ष, सीबीडीटी को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 42(2क) के अधीन विशेष संपरीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों को पैनलबद्ध किए जाने के लिए निमंत्रण संबंधी 'न्यूनतम पात्रता मानदंड' के संबंध में आईसीएआई की चिंताओं से संबंधित प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि 01.09.2018 को जारी आईटीआर-5 उपयोगिता में सुधार किए जाएं।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि 01.09.2018 को जारी प्ररूप सं. 3गख उपयोगिता में सुधार किए जाएं।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कघ के उपबंधों से संबंधित विनिर्दिष्ट एफएक्यू को, जिन्हें आयकर विभाग की वेबसाइट पर रखा गया है, हटाया जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को, सीपीसी (टीडीएस) के चरण-2 (2019-2024) को तैयार करने संबंधी सुझावों को प्रस्तुत किए जाने के संबंध प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया।
- यह अनुरोध करते हुए प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया कि प्ररूप सं. 3गघ और अधिसूचित प्ररूप सं. 3गघ की उपयोगिता में विनिर्दिष्ट असमानता को दूर किया जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को, नए प्रत्यक्ष कर विधान के प्रारूपण में विचारार्थ सुझावों को प्रस्तुत किए जाने के संबंध प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि आईटीआर प्ररूप सं. 7 की उपयोगिता में त्रुटि का सुधार किया जाए।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194झग (विनिर्दिष्ट करार के अधीन संदाय) के अधीन टीडीएस के संदाय के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाए या चालान अधिसूचित किया जाए।
- निम्नलिखित के संबंध में अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया :
 - आय-कर नियम, 1962 के नियम 18खख को संशोधित करने के लिए अनुरोध
 - आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झड के संबंध में प्ररूप सं. 10गगख का संशोधन करने और उक्त प्ररूप में जावा उपयोगिता को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को, तारीख 23.12.2014 के 'प्रत्यक्ष कर विधि, 2014 के अधीन अपराधों के उपशमन के लिए दिशानिर्देशों' में उपांतरणों पर विचार करने का अनुरोध करते हुए प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया गया।
- प्ररूप 3गक/3गख/3गघ के संबंध में आईसीएआई के आरंभिक अंतःनिवेशों का प्रस्तुत किया गया।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि कारबार को आंतरिक मान्यता प्रदान किए जाने से संबंधित कर मुद्दों पर संशोधनों की सिफारिशों पर विचार किया जाए या स्पष्टीकरण जारी किए जाएं।
- वित्त विधेयक, 2019 में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में प्रतिवेदन।
- प्रारूप प्ररूप सं. 3गघ के संबंध में आईसीएआई के अंतःनिवेशों का प्रस्तुत किया गया।
- बट्टा प्राप्त मुक्त नकद प्रवाह पद्धति के अनुसार कोट न किए गए साम्या शेयरों के एफएमवी का निर्धारण करने के प्रतिनिर्देश से नियम 11पक में संशोधन से संबंधित अनुरोध।
- निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए नए अधिसूचित आईटीआर प्ररूपों के संबंध में आईसीएआई की चिंताएं।

(II) संघीय बजट से संबंधित क्रियाकलाप

- बजट-पश्च ज्ञापन, 2018 का प्रस्तुत किया जाना
- बजट-पूर्व ज्ञापन, 2019 का प्रस्तुत किया जाना

(III) अन्य पहलें

- निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आय-कर विवरणी प्ररूपों को समझने संबंधी तकनीकी गाइड का विमोचन।

- “20.08.2018 से प्रभावी अधिसूचना सं. 33/2018, तारीख 20.07.2018 के संबंध में कार्यान्वयन गाइड” का विमोचन।
- सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष करें संबंधी आनलाइन अभिदाय के लिए विक्रेताओं के साथ ठहराव।
- समिति द्वारा वर्ष के दौरान, विभिन्न विषयों जैसे टीडीएस और टीसीएस अनुपालनों में ई और अन्य मुद्दे तथा आय-कर विवरणियों के नए प्रारूपों को समझना और उन्हें फाइल किया जाना, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में हुए हाल ही में उन्नयन, ई अनुपालन – मुद्दे और आगे की राह, खंडवार विश्लेषण और कर संपरीक्षा रिपोर्ट के पुनरीक्षित प्रारूप 3गघ में नई अपेक्षाएं और टीडीएस कटौतीकर्ताओं के लिए सक्षमता निर्माण और प्रारूप 24थ और प्रारूप 16 के भाग ख में किए गए हाल ही के परिवर्तनों के संबंध में पांच लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया था।
- समिति ने वर्ष के दौरान 25 संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कर जागरूकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/ व्याख्यानों का आयोजन किया था।

5.9 आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और आर्थिक सलाह संबंधी समिति (सीईसीएल एंड ईए)

(I) विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/विनियामकों को प्रतिवेदन

आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और आर्थिक सलाह संबंधी समिति ने विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/विनियामकों को प्रतिवेदन किए थे :

- बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 26 और 48 के अधीन, उक्त अधिनियम के अधीन न्याय निर्णायक प्राधिकारी और अपील अधिकरण के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में उपस्थित होने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों को मान्यता दिए जाने से संबंधित प्रतिवेदन विधि और न्याय मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था ;
- फर्म रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के समक्ष आरओएफ पर, फर्मों को रजिस्टर करते समय, संविधान में परिवर्तनों और अन्य संबद्ध विषयों के संबंध में आने वाली समस्याओं से संबंधित मुद्दों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था ;
- भारतीय विधि आयोग को, भारतीय विधि आयोग द्वारा तारीख 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत कुटुंब विधि में सुधार संबंधी परामर्श पत्र में दिए गए इस सुझाव कि हिन्दु अभिवक्त कुटुंब को समाप्त कर दिया जाए, के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था;
- भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए तारीख को आगे बढ़ाए जाने से संबंधित विषय पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और विभिन्न रेरा प्राधिकरणों को प्रतिवेदन और माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 के संबंध में मतों/सुझावों को माननीय सभापति, राज्य सभा, भारतीय संसद् को प्रस्तुत किया गया था ;
- रेरा संबंधी कानून के संबंध में और अधिक जागरूकता लाने तथा उनके कार्यान्वयन में एकसमानता लाने के लिए देश भर के रेरा प्राधिकरणों के मतों के संकलन की आवश्यकता के संबंध में महाराष्ट्र रेरा के मतों को विभिन्न रेरा प्राधिकरणों और व्यापार निकायों के बीच परिचालित किया गया था ; और
- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में उद्घोषित प्रमुख निर्णयों से संबंधित ऐसे विषयों के बारे में केंद्रीय पीएफ आयुक्त को प्रतिवेदन, जो भविष्य निधि कटौती और ईपीएस पेंशन की संगणना को प्रभावित कर सकते हैं।

(II) मार्गदर्शक टिप्पण/तकनीकी गाइड/प्रकाशन आदि

- रेरा के अधीन प्रमाणन और संपरीक्षा हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले पैरामीटरों की सिफारिश करने के उद्देश्य से, श्री विजय गोयल, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री के कर कमलों से 11 फरवरी, 2019 को “भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के अधीन प्रमाणन और संपरीक्षा” शीर्षक वाले एक प्रकाशन का विमोचन किया गया था। आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष सीए. एन.डी. गुप्ता, संसद् सदस्य (राज्य सभा) भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
- ‘अविनियमित निक्षेप स्कीमों का वर्जन अध्यादेश, 2019’ के संबंध में सदस्यों की विशेषज्ञता के विस्तार क्षेत्र को व्यापक बनाने के प्रयास रूप में समिति ने, समिति के तत्वाधान में “अविनियमित निक्षेप स्कीमों का वर्जन अध्यादेश, 2019 के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न” शीर्षक वाला एक ई-प्रकाशन निकाला था।

(III) संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/वेबकास्ट

विभिन्न वाणिज्यिक और आर्थिक विधियों के संबंध में, जिनके अंतर्गत रुपांतरण, नवीकरण और तकनीकी विकास में चार्टर्ड

अकाउंटेंटों की भूमिका, जीएसटी वार्षिक विवरणी, रेरा प्रमाणन और रिपोर्टें तथा निजी न्यासों, फेमा आदि भी हैं, वेबकास्टों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस अवधि के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

(IV) धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने 2018-19 के दौरान पुणे, शोलापुर, मुंबई, बंगलूरु और चंडीगढ़ में धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पांच बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। सरकारी विभागों, बैंकों, विश्विक भ्रातृसंघ और उद्योग तथा व्यवसाय में लगे सदस्यों से युक्त विशिष्ट संकाय ने इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया था।

(V) रोड शो – भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

आईसीएआई ने वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिस्पर्धा समर्थन को बढ़ावा देने और नए तथा बेहतर माध्यमों से बड़ी संख्या में पणधारियों तक पहुंच बनाने के विचार से मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद के विभिन्न अवस्थानों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और कारपोरेट कार्य संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न रोड शो के लिए समर्थन और सहयोग उपलब्ध कराया था।

अध्ययन समूह : “फेमा – विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 संबंधी संदर्भिका” के प्रकाशन का पुनरीक्षण करने और भविष्य निधि संबंधी तकनीकी गाइड और बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों के विकास के लिए पृथक् अध्ययन समूहों का गठन किया गया था।

5.10 अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड

यह सुनिश्चित करने के लिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के डिजिटल युग की चुनौतियों पर खरे उतर पाते हैं और इस युग में उपलब्ध अवसरों का फायदा लेने के लिए उन्हें अग्रता प्राप्त है, उनकी डिजिटल सक्षमताओं का निर्माण करके चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए आईसीएआई ने वर्ष 2018 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (सीआईटी) का अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएवी) में विलयन कर दिया था। डीएएवी अपने लेखांकन तथा आश्वासन के संबंध में प्रौद्योगिकी के प्रभाव से संबंधित मुद्दों पर प्रास्थिति पत्रों और लेखों के माध्यम से ज्ञान का आधार विकसित कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट संबंधी प्रक्रिया स्वचालन, ब्लॉकचेन, क्लाउड संगणना और लेखांकन तथा आश्वासन संबंधी बड़े डाटा के भावी प्रभावों के संबंध में अवधारणा पत्रों को तैयार करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। इसका प्रयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उनके ज्ञान में विस्तार करने और आज के डिजिटल युग में नए क्षेत्रों में उनके कौशलों को विकसित करने में सहायता करना है।

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित प्रमुख क्रियाकलाप किए :

(I) प्रकाशन

- “ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी – अपनाई जाने वाले प्रवृत्तियां और अकाउंटेंसी वृत्ति के लिए विवक्षाएं” विषय पर अवधारणा पत्र संक्षिप्त रूप से ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की मूलभूत अवधारणा और अद्वितीय विशिष्टियों को स्पष्ट करता है, इस नई प्रौद्योगिकी के वर्तमान में किए जाने वाले उपयोग को विशिष्ट रूप से दर्शित करता है। यह पत्र ब्लॉकचेन आधारित प्रणालियों/प्रक्रियाओं के लेखांकन और आश्वासन के संबंध में प्रकाश डालता है और साथ ही लेखांकन फर्मों द्वारा उसे अपनाए जाने और उसके विकास संबंधी चरणों को भी स्पष्ट करता है। पाठकों को उसके व्यावहारिक पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए उसमें मामला अध्ययनों को भी सम्मिलित किया गया है।
- सक्रिय डिजिटल विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए बोर्ड ने इस अवधारणा पत्र को जारी किया है, जो संक्षिप्त रूप से रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन का पर्यावलोकन उपलब्ध कराता है तथा संगठनों द्वारा इस विकासशील प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दस्तावेज आरपीए, आरपीए के उपयोग के लिए ट्रिगर, आरपीए के लिए लक्ष्य क्षेत्रों, आरपीए के लिए महत्वपूर्ण सफलता के कारकों, रोबोटिक उपकरण और विक्रेता, आरपीए का भविष्य – बुद्धिमत्तापूर्ण स्वचालन की ओर, आदि जैसे प्रमुख उद्देश्यों को भी विशिष्ट रूप से दर्शित करता है। लेखांकन कृत्य, कर कृत्य, प्रबंध रिपोर्टिंग और विश्लेषण आदि से संबंधित मामला अध्ययनों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।
- बोर्ड ने “बैंकिंग क्षेत्र में कपट के पूर्व सूचक” नामक प्रकाशन को पुनरीक्षित किया है और इस अद्यतन प्रकाशन निकाला है, जो सदस्यों का इस बारे में मार्गदर्शन करेगा कि वे किस प्रकार समय पर कपट का पता लगाने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और साथ

ही उसके निवारण के लिए नियंत्रणों का भी सुझाव देता है। पुनरीक्षित परिपत्रों के प्रभावों को समाविष्ट करने के अलावा, इस पुनरीक्षित संस्करण में मूलभूत बैंककारी समाधानों (सीबीएस), अंकीय संदाय प्रणाली, इंटरनेट बैंकिंग आदि को सम्मिलित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर्वर्तित कपट संबंधी जोखिमों को भी सम्मिलित करता है।

(II) डाटा विश्लेषण (डीए)/फोरेसिक प्रयोगशालाएं

बोर्ड ने कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में डीए प्रयोगशालाओं को आरंभ किया था। बोर्ड द्वारा कुल 6 डाटा विश्लेषण (डीए)/फोरेसिक प्रयोगशालाएं आरंभ की गई हैं, जहां आश्वासन विश्लेषण के लिए समुन्नत एक्सेल और जीएस (साधारण संपरीक्षा साफ्टवेयर) उपकरण (आईडिया) कार्यकरण (अर्थात् संपरीक्षा परिप्रेक्ष्य से डाटा का विश्लेषण), रिपोर्टिंग, परिणामों का निर्वचन और निर्णय लिए जाने से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। फोरेसिक लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन भी इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सदस्यों को फोरेसिक उपकरणों के संबंध में व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(III) ब्लॉकचेन संबंधी कार्यपालक विकास कार्यक्रम

बोर्ड ने “ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी – डिजिटल युग की ओर प्रस्थान” विषय पर एक कार्यपालक विकास कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की प्रस्तावना को प्रस्तुत करेगा और विभिन्न उद्योगों में उपयोग संबंधी मामलों का विकास करेगा। यह पाठ्यक्रम, पारदर्शी लेखांकन परिस्थितियों को समर्थ बनाने में नवीनीकरण के निबंधनानुसार ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के भविष्य और वर्तमान संपरीक्षा संबंधी व्यवहारों के रूपांतरण में उसकी संभावनाओं को भी समाविष्ट करता है। बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों और दुबई तथा बहरीन में ऐसे 9 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

(IV) सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पत्र पाठ्यक्रम (डीआईएसए)

बोर्ड द्वारा संचालित सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पत्र पाठ्यक्रम (डीआईएसए) को वर्ष 2001 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के लिए आरंभ किया गया था, जिसके संबंध में मांग बढ़ती जा रही थी। डीआईएसए पाठ्यक्रम ने प्रौद्योगिकी, सूचना संबंधी आश्वासन और सूचना प्रबंध संबंधी विशेषज्ञता को संयोजित किया था, जिसने डीआईएसए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों को विश्वसनीय सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार और सूचना सुरक्षा आश्वासन सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में विकसित होने में समर्थ बनाया। वर्ष 2001 से आज की तारीख तक 25,500 से अधिक सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को अर्हित किया है। डीआईएसए का संचालन जुलाई, 2018 में श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के लिए भी किया गया था। डीआईएसए अर्हता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में पृष्ठांकित करने के विचार से बोर्ड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट्स (एनएसआई) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड ने सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अपने अर्हता-पत्र पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को भी अद्यतन किया था। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 91 बैचों का आयोजन किया गया था।

(V) न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड, “न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” का संचालन करता है और आज की तारीख तक लगभग 4500 सदस्यों ने इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है। इस विशेषीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों की, लेखांकन, संपरीक्षा, सीएएपी/डाटा माइनिंग उपकरणों संबंधी कौशलों और कपट/वृत्तियों का पता लगाने संबंधी अन्वेषणात्मक कौशलों को अर्जित करने में सहायता करना है। परिषद् द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान इसके कुल 48 बैचों का आयोजन किया गया था।

(VI) जून, 2018 नई दिल्ली में “आईसीएआई स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, 2018 – नवीनीकरण के रंग”

बोर्ड ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें पर्याप्त परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस स्टार्ट अप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था।

(VII) आईसीएआई ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन, 2018

बोर्ड ने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संबंध में अवधारणात्मक और व्यावहारिक समझ उपलब्ध कराने तथा लेखांकन, आश्वासन और अनुपालन के परिप्रेक्ष्य से विभिन्न उद्योगों में उसके कार्यान्वयन तथा चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सुसंगत सलाह/आश्वासन सेवाओं को प्रदान करने हेतु सशक्त बनाने के उद्देश्य से 23 अगस्त, 2018 को एक ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था।

(VIII) डाटा विश्लेषण सम्मेलन, 2018 – आश्वासन सेवाओं का रूपांतरण

बोर्ड ने 20 अक्तूबर, 2018 को डाटा विश्लेषण सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में संपरीक्षा प्रक्रियाओं – जोखिम निर्धारण, विश्लेषण पुनर्विलोकन, सारवान परीक्षा, समुन्नत विश्लेषण के संबंध में डाटा विश्लेषण का उपयोग करने हेतु बेहतर जागरूकता प्राप्त करने तथा कारबार प्रचालनों में गहन अंतर दृष्टि उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

(IX) आईसीएआई का रूपांतरण के लिए विघटनकारी नवीनीकरण – डिजिटल और फोरेंसिक विषय पर तीसरा वार्षिक सम्मेलन

- आईसीएआई के डीएएवी ने वृत्ति को प्रभावित करने वाली उभरती प्रौद्योगिकी संबंधी प्रवृत्तियों, कपट से संबंधित हाल ही के रुझानों और कपटों के जोखिम को कम करने के लिए रणनीति को सम्मिलित करने के उद्देश्य से डिजिटल और फोरेंसिक संबंधी एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करने की पहल की थी। इस सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन बोर्ड द्वारा 18-19 जनवरी, 2019 के दौरान रूपांतरण के लिए विघटनकारी नवीनीकरण थीम के साथ किया गया था। इस सम्मेलन की थीम प्रौद्योगिकी का कखगघ था, अर्थात् सत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन पठन, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियां, साइबर सुरक्षा और डाटा विश्लेषण जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर आधारित थे।
- बोर्ड द्वारा डिजिटल व्यवहार वेबीनार शृंखला का आयोजन किया जाता है और अप्रैल, 2019 में “अकाउंटेंटों के लिए साइबर सुरक्षा – अवधारणाएं और उपकरण” विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया गया था।
- डिजिटल रूपांतरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सशक्त करने हेतु प्रौद्योगिकी संबंधी शिखर सम्मेलनों का आयोजन कोयम्बटूर, बेलगाम, भोपाल, वारंगल, इंदौर, कानपुर और लखनऊ में किया गया था।

अकाउंटेंटों और संपरीक्षकों के यूरोपीय फेडरेशन (ईएफएए) ने जून, 2019 में डीएएवी द्वारा जारी डिजिटल कम्पीटेंसी मेच्योरिटी मॉडल (डीसीएमएम) पाठ 1.0 को अपनाया गया है।

(X) इंग्लैंड और वेल्स में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAEW) के साथ सहयोग

आईसीएयूवी और आईसीएआई द्वारा संयुक्त अनुसंधान के बारे में अधिक जानने के लिए वित्त और लेखांकन में स्वचालन के प्रमुख उदाहरण:

- कैसे स्वचालन तैनात किया जा रहा है और इसके व्यावहारिक लाभ हैं
- ऐसे तत्व जो सफल स्वचालन को रेखांकित करते हैं, जैसे कि प्रक्रिया परिवर्तन और प्रबंधन बदलना
- वित्त और लेखा के लेन-देन वाले भागों में काम करने वाले कर्मचारियों पर प्रभाव

अनुसंधान कंपनियों में कई लोगों के साथ साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें वित्त नेता, स्वचालन परियोजनाओं के वितरण में शामिल कर्मचारी और आईटी या अन्य तकनीकी कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा भी की जाएगी।

5.11 नैतिक मानक बोर्ड

हाल ही के वर्षों में जिस प्रकार नैतिकता और ईमानदारी पर बल दिया गया है, वह इस बात पर प्रकाश डालती है कि सोसाइटी इन गुणों को कितना महत्व देती है। नैतिक सिद्धांतों का पालन करने वाले व्यक्ति उस स्तर की विश्वसनीयता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जो अन्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नैतिक आचार एक ऐसा गुण है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति साधारण रूप से अत्यधिक रुचिपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, प्राकृतिक रूप से इससे यह विवक्षित होता है कि वृत्तियों से नैतिकता की आशा सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक की जाती है। यह आशा अपने उच्चतम स्तर पर होती है जब सामने वाला व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट हो क्योंकि वे देश में और उससे परे वित्तीय सत्यनिष्ठा के स्तंभ के समान हैं।

यद्यपि, नैतिकता का लेखांकन वृत्ति के साथ संबंध स्वयं इस वृत्ति जितना पुराना ही है, फिर भी संस्थान की परिपक्व ने, सदस्यों के लिए नैतिकता के ऐसे सिद्धांतों को तैयार करने, जो जनता में विश्वास बनाए रखने की गारंटी प्रदान करने जितने कठोर हों, के प्रमुख उत्तरदायित्व के साथ 1976 में नैतिक मानक बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् “बोर्ड” कहा गया है) का गठन किया था।

बोर्ड का मिशन, उत्कृष्टता, स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा के दीर्घकालिक नैतिक आदर्शों को अक्षुण्ण रखते हुए और साथ ही सदस्यों के सम्मान और हितों की संरक्षा करने के लिए तथा सदस्यों हेतु एक क्रियाशील और समकालीन नैतिक संहिता और नैतिक व्यवहार को तैयार करने के प्रति कार्य करना है।

सदस्यों के लिए नैतिक सिद्धांतों की विरचना करने के अतिरिक्त, बोर्ड उसे निर्दिष्ट किए जाने वाले नैतिक मुद्दों की समीक्षा भी करता है और उनके संबंध में सलाह भी प्रदान करता है। यह समय-समय पर सदस्यों के लिए 'नैतिक संहिता' का पुनर्विलोकन करता है और उसके पुनरीक्षित संस्करणों का प्रकाशन करता है। बोर्ड के अन्य प्रकाशनों, अर्थात् 'नैतिक मुद्दों संबंधी एफएक्यू' और 'स्वतंत्र संपरीक्षकों संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण' को भी समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता है। बोर्ड सदस्यों की ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सक्षमता और वृत्तिकता के संबंध में जनता में जागरूकता और विश्वास का संवर्धन करता है। यह सदस्यों की, किसी अस्तित्व के संपरीक्षकों के रूप में उन्हें अनुचित रूप से हटाए जाने संबंधी शिकायतों के संबंध में तैयार की गई प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करता है और सदस्यों के हितों की संरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- "नैतिक संहिता" को अकाउंटेंटों के अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईईएसबीए) के 2018 संस्करण के अनुरूप पुनरीक्षित किया गया है। अतः, यह नैतिक संहिता, 2009 संस्करण के भाग क का पुनरीक्षित पाठ है। यह पुनरीक्षित संहिता 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगी। नैतिक संहिता का विद्यमान (2009) संस्करण तब तक प्रभावी बना रहेगा। इस पुनरीक्षित संहिता को 4 फरवरी, 2019 को आयोजित संस्थान के वार्षिक समारोह के दौरान जारी किया गया था।
- "नैतिक मुद्दों संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों" को भी पुनरीक्षित किया गया है। पुनरीक्षित संस्करण को 1 जुलाई, 2018 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। इस प्रकाशन के पूर्वतत्तर संस्करण को वर्ष 2012 में जारी किया गया था। नए संस्करण में संस्थान के सदस्यों के लिए उपयोगी पुनरीक्षित मार्गदर्शन और समकालीन मुद्दे अंतर्विष्ट हैं।
- सी.ए. संजीव कुमार चौधरी, पूर्व परिषद् सदस्य और पूर्व अध्यक्ष, नैतिक मानक बोर्ड को अकाउंटेंटों के अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईईएसबीए) 2019-2022 की अवधि के दौरान सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(II) नैतिक मानक बोर्ड द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

- वहां हितों का कोई विरोध अंतर्विष्ट नहीं है, जहां बैंक की किसी शाखा के उधार लेने वाले खाते का वर्तमान आस्ति संपरीक्षक बैंक की किसी अन्य शाखा का कानूनी संपरीक्षक है।
- किसी संपरीक्षक को उसके कार्य संबंधी कागज पत्रों का आदान-प्रदान करने से उस समय छूट प्राप्त नहीं होगी, यदि कोई विधि या विनियम विनिर्दिष्ट रूप से संपरीक्षक से उसके कार्य संबंधी कागज पत्रों को साझा करने की अपेक्षा करता है।
- कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो किसी फर्म में कोई भागीदार है, उक्त कंपनी की किसी विदेशी समनुपंगी के निदेशक के रूप में हैसियत को स्वीकार कर सकता है (जहां उक्त फर्म को भारत में उसकी मूल कंपनी के कर संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है) यदि वह यह सुनिश्चित करता है कि वह कर संपरीक्षा नियोजन संबंधी सूचना के विषयों पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में समर्थ नहीं होगा।
- किसी कंपनी के कारबार के सामान्य अनुक्रम में, सनिकट कीमत पर किए गए किसी वाणिज्यिक संव्यवहार का परिणाम उसे उधारग्रस्त करने वाला नहीं होगा (कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार), यदि बकाया रकम का समाधान उन्हीं निबंधनों के अनुसार कर दिया जाता है, जिनकी प्रस्थापना अन्य ग्राहकों को की गई थी और साथ ही ऐसा आईसीएआई की नैतिक संहिता में उपबंधित सुरक्षोपायों, यदि लागू हों, के अधीन रहते हुए किया जाता है।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को एमएसएमई प्रवर्ग के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 या नैतिक संहिता के अधीन उसके संबंध में कोई प्रतिषेध नहीं है।
- आईसीएआई की नैतिक संहिता, 2009 के अनुसार किसी कंपनी के आंतरिक संपरीक्षक द्वारा उक्त कंपनी के शेयरों को अर्जित/क्रय करने के संबंध में कोई प्रतिषेध नहीं है।

- व्यवसायरत सदस्य के लिए यह अनुज्ञेय है कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के अनुसार कोई मध्यस्थ बन सके। भारतीय माध्यस्थम् परिषद् (आईसीए) के पैनल में प्रवेश करने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह मध्यस्थ बनने के समनुरूप है और इसलिए वह अनुज्ञेय है।
- कोई सदस्य किसी कंपनी के शेयरों को केवल एक निवेश के रूप में ही धारण कर सकेगा। तथापि, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (11) को ध्यान में रखते हुए, उसके लिए शेयरों के क्रय और विक्रय के कारबार में नियोजित होना अनुज्ञेय नहीं है और उसे ऐसा कोई कारबार करने के लिए पूर्व और विनिर्दिष्ट अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- व्यवसाय के प्रमाणपत्र को धारण करने वाले किसी ऐसे सदस्य को, जो विदेश में कोई वेतन वाला नियोजन कर रहा है, अंशकालिक रूप से व्यवसायरत समझा जाएगा। वह किसी सीए फर्म में एक भागीदार के रूप में बना रह सकता है क्योंकि अंशकालिक व्यवसायरत सदस्य के लिए केवल एक प्रतिषेध यह है कि वह अधिप्रमाणन कृत्यों को नहीं कर सकता है। अतः, अंशकालिक व्यवसायरत किसी सदस्य के लिए किसी सीए फर्म का भागीदार बनना प्रतिषिद्ध नहीं है। तथापि, उसे ऐसी संपरीक्षाओं की संख्या, जिसके लिए सीए फर्म हकदार है, के प्रयोजनों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।
- प्रबंध परामर्श और अन्य सेवाओं संबंधी दिशानिर्देशों की प्रविष्टि (xv) के अनुसार शेयरों और कारबार का मूल्यांकन तथा समामेलन और विलयन तथा अर्जन व्यवसायरत सदस्यों के लिए अनुज्ञेय है। तदनुसार, केवल ऐसे मूल्यांकनों को ही व्यवसायरत सदस्य के दृष्टिकोण से अनुज्ञेय माना जाएगा। व्यवसायरत किसी सदस्य के लिए किसी अन्य प्रकार का मूल्यांकन करना अनुज्ञेय नहीं है।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (8) के अधीन संसूचना की अपेक्षा को किसी ऐसी परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है, जहां कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, जो पूर्व में संपरीक्षक थी, अब विद्यमान नहीं है। तथापि, आने वाले संपरीक्षक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस तथ्य की संस्थान से पुष्टि करे।
- कोई सदस्य, अन्य बातों के साथ, फर्म के साइन बोर्ड पर फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का उल्लेख नहीं कर सकता। तथापि, फर्म के परिसरों के भीतर फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का उल्लेख करते हुए एक साइन बोर्ड रखा जा सकता है क्योंकि वह साधारण रूप से विश्व के लिए उस फर्म का विज्ञापन नहीं समझा जाएगा, अपितु उसे केवल फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का उपदर्शन मात्र माना जाएगा, जिस तक केवल उसके ग्राहकों/ऐसे व्यक्तियों की ही पहुंच होगी, जो स्वैच्छिक रूप से पहले से ही फर्म के परिसरों के अंदर मौजूद है।
- किसी सदस्य के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि वह किसी विधि फर्म विजिटिंग कार्ड पर अपने नाम के लिखे जाने को अनुज्ञात करे।
- व्यवसायरत किसी सदस्य के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि वह किसी सभा या संगोष्ठी की मेजबानी करे तथा इस संबंध में कोई प्रतिनिधिमंडल संबंधी फीस और प्रायोजन संबंधी फीस का संग्रहण करे।
- “संवीक्षक” की भूमिका सदस्य के व्यवसाय के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
- व्यवसायरत सदस्य के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि वह अपने (सीए फर्म के) कार्यालय परिसर और कोचिंग केंद्र को एक ही स्थान पर रखे।
- विदेश में कोई शैक्षिक संस्था आरंभ करने की परिकल्पना करने वाले किसी सदस्य का प्रतिनिधित्व, संस्था की स्थापना को किए जाते समय एक या अधिक माध्यमों से सदस्य के रूप में ही किया जाएगा। तदनुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के परिशिष्ट (9) के “विनिर्दिष्ट रूप से मंजूर की जाने वाली अनुमति” की प्रविष्टि (5) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (11) के उपबंध ऐसे सदस्य के संबंध में लागू होंगे। अतः, उसे ऐसी कोई शैक्षिक संस्था आरंभ करने से पूर्व परिषद् की विनिर्दिष्ट और पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

5.12 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)

(I) राय

तेजी से परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियां प्रायः संगठनों से अपेक्षा करती हैं कि वे जटिल कारबार संव्यवहार करें। ऐसे संव्यवहारों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग करते समय निर्वचन और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखांकन मानकों (इंड

एएस) के निबंधनानुसार कुछ कंपनियों के लिए लेखांकन सिद्धांतों में व्यापक परिवर्तनों के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग में भी लेखांकन वृत्तिकों के समक्ष उनके कर्तव्यों के निर्वहन में कतिपय चुनौतियां सामने आती हैं। इससे, ऐसे विषयों के संबंध में एक प्राधिकृत विशेषज्ञ मार्गदर्शन की आवश्यकता सामने आती है। यहां से आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाह समिति (ईएसी) की भूमिका आरंभ होती है, जो सदस्यों को विनिर्दिष्ट परिस्थितियों/स्थितियों के अधीन लेखांकन और/या संपरीक्षा संबंधी सिद्धांतों के संबंध में विनिर्दिष्ट मुद्दों के बारे में इस प्रकार के दिशानिर्देश प्रदान करती है। ईएसी, संस्थान की परिषद् द्वारा विरचित सलाहकार सेवा नियमों, जिन्हें समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता है, के अनुसार सदस्यों द्वारा लेखांकन और/या संपरीक्षा संबंधी सिद्धांतों के लागू होने और कार्यान्वयन के संबंध में उठाए गए विनिर्दिष्ट प्रश्नों पर राय के रूप में दिशानिर्देश प्रदान करती है। इन नियमों के अनुसार, समिति ऐसे प्रश्नों का प्रत्युत्तर नहीं देती है, जिसमें विभिन्न अधिनियमितियों का केवल विधिक निर्वचन ही अंतर्बलित है। इसके अतिरिक्त, यह ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर नहीं देती है, जो ऐसे किसी मामले से संबंधित हैं, जो संस्थान की अनुशासन समिति, विधि के किसी न्यायालय, आय-कर प्राधिकारियों या सरकार के किसी अन्य उपयुक्त विभाग के समक्ष लंबित हैं। उक्त नियम आईसीएआई की वेबसाइट पर हाइपर लिंक http://www.icaai.org/new_category.html?c_id=142 के अधीन उपलब्ध हैं या उन्हें नई दिल्ली स्थित संस्थान के प्रधान कार्यालय से अभिप्राप्त किया जा सकता है।

समयानुसार, ईएसी की भूमिका को, उसके द्वारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर उद्यमों, उद्योग और व्यवसाय में लगे सदस्यों और साथ ही विनियामक और शासकीय प्राधिकारियों, जैसे कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) आदि, जो समय-समय पर उनके सामने आने वाले लेखांकन संबंधी प्रश्नों/मुद्दों पर राय की मांग करते हुए ईएसी से संपर्क करते हैं, द्वारा भलीभांति मान्यताप्राप्त है। विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा अभिव्यक्त की गई राय, शंकाओं के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों तथा किसी विशिष्ट राय को समिति द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की तारीख को यथा लागू सुसंगत विधिक स्थिति और लेखांकन/संपरीक्षा मानकों पर आधारित होती हैं। राय को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख को प्रत्येक राय के साथ उपदर्शित किया जाता है। अतः, राय को पश्चातवर्ती घटनाओं और/या लागू विधिक स्थिति और लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों में संशोधनों के अवलोक में पढ़ा और लागू किया जाना चाहिए।

1.4.2018 से 30.06.2019 की अवधि के दौरान, समिति ने संस्थान के सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों पर 50 रायों को और विनियामकों/शासकीय प्राधिकारियों से प्राप्त विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर 3 रायों को अंतिम रूप दिया था।

सदस्यों के फायदे के लिए, ईएसी द्वारा नियमित रूप से रायों के सारसंग्रह का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें किसी एक वर्ष के दौरान दी गई रायों को सारसंग्रह के एक भाग के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अभी तक, सारसंग्रह 35 जिल्दों को विक्रय हेतु जारी किया जा चुका है, जिन्हें अत्यधिक संख्या में पाठक प्राप्त हुए हैं। सभी रायों के सारसंग्रह के सभी 35 जिल्दों में अंतर्विष्ट लगभग 1400 रायों को सम्मिलित करने वाली एक सीडी को, जो समन्वित और उपयोक्ता मित्र खोज प्रसुविधा से लैस है, भी जारी किया गया है, जो रायों के सारसंग्रह की जिल्द 35 के साथ उपलब्ध है। श्रृंखला की अगली जिल्द, अर्थात् रायों के सार संग्रह की जिल्द 36 संकलनाधीन है और यह आशा की जाती है कि उसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई कुछ राय, जिनमें साधारण वृत्तिक हित अंतर्बलित होता है, आईसीएआई के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित की जाती हैं। समिति की हाल ही की राय को संस्थान की वेबसाइट पर समिति के ज्ञान आदान-प्रदान संबंधी पृष्ठ पर भी रखा जाता है।

(II) वर्ष के दौरान दी गई राय

समिति ने वर्ष के दौरान विभिन्न रायों को जारी किया था जैसे कि व्यापार का शुद्धकरण, व्यापार प्राप्तियों और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों का शुद्धकरण, दीर्घकालिक निवेशों के संबंध में हानिकरण, हानि का आपवादिक मद के रूप में प्रकटन, मूल कंपनी द्वारा किसी बैंक को, उसकी कार्यपालन बाध्यता के मद्दे उसके पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी की ओर से कार्यपालन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए जारी किसी निगम गारंटी (गारंटी विलेख) के संबंध में आकस्मिक दायित्व का एकल वित्तीय विवरणों में प्रकटन, अग्रिम फीस के संबंध में अर्जित व्याज को मान्यता प्रदान करने संबंधी लेखांकन व्यवहार क्योंकि उसकी आय इंडेएस 18, आदि के उपबंधों के अनुसार सही है।

5.13 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी)

आईसीएआई, वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार लाने के अपने प्रयासों के भागरूप में एफआरआरबी के माध्यम से विभिन्न उद्यमों के

साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करता है। बोर्ड का उद्देश्य उत्तम वित्तीय रिपोर्टिंग की परिस्थितियों को बनाए रखना और साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तम शासन में पारदर्शिता का संवर्धन करना भी है, जो संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में निवेशकों के विश्वास के संवर्धन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड विभिन्न विनियामकों, अर्थात् एमसीए, सेबी, ईसीआई और अन्य विनियामकों की, समय-समय पर उनके द्वारा निर्दिष्ट मामलों का पुनर्विलोकन करके सहायता करता है। इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने स्वविवेकानुसार चुने गए या विशेष मामले के रूप में 65 मामलों का पुनर्विलोकन किया था।

आईसीएआई ने स्वविवेकानुसार एक सक्रिय उपाय के रूप में और इसमें अंतर्बलित लोक हित को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी) के अधीन शैल कंपनी पुनर्विलोकन समूह (एससीआरजी) का गठन किया। एससीआरजी, विनियामक/शासकीय निकायों, जैसे कि "शैल कंपनियों संबंधी कार्यबल", आदि से प्राप्त प्रतिनिर्देशों पर शैल कंपनियों का पुनर्विलोकन करता है।

(I) समाज के प्रति योगदान – राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

बोर्ड द्वारा इस अवधि के दौरान विनियामकों का समर्थन करने के उसके प्रयासों के भागरूप में निम्नलिखित महत्वपूर्ण समनुदेशन पूरे किए गए थे :

- विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट किए गए मामलों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति : भारत निर्वाचन आयोग ने, विभिन्न राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं के पुनर्विलोकन में एफआरआरबी की भूमिका की सराहना की थी और साथ ही पूर्व वर्षों में राजनैतिक दलों के संपरीक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करने के लिए भी उसकी अनुशंसा की थी। उसने एफआरआरबी से पुनः यह अनुरोध किया है कि वह कम से कम छह ऐसे राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन करे, जो मान्यताप्राप्त दल हैं और जिनकी आय/व्यय 10 करोड़ रुपए से अधिक है। तदनुसार, बोर्ड ने राजनैतिक दलों के 18 वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन किया था, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 से संबंधित थे। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने विशेष मामलों के रूप में कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए तथा मीडिया रिपोर्टों और प्राप्त हुए अन्य प्रतिनिर्देशों के आधार पर विभिन्न उद्यमों के 13 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट के पुनर्विलोकन का कार्य भी किया है।
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के साथ बैठक : एफआरआरबी की प्रक्रिया को समझने के लिए एनएफआरए ने आईसीएआई से एक बैठक का अनुरोध किया था। श्री आर. श्रीधरन, अध्यक्ष, एनएफआरए और श्री प्रसनजीत मुखर्जी, सदस्य, एनएफआरए के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष, एफआरआरबी ने उसके विस्तार क्षेत्र, उसकी प्रक्रियाओं और योगदान तथा साथ ही ऐसे उपायों का हवाला देते हुए, जिनके माध्यम से एफआरआरबी ने समय-समय पर विभिन्न विनियामकों का समर्थन किया है, एफआरआरबी के पर्यावलोकन के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण किया था। साथ ही, उन्होंने ऐसी अनेक घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की थी, जहां एफआरआरबी द्वारा पाई गई अनियमितताओं/अननुपालनों को उद्यम से सुसंगत विनियामक निकाय (एमसीए/सेबी/ईसीआई) को अग्रेषित किया गया है।
- एफआरआरबी ने 23 जनवरी, 2019 को आईसीएआई भवन, नई दिल्ली में अपनी 100वीं बैठक का आयोजन किया था। इस अवसर पर, बोर्ड ने तकनीकी पुनर्विलोककों और समूह सदस्यों के लिए एक वेबकास्ट का भी आयोजन किया था। अध्यक्ष, एफआरआरबी, उपाध्यक्ष, एफआरआरबी ने उनके योगदान को मान्यता प्रदान की थी और साथ ही पुनर्विलोकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में उनकी सराहना की थी और साथ ही बोर्ड की आगे की कार्ययोजना के बारे में भी बताया था। कुछ केंद्रीय परिषद् सदस्यों, देश भर से तकनीकी पुनर्विलोककों और समूह सदस्यों ने इस वेबकास्ट में भाग लिया था। इस वेबकास्ट को, इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों से व्यापक अनुशंसा प्राप्त हुई थी।

इसके अतिरिक्त वर्तमान और साथ ही पूर्व बोर्ड सदस्यों के योगदान और प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। सीए नवीन एन.डी. गुप्ता, अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए. प्रफुल पी. छाजेड़, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, सीए. टी.एस. विश्वनाथ, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए. एन.डी. गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और राज्य सभा के माननीय सदस्य सीए. अमरजीत चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए. जयंत पी.

गोखले, सी.ए. विनोद जैन, सी.ए. बाबू अब्राहम कल्लीवायलिल, बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी और साथ ही कुछ परिषद् सदस्य, तकनीकी पुनर्विलोकक, वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह के सदस्य भी उपस्थित थे।

(II) प्रकाशन : जर्नल में लेख

बोर्ड ने, पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए अनुपालनों के संबंध में संस्थान के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को अवगत कराने के विचार से, विभिन्न लेखांकन मानकों से संबंधित 'रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अनुपालन' विषय से संबंधित लेखों की एक शृंखला का जर्नल में प्रकाशन आरंभ किया था। इस दिशा में, एएस 1 : लेखांकन नीतियों का प्रकटन, एएस 15 : कर्मचारियों के फायदे, एएस 3 : नकद प्रवाह विवरण, एएस 2 : मद सूचियां और एएस 18 : संबद्ध पक्षकार प्रकटनों से संबंधित 'रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अनुपालन' विषय से संबंधित चार लेखों को संस्थान के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के क्रमशः नवंबर, 2018, अप्रैल, 2019, मई, 2019 और जून, 2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया है।

(III) सदस्यों को सशक्त करना और सक्षमता निर्माण

⇒ वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में किए गए परिवर्तनों के संबंध में सदस्यों के ज्ञान में अभिवृद्धि करने और उन्हें बोर्ड द्वारा विभिन्न वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए सामान्य अनुपालनों के बारे में अवगत कराने के लिए इस अवधि के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए थे:

- मार्च, अप्रैल, मई और जून, 2019 मास के दौरान एएस 15, एएस 3, एएस 2, एएस 18 और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अनुपालनों के संबंध में चार लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया था, जिनमें सदस्यों ने बड़ चढ़कर भाग लिया था।
- एफआरआरबी द्वारा गुरुग्राम, कोलकाता, लुधियाना और चंडीगढ़ में "वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों" संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। गुरुग्राम और कोलकाता में इन कार्यक्रमों में क्रमशः 156 और 113 सदस्यों ने भाग लिया था तथा लुधियाना-चंडीगढ़ में प्रत्येक नगर में 150 से अधिक सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था।
- तकनीकी पुनर्विलोककों और एफआरआरजी सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: तकनीकी पुनर्विलोककों (टीआर) और वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह (एफआरआरजी) के सदस्यों को इंड एएस के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करने तथा इंडएएस आधारित वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन हेतु आवश्यक कौशलों से उन्हें सुसज्जित करने के लिए एफआरआरबी द्वारा 'तकनीकी पुनर्विलोककों और एफआरआरजी सदस्यों के लिए दो दिवसीय आवासीय कार्यशाला' का आयोजन किया गया था।
- बोर्ड ने 14 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में 'वित्तीय विवरणों को तैयार करने वाले व्यक्तियों और उनके संपरीक्षकों के लिए संगोष्ठी' का आयोजन भी किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एनआईआरसी द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम का उदघाटन अध्यक्ष, आईसीएआई और श्री वी. कुरियन, पूर्व डीजी (वाणिज्यिक) सी एंड एजी द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपने सर्वांगीण अनुभव को इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के साथ साझा करके उनके ज्ञान को समृद्ध बनाया था। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करने के विचार से एक पैनल परिचर्चा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विख्यात निगमों के सीएफओ और साथ ही व्यवसायगत अनुभव प्राप्त सदस्यों को इस विषय पर उनके विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में 176 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था तथा इसे इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों और संकाय की अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त हुई थी।

5.14 अप्रत्यक्ष कर समिति (आईटीसी)

(I) सरकार को अंतःनिवेश/समर्थन : समिति ने सरकार को निम्नलिखित अंतःनिवेश/सुझाव प्रस्तुत किए हैं

- 26 सितंबर, 2018 को वार्षिक विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-09 के संबंध में सुझाव।
- 11 दिसंबर, 2018 को जीएसटी संपरीक्षा प्ररूप जीएसटीआर-09 के संबंध में सुझाव।
- 31 अगस्त, 2018 को जीएसटी संबंधी प्रारूप विवरणी प्ररूपों के संबंध में सुझाव।
- 12 जुलाई, 2018 को जीएसटी विधि के संबंध में सुझाव।

- 18 जुलाई, 2018 को जीएसटी विधि में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में सुझाव ।
- 17 जुलाई, 2018 को जीएसटी के अधीन वैकल्पिक कार्य योग्य विलोम प्रभार तंत्र ।
- बजट-पत्र ज्ञापन, 2018
- जीएसटी लेखांकन, बिलिंग और विवरणी फाइल करने संबंधी साफ्टवेयर के परीक्षण हेतु जीएसटीएन में सदस्यों का नामनिर्देशन ।

(II) सरकार को/उसके समक्ष प्रतिवेदन/प्रस्तुतीकरण : समिति ने सरकार को निम्नलिखित विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे :

- 17 अप्रैल, 2018 को मंत्रियों के समूह (जीओएम) के साथ जीएसटी विवरणी फाइल करने के संबंध में परामर्शी बैठक ।
- 8 अक्तूबर, 2018 को सीबीआईसी और जीएसटीएन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ।
- 4 दिसंबर, 2018 को प्ररूप जीएसटीआर 9 और 9ग को फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने के लिए प्रतिवेदन ।
- 15 अक्तूबर, 2018 को वित्तीय वर्ष 2017-18 के संबंध में 31 दिसंबर, 2018 तक जीएसटी के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की अनुमति देने के लिए प्रतिवेदन ।
- 4 अक्तूबर, 2018 को जीएसटी के कार्यान्वयन के पश्चात् एमवीएटी अधिनियम के अधीन टीडीएस की कटौती न करने का सुझाव देते हुए प्रतिवेदन ।
- 29 मई, 2018 को वेबसाइट पर अग्रिम विनिर्णय के निर्णय को रखे जाने संबंधी प्रतिवेदन ।

(III) प्रकाशन – एक अनुसंधान पहल : समिति ने जीएसटी/सेवा कर/ सीएसटी/ सीमाशुल्क/ एफटीपी के संबंध में निम्नलिखित प्रकाशन/पुनरीक्षित प्रकाशन निकाले :

- वार्षिक विवरणी और जीएसटी संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड – दूसरा संस्करण - मई, 2019 (नया और एक बार पुनरीक्षित)
- जीएसटी वार्षिक विवरणी हैंडबुक - प्रथम संस्करण - मई, 2019
- जीएसटी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री – सातवां संस्करण - मार्च, 2019
- ई-वे विधेयक संबंधी ई-प्रकाशन - चौथा संस्करण - फरवरी, 2019
- सरकार को/द्वारा जीएसटी के अधीन पूर्तियों संबंधी ई-प्रकाशन – प्रथम संस्करण - जनवरी, 2019
- जीएसटी के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों संबंधी ई-प्रकाशन – प्रथम संस्करण - जनवरी, 2019
- वाणिज्य के छात्रों के लिए जीएसटी विधि संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री – प्रथम संस्करण - जनवरी, 2019
- सीमा शुल्क और एफटीपी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री – तीसरा संस्करण - जनवरी, 2019
- जीएसटी के अधीन प्रतिदाय संबंधी ई-प्रकाशन – प्रथम संस्करण - दिसंबर, 2018
- जीएसटी संबंधी बेयर विधि – तीसरा संस्करण- नवंबर, 2018
- जीएसटी के अधीन वर्गीकरण संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - जुलाई, 2018
- जीएसटी संशोधनों संबंधी ई-हैंडबुक - प्रथम संस्करण - जून, 2018
- जीएसटी के अधीन जॉब वर्क संबंधी ई-हैंडबुक - दूसरा संस्करण - जून, 2018
- बैंककारी क्षेत्र में जीएसटी अनुपालन - छठा संस्करण - अप्रैल, 2019

(IV) दुबई में वैट संबंधी पहलें : 1 जनवरी 2018 से संयुक्त अरब अमीरात में वैट को कार्यान्वित किया गया है । वहां मौजूद सदस्यों की सहायता करने के विचार से समिति ने निम्नलिखित पहलें की हैं :

- संयुक्त अरब अमीरात वैट संबंधी बीजीएम का पुनरीक्षण – तीसरा संस्करण – जून, 2018
- संयुक्त अरब अमीरात वैट संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन
- संयुक्त अरब अमीरात वैट पर लाइव वेबकास्ट की श्रृंखला का आयोजन

(V) ई-पहलें

- जीएसटी संपरीक्षा संबंधी ई-पठन : समिति ने जीएसटी के लगभग सभी विषयों को सम्मिलित करते हुए रिकार्ड किए गए वीडियो सत्रों के माध्यम से जीएसटी संबंधी ई-पठन को आरंभ किया है । इसके लिए 1160 पणधारियों ने इसकी सदस्यता प्राप्त की और इस पहल का फायदा उठाया ।

- मुकदमा प्रबंध संबंधी ई-पठन : अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सदस्यों में आगे और सक्षमता के निर्माण के लिए समिति ने मुकदमा प्रबंध संबंधी 13 सत्रों को रिकार्ड किया था और उन्हें ई-पठन के रूप में संपरिवर्तित किया था।
- जीएसटी संपरीक्षा संबंधी लाइव वेबकास्ट श्रृंखला : समिति ने जीएसटी संपरीक्षा के संबंध में जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, 2018 के दौरान लाइव वेबकास्टों की तीन श्रृंखलाओं का आयोजन किया था।
- सीमाशुल्क और एफटीपी संबंधी लाइव वेबकास्ट श्रृंखला : अप्रत्यक्ष कर क्षमताओं के सकल निर्माण के लिए समिति 2-9 फरवरी, 2019 के दौरान सीमाशुल्क और एफटीपी संबंधी लाइव वेबकास्ट श्रृंखला का आयोजन कर रही है, जिसमें 10 सत्र अंतर्विष्ट हैं।
- छात्रों के लिए जीएसटी संबंधी लाइव वेबकास्ट श्रृंखला : समिति ने, अध्ययन बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से 14, 15, 21, 22, 28 और 29 जुलाई, 2018 तथा 4, 5, 11 और 12 अगस्त, 2018 के दौरान छात्रों के लिए जीएसटी संबंधी लाइव वेबकास्ट श्रृंखला का आयोजन किया है।
- जीएसटी के विभिन्न पहलुओं संबंधी लघु वीडियो : समिति ने जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर 70 लघु वीडियो को रिकार्ड किया है, जिन्हें यू ट्यूब पर निःशुल्क रूप से अपलोड किया गया है।
- जीएसटी संबंधी आईसीएआई का ई-न्यूज़ लैटर : आईसीएआई अप्रैल, 2017 से अपना जीएसटी संबंधी न्यूज़ लैटर जारी कर रहा है। जून, 2019 तक इसके 23 संस्करणों को जारी किया जा चुका है।
- जीएसटी संबंधी मानकीकृत पीपीटी : समिति ने जीएसटी संबंधी मानकीकृत पीपीटी को विकसित किया है तथा उसे संकाय सदस्यों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और जीएसटी संबंधी कार्यक्रमों के सत्रों में एकसमानता लाने और साथ ही पीपीटी के माध्यम से जीएसटी के पठन के लिए सदस्यों को एक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट पर रखा था।
- सरकार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम : सरकार को सक्षमता निर्माण में सहायता करने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करने के लिए समिति ने देश भर की विभिन्न कमीशनरियों में जीएसटी संबंधी सात प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

(VI) पाठ्यक्रमों, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के माध्यम से सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

- **जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** समिति ने सदस्यों को प्रणालीगत रीति में जीएसटी के क्षेत्र में विशेषीकृत और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराने के विचार से तथा उनके कौशलों में अभिवृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 25 बैचों का संचालन किया है, जिसमें 1227 सदस्यों ने भाग लिया है।
- **कार्यक्रम, संगोष्ठियां और सम्मेलन :** इस अवधि के दौरान समिति द्वारा 61 कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया है, जिनमें 12,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था।
- **जीएसटी के सुचारू क्रियान्वयन में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए अध्ययन समूह का सृजन :** समिति ने जीएसटी के सुचारू क्रियान्वयन में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए राज्य स्तरीय जीएसटी संबंधी उन्नीस (19) अध्ययन समूहों का सृजन किया है।
- **विधिक अद्यतन जानकारी सहित अप्रत्यक्ष कर संबंधी अद्यतन जानकारी –** सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से, जीएसटी सहित अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के संक्षिप्त विवरण को आईडीटी नेट पर रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के बीच समिति की वेबसाइट www.idtc.icaai.org के माध्यम से नियमित रूप से परिचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, समिति ने हाल ही में उसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष करों संबंधी अद्यतन विधिक जानकारी भेजनी आरंभ की है।
- भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उस समय आईसीएआई के जीएसटी संबंधी प्रयासों को अभिस्वीकार किया था जब उन्होंने अपने सीए संदेश के दौरान कहा था कि "एक वर्ष पूर्व, जब राष्ट्र ने एक राष्ट्र एक कर के उद्देश्य की दिशा में अपने कदम बढ़ाने आरंभ किए थे, उस समय मुझे आप लोगों (सीए) के भ्रातृसंघ को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमने माल और सेवाकर को सफलतापूर्वक लागू करके भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक नए युग को प्रारंभ किया है। यह उपलब्धि आप लोगों (सीए) के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान के बिना प्राप्त नहीं हो सकती थी, जिसके दौरान आपने न केवल

कारबारों को नई कर व्यवस्था को अपनाने में सहायता की अपितु साथ ही प्रणाली को सरल बनाने के लिए नवीन उपायों को भी लागू किया।

5.15 आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड

वैश्वीकरण, अवनियमीकरण, कारबार में बढ़ती जटिलता, आईटी प्रणालियों में उन्नति और पणधारियों की बढ़ती आशाओं के इस युग में, इन परिवर्तनों को सुकर बनाने वाले आंतरिक संपरीक्षकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका ध्यान का केंद्र बनी हुई है। अतः, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्यों को, उन्हें इन उच्चतर कर्तव्यों के निर्वहन में समर्थ बनाने हेतु बेहतर रूप से सुसज्जित करने की आवश्यकता में बढ़ोतरी हो रही है। आईसीएआई इन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और वह अपने आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंटों को आधुनिक तकनीकी दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए अनेकों उत्कृष्ट पहलें अपना रहा है। वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों का एक विस्तृत पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

(I) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक

बोर्ड, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों को तैयार करता है, जो सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु मूलभूत सिद्धांतों को अधिकथित करने के अलावा उनके कार्यपालन संबंधी वैचकारों के रूप में भी कार्य करते हैं। बोर्ड ने इन मानकों को पुनरीक्षित करने की कार्यवाही आरंभ की है, जिससे उन्हें सिद्धांतों पर आधारित किया जा सके और उन्हें चरणबद्ध रीति में कंपनियों के कतिपय वर्ग के लिए आज्ञापक बनाया जा सके। पुनरीक्षित मानकों को पुनः संख्यांकित किया गया है तथा प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है : मूल अवधारणाओं संबंधी मानक (100 शृंखला), आंतरिक संपरीक्षा प्रबंध संबंधी मानक (200 शृंखला), संपरीक्षा समनुदेशनों संबंधी मानक (300-400 शृंखला), विशेषीकृत क्षेत्रों संबंधी मानक (500 शृंखला), क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (600 शृंखला) और प्रकीर्ण विषयों संबंधी मानक (700 शृंखला)। ये सिद्धांत आधारित मानक आंतरिक संपरीक्षा क्रियाकलापों के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराते हैं, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी कार्यपालन के मूल्यांकन के लिए आधार की स्थापना करते हैं और संगठन संबंधी प्रक्रियाओं और प्रचालनों में सुधार लाते हैं। इस अवधि के दौरान आंतरिक संपरीक्षा मानकों संबंधी बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा से संबंधित निम्नलिखित मानकों को पुनरीक्षित किया है और जारी किया है :

- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी ढांचे और मानकों का प्राक्कथन
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षाओं को शासित करने वाला ढांचा
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा के आधारीक सिद्धांत
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 210, आंतरिक संपरीक्षा कृत्यों का प्रबंध
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 220, सकल आंतरिक संपरीक्षा योजना का संचालन
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 310, आंतरिक संपरीक्षा समनुदेशनों संबंधी योजना
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 320, आंतरिक संपरीक्षा साक्ष्य
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 330, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी दस्तावेजीकरण
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 110, आश्वासन की प्रकृति
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 230, आंतरिक संपरीक्षा के उद्देश्य
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 240, किसी विशेषज्ञ के कार्य का उपयोग
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 360, प्रबंधन के साथ परस्पर संपर्क
- ⇒ आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 370, परिणामों की रिपोर्टिंग

- बोर्ड ने सदस्यों को विद्यमान मानकों के सेट का एकल संदर्भ उपलब्ध कराने के लिए आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों (1 फरवरी, 2019 को यथा विद्यमान) के सार संग्रह को जारी किया है।

(II) उद्योग विनिर्दिष्ट और साधारण आंतरिक संपरीक्षा गाइड

बोर्ड ने विभिन्न परियोजनाओं, अर्थात् बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा के मैनुअल के पुनरीक्षण (2016 संस्करण), एफएमसीजी सेक्टर की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, सीमेंट उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, भेषजीय उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, टायर उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी

तकनीकी गाइड, स्टॉक दलालों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड का पुनर्विलोकन करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया है।

(III) बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

सदस्यों को बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी जटिलताओं को समझने में समर्थ बनाने के लिए आईसीएआई का आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड “बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा” संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है। बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 61 बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और इस अवधि के दौरान लगभग 1780 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक अर्जित किया है। लगभग 1150 अभ्यर्थियों के लिए अगस्त, 2019 में आनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।

(IV) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड ने “आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” की पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण किया है, जिसका, उसमें नए विषयों और सूचना प्रौद्योगिकी को पूर्णरूपेण समाविष्ट करते हुए, पूर्णतया सुधार किया गया है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आंतरिक संपरीक्षा के सिद्धांतों और अवधारणाओं, विशेष रूप से जोखिम प्रबंध और शासन संबंधी अवधारणाओं से उनके जुड़े होने के संबंध में शिक्षित करना, आंतरिक संपरीक्षा की योजना को तैयार करने और उसका संचालन करने के लिए व्यावहारिक उद्भासन उपलब्ध कराना, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और विशेषीकृत उपकरणों का उपयोग करते हुए, वर्तमान सर्वोत्तम व्यवहारों को समझना और जोखिमों को कम करने के लिए उन्हें उपयोग करने के मार्गों और कारबार संबंधी चुनौतियों का सामना करने और सदस्यों की, अत्यधिक वृत्तिक रूप से सर्वोत्तम आंतरिक संपरीक्षा संचालन करने के लिए अपेक्षित सभी कौशलों और ज्ञान को अर्जित करने में सहायता करना है, जो न केवल आधारीक आश्वासन उपलब्ध कराते हैं अपितु इन संगठनों से मूर्त मूल्य भी जोड़ने की अपेक्षा करते हैं।

परिषद् ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पुनरीक्षित पाठ्यचर्या को हाल ही में अनुमोदित किया है और बोर्ड ने इसकी मोडेलिटिज को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। उक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के बैचों को भारत के महानगरों में आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ई-पठन संबंधी सभी माड्यूलों की वीडियो रिकार्डिंग कर ली गई है और उन्हें संस्थान के ई-पठन मंच पर अपलोड किया जा रहा है।

(V) बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड ने वर्ष 2018 में एक नई पहल की है, जिसके अंतर्गत बोर्ड ब्लू जीस लिंक के माध्यम से कक्षाओं का संचालन करेगा और यह लिंक बोर्ड द्वारा उन कक्षाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा में भाग लेने वाले व्यक्ति अपने लैपटाप/कंप्यूटर प्रणाली पर उस लिंक के माध्यम से लॉगिन करेंगे। इस प्रकार कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए उनके स्थान या शाखा परिसरों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ब्लू जीस के माध्यम से, कक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों और वक्ताओं को कहीं से भी आमने-सामने जोड़ा जाएगा। बोर्ड ने दिसंबर, 2018 में अनंतपुर में इस वर्चुअल पाठ्यक्रम के पहले बैच का सफलतापूर्वक आयोजन किया था।

(VI) बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी ई-पठन

सदस्यों को सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के लिए आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने “बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम” के ई-पठन माड्यूलों को विकसित करने की परियोजना को आरंभ किया है, जिसमें समवर्ती संपरीक्षा के व्यावहारिक पहलुओं से संबंधित क्विज़ों और मामला अध्ययनों को सम्मिलित किया जाएगा।

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ई-पठन संबंधी सभी माड्यूलों की वीडियो रिकार्डिंग कर ली गई है और उन्हें संस्थान के ई-पठन मंच पर अपलोड किया जा रहा है।

(VII) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी जागरूकता के लिए कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और वेबीनार

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के विचार से बोर्ड ने इस अवधि के दौरान, विभिन्न अवस्थानों पर आंतरिक संपरीक्षा संबंधी 8 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। बोर्ड ने 27 अप्रैल, 2018 को “समवर्ती संपरीक्षा को और अधिक प्रभावी और सुसंगत बनाने” संबंधी 29वें वेबीनार का भी आयोजन किया था।

(VIII) आंतरिक संपरीक्षा वृत्ति की 2019 में प्राप्ति संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट

यह भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा भारत में आंतरिक संपरीक्षा वृत्तियों के संबंध में आरंभ किया गया पहले व्यापक सर्वेक्षणों में से एक है और इसका संचालन आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड के तत्वाधान में किया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान, इसमें भाग लेने वाले 406 व्यक्तियों के मत प्राप्त किए गए थे, जिनमें उद्योग (44%) और व्यवसाय में लगे (56%), दोनों प्रकार के सदस्यों और अन्यो को सम्मिलित किया गया था और इस सर्वेक्षण में 27 प्रश्नों का उपयोग करते हुए विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित किया गया था तथा इस सर्वेक्षण का आयोजन नवंबर और दिसंबर, 2018 के दौरान किया गया था। यह रिपोर्ट इस कार्य का परिणाम है और इसे, भारत में आंतरिक संपरीक्षा वृत्ति के संबंध में, उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के अंतःनिवेश के आधार पर वर्तमान के रुझानों का आकलन करने और भविष्य की संभावनाओं का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है।

5.16 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति**(I) सरकार को प्रतिवेदन/उसके साथ परस्पर क्रियाएं**

- भुवनेश्वर में अंतरण कीमत निर्धारण यूनिट की स्थापना के लिए सीबीडीटी को अनुरोध
- आय-कर की विवरणी में विदेशी कर प्रत्यय का दावा करने के लिए प्ररूप सं. 67 को फाइल करने में आने वाली कठिनाईयों और चुनौतियों तथा आय-कर विवरणी में भारतीय बैंक खाते को रिपोर्ट किए जाने के संबंध में प्रतिवेदन
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी बजट-पूर्व ज्ञापन को प्रस्तुत किया जाना
- सीबीडीटी से स्थायी स्थापनों (पीई) को होने वाले लाभ से संबंधी नियमों के संशोधन से संबंधित प्रस्तावों के बारे में जनता से परामर्श करने हेतु अनुरोध किया गया था।

(II) अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वेबकास्ट

- समिति द्वारा 14 जुलाई, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा द्वारा की गई थी और जिसमें अनिवासी कराधान – प्रमुख मुद्दे, स्थायी स्थापन – वर्तमान विधिक रुझान, बीईपीएस कार्ययोजनाएं और बहुपक्षीय लिखतें (एमएलआई), साधारण प्रति अपवंचन नियम (जीएएआर) और धारा 195 – करों का प्रतिधारण करना, जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र सम्मिलित थे।
- आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति द्वारा 4.9.2018 को “हांगकांग अंतरण कीमत निर्धारण विधान – बीईपीएस विधेयक के संबंध में एक पर्यावलोकन” विषय पर एक लाइव वेबकास्ट।
- आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति द्वारा 25.04.2019 को “जीएएआर – मुद्दे और मामला अध्ययन” विषय पर एक लाइव वेबकास्ट।
- आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति द्वारा 30.05.2019 को “स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस – मामला अध्ययन” विषय पर एक लाइव वेबकास्ट।

(III) अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा

समिति ने इस अवधि के दौरान, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, गाजियाबाद, पुणे, त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम और कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा के 14 बैचों का संचालन किया था।

(IV) अन्य पहलें

- समिति ने ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी ई-न्यूज़ लैटर के नौवें संस्करण को जारी किया था।
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी प्रमाणपत्र कार्यक्रम के लिए निर्धारण परीक्षाओं के दो प्रयासों का आयोजन अप्रैल, 2018 और अक्तूबर, 2018 के दौरान किया गया।
- समिति ने निम्नलिखित व्यौरों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ ई-पठन माड्यूल को भी सम्मिलित किया है :
 - आधार क्षरण और लाभ का स्थानांतरण (कार्ययोजना 8-10 और 13 को छोड़कर) तथा बहु पक्षीय लिखतें।

- आधार क्षरण और लाभ का स्थानांतरण - कार्ययोजना 8-10 ।
- अंतरण कीमत निर्धारण दस्तावेजीकरण और प्रारूपण (बीईपीएस कार्ययोजना 13 सहित)
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी पाठ्यक्रम और अनिवारियों के कराधान में डिप्लोमा संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री का पुनरीक्षण ।
- सीए जर्नल में अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी लेखों का योगदान ।
- घरेलू और साथ ही विदेशों में रहने वाले सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय कराधान के विषय पर नियमित रूप से अद्यतन जानकारी देना ।

5.17 उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति

यह समिति व्यक्ति और संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बिठाने, उद्योग और आईसीएआई के बीच अंतरापृष्ठ का सृजन करने और चार्टर्ड अकाउंटेंट को उनके पारंपरिक क्षेत्रों से परे कंपनी, कारबार और वाणिज्य के कार्यकरण से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में एक ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने/स्थापित करने के लिए एक प्रभावी मंच का प्रयोजन सिद्ध करती है। यह समिति उद्योग और कारबार में सेवारत सीए और संस्थान के बीच निकट संबंध को प्रोत्साहित करने तथा उसमें अभिवृद्धि करने का कार्य करती है। इस प्रयास का समर्थन करने के लिए, सीएमआईएंडबी सदस्यों के फायदे के लिए विभिन्न ज्ञानवर्धन सम्मेलनों, उद्योग बैठकों और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। सीएमआईएंडबी के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में सदस्यों के हित में कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों और आईसीएआई जॉब पोर्टल के माध्यम से युवा और अनुभव प्राप्त, दोनों प्रकार के चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर उपलब्ध कराना, कारबार और उद्योग चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए गौरवशाली आईसीएआई पुरस्कारों का आयोजन करना, वृत्तिक दिलचस्पी के विषयों में सामान्य प्रकाशन जारी करना, सीपीई अध्ययन सर्किलों का सृजन करना, ई-न्यूज़ लैटर का प्रकाशन करना, आदि सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए प्रमुख क्रियाकलापों को नीचे उपदर्शित किया गया है :

(I) नए अर्हित सीए के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

- अगस्त-सितंबर, 2018 : इसका आयोजन 17 केंद्रों में किया गया था, जिसके लिए 5822 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकृत किया था, जिनमें से 3530 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे। इसमें 111 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 1600 अभ्यर्थियों को नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे। घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 22.62 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन (कंपनी को लागत) का प्रस्ताव किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए 35 लाख प्रतिवर्ष के वेतन का प्रस्ताव किया गया था।
- फरवरी-मार्च, 2019 में : इसका आयोजन 17 केंद्रों में किया गया था, जिसके लिए 9011 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकृत किया था, जिनमें से 6646 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे। इसमें 139 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 3815 अभ्यर्थियों को नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे। घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 22.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन (कंपनी को लागत) का प्रस्ताव किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए 36 लाख प्रतिवर्ष के वेतन का प्रस्ताव किया गया था।

(II) विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

लेखांकन सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार की भारतीय चैंपियन सेक्टर पहल में भागीदारी करने के अपने मिशन के अनुरूप आईसीएआई ने अपनी सीईएसडब्ल्यूटीओ, सीएमआईआई और आईए समितियों के तत्वाधान में 14-16 सितंबर, 2018 के दौरान विदेशी कैम्पस नियोजन अभियान का आयोजन किया था। इस अभियान के दौरान साक्षात्कारों का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलौर में किया गया था ; मुंबई, दिल्ली और चेन्नई केंद्रों में आमने-सामने की भौतिक परस्पर क्रियाओं और वीडियो कांफ्रेंसिंग, दोनों को उपलब्ध कराया गया था।

रजिस्ट्रीकृत कंपनियों की कुल संख्या	मध्य-पूर्व और अफ्रीका से भाग लेने वाली कुल कंपनियां	रजिस्ट्रीकृत सदस्य	सूचीबद्ध किए गए सदस्य	भाग लेने वाले सदस्य	प्रस्ताव
42	29	6428	1527	544	66

प्रथम पहल होने के कारण, इस अभियान से अनेक सकारात्मक चीजें सामने आई थी और मध्य-पूर्व में आर्थिक मंदी और धीमी अर्थव्यवस्था के बावजूद आईसीएआई ने अपने सीमित प्रयासों से 42 कंपनियों की दिलचस्पी को आकर्षित किया था और वह भी केवल मध्य-पूर्व से तथा अफ्रीका से केवल एक ही कंपनी ने रजिस्ट्रीकृत किया था।

(III) **नौकरी मेला** : 19 जनवरी, 2019 को मुंबई में आईसीएआई के सीए इंटर/आईपीसीसी/पीई II के अभ्यर्थियों हेतु नौकरी मेले का आयोजन किया गया था।

(IV) अनुभव प्राप्त सीए के लिए नियोजक

- कैरियर अभिवृद्धि कार्यक्रम का संक्षिप्त वर्णन : सीएमआईएंडबी ने 29 जून, 2018 को मुंबई में तथा 30 जून, 2018 को चेन्नई और नई दिल्ली में अपने कैरियर अभिवृद्धि कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। यह कार्यक्रम अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों को प्रमुख संगठनों में अपने कैरियर की प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु नियोजन अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। यह एक भलीभांति तैयार किया गया ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम था, जिनके पास उद्योग में कार्य करने का तीन वर्ष से अधिक का अनुभव है। 17 संगठनों (22 साक्षात्कार दलों) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसके दौरान 291 रिक्तियों को भरा गया था और इस कार्यक्रम हेतु 1,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकृत किया था।
- पार्श्वीय नियोजन : अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों को प्रमुख संगठनों में अपने कैरियर की प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु नियोजन अवसरों के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के विचार से 25 से 28 जून, 2019 के दौरान चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में पार्श्वीय नियोजन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। 14 कंपनियों (17 साक्षात्कार दलों) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसके दौरान 226 रिक्तियों को भरा गया था।

(V) पुरस्कार

- एसएमई लीडर पुरस्कार : समिति ने 26 अक्तूबर, 2018 को मुंबई में, ऐसे सदस्यों, जिन्होंने एसएमई क्रियाकलापों और उससे संबंधित विकास में मूल्यवान योगदान प्रदान किया है, की दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और सफलता का सम्मान करने के लिए सफलतापूर्वक "एसएमई लीडर पुरस्कारों" का आयोजन किया था। श्री मनोहर कुमार, सीएमडी, राष्ट्रीय परियोजना संनिर्माण निगम लिमिटेड की अध्यक्षता वाले ज्यूरी पैनल ने 11 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया था, जिन्हें इस रंगारंग रात्रि कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय लीडर पुरस्कार : समिति ने, भारत से बाहर अवस्थित सदस्यों के लिए, उनकी ऐसी उपलब्धियों को, जिनके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने कैरियर की ऊंचाईयों को छुआ है, मान्यता प्रदान करने हेतु आईसीएआई के आबू धाबी चैप्टर की मेजबानी में 15 नवंबर, 2018 में आबू धाबी में सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय लीडर पुरस्कारों का आयोजन किया था। डा. सुभाष चंद्र खुंटिया, अध्यक्ष, आईआरडीएआई की अध्यक्षता वाले ज्यूरी पैनल ने 7 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया था, जिन्हें इस पुरस्कार समारोह के दौरान सम्मानित किया गया था।
- 12वें आईसीएआई और कारबार उत्कृष्टता पुरस्कार : समिति ने मुंबई स्थित होटल ग्रैंड हयात में सफलतापूर्वक अपने 12वें आईसीएआई और कारबार उत्कृष्टता पुरस्कारों का आयोजन किया था। 29 पुरस्कार विजेताओं को श्री विजय गोयल माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री और सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था, जिसके उपरांत कलाकार श्री मीका सिंह द्वारा गीतों का प्रस्तुतीकरण किया गया था। इस पुरस्कार हेतु विजेताओं का चयन सीए के.के. मिस्त्री, उपाध्यक्ष और सीईओ, एचडीएफसी की अध्यक्षता वाले ज्यूरी पैनल द्वारा किया गया था।

(VI) आयोजित कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान, विभिन्न कार्यक्रमों, जिनके अंतर्गत संगोष्ठियां, लाइव वेबकास्ट, परस्पर क्रियाशील बैठकें, सीएफओ बैठकें आदि भी थे, का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में हाल ही की विधियों, जिसमें जीएसटी पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था, विलयन और अर्जन, संनिर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, ब्लॉकचेन, फिनटेक, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग, स्टार्टअप तैयार करना आदि जैसे विषय सम्मिलित थे।

(VII) उद्योग में लगे सदस्यों के लिए नए सीपीई अध्ययन सर्कल

समिति ने आईसीएआई के उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन किया है : रेमंड लिमिटेड का जे.के. ग्राम, सीपीई अध्ययन सर्कल, एल एंड टी - एमएचपीएस बॉयलर प्राइवेट लिमिटेड (एलएमबी) का फरीदाबाद सीपीई अध्ययन सर्कल, डीएक्ससी

टेक्नोलॉजी का ब्रुक फील्ड सीपीई अध्ययन सर्कल, सुंदरम क्लेटन लिमिटेड का हेडोस रोड सीपीई अध्ययन सर्कल, मैरिको लिमिटेड का ग्रांडे पैलेडियम सीपीई अध्ययन सर्कल, फिलिप्स ग्लोबल सर्विसेज एलएलपी का रामानुजन आईटीपी सीपीई अध्ययन सर्कल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का गाजियाबाद सीपीई अध्ययन सर्कल, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) का आइनोक्स नोएडा सीपीई अध्ययन सर्कल, जिंदल सॉ लिमिटेड का मोती नगर सीपीई अध्ययन सर्कल, सिप्ला लिमिटेड का मुंबई सीपीई अध्ययन सर्कल।

(VIII) सीए जॉब पोर्टल का शुभारंभ :

समिति ने, एक सीए जॉब पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो सीए के लिए सभी प्रकार की नौकरी संबंधी अपेक्षाओं के लिए एक साथ समाधान उपलब्ध कराता है, जहां नियोजता, एक ही स्थान पर उपलब्ध बड़ी संख्या में सुसंगत नौकरी संबंधी विकल्पों में से चयन कर सकते हैं। सीए जॉब पोर्टल मंच की पहुंच को और अधिक विस्तारित करने के लिए समिति ने सीए जॉब पोर्टल की एक मोबाइल ऐप्लीकेशन को भी आरंभ किया है, जिसमें ऐसी विशिष्टियां विद्यमान हैं, जो कैमरा संपर्क सूची कलेंडर आदि से परस्पर क्रिया करती हैं और उन्हें एक साथ लाती हैं, जिससे उपयोक्ता एक बटन दबाकर सुगमता से विभिन्न कार्यों को पूरा कर सकता है। इस सीए जॉब पोर्टल पर वर्तमान में 3614 कंपनियां रजिस्ट्रीकृत हैं, जिनके पास सदस्यों के लिए 1110 रिक्तियां और सीए इंटर उत्कीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 71 रिक्तियां उपलब्ध हैं।

(IX) सहायता पटल की स्थापना

समिति ने, समिति के भीतर, उसे प्राप्त होने वाली उद्योग में लगे सदस्यों की सभी शंकाओं और चिंताओं का निपटारा करने के लिए एक सहायता पटल की स्थापना की है। उद्योग में लगे सदस्य आईसीएआई से संबंधित अपनी शंकाओं को नीचे उल्लिखित चैनलों के माध्यम से समिति को प्रस्तुत कर सकते हैं :

- सहायता पटल, <https://cmib.icai.org> पर एक प्ररूप भरकर, या
- सहायता पटल, cmib@icai.in पर ई-मेल भेजकर, या
- 844851274 पर फोन करके।

5.18 पियर पुनर्विलोकन बोर्ड (पीआरबी)

व्यवसाय करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए पियर पुनर्विलोकन बोर्ड की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी।

पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान के सदस्य आश्वासन सेवा समनुदेशनों को पूरा करते समय (क) यथालागू तकनीकी, वृत्तिक और नैतिक मानकों, जिसके अंतर्गत उनसे संबंधित अन्य विनियामक अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करते हैं और (ख) उनके द्वारा दी जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को पर्याप्त रूप से उपदर्शित करने के लिए दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां सुस्थापित हैं। किसी व्यवसायी इकाई के पियर पुनर्विलोकन का संचालन, पियर पुनर्विलोकन के रूप में ज्ञात एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाता है।

बोर्ड के प्रयास की दो विनियामकों, जैसे कि सेबी और सीएंडएजी द्वारा मान्यता की अपेक्षाओं का नीचे कथन किया गया है :--

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापत्र बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्यक्षीन किया है और जो संस्थान के 'पियर पुनर्विलोकन बोर्ड' द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है; अब वह आवेदन प्ररूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से उनकी पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगता है, ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा आबंटित की जा सके। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सीएंडएजी वार्षिक रूप से आईसीएआई से उन फर्मों के ब्यौरे मांग रहा है, जिन्हें पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

अधिकाधिक फर्मों को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अधीन लाना

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने, जो भारत में सीए फर्मों की आश्वासन सेवाओं के पुनर्विलोकन के संबंध में एक विनियामक है, पियर

पुनर्विलोकन के लिए अधिकाधिक फर्मों को उसके अधीन लाकर आश्वासन सेवाओं के परिधि क्षेत्र में अभिवृद्धि की है। वित्तीय विवरणों में पाए गए अनुपालनों के ऐसे मामलों को, जो सत्य और उचित मत को प्रभावित नहीं करते हैं, अपितु संपरीक्षक की असावधानी को उपदर्शित करते हैं, एफआरआरबी द्वारा पियर पुनर्विलोकन के लिए अग्रेषित किया जाता है जिससे कि सदस्यों द्वारा लागू किए जाने वाला क्वालिटी नियंत्रण ढांचा अभिनिश्चित किया जा सके। साथ ही अब पियर पुनर्विलोककों से यह अपेक्षित है कि वे क्वालिटी पुनर्विलोकनाधीन व्यवसायी इकाई के विस्तार क्षेत्र के संबंध में और साथ ही क्वालिटी पियर पुनर्विलोकन बोर्ड को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के संबंध में आवश्यक अनुपालनों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, पीयू द्वारा किए गए विकास और उसके कार्मिकों को उसकी क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के समर्थन में दी गई संसूचनाओं और उपलब्ध कराए गए संसाधनों तथा निवेश के संबंध में भी व्यवसायी इकाई द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस संक्षिप्त रिपोर्ट को आवधिक रूप से क्यूआरबी को, उसके पुनर्विलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाता है। ऐसे प्रयास संस्थान के विनियामक तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने 30 जून, 2019 तक 11,411 पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्रों पर विचार और उन्हें जारी किया था।

5.19 वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी)

वर्ष 1962 में उसकी स्थापना से ही, वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी) संस्थान के सदस्यों के लिए अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त अवसरों की खोज करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। वृत्तिक विकास में नए क्षेत्रों की खोज करने के अलावा समिति, समाज के विभिन्न वर्गों में फैले बहुल उपयोक्ताओं के साथ संसूचना प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। वर्ष 2019 में, समिति, सहकारिता और एनपीओ सेक्टर संबंधी समिति द्वारा वर्ष 2018-19 में निष्पादित किए जा रहे विभिन्न कार्यों का भी निष्पादन कर रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंटों के विद्यमान और नए क्षेत्रों में कौशल सेटों में अभिवृद्धि करने के विचार से समिति हित के समकालीन क्षेत्रों के संबंध में सगोष्ठियों, कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है।

(I) सभी पीएसबी द्वारा बैंक शाखा संपरीक्षा के आबंटन के लिए साफ्टवेयर का विकास

संस्थान अनेक वर्षों से, पब्लिक सेक्टर बैंकों के बैंक बोर्डों द्वारा स्वयं संपरीक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रबंध मंडल का कोई प्रमुख स्वामित्व संबंधी हित नहीं होता है, प्रबंध मंडल द्वारा संपरीक्षकों की नियुक्ति किए जाने की यह स्वायत्तता बैंककारी जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र में अत्यंत जोखिम पूर्ण है।

इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, पीडीसी ने एक स्वचालित एप्लीकेशन का विकास किया है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बैंक शाखा संपरीक्षकों का चयन करती है। बड़ी संख्या में/सभी बैंकों द्वारा इस प्रकार विकसित साफ्टवेयर के उपयोग से यह आबंटन निष्पक्ष, पारदर्शी और साम्यापूर्ण बनने के अलावा एकसमान भी बन सकेगा। तदनुसार, पीडीसी ने अधिकांश बैंकों के समक्ष इस साफ्टवेयर का प्रदर्शन किया है और इस साफ्टवेयर के उपयोग हेतु पिछले वर्ष के दौरान चलाए जाने वाले उसके सतत अभियान के परिणामस्वरूप, इस साफ्टवेयर का उपयोग 7 बैंकों, अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ बडौदा, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स तथा पब्लिक सेक्टर बैंकों ने आरंभ कर दिया था।

(II) विभिन्न प्राधिकरणों के लिए पैनल

आरबीआई और नाबार्ड के लिए बैंक शाखा संपरीक्षक पैनल : पीडीसी ने, सीए सदस्यों के हेतु साम्यापूर्ण वृत्तिक अवसरों की खोज करने के अपने प्रयास में वर्ष 2018-19 के दौरान एमईएफ एप्लीकेशन को तैयार किया था, जिसमें उनके द्वारा भरे गए मामला संबंधी प्ररूप के संबंध में आईसीएआई के अभिलेखों से आवेदकों का पूर्व डाटा अंतर्विष्ट था। सदस्यों द्वारा, अंकीय रूप से हस्ताक्षरित या स्कैन की गई घोषणा को प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त ऑनलाइन रूप से वित्तीय दस्तावेजों के अपलोड को भी सुकर बनाया गया था।

प्राप्त आवेदनों के अनुसार, आरबीआई के सन्नियमों के अनुसरण में बैंक शाखा संपरीक्षकों का पैनल 2018-19 को तैयार किया गया था और उसे आरबीआई तथा नाबार्ड आदि को प्रस्तुत किया गया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को पैनल : सेबी प्रत्येक वर्ष, सेबी (परस्पर निधि) विनियम, 1996 के विनियम 61(1) के अधीन परस्पर निधियों का निरीक्षण करता है। अभी तक, ऐसी सीए फर्मों, जो सेबी की ओर से यह निरीक्षण करने में दिलचस्पी रखती थी, सेबी के साथ उन्हें पैनलबद्ध किए जाने से संबंधित पात्रता सन्नियमों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करती थी। गत वर्ष, पहली बार सेबी ने

आईसीएआई से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों/एलएलपी के एक पैनल के लिए अनुरोध करते हुए संपर्क किया था। तदनुसार, सेबी को एक पैनल प्रस्तुत किया गया है तथा यह कदम हमारे सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों को उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

वृत्तिक विकास समिति ने निम्नलिखित प्राधिकारणों को भी पैनल प्रस्तुत किए हैं :

- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
- गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ)
- स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, तमिलनाडु
- भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी
- वित्त विभाग, गुजरात सरकार
- वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, भारतीय प्रबंध संस्थान, तिरुचिरापल्ली
- केंद्रीय भांडागार निगम (सीडब्ल्यूसी), दिल्ली आदि

(III) विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन)

चार्टर्ड अकाउंटेंटों संबंधी सेवाओं के दुर्व्यपदेशन और गैर-सीए द्वारा सीए के नकली हस्ताक्षर किए जाने के कपटपूर्ण व्यवहारों को रोकने के लिए, आईसीएआई ने “यूडीआईएन पोर्टल” नामक एक मंच का सृजन करके एक यूडीआईएन संबंधी पहल की है, जहां कोई विनियामक/पणधारी जाकर रियल टाइम में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता का सत्यापन कर सकता है।

अतः, प्रत्येक व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक 18 अंकों वाले प्रणाली जनित किसी संख्यांक का सृजन करना होगा तथा उसे उसके द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले प्रत्येक प्रमाणपत्र/रिपोर्ट/दस्तावेज पर अंकित करना होगा तथा इस प्रकार, विनियामक/ पणधारी, प्रमाणपत्र/रिपोर्ट/दस्तावेज को प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटों के पूर्ववृत्त का सत्यापन कर सकता है।

आईसीएआई की परिषद् के निर्णय के अनुसार, ऐसे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए, जो पूर्ण रूप से व्यवसाय कर रहे हैं, निम्नानुसार चरणबद्ध रीति में यूडीआईएन को आज्ञापक बनाया गया है :

- सभी प्रमाणपत्रों के लिए 1 फरवरी 2019 से।
- सभी जीएसटी और कर संपरीक्षा रिपोर्टों के लिए 1 अप्रैल 2019 से।
- सभी आश्वासन/अधिप्रमाणन कृत्यों के लिए 1 जुलाई 2019 से।

आईसीएआई ने यह मामला विभिन्न विनियामकों और प्राधिकरणों के समक्ष उठाया था और उनसे यह अनुरोध किया था कि वे केवल यूडीआईएन वाले सीए द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों को ही स्वीकार करें और साथ ही सीए द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले सभी प्ररूपों/रिपोर्टों में यूडीआईएन को उल्लिखित करने संबंधी एक आज्ञापक स्तंभ को सम्मिलित करें।

आईसीएआई द्वारा इस प्रकार विकसित यूडीआईएन पोर्टल केवल पूर्णकालिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों को यूडीआईएन का सृजन करने की अनुज्ञा देता है। इस यूडीआईएन प्रणाली का उपयोग करके यूडीआईएन संख्यांक को धारण करने वाले विनियामक एक बटन दबाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पूर्ववृत्त और दस्तावेज की अधिप्रमाणिकता का सत्यापन कर सकते हैं।

यूडीआईएन एक सुरक्षित मंच पर प्रचालन करता है क्योंकि यह किसी दस्तावेज को अपलोड करने या किन्हीं गोपनीय व्यौरों को साझा करने की अपेक्षा नहीं करता है।

यूडीआईएन, वर्ष 2018-19 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है और आईसीएआई के विश्व के ऐसे अग्रणी संस्थानों में से एक है, जिसने यूडीआईएन की अवधारणा को इस प्रकार उपयोग किया है। इस अवधारणा के साथ, बेईमान तत्वों द्वारा कपटों और सीए के नकली हस्ताक्षर अब संभव नहीं रह गए हैं। अकाउंटेंटों के दक्षिण एशियाई फेडरेशन (साफा) के अनेक सदस्य निकायों ने आईसीएआई की इस अद्वितीय पहल के प्रति दिलचस्पी दर्शित की है और आईसीएआई के समन्वयन के अधीन साफा स्तर पर एक साफा कार्यबल का सृजन किया गया है।

(IV) निविदाएं

वृत्तिक सेवाओं संबंधी निविदाएं सदैव एक चिंता का विषय रहा है। पीडीसी ने निविदाओं को प्रदान किए जाने में मूल्यांकन मानदंडों सहित विभिन्न मुद्दों को विभिन्न समयों पर सीबीसी के समक्ष उठाया है।

यह देखा गया है कि कभी-कभी संगठन किसी न्यूनतम फीस का उल्लेख किए बिना या अत्यधिक निम्न न्यूनतम फीस को कोट करते हुए निविदाएं जारी करते हैं। दूसरी ओर, आईसीएआई के सदस्य भी इन निविदाओं के संबंध में अपने प्रत्युत्तर देते हैं, जिनमें न्यूनतम फीस का उल्लेख नहीं होता है और यह परिषद् के दिशानिर्देशों का उल्लंघनकारी है। निविदाओं से संबंधित ऐसे मुद्दों का समाधान करने के लिए, “निविदा संबंधी मुद्दों की मानीटरी” करने के लिए एक समूह का सृजन किया गया है। यह समूह निकाली गई निविदाओं और उनके मानकीकरण की मानीटरी करेगा और वृत्तिक सेवाओं से संबंधित निविदाओं के मूल्यांकन की रीति का निर्धारण करने के लिए सीवीसी से परामर्श करेगा और साथ ही सदस्यों के प्रत्युत्तरों की मानीटरी और विश्लेषण के लिए तंत्र का विकास करेगा और उनसे संबंधित विचलनों को उपयुक्त स्तर पर निर्दिष्ट किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, विभिन्न मुद्दों जैसे कि निविदा दस्तावेज में समनुदेशन की न्यूनतम फीस को कोट करने, कठोर/निर्बंधनकारी पात्रता शर्तों, उन्हें साम्यापूर्ण बनाने आदि के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों को भी विभिन्न प्रतिवेदन अग्रेषित किए गए थे।

(V) आयोजित किए गए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

आईसीएआई की सहकारिता और एनपीओ सेक्टर संबंधी समिति, सहकारिता और एनपीओ से संबंधित दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का आयोजन करती है। वर्ष के दौरान, समिति ने ग्वालियर और कोलकाता में सहकारिता संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दो बैचों तथा नोएडा और सिलिगुड़ी में एनपीओ संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दो बैचों का आयोजन किया था।

(VI) आईआईएम जैसे शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग पर विचार

आईसीएआई ने आईआईएमए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह करार किया गया था कि आईआईएमए द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अनन्य रूप से तैयार, विकसित और परिदत्त किए गए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सह-मेजबानी में भागीदारी की जाएगी। उक्त पाठ्यक्रम के दो बैचों का संचालन युवा सदस्य कौशल और नवीनीकरण विकास समिति द्वारा किया गया था, जिसमें 35 चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने इसमें भाग लिया था और यह अत्यंत सफल सिद्ध हुआ था तथा इस पहल को आगे और बढ़ाते हुए वृत्तिक विकास समिति 7 से 11 अक्तूबर, 2019 के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु अनन्य रूप से तैयार पाठ्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिससे वे कार्यकरण और प्रचालात्मक क्षेत्रों में प्रबंधकीय उत्कृष्टता अर्जित कर सकें।

(VII) सीए निदेशक संवादात्मक बैठक

- बैंकों और पब्लिक सेक्टर अस्तित्वों के बोर्ड में विद्यमान चार्टर्ड अकाउंटेंट निदेशकों के साथ सतत बातचीत बनाए रखने के आशय से, वृत्तिक विकास समिति ने तत्कालीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षों की उपस्थिति में श्री डा. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करके 14 जून, 2018 को नई दिल्ली में सीए निदेशकों के साथ वार्षिक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया था।
- इस वर्ष, इस बैठक के परिधि क्षेत्र को, आस्ति प्रबंध कंपनियों, बीमा कंपनियों और बैंकों के अतिरिक्त अन्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के सीए निदेशकों को सम्मिलित करते हुए और अधिक व्यापक बनाया गया था और इसका आयोजन निगम विधि और निगम शासन समिति के साथ संयुक्त रूप से किया गया था।
- 40 से अधिक सीए निदेशकों ने इस बैठक में भाग लेकर इसकी शोभा बढ़ाई थी तथा इसे अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी, इसमें समकालीन विषयों जैसे निगम शासन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, बैंकों में जोखिम प्रबंध, साइबर सुरक्षा, आदि जैसे तकनीकी विषयों संबंधी तकनीकी सत्रों को सम्मिलित किया गया था।

(VIII) विभिन्न अवस्थानों पर केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों के लिए संगोष्ठियों की श्रृंखला

आरबीआई द्वारा जारी पुनरीक्षित निदेशों/परिपत्रों तथा लेखांकन मानकों जैसे कि एसए 700, एसए 570, एसए 26, एसए 299 आदि में हाल ही में हुए परिवर्तनों के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए पीडीसी द्वारा एएएसबी के साथ संयुक्त रूप से सीएसए के लिए परस्पर क्रियाशील संगोष्ठियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था। इन संगोष्ठियों का उद्देश्य केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों (सीएसए) को बैंकों के संबंध में हाल ही में हुए विनियामक संबंधी परिवर्तनों से अवगत कराना था।

उपरोक्त श्रृंखला के अधीन 19 जनवरी, 23 जनवरी, 30 जनवरी और 7 फरवरी, 2019 को क्रमशः मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में 4 संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था।

(IX) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और अनिगमित निकायों के कार्यकरण के संबंध में राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) की बैठक

आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और चूंकि वे एनबीएफसी के गैर-बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग के संपरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए सामान्यतः भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अनिगमित निकायों (यूआईडी) के निक्षेपों को स्वीकार करने संबंधी क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए अपने प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में राज्य स्तरीय समन्वयन समिति/बैठक (प्रत्येक तीन मास में एकवार) का आयोजन करता है। ऐसी बैठकों के संबंध में सूचना आरबीआई के संबद्ध प्रादेशिक कार्यालय के प्रादेशिक निदेशक द्वारा किया जाता है और इन बैठकों में संबद्ध राज्यों के विभिन्न विभागों जैसे कि वित्त, गृह, विधि आदि, राष्ट्रीय आवासन बोर्ड (एनएचबी), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), चिट फंड रजिस्ट्रार, चिट फंड विभाग, और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के प्रधान सचिवों/सचिवों द्वारा भाग लिया जाता है।

(X) सीएंडएजी द्वारा पैलबद्ध किए जाने संबंधी उसके प्रारूप पुनरीक्षित सनियमों के संबंध में अंतःनिवेशों की ईप्सा

आईसीएआई, जब कभी इस प्रकार की ईप्सा की जाती है तो वह सीए फर्मों को पैलबद्ध किए जाने संबंधी वर्तमान व्यवस्था का पुनर्विलोकन करने के लिए तथा पैलबद्ध सीए फर्मों को पीएसई संपरीक्षाओं के आबंटन को और अधिक सुचारू बनाने के लिए अपने अंतःनिवेश सीएंडएजी को उपलब्ध कराता है।

(XI) अन्य क्रियाकलाप

- आरबीआई, नाबार्ड और आईबीए के साथ बैठक : आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने 3 जून, 2019 को आरबीआई, नाबार्ड और आईबीए के साथ बैठक की थी और इस बैठक में संपरीक्षा में कमियों, संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट में भ्रमता, एलएफएआर और संपरीक्षकों की अर्हता और लेखांकन मानकों के अनुपालन, आदि जैसे वृत्ति से संबंधित विषयों के बारे में अनेक चिंताओं पर विचार-विमर्श किया गया था। अनेकों अन्य विषयों जैसे कि संपरीक्षा फीस को बढ़ाए जाने, कर संपरीक्षा के लिए पृथक् फीस, बैंक संपरीक्षा का संचालन करते समय विभिन्न संपरीक्षकों के सामने आने वाले मुद्दों, किसी एक संपरीक्षक को आबंटित की जाने वाली शाखाओं की सीमित संख्या और आरबीआई की संपरीक्षा के आबंटन के लिए एकमात्र स्वामित्व वाली फर्मों को विचार में लिए जाने आदि पर भी विचार किया गया था।
- “साइबर सुरक्षा ढांचे” विषय पर आरबीआई के साथ बैठक : आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने, “साइबर सुरक्षा ढांचे” के संबंध में कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त प्रमाणन के विषय पर 18 अप्रैल, 2019 को मुंबई में बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के सीएसआईटीई के दल के साथ बैठक की थी। आईसीएआई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, आरबीआई एससीए को उस पद्धति के संबंध में सलाह दी थी, जिसका वे बैंकों द्वारा इस संबंध में अनुपालन के स्तर का निर्धारण करने के लिए अनुसरण करेंगे। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने यह भी सलाह दी थी कि इस संबंध में एससीए द्वारा वृहत प्रारूप संपरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) के साथ इस प्रभाव का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाए।
- भारतीय डाक संदाय बैंकों (आईपीपीबीएस) में वृत्तिक अवसरों का पता लगाना : श्री अनंत नारायण नंदा, सचिव, डाक विभाग और अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उनसे आईपीपीबीएस से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के वृत्तिक कौशल के उपयोग का पता लगाने का अनुरोध किया गया था।
- जम्मू-कश्मीर बैंक के लिए कानूनी संपरीक्षक की नियुक्ति : आईसीएआई द्वारा, जो बैंकों को, उनके संपरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दी गई स्वायत्ता के संबंध में भलीभांति जागरूक है, पूर्व व्यवहार को जारी रखने के लिए सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड हेतु कानूनी संपरीक्षक की नियुक्ति संबंधी विषय को सक्रिय रूप से आरबीआई के समक्ष उठाया गया था। तदनुसार, इस वर्ष के लिए भी संपरीक्षकों की नियुक्ति केवल सीएंडएजी द्वारा की गई थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक (सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग) को तकनीकी सहायता : समिति ने जून, 2018 में नई दिल्ली स्थित आरबीआई में शहरी सहकारी बैंकों के कानूनी संपरीक्षकों के लिए आयोजित कार्यशाला के लिए संकाय उपलब्ध कराने के निबंधनानुसार भारतीय रिजर्व बैंक (सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग) को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी।

(XII) प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन

- भारतीय स्टेट बैंक को प्रतिवेदन : चालू वर्ष के दौरान किसी प्राइवेट सेक्टर/विदेशी बैंक के कानूनी शाखा संपरीक्षकों/संपरीक्षा फर्मों में से किसी की केंद्रीय/शाखा संपरीक्षकों के रूप में नियुक्ति न किए जाने के संबंध में, उक्त प्रभाव की घोषणा को विचार में न

लेने हेतु भारतीय स्टेट बैंक को एक प्रतिवेदन भेजा गया था कि क्योंकि संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 4 विदेशी बैंकों की कानूनी संपरीक्षाओं के साथ-साथ किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की किसी शाखा की कानूनी संपरीक्षा कर सकती है। एसबीआई ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया था।

- मार्च, 2018 में सचिव-सह-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार को, सीए/सीए फर्मों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार के सुसंगत विभाग के साथ रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की संपरीक्षा करने हेतु उनके नामों को पैनलबद्ध किए जाने के लिए आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने के संबंध में दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे।
- अप्रैल, 2018 में आयुक्त, सहकारिता और सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे को सहकारी सोसाइटी के संपरीक्षकों द्वारा, उनके द्वारा संबद्ध जिला उप रजिस्ट्रार और जिला विशेष संपरीक्षक, महाराष्ट्र को अनेक वर्षों से जमा की जाने वाली संपरीक्षा फीस के 20% के प्रतिदाय हेतु प्रतिदाय आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समयावधि को विस्तारित करने के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
- जनवरी, 2019 में, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, गुजरात राज्य को गुजरात में विद्यमान सहकारी सोसाइटियों में संपरीक्षकों को पैनलबद्ध किए जाने के संबंध में और उससे संबंधित मुद्दों/चिंताओं के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
- कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना : जनवरी, 2019 में संयुक्त सचिव (सहकारिता) और केंद्रीय रजिस्ट्रार, कृषि और कृषक कल्याण विभाग, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय को विभिन्न राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के लेखा परीक्षा संबंधी विभिन्न उपबंधों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
- आईडीबीआई बैंक में बैंक शाखा संपरीक्षा आबंटन : 21 जनवरी, 2019 से आईडीबीआई को प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में पुनः प्रवर्गीकृत किए जाने के अनुसरण में आईसीएआई ने आईडीबीआई को प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, जिससे इस वर्ष भी आईडीबीआई की शाखा संपरीक्षा को ऐसी रीति में जारी रखा जा सके, जिससे सभी संपरीक्षक उस कार्य पर बने रहें और तदनुसार आईडीबीआई ने अपने तत्कालीन संपरीक्षकों को उस रूप में बनाए रखा था।

(XIII) वर्ष के दौरान जारी प्रकाशन

- चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसरों संबंधी संक्षिप्त अंतःदृष्टि : ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों, जो उभरते हुए विभिन्न वृत्तिक अवसरों, जैसे रेरा, इंडएएस, कंपनी अधिनियम, 2013, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा और डाटा विश्लेषण (प्रौद्योगिकी का कखगघ), जीएसटी, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों, फॉरेंसिक संपरीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिवाला संबंधी व्यवसाय, पीएसयू और बैंक संपरीक्षा आदि में व्यवसाय कर रहे हैं, पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित किए जाने के विचार से पीडीसी ने “चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसरों संबंधी संक्षिप्त अंतःदृष्टि” नामक एक प्रकाशन ई-पुस्तक के रूप में निकाला है। इसमें, महत्वपूर्ण संपर्क वेब लिंकों के अलावा अधिक मांग वाले क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों तथा अन्य वृत्तिक अवसरों हेतु स्वयं को पैनलबद्ध करने से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है।
- “जीएसटी संबंधी एनपीओ के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न” : समिति ने सदस्यों और साधारण रूप से पणधारियों के फायदे के लिए एनपीओ हेतु जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में अवधारणात्मक स्पष्टता लाने के लिए प्रश्नोत्तरों के रूप में एक प्रकाशन निकाला है।

5.20 लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति (सीपीएफएंडजीए)

समिति द्वारा जारी किए गए प्रकाशन

- समिति ने अपने प्रकाशन “लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त पद” नामक अपने प्रकाशन का पुनरीक्षण किया है, जो लोक वित्त और अर्थशास्त्र से संबंधित शब्दावली/आर्थिक पदों को समझने में उपयोगी सिद्ध होगा।
- “भारत में शहरी स्थानीय निकायों में लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी सुधार” विषय पर एक अनुसंधान अध्ययन तथा “प्रोदभवन लेखांकन संबंधी संक्षिप्त अंतःदृष्टि” नामक एक ब्राशर भी जारी किए गए थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं

समिति ने गंगटॉक, मुंबई, शिमला, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, जिम कार्बेट, आदि सहित विभिन्न स्थानों पर सरकारी विभागों/पीएसयू के साथ अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

लोक वित्त और स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति (सीपीएफएंडएसएलबी)

वर्ष 2019-20 में, एक नई समिति अर्थात् लोक वित्त और स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक संबंधी समिति (सीपीएफएंडएसएलबी) का गठन किया गया है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की, लेखांकन सुधारों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और लोक वित्त प्रबंध के क्षेत्र में सहायता करने के लिए प्रयास करती है। समिति प्रमुख रूप से अपना ध्यान भारत सरकार के विभिन्न टियरों पर पदासीन वित्त पदाधिकारियों की सक्षमता निर्माण पर केंद्रित करती है और इसके लिए वह कार्यशालाओं का आयोजन करने, सुसंगत ई-प्रशिक्षण माड्यूलों को तैयार करने और स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एसएलबी) तैयार करने आदि जैसे विभिन्न उपाय अपनाती है।

5.21 जन संपर्क और सीएसआर क्रियाकलाप

पीआर और सीएसआर संबंधी समिति को इस वर्ष “जनसंपर्क समूह” के रूप में पुनः गठित किया गया था। जनसंपर्क समूह का मिशन, आईसीएआई को एक उत्कृष्ट लेखांकन निकाय और भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट वृत्ति के एकमात्र विनियामक प्राधिकरण के रूप में उसकी छवि को विकसित करना, सुदृढ़ बनाना और उसमें अभिवृद्धि करना है, इसके लिए वह ऐसे विभिन्न मार्गों और उपायों का उपयोग करता है, जिन्हें सीए अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त समझा जाता है।

इसके अतिरिक्त, पीआर समूह अच्छे संबंधों को स्थापित करने के लिए प्रयास करता है और आंतरिक तथा बाह्य जनता के बीच परिप्रेक्ष्य संबंधी खाई को भरने के उद्देश्य से कार्य करता है तथा बेहतर नेटवर्किंग अवसर उपलब्ध कराता है तथा आईसीएआई की दृश्यता में अभिवृद्धि करने हेतु प्रयास करता है। समूह नियमित रूप से विभिन्न पहलें करता है और मीडिया गृहों/पणधारियों/वाणिज्य चैम्बरों/व्यापार निकायों और अन्य की, राष्ट्र और साधारण रूप से समाज के आर्थिक विकास में आईसीएआई और सीए वृत्ति के योगदान को समझने में तथा उसे मान्यता प्रदान करने में सहायता करता है।

पीआर समूह निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी क्रियाकलापों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है, जो ऐसे अनेकों क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व की सटीक सारगर्भिता को उपदर्शित करता है, जिसके परिणामस्वरूप समाज का कल्याण होता है तथा संवहनीय परिस्थितियों का संवर्धन करता है।

(I) वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलाप

- मीडिया के लिए कार्यशालाएं : परिप्रेक्ष्य संबंधी खाई को पाटने के उद्देश्य और राष्ट्र और साधारण रूप से समाज के आर्थिक विकास में आईसीएआई और सीए वृत्ति के योगदान को समझने में तथा उसे मान्यता प्रदान करने में मीडिया की सहायता करने के उद्देश्य से पीआर समूह ने देश भर में मीडिया के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला करने का विनिश्चय किया था। इस श्रृंखला में, पहली मीडिया कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें यह प्रयास किया गया था कि मीडिया भ्रातृसंघ को ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण और तकनीकी मुद्दों के प्रति जागरूक बनाया जाए, जिनके संबंध में आईसीएआई द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यशाला को मीडिया से अत्यधिक उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी, जहां वरिष्ठ मीडिया से संबंधित व्यक्तियों ने आईसीएआई के विशेषज्ञ वक्ताओं से परस्पर बातचीत की थी और संबद्ध विषयों को समझने तथा अपनी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया था। कार्यशाला के दौरान उठाए गए मुद्दों को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुई थी।
- सीए दिवस, 2018 और प्लैटनिम जयंती समारोह : समूह ने आईसीएआई की सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं से, एक सामूहिक प्रभाव का सृजन करने के लिए पूरे देश में आज्ञापक और विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप करके एक संरचित रीति में “सीए दिवस या सीए दिवस सप्ताह (1 जुलाई से 7 जुलाई)” का उत्सव मनाने का अनुरोध किया था। आईसीएआई की प्लैटनिम जयंती और सीए दिवस, 2018 संबंधी समारोह के शुभारंभ को पीआर समूह द्वारा, नीचे उल्लिखित क्रियाकलापों को करके व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था :
- आईसीएआई प्लैटनिम जयंती वर्ष के लिए विशेष स्मृति चिह्न : इस अवसर के लिए विशेष रूप से एक स्मृति चिह्न को तैयार किया गया था, जिसका शासकीय रूप से शुभारंभ 1 जुलाई, 2018 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में

आयोजित एक समारोह के दौरान किया गया था। वर्ष के दौरान, आईसीएआई की सभी संसूचनाओं में इस स्मृति चिह्न का उपयोग किया जा रहा है।

- प्रकाशन : प्लेटिनम जयंती समारोह के उपलक्ष में विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रकाशनों को जारी किया गया था।
- भारत में लेखांकन वृत्ति का इतिहास – जिल्द 3 : पीआर समूह के तत्वाधान में “भारत में लेखांकन वृत्ति का इतिहास” प्रकाशन की जिल्द 3 को निकालने के लिए एक समूह का गठन किया गया था। यह प्रकाशन, भारतीय लेखांकन वृत्ति के विकास के लिए आईसीएआई द्वारा किए गए प्रयासों को उपदर्शित करने का एक विनीत प्रयास है और इस प्रकाशन में हमारे पूर्वजों, पूर्व अध्यक्षों तथा केंद्रीय परिषद् के सदस्यों के योगदान को विशिष्ट रूप से दर्शित किया गया है।
- ट्रेजर ट्रोव आफ विजडम फ्रॉम विजनरीज़ – पूर्व अध्यक्षों, आईसीएआई के वक्तव्य – जिल्द 2: हमारे माननीय पूर्व अध्यक्षों को उनके अथक प्रयासों और वृत्ति के लिए उनकी प्रतिबद्धता और सुदृढ़ प्रतिज्ञता के लिए सच्ची कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने के प्रयास के भागरूप में समूह ने “ट्रेजर ट्रोव आफ विजडम फ्रॉम विजनरीज़ – पूर्व अध्यक्षों, आईसीएआई के वक्तव्य – जिल्द 2” नामक एक प्रकाशन को जारी किया था। यह विशिष्ट प्रकाशन, गत 7 दशकों की संस्थान की यात्रा के महत्व को दर्शित करता है, जिसे संस्थान के वार्षिक समारोह के दौरान पूर्व अध्यक्षों द्वारा दिए गए वक्तव्यों के संकलन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
- आडियो-वीडियो (एवी) फिल्में : गत 7 दशकों के दौरान संस्थान द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व को, महत्वपूर्ण अतिथियों/विशिष्ट व्यक्तियों/पणधारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के विचार से पीआर समूह द्वारा कुछ एवी फिल्मों को तैयार किया गया था, जिन्हें सीए दिवस पर नई दिल्ली में दिखाया गया था।
- आईसीएआई की प्लेटिनम जयंती के संबंध में एवी : यह एवी लेखांकन वृत्ति के इतिहास का पता लगाती है और पिछले 7 दशकों के दौरान आईसीएआई की मील का पत्थर साबित हुई उपलब्धियों को उपदर्शित करती है, जिसे बालीवुड कलाकार बोमन ईरानी द्वारा बेहतरीन ढंग से बताया गया है।
- आईसीएआई – एक ट्रेजर ट्रोव : हमारे पूर्व पदधारियों, माननीय पूर्व अध्यक्षों ने एक उत्तम भविष्य तैयार करने के लिए सभी संभव प्रयास किए थे और उन्होंने इस वृत्ति को समर्पित रूप से इस प्रकार दिशा प्रदान की है कि वह एक उदाहरणात्मक प्रतीक बन गई है। ट्रेजर ट्रोव संबंधी एवी हमारे उन्हीं पूर्वजों के प्रति एक श्रद्धांजलि है।
- “भारत में लेखांकन वृत्ति का इतिहास – जिल्द 3” नामक प्रकाशन के बारे में एवी : इस एवी की अवधारणा, दर्शकों के समक्ष इस प्रकाशन की तीसरी जिल्द को निकाले जाने के महत्व को उपदर्शित किए जाने हेतु तैयार की गई थी, जो पिछले 20 वर्षों के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों और आईसीएआई द्वारा प्राप्त किए गए मील के पत्थरों और उपलब्धियों को दर्शाती है।
- सीए दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के वीडियो संदेश : सीए दिवस के अवसर पर, सीए भ्रातृसंघ को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के संदेशों की एक वीडियो क्लिप तैयार की गई थी और उसे आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। उसे सीए दिवस समारोह के दौरान भी चलाया गया था। इस वीडियो के लिंक को संदर्भ हेतु सभी संबद्ध व्यक्तियों को अग्रेषित किया गया था।
- अति विशिष्ट व्यक्तियों के विशेष वीडियो संदेश : सीए भ्रातृसंघ को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए अति विशिष्ट व्यक्तियों – सीए. पीयूष गोयल, सीए. सुरेश प्रभु और सीए. के. रहमान खान के वीडियो संदेशों को रिकार्ड किया गया था और उन्हें 1 जुलाई को विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान चलाया गया था।
- निगम को अद्यतन बनाए जाने संबंधी फिल्म 2018-19 : आईसीएआई निगम फिल्म को, एचओ/डीसीओ/आरसी/शाखाओं द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनों, संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि के दौरान चलाया जाता है। समूह ने वर्ष 2018-19 के लिए आईसीएआई निगम फिल्म को अद्यतन बनाया था और उसे सभी संबद्ध व्यक्तियों के संदर्भ हेतु आईसीएआई टीवी पर अपलोड किया गया था और उसके लिंक को संदर्भ हेतु सभी संबद्ध व्यक्तियों को अग्रेषित किया गया था।

(II) सीए दिवस, 2018 समारोह के दौरान किए गए अन्य क्रियाकलाप

- इस अवसर पर विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों से शुभ संदेशों को आमंत्रित किया गया था। प्रत्येक वर्ष की भांति चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के विशेष अंक को सीए दिवस के उपलक्ष में निकाला गया था। इस संबंध में, कुल 24 संदेश प्राप्त हुए थे, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के जुलाई, 18 के अंक में प्रकाशित किया गया था।
- पत्रिकाओं में विज्ञापन : आईसीएआई की ब्रांड छवि बनाने और सीए के महत्व और योगदान को पुनः दोहराने के लिए विभिन्न समाचार/कारबार पत्रिकाओं, अर्थात् द वीक, बिजनेस टूडे, आउट लुक एंड आउट लुक बिजनेस के जुलाई अंकों में विज्ञापनों को प्रकाशित किया गया था।

(III) आईसीएआई निर्वाचन, 2018 का संवर्धन : आडियो विजुअल और पोस्टर

- निर्वाचनों के संबंध में बेहतर जागरूकता के सृजन करने, निर्वाचनों में भाग लेने के महत्व को समझाने और वास्तविक निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के संबंध में सभी सदस्यों को सूचना देने के उद्देश्य से मतदान प्रक्रिया से संबंधित कुछ आडियो वीडियो फिल्में तैयार की गई थी, जिनके द्वारा सदस्यों को मतदान प्रक्रिया हेतु निमंत्रित करने, अधिमानी मतदान करने की प्रक्रिया और उन्हें मतदान के बारे में याद दिलाने संबंधी वीडियो तैयार किए गए थे, जिससे सदस्यों, विशेषकर नए सदस्यों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके और साथ ही आईसीएआई की निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टता को लाया जा सके। इसके अतिरिक्त, अंतिम एबी को वाट्सअप समूहों/सोशल मीडिया के माध्यम से सदस्यों को मतदान करने हेतु प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने हेतु परिचालित किया गया था।
- आईसीएआई के त्रैवार्षिक निर्वाचनों का प्रचार करने और सदस्यों के बीच निर्वाचन प्रक्रिया तथा अनुसरित की जाने वाली प्रणालियों के बारे में स्पष्टता लाने हेतु एक पोस्टर तैयार किया गया था, जिसे पूरे भारत के मतदान केंद्रों पर लगाया गया था।
- व्यापक पहुंच हेतु पोस्टरों और आडियो वीडियो फिल्मों को सोशल मीडिया तथा आईसीएआई की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था।
- मीडिया द्वारा मिथ्या रिपोर्टिंग की प्रतिक्रिया में संपादकों को पत्र : आईसीएआई को ऐसी कतिपय मीडिया रिपोर्टों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, जो वृत्ति और उसके सदस्यों की खराब छवि को दर्शित करती हैं। पीआर समूह ने उस रीति के संबंध में दृढ़ता से आक्षेप किया था, जिसमें ऐसे समाचार-पत्रों को प्रमुख समाचार-पत्रों में मुद्रित किया गया था, जिससे वृत्ति के सम्मान को ठेस लगी थी। तदनुसार, ऐसे समाचार-पत्रों, जिन्होंने जनता की दृष्टि में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की वृत्ति की छवि को खराब करने तथा उनकी ख्याति को नष्ट करने वाली प्रतिकूल रिपोर्टों को प्रकाशित किया था, के संपादकों को पत्र जारी किए थे। उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे संबंधित विषय के बारे में समुचित शुद्धिपत्र प्रकाशित करें।
- आईसीएआई ने भारतीय प्रैस परिषद् (पीसीआई) को कुछ प्रकाशनों के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टों के प्रकाशन के लिए शिकायतें फाइल की थी। इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी और पीसीआई ने दो प्रकाशनों अर्थात् द इकोनॉमिक टाइम्स और हिन्दूस्तान (हिंदी) की, मिथ्या रिपोर्टिंग करने और चार्टर्ड अकाउंटेंट भ्रातृसंघ की खराब छवि प्रस्तुत करने के लिए निंदा की थी। प्रैस परिषद् ने अपनी जांच रिपोर्टों को सही ठहराते हुए द इकोनॉमिक टाइम्स को एक कड़ी 'परिनिंदा' जारी की थी, वहीं हिन्दूस्तान को, समाचार-पत्र में पीसीआई द्वारा पारित आदेश को तुरंत प्रकाशित करने के निदेशों के साथ एक 'चेतावनी' जारी की गई थी। अन्य प्रकाशनों से संबंधित मामलों के बारे में भी पीसीआई के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।
- अखिल भारतीय सदस्यों को महत्वपूर्ण मीडिया क्लिपिंग – संसूचना : पीआर समूह द्वारा यह विनिश्चय किया गया था कि सीए वृत्ति/आईसीएआई से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो क्लिपिंगों या अन्य सुसंगत समाचारों को साप्ताहिक आधार पर अखिल भारतीय सदस्यों को अग्रेषित किया जाना चाहिए जिससे सदस्यों की जानकारी में नवीनतम समाचारों और अद्यतन घटनाओं को लाया जा सके। अखिल भारतीय सदस्यों को प्रथम मेलर मई मास से आरंभ किया गया था।
- आईसीएआई वर्ष बुक 2018-19 : संस्थान/समितियों/विभागों/प्रादेशिक कार्यालयों/शाखाओं द्वारा वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण पहलों और उनकी उपलब्धियों को दर्शित करने वाले एक विस्तृत दस्तावेज को "वर्ष बुक" नामक प्रकाशन के माध्यम से निकाला गया था। पीआर समूह ने सभी समितियों/शाखाओं/प्रादेशिक कार्यालयों से जानकारी को प्राप्त किया था तथा उससे

“वर्ष बुक : 2018-19 : सेवा, समर्थन और भारत के विकास की कहानी को सुदृढ़ता प्रदान करने के 70 वर्ष” नामक दस्तावेज को संकलित और तैयार किया गया था।

(IV) सरकार की पहलों में भागीदारी

- फरवरी-दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और अभियानों का संवर्धन करने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप किए थे। राष्ट्र निर्माण में एक सच्चे भागीदार के रूप में और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के मद्दे सरकार की पहलों को अग्रसर करने में आईसीएआई ने सक्रिय रूप से समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति योगदान किया था।
- सरकार के निम्नलिखित अभियानों को, सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को सहबद्ध करते हुए अखिल भारतीय रूप से चलाया गया था :

क्रम सं.	अभियान
1.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छता पखवाड़े (1-15 अगस्त, 2018) को मनाना
2.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया स्वच्छता ही सेवा (15 सितंबर - 2 अक्तूबर, 2018)
3.	महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ को मनाना (2 अक्तूबर, 2018 से 2 अक्तूबर, 2020)
4.	केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आरंभ किया गया सतर्कता जागरुकता सप्ताह (29 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2018)
5.	गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्तूबर, 2018)
6.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया संविधान दिवस (26 नवंबर, 2018)
7.	लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2019 के लिए नामनिर्देशनों को आमंत्रण।

- स्वच्छता अभियान : स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) या स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्तूबर, 2014 को महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को जनजागरुकता अभियानों द्वारा अग्रसर करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। 2 अक्तूबर, 2014 का दिन आईसीएआई के लिए गर्व का दिन था जब माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य अस्तित्वों और संगठनों के साथ आईसीएआई को इस महान अभियान से सहबद्ध होने हेतु नामनिर्दिष्ट किया था। इस सामाजिक पहल को अग्रसर करने हेतु नामनिर्दिष्ट किए जाने के समय से ही संस्थान अपनी पांच प्रादेशिक परिषदों 164 शाखाओं के माध्यम से अनेक अभियानों और जनजागरुकता कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।
- इस वर्ष भी अनेकों क्रियाकलाप किए गए थे, जैसे कि स्वच्छता अभियान/स्वच्छता संबंधी शपथ ग्रहण करना/पौधा रोपण/ग्रीन मैराथन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरुकता का सृजन करना आदि। प्रधानमंत्री के स्वप्न को पूरा करने के मद्दे नियमित आधार पर अनेक पहलों की जाती हैं और ये पहलें विशेष रूप से अनेकों महत्वपूर्ण अवसरों पर जैसे सीए दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि के दौरान की जाती हैं। इनका उद्देश्य स्वच्छता की आवश्यकता के प्रति जनता, आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों और पणधारियों, पदधारियों और कर्मचारिवृंद को संवेदनशील बनाना और उससे जुड़े फायदों के बारे में उनकी जागरुकता का संवर्धन करना है।
- पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस : इस अवसर को मनाने के लिए आईसीएआई ने सभी सदस्यों और छात्रों को स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के लिए योग को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करने हेतु प्रोत्साहित करने की एक पहल की थी। समूह ने आईसीएआई की सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं से यह अनुरोध किया था कि वे 21 जून, 2019 को देश भर में पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जोर-शोर से मनाएं। सभी संबद्ध व्यक्तियों को यह सलाह दी गई थी कि वे विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप करके इस दिवस को मनाएं। इस पहल के संबंध में उत्तम प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी।

(V) अन्य पहलें

- मुद्रण/इलैक्ट्रानिक और आनलाइन मीडिया के अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से संस्थान की सभी प्रमुख पहलों का संवर्धन किया गया था।
- मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में आमने-सामने साक्षात्कारों के माध्यम से अभिवृद्धि हुई थी, जिनके द्वारा मीडिया को निरंतर रूप से होने वाली पाठ्यचर्या, वृत्ति, नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने, सीए के लिए नए दिशानिर्देश, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के दौरे और अन्य क्रियाकलापों तथा आयोजनों से संबंधित नवीनतम घटनाओं से अवगत कराया गया था।
- समूह ने आज के निरंतर क्रियाशील संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति की संभावनाओं और परिधि क्षेत्र का, लेखों और साथ ही परस्पर क्रियाशील बैठकों/राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर प्रैस को जारी की गई विज्ञप्तियों और विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से संवर्धन किया था।
- आईसीएआई के संबंध में जागरूकता का सृजन करने और उसके मूल डोमेन का संवर्धन करने के लिए समाचार पत्रों/कारबार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे।
- आईसीएआई के भीतर विभिन्न विभागों, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं को, आईसीएआई और उसके कार्यालयों/संबद्ध संगठनों से जोड़े रखने और संसूचना संबंध विकसित करने के विचार से संभार समर्थन उपलब्ध कराया गया था।
- पीआर कार्य के भागरूप में मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया में आईसीएआई की विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/आयोजनों को उपयुक्त रूप से कवर किया गया था।
- समकालीन मुद्दों से संबंधित लेखों को प्रमुख कारबार पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया था।

5.22 अनुसंधान समिति

अनुसंधान समिति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सबसे अधिक पुरानी गैर स्थायी समितियों में एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यवर्धन करने के विचार से लेखांकन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। यह समिति लेखांकन पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण तैयार करती है, जिन्हें परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है। समिति, साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों के संबंध में तकनीकी गाइडों, अध्ययनों, मोनाग्राफों आदि को भी निकालती है। समिति वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में सुधार करने के विचार से अपनी एक उप समिति, शील्ड पैनल के माध्यम से एक वार्षिक प्रतियोगिता, अर्थात् 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' का भी आयोजन करती है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

इन पुरस्कारों को वर्ष 1958 से वार्षिक रूप से प्रदान किया जा रहा है। विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में पुरस्कार विजेताओं का चयन एक 3 टियर ठोस मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है : सर्वप्रथम प्रारंभिक मूल्यांकन तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात् शील्ड पैनल द्वारा सूचीबद्ध वार्षिक रिपोर्टों का पुनर्विलोकन किया जाता है और इनका अंतिम पुनर्विलोकन एक बाहरी ज्यूरी द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2017-18 की प्रतिस्पर्धा के लिए ज्यूरी की बैठक 19 जनवरी, 2019 को मुंबई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता श्री यू.के. सिन्हा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई थी। पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए बैठक में भाग लेने वाले ज्यूरी के अन्य सदस्यों में सीए एन.पी. शारदा, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, श्री टी.वी. मोहनदास पई, मणिपाल ग्लोबल सर्विस के अध्यक्ष और पूर्व सीएफओ, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री प्रवीण कुटुम्बे, सदस्य (वित्त और निवेश), आईआरडीएआई, श्री निलेश शाह, प्रबंध निदेशक, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, श्री संजय झांवर, प्रबंध भागीदार, मैसर्स चिर अमृत लीगल एलएलपी, श्री अनिल बाफना, वरिष्ठ भागीदार, ए बाफना एंड कंपनी, सुश्री पिकी मेहता, सीएफओ, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड, श्री एम.के. शर्मा, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित थे।

पुरस्कारों की स्कीम के अनुसार सर्वोत्तम प्रविष्टि और दूसरी सर्वोत्तम प्रविष्टि के लिए क्रमशः एक स्वर्ण शील्ड और एक रजत शील्ड पुरस्कार में प्रदान की जाती है। ऊपर उल्लिखित पुरस्कारों के अलावा सराहनीय प्रविष्टियों के लिए पट्टिकाएं पुरस्कार में दी जाती हैं। हाल ऑफ

फेम पुरस्कार ऐसे अस्तित्वों को प्रदान किया जाता है, जो किसी विशिष्ट प्रवर्ग में लगातार पांच स्वर्ण शील्ड का विजेता रहा हो। 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 2 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया था। माननीय श्री न्यायमूर्ति पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आईटीएटी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। कुल 10 पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिनमें 2 स्वर्ण शील्ड, 6 रजत शील्ड और 2 पट्टिकाएं सम्मिलित थीं।

5.23 पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीसीएमएंडआईपी)

पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीसीएमएंडआईपी) को परिषद् द्वारा वर्ष 1993-94 में आईसीएआई की एक गैर-स्थायी समिति के रूप में गठित किया गया था। उसके पश्चात् 1998-99 में समिति के नाम को परिवर्तित करके "वित्तीय बाजार और निवेशकों की संरक्षा संबंधी समिति" कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-18 में, तत्कालीन पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति का बैंककारी वित्तीय सेवा और बीमा समिति में विलयन कर दिया गया था और 2018 में पुनः उसे पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति के रूप में गठित किया गया है।

समिति सरकार/विनियामकों को प्रस्तुत किए जाने के लिए पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न विधेयकों/विनियमों/ अधिसूचनाओं/ परिपत्रों और अन्य दस्तावेजों के संबंध में सुझाव देती है। इसके अतिरिक्त, समिति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संगम से नियमित रूप से परस्पर क्रियाएं करती है, उदाहरण के लिए, ऐसी परस्पर प्रतिक्रियाएं निक्षेपकर्ताओं, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का प्रबंध, बैंक प्रचालन और पर्यवेक्षण, प्रतिभूतिकरण से संबंधित मुद्दों, सीए द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आरबीआई का गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों संबंधी विभाग, सहकारी बैंकों के विनियामक प्राधिकारी, उनकी निवेश नीति से संबंधित रणनीतियां/सिफारिशें, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीय बाजारों से संबंधित मामले, नियंत्रण अर्जित करने, सुमेलन, विलयन, (कर मुक्त क्षेत्र, भागीदारी टिप्पण, चलायमान मुद्रा, निगम शासन विनियामक अनुपालन आदि), परस्पर निधियां, विदेशी संस्थागत निवेशक, मध्यवर्ती, प्रतिभूति विधियां, आदि, अग्रिम बाजार आयोग (एफएमसी), जिसके अंतर्गत एनसीडीएक्स और एमसीएक्स, स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, पूंजी बाजार और निवेशकों की संरक्षा संबंधी मुद्दे सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए थे :

- राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार के रूप में उभरने और साधारण जनता में, वित्तीय प्रतिभूतियों में उनके धन को निवेश करने से संबंधित किए जाने वाले और न किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जागरूकता का सृजन करने और वित्तीय साक्षरता का संवर्धन करने के उद्देश्य से समिति कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) के तत्वाधान में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन करती है। इन कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न संसाधन व्यक्तियों और कार्यक्रम आयोजक इकाइयों (प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं, अध्ययन सर्कलों, अध्ययन चैप्टरों और अध्ययन समूहों) के माध्यम से देश भर में किया जाता है।
- भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के तत्वावधान में समिति ने 671 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 1 जुलाई, 2018 को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के प्लेटिनम जयंती समारोह के अवसर पर दिए गए भाषण की रूपरेखा के अनुसार, जहां उन्होंने आईसीएआई से हमारे देश की महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता का सृजन करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऊपर उल्लिखित आईएपीए में कुल 38,322 व्यक्तियों को, जिनमें 15,372 महिलाएं भी सम्मिलित थी, वित्तीय रूप से शिक्षित किया गया था।
- वर्तमान में समिति को आईसीएआई के अखिल भारतीय सदस्यों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, अर्थात् "विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" का आयोजन करने का कार्य सौंपा गया है।
- समिति ने, आज की तारीख तक विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 51 बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस अवधि के दौरान समिति ने विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 7 बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिनमें आईसीएआई के कुल 46 सदस्यों ने विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या के लिए अपना नामांकन किया था।
- समिति ने, पूर्व में 24 और 25 नवंबर, 2018 के दौरान आयोजित विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के

पूर्व बैचों के लिए आयोजित मूल्यांकन परीक्षा के परिणामों की घोषणा 21 जनवरी, 2019 को की थी। इस परीक्षा के लिए कुल 69 सदस्य उपस्थित हुए थे, जिनमें से 63 सदस्यों ने इस परीक्षा को अर्हित कर लिया था।

- समिति ने, 12-17 मार्च, 2018 और 11-16 जून, 2018 के दौरान 2 चरणों में विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से एचपीसीएल, पुणे के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे के पदधारियों के लिए तैयार किया गया था, जिसके लिए 18 सदस्यों ने नामांकन किया था और इसे अर्हित किया था।
- समिति, सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और वेबकास्टों के आयोजन में एक अधिकाधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है।
- 9.2.2019 को दिल्ली में आयोजित आईसीएआई दीक्षांत समारोह, 2019 के अवसर पर विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री के दूसरे संस्करण, अर्थात् “विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध के सिद्धांत और अभ्यास” (माड्यूल 1, 2 और 3) को जारी किया गया था।

5.24 इंड एस कार्यान्वयन समिति

इंड एस कार्यान्वयन समिति का गठन वर्ष 2011 में देश में इंडएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। परिषद् वर्ष 2017-18 के दौरान उक्त समिति को इंड एस कार्यान्वयन समूह के रूप में पुनः गठित किया गया था। तथापि, समूह के प्रयोजन और पहलें समान रही थी। मई, 2019 में, आईसीएआई की परिषद् ने इस समूह की प्रास्थिति पर पुनः विचार किया था तथा इसे इंड एस कार्यान्वयन समिति के रूप में पुनः गठित करने का निर्णय लिया था।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने वैश्विक रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों की आवश्यकता को पूरा करने तथा आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। आईसीएआई ने इन मानकों के क्रियान्वयन के लिए अपने सर्वाधिक कठोर प्रयासों को किया है और इस तथ्य और इन मानकों को तैयार करने के पीछे सार और तर्क को ध्यान में रखते हुए पूरे राष्ट्र में इनको अपनाए जाने पर बल दिया है, जिससे वे कार्यान्वयन के पश्चात् संगत बने रह सकें। आज के दिन, हम अपने राष्ट्र की इस दिशा में की गई प्रगति की सराहना कर रहे हैं, जिसके द्वारा कंपनियों के विनिर्दिष्ट वर्ग के संबंध में इंडएस को चरणबद्ध रीति में अपनाए जाने को पूरा करके परिस्थितियों में पूर्णतया परिवर्तन कर दिया गया है। इंड एस कार्यान्वयन समिति द्वारा, इंड एस के अपनाए जाने की आवश्यकता और महत्व पर बल देने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। समिति ने, अत्यधिक निश्चयपूर्वक, पूर्व में प्रयुक्त किए जाने वाले जीएएपी से इंड एस के अंतरण को सुचारु बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया है। इंड एस कार्यान्वयन समिति द्वारा सदस्यों और अन्य पणधारियों को अधिसूचित इंड एस के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए अनेकों पहलें की गई हैं।

इंड एस के उसी भावना के साथ, जिसमें उन्हें तैयार किया गया है, कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और साथ ही सदस्यों और अन्य पणधारियों को उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के विचार से, इंड एस कार्यान्वयन समिति इंड एस के संबंध में शैक्षिक सामग्रियां जारी करता है, जिनमें संबंधित इंड एस का संक्षिप्त विवरण और ऐसे मुद्दों को सम्मिलित करते हुए, जिनके मानक के कार्यान्वयन के दौरान बार-बार सामने आने की संभावना है, बहुधा पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अंतर्विष्ट होते हैं। इस अवधि के दौरान, सात (7) इंड एस के संबंध में छह (6) शैक्षिक सामग्रियां निकाली गई हैं। अभी तक समिति द्वारा सोलह (16) इंड एस से संबंधित पन्द्रह (15) शैक्षिक सामग्रियां जारी की गई हैं। यह समिति सभी इंड एस पर शैक्षिक सामग्रियां निकालने के लिए कार्य कर रही है।

उपरोक्त के अलावा, समिति ने अपने “भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस): एक पर्यावलोकन (पुनरीक्षित 2019)” शीर्षक वाले प्रकाशन का पुनरीक्षण किया, जो इस प्रकाशन का चौथा संस्करण है, जिसमें आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) से संबंधित विभिन्न पहलुओं को अंतर्विष्ट करने वाला पर्यावलोकन सम्मिलित है, जैसे कि इंड एस को लागू किए जाने संबंधी कार्ययोजना, आईएफआरएस/आईएस से ली गई सामग्री, विद्यमान लेखांकन मानक के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में इंड एस के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग में परिवर्तन, सभी इंड एस का संक्षिप्त विवरण, आदि। इसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मार्च, 2019 में अधिसूचित इंड एस के सभी हाल ही के संशोधनों, विशेष रूप से नए पट्टा संबंधी मानक (इंड एस 116) और उसके अन्य पारिणामिक संशोधनों को भी सम्मिलित किया गया है।

जैसे ही देश में इंड एएस का कार्यान्वयन आरंभ हुआ, सदस्यों, तैयार करने वाले व्यक्तियों और अन्य पणधारियों द्वारा इंड एएस के लागू होने/क्रियान्वयन के संबंध में अनेक मुद्दे उठाए गए थे। समयबद्ध और त्वरित रीति में अंतरण संबंधी शंकाओं का समाधान करने के लिए एक इंड एएस तकनीकी प्रसुविधा सेवा समूह (आईटीएफजी) (जिसे पूर्व में इंड एएस संपरिवर्तन सुविधा सेवा समूह के रूप में जाना जाता था) का वर्ष 2016 में गठन किया गया था, जो समय-समय पर कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए स्पष्टीकारक बुलेटिन निकालता है। इस समूह में अकाउंटेंसी फर्मों से विशेषज्ञ, उद्योग के प्रतिनिधि और अन्य विशिष्ट वृत्तिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। इस अवधि के दौरान, छह (6) आईटीएफजी स्पष्टीकारक बुलेटिन जारी किए गए हैं। आज की तारीख तक, समूह ने अपने 20 स्पष्टीकारक बुलेटिनों के माध्यम से 148 मुद्दों पर स्पष्टीकरण निकाले हैं।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों हेतु संदर्भ की सुगमता के लिए “आईटीएफजी स्पष्टीकारक बुलेटिन” (जिसके अंतर्गत दिसंबर, 2018 तक जारी स्पष्टीकरण भी हैं) शीर्षक वाला एक प्रकाशन निकाला गया है, जिसमें आईटीएफजी स्पष्टीकारक बुलेटिनों के माध्यम से पूर्व में स्पष्ट किए गए सभी मुद्दों का विषयवार संकलन एक स्थान पर उपलब्ध कराया गया है।

सदस्यों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों का यथा संभवशीघ्र समाधान करने के लिए “इंड एएस के कार्यान्वयन संबंधी सहायता - पटल” को भी आरंभ किया गया था, जिसमें सदस्य अपनी शंकाओं, प्रश्नों और सुझावों को आनलाइन रूप से एक लिंक को क्लिक करके प्रस्तुत कर सकते हैं।

समिति कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करके इंड एएस के समुचित कार्यान्वयन के लिए सदस्यों और अन्य पणधारियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए भी पर्याप्त उपाय कर रही है।

समिति इंड एएस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर में तथा विदेशों में भी इंड एएस संबंधी 12 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करती है। इस पाठ्यक्रम की व्यापक सत्र योजना को इस विचार से तैयार किया गया है कि वह सदस्यों को इंड एएस के क्षेत्र में सक्षम बनाए। इस अवधि के दौरान इंड एएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 29 बैचों का संचालन किया गया है, जिनमें लगभग 1100 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। अभी तक, लगभग 9790 सदस्यों ने देश भर में और विदेशों में स्थित अवस्थानों पर इंड एएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

समिति देश भर के विभिन्न अवस्थानों पर एक/दो दिवसीय इंड एएस संबंधित जागरुकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। इन जागरुकता कार्यक्रमों में, आधारीक मानकों, जो इंड एएस के अधीन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने के लिए भूमिका स्वरूप हैं, के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इंड एएस और विद्यमान एएस के बीच अंतर को भी विनिर्दिष्ट रूप से बताया जाता है ताकि सदस्यों और पणधारियों को इस संबंध में शिक्षित किया जा सके कि इंड एएस के अधीन लेखांकन किस प्रकार विद्यमान एएस के अधीन किए जाने वाले लेखांकन से भिन्न होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, समिति विभिन्न विनियामकों, संगठनों, निगम घरानों के पदधारियों/कर्मचारियों के लिए इंड एएस संबंधी घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। इस अवधि के दौरान, इलाहाबाद बैंक और आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड के पदधारियों के लिए इंड एएस संबंधी विभिन्न ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

उपरोक्त पहलों के अतिरिक्त, समिति, इंड एएस के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए समय-समय पर इंड एएस संबंधी वेबकास्टों का भी आयोजन करती है। हाल ही में, नए पट्टा संबंधी मानकों, अर्थात् इंड एएस 116, पट्टे के संबंध में समिति द्वारा दो वेबकास्टों का आयोजन किया गया था और ये वेबकास्ट icai.tv.com पर सुगमता से उपलब्ध हैं।

समिति, इंड एएस के कार्यान्वयन के संबंध में इस संपरिवर्तन को सुचारु बनाने तथा इंड एएस के बारे में ज्ञान और जागरुकता का सृजन करने के लिए प्रत्येक संभव उपाय कर रही है।

5.25 संपरीक्षा समिति

संपरीक्षा समिति का गठन संस्थान की परिषद् द्वारा शासित होता है। संपरीक्षा समिति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सत्य और उचित हैं, संस्थान की वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रकटन का पुनर्विलोकन करती है। यह समिति संस्थान की विभिन्न इकाईयों के लिए संपरीक्षकों की नियुक्ति करते समय स्वतंत्रता और ईमानदारी को सुनिश्चित करती है। संपरीक्षा समिति, उसकी प्रत्येक प्रादेशिक परिषदों में अवस्थित पांच प्रादेशिक संपरीक्षा समितियों के माध्यम से प्रचालन करती है।

5.26 बंकीय रूपांतरण और प्रक्रिया पुनः इंजीनियरी समूह (डीटीएंडपीआरजी)

(I) आईसीएआई मोबाइल ऐप

आईसीएआई नाओ और आईसीएआई सोशल मीडिया मंच ने, आईसीएआई के विभिन्न आयोजनों को लोकप्रिय बनाने और इसकी प्रमुख उपलब्धियों और पहलों के बारे में छात्रों, सदस्यों और संस्थान के अन्य पणधारियों को बिना किसी लागत के अवगत कराने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है।

इस ऐप को 5 लाख उपयोक्ताओं द्वारा डाउनलोड किया गया है। ऐप स्टोर पर इसे 5 में से 4.2 की रेटिंग प्राप्त हुई है और इसे शिक्षा प्रवर्ग में निःशुल्क ऐप की टॉप 100 सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

(II) आईसीएआई सोशल नेटवर्किंग

आईसीएआई के सोशल मीडिया अकाउंटों को फेसबुक, ट्विटर, लिंकडिन और यू ट्यूब पर सफलतापूर्वक तैयार किया गया है।

आईसीएआई की सोशल मीडिया नेटवर्किंग में उपस्थिति में सतत रूप से वृद्धि हो रही है और उसे फालो करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 5,89,000+ उपयोक्ताओं से अधिक हो गई है। (फेसबुक 90,000+, ट्विटर 81,000+, लिंकडिन 3,73,000+ और यू ट्यूब 45,000+)

5.27 क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी)

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड को केंद्रीय सरकार द्वारा 28 जून, 2007 को निम्नलिखित कृत्य करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28 के अधीन उसमें निहित शक्तियों के अनुसरण में गठित किया गया था :

- परिषद् को आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में सिफारिशें करने ;
- आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा संबंधी सेवाएं भी हैं, की क्वालिटी का पुनर्विलोकन करने ; और
- आईसीएआई के सदस्यों का, सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने और विभिन्न कानूनी तथा अन्य विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु मार्गदर्शन करने ।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन परिषद् का एक कृत्य यह है कि वह उसके द्वारा बनाए गए क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की आईसीएआई के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में की गई सिफारिशों पर विचार करे। पूर्वोक्त खंड (ण) यह भी उपबंध करता है कि ऐसी सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाईयों के ब्यौरे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करे। पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसरण में, यह रिपोर्ट किया जाता है कि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिषद् को सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख(क) के अधीन 1 प्रतिनिर्देश प्राप्त हुआ था। उस पर परिषद् द्वारा अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था। इस संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

- आईसीएआई के अनुशासन तंत्र के अधीन आगे और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट किए गए प्रतिनिर्देशों की संख्या – 1
- ऐसे प्रतिनिर्देशों की संख्या, जहां तकनीकी पुनर्विलोकक की टीका-टिप्पणियों को सदस्यों/फर्मों को सलाह के रूप में जारी करने का विनिश्चय किया गया था – शून्य
- ऐसे प्रतिनिर्देशों की संख्या, जिन्हें बंद करने का विनिश्चय किया गया था – शून्य
- परिषद् के विचारार्थ लंबित प्रतिनिर्देशों की संख्या – शून्य

5.28 प्रबंध समिति

प्रबंध समिति, जिसका गठन वर्ष 2015 में परिषद् की एक गैर-स्थायी समिति के रूप में किया गया था, के उद्देश्यों में शाखाओं के सृजन, विदेशों में चैप्टरों की स्थापना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ एमओयू/एमआरए करने, आईसीएआई के केंद्रीय संपरीक्षकों की नियुक्ति, संस्थान के वार्षिक लेखाओं, केंद्रीय सरकार और अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट मामलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में संशोधन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं से

संबंधित मामलों, सदस्यों/सीए फर्मों/एलएलपी /विलयनों/निर्विलयनों/ नेटवर्किंग संबंधी मामलों और संस्थान की अन्य समितियों/विभागों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों, जिनमें प्रशासनिक और नीतिगत विवक्षाएं अंतर्बलित हैं, पर विचार करना और जहां कहीं अपेक्षित हो, परिषद् को अपनी सिफारिशें करना भी सम्मिलित है।

5.29 मूल्यांकन मानक बोर्ड (वीएसबी)

मूल्यांकन मानक बोर्ड का गठन आईसीएआई द्वारा जारी किए जाने वाले मूल्यांकन मानकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। बोर्ड मानकों के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर निर्वचन, मार्गदर्शन और तकनीकी सामग्री उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

उपलब्धियां और पहलें

(I) चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उनके मूल्यांकन संबंधी समनुदेशनों में अनुसरित किए जाने के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को जारी किया गया था :

संगत, एकसमान और पारदर्शी मूल्यांकन नीतियों को बनाए रखने और भारत में प्रयोग किए जाने वाले विविध व्यवहारों को सुमेलित करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् ने अपनी 375वीं बैठक में मूल्यांकन मानकों को जारी किया है। ये मूल्यांकन मानक भारत में जारी किए जाने वाले मूल्यांकन मानकों का प्रथम सेट हैं।

मूल्यांकन मानक एक ऐसा ढांचा अधिकथित करते हैं, जिससे मूल्यांकन परिणाम की उपधारणा और क्वालिटी में एकसमानता सुनिश्चित की जा सके। आईसीएआई द्वारा निम्नलिखित मूल्यांकन मानक जारी किए गए हैं :--

- भारतीय मूल्यांकन मानक - 101 परिभाषाएं
- भारतीय मूल्यांकन मानक - 102 मूल्यांकन आधार
- भारतीय मूल्यांकन मानक 103 – मूल्यांकन उपधारणा और पद्धति
- भारतीय मूल्यांकन मानक - 201 कार्य, विश्लेषण और मूल्यांकन का विस्तार क्षेत्र
- भारतीय मूल्यांकन मानक - 202 रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण
- भारतीय मूल्यांकन मानक 301 – कारबार मूल्यांकन
- भारतीय मूल्यांकन मानक - 302 अमूर्त आस्तियां
- भारतीय मूल्यांकन मानक - 303 वित्तीय लिखतें।

इन मानकों को, आईसीएआई के मूल्यांकन मानकों के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने संबंधी ढांचे और आईसीएआई मूल्यांकन मानकों के प्रकथन के साथ पढ़ते हुए लागू करना होगा। यह मूल्यांकन ऐसी अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को अधिकथित करता है, जिन्हें भारत में विद्यमान विधिक ढांचे और व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए साधारण रूप से अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किया जाता है। ये मानक वर्तमान में सिफारिशात्मक प्रकृति के हैं और इन्हें आज्ञापक बनाया जाना प्रस्तावित है।

(II) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का सृजन

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों को नामांकित और विनियमित करने या कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसार मूल्यांकक सदस्यों को सम्मिलित करने और उससे आनुषंगिक कृत्यों के निर्वहन हेतु आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का सृजन किया है, जो धारा 8 के अधीन एक प्राइवेट कंपनी है। आईसीएआई आरबीओ प्रतिभूति या वित्तीय आस्ति वर्ग के लिए रजिस्ट्रीकृत है।

(III) कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19 के दौरान, एमसीए/आईबीबीआई को निम्नलिखित प्रतिवेदन/सुझाव प्रस्तुत किए गए थे :

- “मूल्यांकन मानकों के संबंध में सलाह देने वाली समिति” हेतु नामांकन और आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को राष्ट्रीय मानकों के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में।
- कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 से संबंधित मुद्दों।
- मूल्यांकन संबंधी विषयों पर सलाह देने वाली समिति की प्रारूप रिपोर्ट के संबंध में टीका-टिप्पणियां।

(IV) आईसीएआई आरबीओ पठन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ

आईसीएआई आरबीओ ने अपनी पठन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किया था, जो एक ई-पठन मंच है और जो अध्ययन सामग्री के रूप में आस्ति वर्ग - “प्रतिभूति या वित्तीय आस्तियों” के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विहित की गई पाठ्यचर्या से संबंधित अवधारणाओं को उपलब्ध कराता है और साथ ही उन्हें बहु विकल्प वाले प्रश्नोत्तरों के रूप में मोक परीक्षा द्वारा संपूरित करता है। यह पठन प्रबंध प्रणाली सदस्यों के लिए आईबीबीआई मूल्यांकक परीक्षा हेतु तैयारी को सुकर बनाती है।

(V) आईसीएआई आरबीओ द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन माड्यूल

शैक्षिक पाठ्यक्रम के संबंध में सदस्यों की, वस्तु विषय को समझने में सहायता करने के विचार से 4 अध्ययन माड्यूल तैयार किए गए हैं :

- माड्यूल 1 के अंतर्गत मूल्यांकन का ब्यौरेवार पर्यावलोकन और अवधारणाएं हैं
- माड्यूल 2 के अंतर्गत मूल्यांकन संबंधी ब्यौरेवार दृष्टिकोण और पद्धतियां हैं
- माड्यूल 3 के अंतर्गत न्यायिक उदघोषणाएं हैं
- माड्यूल 4 के अंतर्गत पाठ्यचर्या के अनुसार सुसंगत विधियां और विनियम हैं।

(VI) प्रकाशनों की शृंखला – मूल्यांकन : वृत्तियों की अंतःदृष्टि

मूल्यांकन मानक बोर्ड ने “मूल्यांकन : वृत्तियों की अंतःदृष्टि – शृंखला - 1, शृंखला - 2 और शृंखला - 3” का प्रकाशन किया है। इस प्रकाशन शृंखला में 61 लेखों का समूह अंतर्विष्ट है। यह प्रकाशन मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यावहारिक अंतःदृष्टि और मामला अध्ययनों को उपलब्ध कराता है, जो मूल्यांककों, मूल्यांकन रिपोर्टों के उपयोक्ताओं और मूल्यांकन का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

(VII) साफा देशों के साथ आईसीएआई मूल्यांकन मानकों से संबंधित आउटरीच कार्यक्रम

चूंकि, साफा देशों में कोई मूल्यांकन मानक विद्यमान नहीं है, इसलिए आईसीएआई साफा देशों को आईसीएआई मूल्यांकन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। बोर्ड इन देशों में मूल्यांकन संबंधी शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा आईसीएआई मूल्यांकन मानकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके इस कार्य को आरंभ कर रहा है।

(VIII) कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 19 के अधीन कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित मूल्यांकन मामलों के संबंध में सलाहकारी समिति की बैठक

आईसीएआई, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 19 के अधीन मूल्यांकन मामलों के संबंध में सलाहकारी समिति का एक सदस्य है। समिति का सृजन, केंद्रीय सरकार को कंपनियों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु मूल्यांकन मानकों और नीतियों की विरचना तथा उन्हें अधिकथित किए जाने के लिए किया गया है। सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत की है, जिसमें यह कथन किया गया है कि भारत में मूल्यांकन मानक विद्यमान नहीं हैं और आईसीएआई के मूल्यांकन मानकों का कोई पूर्ववर्ती रिकार्ड नहीं है। अतः, आईसीएआई ने कारणों सहित अपने विभेदकारी टिप्पण को प्रस्तुत किया है।

(IX) आईसीएआई मूल्यांकन मानकों की आईवीएससी की तुलना में प्रमुख विशिष्टियां

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने आईसीएआई से यह अनुरोध किया था कि वह आईसीएआई के मूल्यांकन मानकों, 2018 की आईवीएससी द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों की तुलना में प्रमुख विशिष्टियों को प्रस्तुत करे। इस संबंध में, आईसीएआई के मूल्यांकन मानकों, 2018 की आईवीएससी द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों की तुलना में प्रमुख विशिष्टियों का वर्णन करते हुए एक ब्यौरेवार दस्तावेज कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

(X) प्रादेशिक परिषदों और शाखा वेबकास्टों द्वारा आयोजित किए जाने वाले आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 संबंधी जागरूकता कार्यक्रम

- मूल्यांकन मानक बोर्ड, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के साथ संयुक्त रूप से आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 संबंधी अर्ध-दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से कर रहा है।

- मूल्यांकन मानक बोर्ड ने, आईसीएआई आरबीओ के साथ संयुक्त रूप से 18 अप्रैल, 2019 को “मूल्यांकन मानक और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के लिए नैतिक संहिता” संबंधी एक वेबकास्ट का आयोजन किया था। इस वेबकास्ट का प्रयोजन, अनुसरित किए जाने वाले मूल्यांकन मानकों और विनिर्दिष्ट मूल्यांकन संबंधी समनुदेशन को पूरा करते समय अनुपालन की जाने वाली नैतिक संहिता के संबंध में बड़ी संख्या में मौजूद श्रोताओं को जानकारी उपलब्ध कराना था। इस वेबकास्ट को डा. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा संबोधित किया गया था। यह वेबकास्ट 4,000 से अधिक सदस्यों द्वारा देखा गया था।

(XI) कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 में संशोधन

आईसीएआई नियमित रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 13 नवंबर, 2018 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने चौथे संशोधन नियमों के माध्यम से कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 में संशोधन किए थे। इनमें से एक प्रमुख संशोधन यह है कि अब ऐसा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके पास तीन वर्षों का अनुभव है और जो स्नातक नहीं है, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए पात्र है। इस संशोधन से पूर्व, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्नातक होना आवश्यक था।

(XII) प्रकाशन – मूल्यांकन संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

मूल्यांकन मानक बोर्ड ने आईसीएआई के रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के साथ संयुक्त रूप से फरवरी, 2019 में “मूल्यांकन संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों” का प्रकाशन किया था। यह प्रकाशन व्यापक रूप से वित्तीय आस्तियों या प्रतिभूतियों के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित करता है। इस प्रकाशन को, हमारे सदस्यों और अन्य पणधारियों की सहायता करने हेतु प्रश्नोत्तर प्ररूप में तैयार किया गया है जिससे वे मूल्यांकन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में अवधारणात्मक स्पष्टता को अर्जित करने में समर्थ हो सके।

(XIII) मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड

मूल्यांकन मानक बोर्ड ने “मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड” नामक प्रकाशन को पुनरीक्षित करके उसे अद्यतन बनाया है। इस प्रकाशन को, हमारे सदस्यों और अन्य पणधारियों की सहायता करने हेतु प्रश्नोत्तर प्ररूप में तैयार किया गया है जिससे वे मूल्यांकन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में अवधारणात्मक स्पष्टता को अर्जित करने में समर्थ हो सके। यह प्रकाशन व्यापक रूप से ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करता है, जिन्हें वित्तीय आस्तियों या प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करते समय पूछा जाता है।

5.30 कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड

राष्ट्र की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए और विभिन्न कराधान विधियों (प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार की विधियों) के अधीन अनुपालनों की रिपोर्टिंग में सुधार लाने के लिए परिषद् द्वारा वर्ष 2018-19 में पहली बार कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किया है। यह परिकल्पना की गई है कि बोर्ड द्वारा किए जाने वाले पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करेंगे कि सदस्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के अधीन विहित विभिन्न रिपोर्टों का प्रमाणन करते समय और अधिक बेहतर तत्परता का प्रयोग करेंगे और दीर्घकाल में यह उपाय उनके द्वारा की जाने वाली सकल रिपोर्टिंग और प्रमाणन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा।

(I) कर संपरीक्षा रिपोर्टों का चयन : परिधि क्षेत्र को व्यापक बनाना

पुनर्विलोकन के परिधि क्षेत्र को व्यापक बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ने चालू परिषद् वर्ष में अपने निर्देश निबंधनों को उपांतरित किया है, जिससे उनमें पूर्व में कथित ‘अस्तित्व’ शब्द के स्थान पर ‘व्यक्तियों’ शब्द को रखा जा सके। तदनुसार, परिषद् वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड ने टॉप 100 व्यष्टियों, फर्मों और एलएलपी की कर संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने का विनिश्चय किया था, जिनमें से प्रत्येक की कुल आवर्त 100 करोड़ रुपए से अधिक थी और साथ ही टॉप 100 न्यासों, जिनकी कुल आवर्त 10 करोड़ रुपए से अधिक थी, की कर संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने का भी निर्णय लिया गया था। इस संबंध में, सदस्य (आईटीएंडसी), सीबीडीटी को यह अनुरोध करते हुए पत्र भेजा गया है कि वह ऊपर उल्लिखित निर्धारितियों के संबंध में कर संपरीक्षकों द्वारा अपलोड की गई कर संपरीक्षा रिपोर्टों को उनके अन्य अनुलग्नकों सहित आईसीएआई को उपलब्ध कराने में सहायता करें।

(II) परिषद् वर्ष 2018-19 के दौरान चुनी गई कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति :

बोर्ड ने परिषद् वर्ष 2018-19 के दौरान 100 कंपनियों का, निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित उनकी कर संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए स्व:विवेकानुसार चयन किया था। इस संबंध में, कर संपरीक्षकों से 95 कर संपरीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इन रिपोर्टों का प्रारंभिक पुनर्विलोकन, बोर्ड के साथ पैनलबद्ध तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा पूरा कर लिया गया है। इनमें से 30 आरंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों को, विभिन्न बोर्ड सदस्यों के समन्वयनाधीन गठित कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन समूहों को रिपोर्टों का द्वितीय पुनर्विलोकन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। शेष 5 कर संपरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में अध्यक्ष, सीबीडीटी को यह अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा गया है कि वह इन उद्यमों की कर संपरीक्षा रिपोर्टों को आईसीएआई को उपलब्ध कराने में सहायता करे, जिससे बोर्ड द्वारा उनका ब्यौरेवार पुनर्विलोकन किया जा सके।

(III) "कर संपरीक्षा संबंधी मुद्दे" प्रकाशन का पुनरीक्षण

बोर्ड ने, वर्ष 2000 में आईसीएआई की प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा जारी "कर संपरीक्षा संबंधी मुद्दे" प्रकाशन, जिसमें अंतिम पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था, का पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है, जिससे उसे अद्यतन बनाया जा सके तथा उसमें ऐसी घटनाओं को, जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुई हैं, सम्मिलित करके सदस्यों का कर संपरीक्षा रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में मार्गदर्शन किया जा सके।

5.31 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति

इस वर्ष एक नई समिति, अर्थात् दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति का गठन किया गया है, जो विनिर्दिष्ट रूप से दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी विधियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह एक उभरता क्षेत्र है और इसने सदस्यों के लिए नए वृत्तिक अवसरों का सृजन किया है। इस समिति का उद्देश्य साधारण रूप से सदस्यों के बीच दिवाला समाधान के क्षेत्र में व्यवसाय के नए क्षेत्रों के बारे में जागरूकता लाना और सदस्यों को विधि के व्यवहारिक पहलुओं और प्रक्रियाओं के संबंध में शिक्षित करना है।

(I) "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न – पुनरीक्षित जुलाई, 2019 संस्करण" नामक प्रकाशन :

- समिति ने ऐसे संशोधनों को सम्मिलित करते हुए, जिन्हें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में किया गया है, "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न – पुनरीक्षित जुलाई, 2019 संस्करण" नामक प्रकाशन को जारी किया है।

(II) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित अद्यतन जानकारी

- आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति ने सदस्यों के फायदे के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता विधियों से संबंधित अद्यतन जानकारी को जारी किया है। यह अद्यतन जानकारी, जिसे नियमित आधार पर जारी किया जाएगा, मामला संबंधी अद्यतन जानकारी, अद्यतन समाचारों और साथ ही समिति की पहलों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएगी।

(III) आयोजित किए गए कार्यक्रम/कार्यशालाएं

- मई, 2019 में नागपुर में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के संबंध में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
- जून, 2019 में गाजियाबाद में आईबीसी और आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
- अप्रैल-मई, 2019 के दौरान जयपुर, मुंबई और नोएडा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान के साथ संयुक्त रूप से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त युवा सदस्यों के लिए स्नातक दिवाला कार्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

(IV) वेबकास्ट

- समिति ने, अप्रैल, 2019 में 'दिवाला : बहु आयामी अवसरों के साथ एक उभरती वृत्ति' विषय पर एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था।
- मई, 2019 में, 'युवा सदस्यों के लिए खातक दिवाला कार्यक्रम' संबंधी लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया गया था, जिसे डा. एम.एस. साहू, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड तथा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ पदधारियों द्वारा संबोधित किया गया था।

5.32 महिला सदस्य सशक्तिकरण समूह

वृत्ति में महिला सदस्यों की उपस्थिति को मान्यता प्रदान करने और उन्हें सभी स्तरों, अर्थात् निगम नेतृत्व से लेकर शिक्षा और व्यवसाय तक मुख्य कार्यपालनकर्ता बनाने हेतु पहले करने के लिए वर्ष 2019 में परिषद् द्वारा महिला सदस्य सशक्तिकरण समूह का गठन किया गया था।

इस समूह ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किए :

- महिला पोर्टल (<https://womenportal.icaai.org/>) महिला सदस्यों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से वे अपनी अपेक्षाओं को सामने रख सकती हैं तथा प्रदेश/शाखा के आधार पर उन्हें उपलब्ध नमनीय कार्यघंटों संबंधी विकल्पों की खोज कर सकती हैं। इसका उद्देश्य महिला सदस्यों को, उनकी जानकारी को अद्यतन बनाने और अपने विचारों तथा चिंताओं को साझा करने के लिए एक सामान्य मंच उपलब्ध कराना भी है।
- महिला सदस्यों को स्वयं के लिए उच्चतर उपलब्धियों के उद्देश्य को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए समूह ने महिला सदस्यों से उनकी सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया है, जिन्हें महिला पोर्टल पर अपलोड किया गया था।
- महिला सदस्यों की उपस्थिति को मान्यता प्रदान करने के लिए, समूह ने आईसीएआई के साथ सहबद्ध महिला सदस्यों के व्यौरों को अपलोड किया है।
- समूह ने वृत्ति में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं और महिला वृत्तिकों को उनके प्रयासों में सफलता को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए विख्यात महिला सदस्यों के प्रेरणादायक वीडियो अपलोड करने की योजना तैयार की है। अभी तक, सीए आर.एम. विशाखा, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडिया फर्स्ट लाइव इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एक प्रेरणादायक वीडियो के रूप में एक पायलेट वीडियो को अपलोड किया गया है।
- समूह ने सेतु कार्यक्रम, अर्थात् महिला सदस्यों और व्यवसायगत सीए फर्मों के बीच की खाई को भरने संबंधी कार्यक्रम के साथ देश भर में 10 महिला सदस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों का आयोजन गांधीनगर, भुवनेश्वर, इंदौर, भोपाल, चेन्नई, सलेम आदि स्थानों पर किया गया था। 1100 से अधिक व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया था। इन कार्यक्रमों की संरचना को ऐसी रीति में तैयार किया गया था, जिससे महिला सदस्यों को सामाजिक और साथ ही वृत्तिक, दोनों ही क्षेत्रों में सशक्त बनाया जा सके।

6. सीए सेवाओं के निर्यात और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति

वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा लेखांकन और वित्तीय सेवा क्षेत्र की, 12 चैंपियन सेक्टरों में से एक के रूप में पहचान की गई है, जिससे भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी सेवाओं संबंधी निर्यात का संवर्धन करके भारत सरकार के इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। परिषद् वर्ष 2018-19 के दौरान परिषद् ने चैंपियन सेक्टर संबंधी पहलों और उससे संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित कार्य को करने हेतु एक गैर-स्थायी समिति के रूप में सीए सेवाओं के निर्यात और डब्ल्यूटीओ संबंधी एक नई समिति का गठन किया था।

(I) लेखांकन और वित्तीय क्षेत्र (चैंपियन सेक्टर) के लिए निर्यात संबंधी संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करना

- चैंपियन सेक्टर के लिए प्रस्ताव : चूंकि सेवाओं संबंधी क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से भारत की जीडीपी, निर्यात और नौकरियों के सृजन के प्रति योगदान करता है, इसलिए चैंपियन सेवा सेक्टरों में बड़ी हुई उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा भारत से विभिन्न सेवाओं के

निर्यात को आगे और बढ़ावा देगी। इस संबंध में आईसीएआई, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के मार्गदर्शन के अधीन चैंपियन सेक्टर संबंधी विभिन्न पहलों के संबंध में कार्य कर रहा है। आईसीएआई ने सीईएसडब्ल्यूटीओ के माध्यम से चैंपियन सेक्टर संबंधी कार्य योजना के अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है।



- जीएसटी लेखा सहायक : भारत में इस क्षेत्र में स्नातकों को नियोजित करने संबंधी संभावनाओं का प्रसार और संवर्धन करने के लिए इस समिति ने आईसीएआई एआरएफ के साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन के अधीन चैंपियन सेक्टर संबंधी एक पहल के रूप में भारतीय स्नातकों हेतु जीएसटी लेखा सहायक स्कीम के संबंध में कार्य किया था। चैंपियन सेक्टर संबंधी स्क्रीनिंग समिति ने, आईसीएआई एआरएफ के माध्यम से आईसीएआई द्वारा यथा प्रस्तावित जीएसटी लेखा सहायक स्कीम के लिए 975 करोड़ रुपये की रकम का अनुमोदन किया था। यह स्कीम जीएसटी के तुरंत अनुपालन में भारतीय उद्योग की सहायता करने के लिए जीएसटी सहायकों के दूसरे टियर के विकास को सुकर बनाएगी। यह स्कीम भारत में नौकरियों के सृजन के लिए भारत में स्नातकों हेतु आगे के मार्ग को प्रशस्त करेगी।
- भारत में निवेश के साथ समझौता जापान पर हस्ताक्षर : प्लेटिनम जयंती समारोह के दौरान आईसीएआई ने, आईसीएआई की सीए सेवाओं के निर्यात और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति के तत्वाधान में भारत में निवेश के साथ फरवरी, 2019 में एक समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता जापान का उद्देश्य भारत में विदेशी निवेश के क्षेत्र में सहायता करना और उसका संवर्धन करना तथा भारत से बाहर भारतीय निवेश को बढ़ावा देना है। इस समझौता जापान का आशय यह भी है कि भारत में आने वाले और भारत से बाहर जाने वाले संभावित निवेशकों को आवश्यक मार्गदर्शन और सलाह उपलब्ध कराई जाए तथा भारत को निवेश एक हेतु एक मैत्रीपूर्ण गंतव्य स्थान के रूप में सुस्थापित करने के उद्देश्य का संवर्धन किया जा सके।
- ज्ञान में भागीदार : राष्ट्र के एक भागीदार के रूप में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने सीईएसडब्ल्यूटीओ के माध्यम से 15 से 18 मई, 2018 के दौरान सेवाओं संबंधी वैश्विक प्रदर्शनी (जीईएस) में "ज्ञान में भागीदार" के रूप में भाग लिया था और उसे इस प्रदर्शनी में 'राष्ट्र निर्माण में भागीदार' के रूप में अपनी भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए एक पैवेलियन भी आवंटित किया गया था। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 15 मई, 2018 को वैश्विक सेवा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, जिसके पश्चात् लेखांकन और वित्तीय सेवाओं सहित 12 चैंपियन सेक्टरों की घोषणा की गई थी। उसके पश्चात् भारत के माननीय राष्ट्रपति ने सीए सुरेश प्रभु के साथ आईसीएआई के पैवेलियन का दौरा भी किया था। सीए सुरेश प्रभु ने उस दिन विशेष सचिव, वाणिज्य और श्री सुधांशु पांडे, संयुक्त सचिव के साथ आईसीएआई पैवेलियन का एक ब्यौरेवार दौरा किया था।

(II) बैठकें

- विस्तारित भारत-चिली अधिमानी व्यापार करार के अधीन संयुक्त प्रशासन समिति की दूसरी बैठक के संबंध में अंतःमंत्रालयीय बैठक ।
- व्यापार और सेवाओं संबंधी डब्ल्यूटीओ नीति पुनर्विलोकन बोर्ड, जहां सीए सेवाओं के निर्यात के संवर्धन के लिए संयुक्त सहयोग और एमआरए हेतु अनुरोध किया गया था ।
- चैंपियन सेवा सेक्टर स्कीम (सीएसएसएस) के संबंध में व्यय संबंधी वित्त समिति (ईएफसी) के लिए प्रारूप टिप्पण ।
- भारत-पेरु बातचीत के अधीन अंतःमंत्रालयीय पणधारियों के साथ परामर्श ।
- भारत-जापान सीईपीए के अधीन करार किए गए अनुसार सेवाओं में व्यापार संबंधी चैंप्टर के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु सेवाओं में व्यापार के गठन की बाबत प्राकृतिक व्यक्तियों का संचलन (एमओएनपी) ।
- भारत और वियतनाम के बीच व्यापार बैठक संबंधी चौथे संयुक्त उप आयोग के लिए मुद्दे ।
- भारत-चीन : सेवाओं में व्यापार संबंधी संयुक्त कार्यकारी समूह की चौथी बैठक ।
- आरसीईपी करार के अधीन सेवाओं में व्यापार संबंधी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पणधारियों से परामर्श का आयोजन 22 अप्रैल, 2019 को किया गया था, जिसमें आईसीएआई ने आरसीईपी करार के 15 देशों के साथ परस्पर हित के क्षेत्रों में सक्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के संबंध में अपनी दिलचस्पी अभिव्यक्त की थी, जिसके पश्चात् भविष्य में परस्पर मान्यता करारों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(III) विदेशों में स्थित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए विदेशों में स्थित आईसीएआई के चैंप्टरों के समन्वय से विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

- आईसीएआई ने, लेखांकन सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार की चैंपियन सेक्टर पहल में भागीदारी करने के अपने मिशन के अनुरूप सीए सेवाओं के निर्यात और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति और उद्योग तथा कारबार में लगे सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी समितियों के तत्वाधान में 14-16 सितंबर, 2018 के दौरान विदेशी कैम्पस नियोजन अभियान का आयोजन किया था । इन कार्यक्रमों का संचालन जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलौर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तथा मुंबई, दिल्ली और चेन्नई स्थित केंद्रों में आमने-सामने की परस्पर क्रिया और वीडियो कांफ्रेंसिंग, दोनों के माध्यम से किया गया था ।
- प्रथम पहल होने के बावजूद इस अभियान के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए थे, बावजूद इसके कि मध्य-पूर्व में आर्थिक मंदी का दौर जारी है । आईसीएआई ने अपने सीमित प्रयासों से 42 कंपनियों का ध्यानाकर्षण किया था और वह भी केवल मध्य-पूर्व की तथा अफ्रीका से केवल एक कंपनी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था ।
 - 42 कंपनियों ने रजिस्ट्रीकृत किया था
 - 29 कंपनियों ने भाग लिया था
 - मध्य-पूर्व और अफ्रीका से कंपनियां
 - 6428 सदस्यों ने रजिस्ट्रीकृत किया था
 - 1527 सदस्यों को सूचीबद्ध किया गया था
 - 544 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे
 - 66 सदस्यों को नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया था

(IV) सदस्यों के बीच विदेशी भाषा का संवर्धन

संस्थान ने चार्टर्ड अकाउंटेंटसी सेवाओं के निर्यात पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जहां उसके 20,000 से अधिक सदस्य विदेशों में अवस्थित हैं । इसके अतिरिक्त, विदेशों में नए नियोजनों के सृजन के साथ, इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि आईसीएआई अपने सदस्यों और छात्रों को फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, अरबी और चीनी भाषा संबंधी कौशलों में प्रशिक्षित करे । इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा चैंपियन सेक्टर संबंधी अपनी कार्ययोजना में भी उल्लेख किया गया है ।

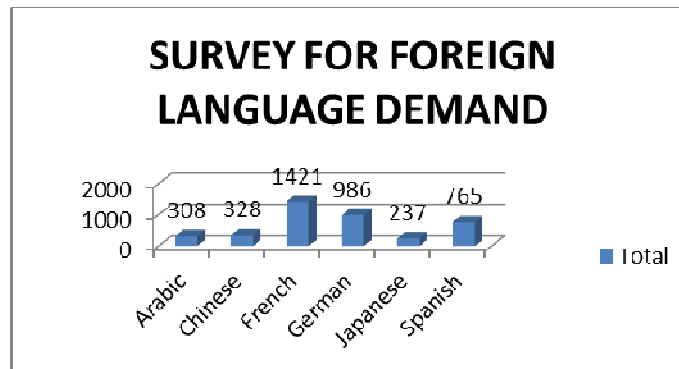
- इंस्टिट्यूटो सर्वेटिस, स्पेनिश दूतावास सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से स्पेनिश भाषा पठन पाठ्यक्रम – 45-50 अभ्यर्थियों से युक्त 9 बैचों ने इस पाठ्यक्रम को पूरा किया है, जिसमें से 5 बैचों का दिल्ली में और 4 बैचों का मुंबई में आयोजन किया गया था।
- गोथ इंस्टिट्यूट मैक्समूलर भवन (भारत में जर्मन सांस्कृतिक संस्थान, जो जर्मन भाषा के पठन का संवर्धन करता है) के माध्यम से जर्मन भाषा पठन पाठ्यक्रम – जर्मन पाठ्यक्रम के पहले बैच को जनवरी, 2019 में आरंभ किया गया था।
- ऐलायेंस फ्रेंकाइस डे दिल्ली के माध्यम से फ्रेंच भाषा पठन पाठ्यक्रम – फ्रेंच पाठ्यक्रम के पहले बैच को फरवरी, 2019 में आरंभ किया गया था।
- अरबी भाषा संबंधी जागरूकता सत्र : 14 मई, 2019 को दुबई स्थित एटन संस्थान के सहयोग से दुबई नॉलेज पार्क में आईसीएआई के विदेशी कार्यालय द्वारा अरबी भाषा संबंधी एक दिवसीय सत्र की मेजबानी की गई थी, जिसमें अरबी भाषा की मांग का निर्धारण करने के लिए 100 से अधिक सदस्यों ने सफलतापूर्वक भाग लिया था। जापानी, अरबी और चीनी भाषाओं के पठन पाठ्यक्रमों के संबंध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(V) भारत से लेखांकन सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में स्थित आईसीएआई के सदस्यों के लिए सर्वेक्षण

- 214 सदस्यों ने प्रतिक्रिया प्रस्तुत की थी।
- प्रतिक्रियाएं देने वाले व्यक्ति मध्य-पूर्व, यू.के., कनाडा, आयरलैंड, एशिया आस्ट्रेलिया और अफ्रीकी क्षेत्रों में उपस्थित थे।
- इस सर्वेक्षण का आशय, प्रत्याशाओं की खाई को भरना तथा विदेशों में स्थित सदस्यों संबंधी मुद्दों को समझना था।
- उनसे सुझावों और अंतःनिवेशों का अनुरोध किया गया था, जिससे आईसीएआई को ब्रांड भारतीय सीए का वैश्विक रूप से संवर्धन करने और ऐसी विभिन्न बाधाओं/सीमाओं का समाधान करने में भी सहायता मिल सके, जो भारतीय सीए के सामने विदेशों में आती हैं।

(VI) आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों से विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों के संबंध में अधिमानता की ईप्सा करने संबंधी सर्वेक्षण

समिति ने विदेशी भाषा के लिए मांग का निर्धारण करने के लिए एक आनलाइन सर्वेक्षण आरंभ किया था। आज की तारीख तक समिति को नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार 4045 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं :--



(VII) सदस्यों को सेवाएं

- उत्तम छवि संबंधी आनलाइन सेवा का शुभारंभ – उत्तम छवि संबंधी प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने तथा उसे जारी करने को जून, 2018 से आनलाइन बनाया गया है और अब सदस्य यह प्रमाणपत्र एक सप्ताह के समय में प्राप्त कर सकते हैं।
- यह पहल हमारे विदेशों में स्थित सदस्यों और विदेशों में जाने के लिए इच्छुक सदस्यों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोग पहल है। उक्त ई-सेवा सदस्यों के लिए, उन्हें सुगम नियोजन, अर्हता संबंधी उन्नयन को विदेशों में प्राप्त किए जाने को सुकर बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई है।

(VIII) अंतर्राष्ट्रीय सक्षमता निर्माण

- 7 से 9 मई, 2019 के दौरान आईसीएआई के तकनीकी सहयोग से राजस्व और सीमाशुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय, भूटान द्वारा भूटानी लेखांकन मानकों/ आईएफआरएस एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।
- 11 अप्रैल, 2018 को नेपाल से 21 वरिष्ठ भविष्य निधि अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आईसीएआई का दौरा किया था।
- 30 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में 'भारत में निवेश संबंधी अवसर – आगामी वृत्तिक अवसर' विषय पर प्रथम लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया गया था, जिसे श्री दीपक बागला, एमडी और सीईओ, इन्वेस्ट इंडिया ने संबोधित किया था।
- 19 जून, 2019 को सीए हंस राज चुघ, केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई द्वारा "सेवाओं के निर्यात के लिए अवसर, पद्धतियां और प्रोत्साहन - विशेष रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए" विषय पर एक वेबकास्ट।

7. अन्य क्रियाकलाप**7.1 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति**

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति, प्रबंध लेखांकन के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें वित्त और अन्य संबद्ध विषय भी सम्मिलित हैं, के संबंध में अग्रिम जानकारी और विशेषीकृत प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। समिति द्वारा प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी एक विशेषीकृत डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी इस अर्हता पश्चात् पाठ्यक्रम को आरंभ करने के लिए समिति इस पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यचर्या और सलेब्स के संबंध में कार्यवाही कर रही है। समिति इस एक सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम को किसी विख्यात कारबार विद्यालय के साथ संयुक्त रूप से संचालित किए जाने के लिए सहयोग कर रही है, जिसमें सदस्यों को प्रबंध संबंधी अवधारणाओं, नेतृत्व संबंधी कौशलों और निर्णय लिए जाने संबंधी बुद्धिमत्ता के संबंध में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपने प्रबंध संबंधी कृत्यों को और अधिक दक्षता और प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।

सदस्यों के लिए पहले

- प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी इस अर्हता पश्चात् पाठ्यक्रम (पीक्यूसी एमबीएफ), जिसे गत वर्ष कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, की पाठ्यचर्या और सलेब्स को तैयार किया जा रहा है। समिति ने, इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के एक सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रबंध संस्थानों से बैठकों का आयोजन किया है।
- समिति ने नवंबर-दिसंबर, 2018 मासों के दौरान कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए परीक्षा का संचालन किया था।
- समिति ने मई-जून, 2018 मासों के दौरान कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए परीक्षा का संचालन किया था।

उद्योग/निगम संबंधी पहले/कार्यक्रम

- समिति ने, 15 दिसंबर, 2018 को अपनी इंदौर ब्रांच में वित्तीय रिपोर्टिंग और जीएसटी संबंधी एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की इंदौर शाखा द्वारा की गई थी।

7.2 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (एससीएमईएंडपीएस)

इस समिति का उद्देश्य, आईसीएआई और उद्यमों या लोक सेवा में लगे सदस्यों के बीच परस्पर फायदाप्रद सक्रिय संबंध स्थापित करना है। समिति ऐसी परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन करती है, जो परस्पर फायदाप्रद हैं। युवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से भी अनेक क्रियाकलाप आरंभ किए गए थे।

(I) 25 मई, 2018 को नई दिल्ली में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की क्षेत्रीय बैठक

उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति ने 25 मई, 2018 को नई दिल्ली में लोक सेवा में लगे सदस्यों की एक क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया था। इस क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में लोक सेवा में लगे अन्य सीए सदस्यों के अलावा सीए अनिल आर. दवे, माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय, सीए विभू बखरु, आसीन न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, सीए दीपक कुमार केडिया, अपर निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली, सीए राकेश राठी, डीआईजी पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीए उपेन्द्र गुप्ता, आईआरएस, आयुक्त, (जीएसटी) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय सम्मिलित थे।

इस क्षेत्रीय बैठक के दौरान, आईसीएआई ने लोक सेवा में लगे सीए सदस्यों को सुगमतापूर्वक आईसीएआई के साथ जोड़ने और उनके अभिलेखों को सुगमता से अद्यतन बनाने हेतु एक मोबाइल ऐप्लीकेशन का शुभारंभ किया था। वृत्तिक अकाउंटेंटों की सक्षमताओं और कौशल सेटों में सुधार करने के उपायों संबंधी महत्वपूर्ण परिचर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, इस बात पर भी विचार-विमर्श किया गया था कि पणधारियों की प्रत्याशाओं को किस प्रकार पूरा किया जाए और आईसीएआई की लोक छवि में किस प्रकार और सुधार लाया जाए। सदस्यों ने, अंकीय प्रौद्योगिकियों में होने वाले परिवर्तनों से उदभूत होने वाली वृत्ति की बदलती आवश्यकताओं पर भी विचार किया था। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्रीय बैठक के दौरान आईसीएआई ने सीए उपेन्द्र गुप्ता, आयुक्त, जीएसटी को, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्राप्त हुए प्रधानमंत्री पुरस्कार, जिसे "जीएसटी दल, राजस्व विभाग, भारत सरकार" को प्रदान किया गया था, के लिए सम्मानित किया गया था।

(II) 25-27 जनवरी, 2019 के दौरान तिरुपति में लोक सेवा में लगे आईसीएआई के सदस्यों की आवासीय बैठक

उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति ने 25-27 जनवरी, 2019 के दौरान तिरुपति में आईसीएआई के सदस्यों की एक आवासीय बैठक का आयोजन किया था।

इस आवासीय बैठक का उद्घाटन सीए प्रफुल प्रेमसुख छाजेड, उपाध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा किया गया था। इस बैठक में लोक सेवा में लगे अनेक सदस्यों ने भाग लिया था, अर्थात्, आईसीएआई के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल प्रेमसुख छाजेड द्वारा आवासीय बैठक का उद्घाटन किया गया था। इस बैठक में लोक सेवा में लगे अनेक सदस्यों अर्थात् सीए. अरुण कुमार गुजराती, माननीय भूतपूर्व सभापति, महाराष्ट्र विधान परिषद्, सी.ए. भानुदास के. मुरकुटे, माननीय पूर्व विधायक, महाराष्ट्र विधान परिषद्, सीए. दीपक केडिया, अपर निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, सीए. मनीष बोराड, अकाउंटेंट सदस्य, आयकर अपील अधिकरण, सीए. मनोज कुमार अग्रवाल, अकाउंटेंट सदस्य, आयकर अपील अधिकरण, सीए. अमित मित्तल, आईआरएस, संयुक्त आयकर आयुक्त, सीए. महेश कुमार, आईआरएस आय-कर आयुक्त (अग्रिम कीमत निर्धारण करार) सीए. सारिका जैन, आईआरएस सहायक सीआईटी, मुंबई सीए. सुमित कुमार अग्रवाल सहायक आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, प्रभाग-II, रायपुर सीए. अजय अग्रवाल, आईआरएस रायपुर संपरीक्षा आयुक्त, रायपुर छत्तीसगढ़, सीए. सतीश कुमार गर्ग, प्रधान निदेशक, संपरीक्षा (रेल), सीए. सौरभ देशमुख, निदेशक, संचार मंत्रालय सीए. उमेश कुमार अग्रवाल, आयकर संयुक्त आयुक्त, सीए. नेहा जैन, सहायक निदेशक (लागत), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली, सीए. अमित अरोड़ा, पत्रकार और वार्ता संचालक, दूरदर्शन ने भाग लिया था।

आवासीय बैठक के दौरान, लोक सेवा और उद्यमों में लगे सदस्यों संबंधी समिति ने अपनी एक पृथक् वेबसाइट को आरंभ किया था, जिससे प्रभावी रूप से आईसीएआई और सदस्यों के बीच में संबंधों को सुदृढ़ किया जा सके।

इस बैठक की शोभा सीए अरुण कुमार गुजराती, माननीय भूतपूर्व सभापति, महाराष्ट्र विधान परिषद् द्वारा "लोक विश्वास और भरोसा कैसे बढ़ाएं" विषय पर दिए गए एक विशेष संबोधन द्वारा बढ़ी थी, जिसमें उन्होंने लोक विश्वास को स्थापित करने के महत्व के मुद्दे पर गहन विचार किया था, जिससे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वृत्ति की साख बढ़े और साथ ही वृत्ति के मूल्य और उपयोगिता में भी वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त, सीए दीपक केडिया, अपर निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय ने "प्रति धनशोधन अधिनियम - चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका" विषय पर एक संबोधन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रति धनशोधन अधिनियम के मुद्दे के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की समझ में अभिवृद्धि करने के मुद्दे पर विचार किया जिससे समाज का साधारण मूल्यवर्धन किया जा सके। लेखांकन वृत्ति को प्रभावित करने वाली हाल ही की घटनाओं से संबंधित अनेक अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई थी तथा सरकार, विनियामकों, मीडिया, छात्रों और अन्य पणधारियों के बीच सीए वृत्ति के सकारात्मक सुदृढ़ बिन्दुओं का प्रचार करने के संबंध में प्राप्त हुए सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। लोक सेवा में लगे

सदस्यों ने इलैक्ट्रानिक प्रणालियों, ई-अनुपालनों के क्षेत्र में हुई हाल ही की घटनाओं से संबंधित समकालीन मुद्दों पर भी विचार किया था और इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि अनुशासन तंत्र में किस प्रकार सुधार किया जा सके, जिससे प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और साथ ही आईसीएआई की विनियामक प्रणाली में जनता के विश्वास में बढ़ोतरी हो।

(III) वेबकास्ट

उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति की अनन्य वेबसाइट और उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति के लिए मोबाइल ऐप्लीकेशन को आरंभ किया गया था, जिससे लोक सेवा में लगे सदस्यों को आईसीएआई के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए एक अंतः पृष्ठ उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही वे आईसीएआई में अपने प्रोफाइल को अपडेट करने में भी समर्थ बन सकें।

7.3 विधिक सलाहकार खंड

इस अवधि के दौरान, विधिक खंड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किए गए थे :

- 1.4.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 5 है।
- विधिक रायों, अध्ययनों और रिपोर्टों के रूप में प्रभावी विधिक सहायता को उपलब्ध कराना, जैसा कि समय-समय पर संस्थान की परिषद्/कार्यपालक समिति/ विभिन्न गैर-स्थायी समितियों और विभागों द्वारा अपेक्षा की जाए।
- आईसीएआई के हित को ठोस रूप से सुनिश्चित करने के लिए संस्थान के प्रशासनिक कार्यकरण से उद्भूत होने वाली विधि के सारवान और प्रक्रियात्मक प्रश्नों की विविध श्रृंखला पर उपयुक्त विधिक सलाह उपलब्ध कराना, जैसा कि प्रचालनात्मक विभागों द्वारा अपेक्षित किया जाए।
- आईसीएआई के प्रचालन विभागों और विभिन्न समितियों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार संविदाओं, निविदाओं, दस्तावेजों और अन्य विधिक दस्तावेजों के पुनर्विलोकन, उनके संबंध में बातचीत, उनके प्रारूपण और विधीक्षा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण और पर्यावलोकन करना।
- नीतियों को तैयार करने के संबंध में विधिक सूक्ष्मताओं का ध्यान रखने के लिए यथा अपेक्षित रूप में विभिन्न स्थायी और गैर-स्थायी समितियों, अध्ययन समूहों और कार्यबलों में सेवा प्रदान करना।
- जब कभी आवश्यक हो, विधिक उपचारों का अवलंब लेने के विषयों में सलाह देना और प्राप्त हुई विधिक सूचनाओं का उत्तर तैयार करने में प्रचालन विभागों और समितियों की सहायता करना।

7.4 अवसंरचना विकास संबंधी समिति (आईडीसी)

अवसंरचना विकास संबंधी समिति का सृजन वर्ष 2014 में संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति के रूप में किया गया था। इस समिति ने शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों के लिए अवसंरचना नीति की विरचना की थी। वर्ष 2014 से, आईसीएआई ने एक ठोस अवसंरचना नीति स्थापित की है, जो वित्तीय विवेक और अनुशासन को सुनिश्चित करती है। यह नीति इस बात को परिभाषित करती है कि किस प्रकार की प्रसुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, स्थानीय अवसंरचना समितियों की संरचना कैसी हो, भूमि/भवन के अर्जन के नीति और प्रक्रिया, संकेतात्मक क्षेत्र, प्रधान कार्यालय से अनुज्ञेय अनुदान, संस्थान के भीतर विभिन्न प्राधिकारियों में निहित शक्तियां और उनका प्रत्यायोजन। चूंकि नीति स्वयं वित्तीय शक्तियों को परिभाषित करती है इसलिए वर्ष 2014 के पश्चात् से सभी अवसंरचना परियोजनाएं वित्त समिति की बजाए आईडीसी द्वारा अनुमोदित की जा रही हैं। अवसंरचना नीति को विरचित किए जाने के समय से ही आईसीएआई ने निम्नलिखित परियोजनाओं को आरंभ किया है :

नई अवसंरचना का क्रय	अनुमोदित संनिर्माण संबंधी प्रस्ताव	संदान में प्राप्त संपत्ति
कन्नूर, जालंधर, जबलपुर, गोवा, गुरुग्राम, मुरादाबाद, पाली, आगरा, गोरखपुर, कर्नाल, किशनगढ़, लातूर, पटियाला, उज्जैन और रतलाम	अजमेर, सूरत, हुबली, भोपाल, राजमहेंद्रवरम, उत्कृष्टता केंद्र जयपुर, बठिंडा, बरेली, जोधपुर, रायपुर, कन्नूर, गज़ियाबाद, गोवा, रायपुर और रोहिणी	बंगलूर स्थित संदान में प्राप्त संपत्ति

आईसीएआई द्वारा अभी तक स्थापित कुल 164 शाखाओं में से, 99 शाखाओं के पास अपने स्वयं के परिसर हैं, जिनके अंतर्गत 14 ऐसी शाखाएं (जो वर्तमान में किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) भी हैं, जिन्होंने अतिरिक्त परिसरों के लिए भूमि का उपापन किया है और या तो उन्होंने संनिर्माण आरंभ कर दिया है या संनिर्माण आरंभ होने वाला है। 16 शाखाओं (जो अपने स्वयं के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) ने, जिनके पास अभी तक अपने स्वयं के परिसर नहीं हैं, भूमि का उपापन किया है और या तो उन्होंने संनिर्माण आरंभ कर दिया है या संनिर्माण आरंभ होने वाला है। 51 शाखाओं के पास अपने स्वयं की भूमि या भवन नहीं है। 15 जुलाई, 2019 तक क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	विशिष्टियां	टिप्पणियां					योग
		डब्ल्यूआईआरसी	एसआईआरसी	ईआईआरसी	सीआईआरसी	एनआईआरसी	
1.	शाखाओं की कुल संख्या	35	45	13	47	24	164
2.	अपने स्वयं का परिसर रखने वाली शाखाओं की संख्या	21	33	6	29	10	99
3.	ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास भूमि है और जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है (जो किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं)	1	1	0	7	5	14
4.	ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास अपने परिसर के अलावा ऐसी भूमि भी है जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है (जो अपने स्वयं के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं)	5	2	1	7	1	16
5.	ऐसी शाखाओं की कुल संख्या, जिनके पास न तो भूमि है और न ही भवन	13	11	7	11	9	51

7.5 अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति

(I) विदेशों में वृत्तिक अवसरों की मान्यता के लिए आईसी की पहलें

अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी उपस्थिति को उपदर्शित करने के लिए आईसीएआई, सदस्यों की अर्हताओं को परस्पर रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए वैश्विक लेखांकन निकायों के साथ अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करार कर रहा है। वर्ष के दौरान, विभिन्न लेखांकन निकायों के साथ हस्ताक्षरित अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करारों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

- आईसीएआई और एसएआईसीए के बीच एमआरए पर 4 जून, 2018 को जोहान्सबर्ग में औपचारिक रूप से सीए. नवीन एन.डी. गुप्ता, तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई और सुश्री फनीसा लामोला, तत्कालीन सीईओ, एसएआईसीए द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सीए. प्रफुल छाजेड, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई और डा. के.जे. श्रीनिवास, माननीय महाकाउंसेल, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका भी इस अवसर पर मौजूद थे। यह एमआरए दोनों देशों के बीच एक-दूसरे की अर्हता को परस्पर मान्यता दिए जाने को सुकर बनाएगा और दो संस्थानों के बीच एक जोड़ने वाले तंत्र को विहित करके उत्तम छवि वाले सदस्यों के प्रवेश को भी सुकर बनाएगा।
- आईसीएआई और सीपीए कनाडा के बीच 17 नवंबर, 2018 को टोरंटो, कनाडा में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आईसीएआई और सीपीए कनाडा के बीच यह समझौता ज्ञापन सदस्यों के सीमापार आदान-प्रदान को सुकर बनाएगा और भारत तथा कनाडा के बीच के संबंधों को आगे और सुदृढ़ करेगा।
- सीपीए आयरलैंड के साथ एक एमआरए पर 5 अक्तूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार आईसीएआई और सीपीए आयरलैंड के सदस्यों की अर्हताओं की परस्पर मान्यता को अनुज्ञात करेगा।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संघ के मंत्रिमंडल ने 7 मार्च, 2019 को आईसीएआई और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीईडब्ल्यू) के बीच समझौता ज्ञापन के नवीकरण का अनुमोदन किया है। यह

समझौता ज्ञापन विश्व के दो विशालतम संस्थानों के सदस्यों हेतु परस्पर मान्यता और परीक्षा संबंधी ठहरावों के लिए उपबंध करेगा। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख को निर्धारित किया जा रहा है और उस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की आशा की जाती है।

(II) आईसीएआई की ब्रांड इकिटी का वैश्वीकरण

वर्तमान में आईसीएआई के पास 34 विदेशी चैप्टर हैं, जो समान अर्हताएं रखने वाले देशों के बीच सीए के ब्रांड का संवर्धन करते हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैरियर अवसरों के संवर्धन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। इस अवधि के दौरान नीचे दिए गए व्यौरों के अनुसार आईसीएआई के तीन चैप्टरों का शुभारंभ किया गया था :

- 6 जुलाई, 2018 को आईसीएआई के 32वें मलेशिया (कवालालम्पुर) चैप्टर का शुभारंभ।
- 18 सितंबर, 2018 को आईसीएआई के 33वें जापान (टोकियो) चैप्टर का शुभारंभ।
- 17 जनवरी, 2019 को आईसीएआई के 34वें आयरलैंड (डबलिन) चैप्टर का शुभारंभ।
- 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान मुंबई, भारत में अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस की मेजबानी आईसीएआई द्वारा की जाएगी।

(III) भारत का डब्ल्यूसीओ 2022 की मेजबानी के लिए चुना जाना

अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओ) का आयोजन प्रत्येक चार वर्षों में इंटरनेशनल फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी), जो लेखांकन वृत्ति के लिए एक विश्वव्यापी संगठन है, के तत्वाधान में किया जाता है और यह वृत्तिक अकाउंटेंटों के वैश्विक आयोजनों के अत्यधिक सम्माननीय आयोजनों में से एक है, जिसमें लगभग 6,000 प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे और उन्होंने लेखांकन तथा संबद्ध क्षेत्रों में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया था। आईसीएआई ने, जो आईएफएसी का सदस्य है, डब्ल्यूसीओ 20-22 की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया था और सदस्य निकाय के सामर्थ्य और अनुभव, प्रस्तावित आयोजन स्थल की उपयुक्तता, उसके आने वाले संभावित प्रतिनिधियों के बीच उसके प्रति आकर्षण के संबंध में एक कड़े निर्धारण के पश्चात्, जिसके अंतर्गत 1-2 जून, 2018 के दौरान क्रमशः दिल्ली और मुंबई में आईएफएसी के प्रतिनिधि मंडल के स्थल दौर भी थे, आईसीएआई ने डब्ल्यूसीओ 2022 की मुंबई में मेजबानी करने का गौरव प्राप्त किया था।

अकाउंटेंटों की 21वीं विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओ) के बेटन को औपचारिक रूप से सीए नवीन एन.डी. गुप्ता, तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई को, सिडनी में आयोजित 20वीं डब्ल्यूसीओ 2018 के समापन समारोह के दौरान डा. इन की जू, अध्यक्ष आईएफएसी द्वारा सौंपा गया था। माननीय श्री बी.वनलालवावना, सिडनी में भारत के महा कौंसल भी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने थे।

(IV) प्रतिनिधि मंडलों द्वारा आईसीएआई का दौरा

- श्री अब्दुलवाहिद आबू, पूर्व सदस्य, आईएफएसी एसएमपी समिति ने 13-23 अप्रैल, 2018 के दौरान भारत का दौरा किया और भारत में एसएमपी के सक्षमता निर्माण के संबंध में दिल्ली, जयपुर और मुंबई में सदस्यों को संबोधित किया। व्याख्यानो का समन्वय आईसीएआई की सेवारत सदस्यों की सक्षमता निर्माण समिति द्वारा किया गया था।
- आईएफएसी के एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें सुश्री रैचल ग्रिम्स, तत्कालीन अध्यक्ष, आईएफएसी, श्री फैजुल चौधरी, तत्कालीन सीईओ, आईएफएसी और डॉ. गैरी फलुग्राथ, तत्कालीन वरिष्ठ निदेशक (लोक नीति और विनियमन), आईएफएसी ने 1-2 जून, 2018 के दौरान क्रमशः दिल्ली और मुंबई का, भारत में डब्ल्यूसीओ 2022 की मेजबानी के स्थल को देखने और उसका निरीक्षण करने के लिए दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन-सह-कंवेन्शन केंद्र (आईईसीसी) के प्रस्तावित स्थल का भी दौरा किया था और उन्होंने श्री अरविन्द केजरीवाल, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, श्री इंजेती श्रीनिवास, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और श्री अर्जुन राम मेघावल, संघ के तत्कालीन संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री से भी मुलाकात की थी।
- 2 जून, 2018 को इस प्रतिनिधि मंडल ने धीरूभाई अंबानी अंतर्राष्ट्रीय कंवेन्शन और प्रदर्शन केंद्र (डीआईसीसी) (जिओ वर्ल्ड सेंटर), जो भारत में आईएफएसी द्वारा दूसरे संभावित आयोजन स्थल के रूप में सूचीबद्ध है, का भी दौरा किया था। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधि मंडल ने श्री विनोद तावडे, माननीय शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, श्री मुकेश अंबानी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का भी दौरा किया था।

- आईएफएसी की तत्कालीन अध्यक्ष सुश्री रेचल ग्रिम्स, 1 जुलाई, 2018 को आईसीएआई के प्लेटिनम जयंती समारोह में सम्मानित अतिथि थी, जिसका उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने औपचारिक रूप से यह घोषणा की थी कि डब्ल्यूसीओ, 2022 की मेजबानी आईसीएआई द्वारा मुंबई, भारत में की जाएगी।
- सीपीए आस्ट्रेलिया से एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सुश्री डेबोरा ल्यूम, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मार्क चाऊ, प्रादेशिक महाप्रबंधक कारबार विकास और श्री लेस्ली लियु, प्रादेशिक प्रबंधक एमईएसए ने 30 अप्रैल, 2019 को आईसीएआई के प्रधान कार्यालय का दौरा किया था, जिसके दौरान आईसीएआई और सीपीए आस्ट्रेलिया के बीच परस्पर मान्यता प्रदान करने संबंधी करार (एमआरए) के, जो सितंबर, 2019 में समाप्त हो रहा है, नवीकरण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। दोनों संस्थानों ने परस्पर सहयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में भी परिचर्चा की थी।
- डा. इन की जू, अध्यक्ष, आईएफएसी और श्री रसेल गुथ्री, सीएफओ और कार्यपालक निदेशक, आईएफएसी ने 1 जुलाई, 2019 को आईसीएआई प्लेटिनम जयंती समारोह में भाग लेने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था। इस समारोह का उद्घाटन श्री एम. वैकेया नायडू, भारत के माननीय उप राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान मुंबई, भारत में डब्ल्यूसीओ 2022 के सफलतापूर्वक आयोजन के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया था।

(V) सम्मेलन/कार्यक्रम

- आईसीएआई और सीपीए आस्ट्रेलिया ने, एमआरए के माध्यम से सीपीए आस्ट्रेलिया की परीक्षाओं को अर्हित करने के पश्चात् आस्ट्रेलिया में उपलब्ध अवसरों के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए जून, 2018, सितंबर, 2018 और जून, 2019 के दौरान टियर 1 और टियर 2 नगरों में संयुक्त रूप से कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया था।
- आईसीएआई ने 10 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में एशिया और प्रशांत अकाउंटेंटों के कन्फेडरेशन (कापा) की पब्लिक सेक्टर वित्तीय प्रबंध समिति (पीएसएफएमसी) के साथ एक बैठक का आयोजन किया था। कापा पीएसएफएमसी बैठक के साथ-साथ आईसीएआई ने, 11 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर वित्त प्रबंध के संबंध में आईसीएआई-कापा संयुक्त गोलमेज पणधारी बैठक का भी आयोजन किया था। इस परिचर्चा का उद्देश्य भारत में पब्लिक सेक्टर वित्त प्रबंध का एक संक्षिप्त पर्यावलोकन और पब्लिक सेक्टर में वित्त प्रबंध में सुधार करने में लेखांकन वृत्ति की भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना था। 15 देशों से आए प्रतिनिधियों ने इस आयोजन में भाग लिया था। श्री शशिकांत शर्मा, भारत के पूर्व नियंत्रक लेखापरीक्षक ने इस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर उसकी शोभा बढ़ाई थी।
- पणधारियों की इस बैठक में सीजीए, सीएंडएजी, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, डाक विभाग से 60 से अधिक वरिष्ठ पदधारियों और दिल्ली के भिन्न-भिन्न नगर निगमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- आईसीएआई ने 12 और 13 अप्रैल, 2018 के दौरान होटल ताज महल पैलेस, मुंबई में लेखांकन मानक निर्धारकों के अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफएएसएस) की एक दो दिवसीय बैठक की मेजबानी की थी, जहां लेखांकन मानकों के क्षेत्र में उभरते प्रतिमान के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। लेखांकन मानक निर्धारकों के अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफएएसएस) (जो पूर्व में राष्ट्रीय मानक निर्धारक, एनएसएस के रूप में ज्ञात था), पूरे विश्व के राष्ट्रीय लेखांकन मानक निर्धारकों का एक समूह है, जिसमें अन्य ऐसे संगठनों को भी सम्मिलित किया गया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों में गहन रूप से संलग्न हैं। आईएएसबी की उपाध्यक्ष सुश्री सू लॉयड और आईएफएएसएस के अध्यक्ष सुश्री लीजल नोर ने 25 से अधिक देशों से आए प्रतिनिधियों और साथ ही विश्व के विभिन्न अन्य लेखांकन निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के साथ इस बैठक में भाग लिया था। श्री विनोद राय, भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और आईएफआरएस के संस्थापक न्यासी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।

(VI) अविकसित देशों को तकनीकी सहायता

- आईसीएआई ने आईसीएएन को, उसकी परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी, जिसके संबंध में आईसीएएन के अधिकारियों ने 8 अप्रैल, 2019 को भारतीय परीक्षा प्रणाली का परिशीलन करने और

परीक्षाओं के सुचारु संचालन/प्रवाह से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार-विमर्श करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था।

- आईसीएआई और सीपीएपीएनजी एक द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं और उसके अनुसरण में आईसीएआई को सीपीएपीएनजी से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वह उनके सीपीए माड्यूल के लिए पाठ्यक्रम संबंधी पाठ्यचर्या में सुधार करे। आईसीएआई ने उनके माड्यूलों में सुधार करने के लिए एक मूल्यांकन/अध्ययन आरंभ किया है। आईसीएआई ने सीपीएपीएनजी की आईएफएसी की पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने में भी सहायता की है।
- आईसीएआई और नेशनल बोर्ड आफ अकाउंटेंट्स एंड आडिटर्स (एनबीएए), तंजानिया के बीच समझौता ज्ञापन – आईसीएआई ने तारीख 18 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् तारीख 6 सितंबर, 2018 को नेशनल बोर्ड आफ अकाउंटेंट्स एंड आडिटर्स (एनबीएए), तंजानिया के साथ एक तकनीकी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। यह एमओयू सदस्य प्रबंध, वृत्तिक आचार, तकनीकी अनुसंधान, सतत वृत्तिक विकास, वृत्तिक लेखांकन प्रशिक्षण, संपरीक्षा क्वालिटी मानीटरी, लेखांकन ज्ञान की अभिवृद्धि, वृत्तिक और बौद्धिक विकास के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है।
- आईसीएआई और इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आफ केनिया के बीच समझौता ज्ञापन – आईसीएआई और इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आफ केनिया ने 21 जनवरी, 2019 को संयुक्त अनुसंधान, क्वालिटी संबंधी समर्थन, सामर्थ्य और सक्षमता निर्माण, प्रशिक्षु अकाउंटेंट आदान-प्रदान कार्यक्रमों और सतत वृत्तिक विकास संबंधी पाठ्यक्रमों, ज्ञान के आदान-प्रदान संबंधी कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करके ज्ञान के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग और सहायता को स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
- आईसीएआई और बहराइन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (बीआईबीएफ), बहराइन के बीच समझौता ज्ञापन – आईसीएआई ने बहराइन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (बीआईबीएफ), बहराइन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 18 जुलाई, 2018 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 30 जुलाई, 2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता ज्ञापन बहराइन के भीतर लेखांकन, वित्तीय और संपरीक्षा आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए एक साथ कार्य करने से संबंधित है। चूंकि, बहराइन में कोई स्थानीय वृत्तिक लेखांकन संस्थान नहीं है और आईसीएआई बीआईबीएफ के साथ सहयोग कर रहा है, इसके परिणामस्वरूप यह संभावना है कि बहराइन में वर्तमान में कार्य करने वाले भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों की एक सकारात्मक छवि का निर्माण हो और ऐसे व्यक्तियों को, जो बहराइन जाने का आशय रखते हैं, वहां स्थानांतरित होने में सुगमता होगी।
- आईसीएआई और साऊदी आर्गेनाइजेशन फार सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एसओसीपीए) के बीच समझौता ज्ञापन - श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 4 जुलाई, 2018 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 2014 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया था और साथ ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और साऊदी अरब के साऊदी आर्गेनाइजेशन फार सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एसओसीपीए) के बीच इस समझौता ज्ञापन के नवीकरण के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह समझौता ज्ञापन निगम शासन, तकनीकी अनुसंधान और सलाह, क्वालिटी आश्वासन, फॉरेंसिक लेखांकन, लघु और मध्यम आकार के व्यवसायियों (एसएमपी) संबंधी मुद्दों, इस्लामी वित्त पोषण, सतत वृत्तिक विकास (सीपीडी) और लेखांकन वृत्ति से संबंधित परस्पर हित के अन्य विषयों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के ढांचे का संवर्धन करने की परिकल्पना करता है।
- सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आफ अफगानिस्तान (सीपीए अफगानिस्तान) के साथ समझौता ज्ञापन किए जाने हेतु संघ के मंत्रिमंडल का अनुमोदन - श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 24 अक्तूबर, 2018 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आफ अफगानिस्तान (सीपीए अफगानिस्तान) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह समझौता ज्ञापन “अफगानिस्तान लेखांकन बोर्ड (एएबी)” की सक्षमता निर्माण, अफगानिस्तान में आईटी सक्षमता और क्वालिटी आश्वासन को सुदृढ़ करने के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग हेतु ढांचे की स्थापना करेगा।

(VII) रचना खंडों के लिए कार्यकरण

- वैश्विक ई किटों का पुनरीक्षण : आईसीएआई के पास 34 विदेशी चैप्टर हैं, जो भारतीय सीए के ब्रांड को, समान प्रकार की अर्हता रखने वाले देशों में संवर्धित करते हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैरियर संवर्धन हेतु मार्ग प्रशस्त करते हैं। आईसीएआई ने अनेक ऐसे देशों में, जहां उसके चैप्टर विद्यमान हैं, अपने सदस्यों के फायदे के लिए वैश्विक कैरियर ई-किटों को आरंभ किया। इन वैश्विक कैरियर ई किटों में अधिकारिता संबंधी साधारण जानकारी सम्मिलित होती है, जैसे कि भौगोलिक ब्यौरे, आर्थिक परिस्थितियां, उपयोगी कारबार संबंधी जानकारी, वीजा अध्यपेक्षाएं आदि। इसके अतिरिक्त, उपयोगी जानकारी जैसे कि स्थानीय चैप्टर के संपर्क के ब्यौरे, एमओयू/एमआरए और एफएक्यू को भी विदेशों में स्थित सदस्यों हेतु इन ई-किटों में सम्मिलित किया जाता है। इन किटों से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे सदस्यों को ऐसी विदेशी अधिकारिताओं में आने वाले समय में सेवा संबंधी एक आरंभिक अंतःपृष्ठ स्थापित करने में सहायता करेंगी। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आईसीएआई के 14 चैप्टरों को सम्मिलित करने वाली 11 ई किटों को गहन रूप से पुनरीक्षित किया गया था और अद्यतन बनाया गया था।
- आईसीएआई का प्रथम विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम : आईसीएआई की सीए सेवाओं के निर्यात और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति (सीईएस एंड डब्ल्यूटीओ), कारबार और उद्योग में लगे वृत्तिक अकाउंटेंटों संबंधी समिति (सीपीएवीआई) और अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति ने एकसाथ मिलकर 14-16 सितंबर, 2018 के दौरान पूरे भारत में स्थित विभिन्न केंद्रों पर संस्थान के सर्वप्रथम विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु सहयोग किया था। इस नियोजन अभियान की प्रमुख विशिष्टि यह है कि वह न केवल नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए उपलब्ध था, अपितु उसमें अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट भी भाग ले सकते थे। 6400 से अधिक सदस्यों ने उक्त विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम हेतु स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किया था।

7.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करने के लिए भारत के नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन जानकारी तक पहुंच में समर्थ बनाने हेतु सूचना का अधिकार उपलब्ध कराया था। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), जो संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में परिकल्पित किए गए अनुसार एक लोक प्राधिकारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केन्द्रीय सूचना आयोग के निदेश के अनुपालन में इस लोक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्रकटन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटन किए गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट www.icai.org पर रखा गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 761 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका उत्तर दिया गया था।

7.7 एक्सबीआरएल

विनियामकों, तकनीकी व्यक्तियों, निगमों और शिक्षाविदों को भारत में एक्सबीआरएल के संवर्धन हेतु संस्थान के प्रयासों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, संस्थान ने एक्सबीआरएल इंडिया के एक धारा 25 की कंपनी के रूप में निगमन को सुकर बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रानिक कारबार रिपोर्टिंग के मानक के रूप में एक्सबीआरएल के अपनाए जाने का संवर्धन और प्रोत्साहन करना है, यह कार्य वर्गीकरणों के विकास, एक्सबीआरएल संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण को सुकर बनाकर पूरा किया जाता है। इसके साथ ही, वैश्विक रूप से एक्सबीआरएल की बढ़ती महत्ता को ध्यान में रखते हुए, एक्सबीआरएल इंडिया ने वैश्विक रूप से एक्सबीआरएल फाइलिंग को सुकर बनाने तथा उसके संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु एक्सबीआरएल इंटरनेशनल इंक की सदस्यता प्राप्त की है। वर्तमान, में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), क्रमशः “विनियामकों और स्टॉक एक्सचेंजों” और “विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं” के प्रवर्ग के अधीन एक्सबीआरएल के सदस्य हैं।

एक्सबीआरएल इंडिया कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के लिए एक्सबीआरएल वर्गीकरणों का विकास और अनुरक्षण कर रहा है। एक्सबीआरएल इंडिया ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए दो वर्गीकरणों को विकसित किया है, प्रथम लेखांकन मानकों का अनुसरण करने वाली कंपनियों हेतु वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण है तथा अन्य इंड एस का अनुसरण करने वाली कंपनियों के लिए इंड एस वर्गीकरण है। एक्सबीआरएल इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मार्गदर्शन और समर्थन के माध्यम से इंड एस वर्गीकरण को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय विवरणों की एक्सबीआरएल फाइलिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

(I) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग संबंधी अपेक्षाएं

- इंड एस वर्गीकरण में संशोधन : निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए इंड एस वर्गीकरण का संशोधन किया गया है :
 - वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, नए राजस्व मानकों, अर्थात् इंड एस 115, 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' के कार्यान्वयन और इंड एस 11 और इंड एस 18 को वापस लिए जाने,
 - अन्य इंड एस अर्थात् इंड एस 7, 'नकद प्रवाह का विवरण' में संशोधन
 - इंड एस का अनुपालन करने वाली अनुसूची 3 में संशोधन
 - कारपोरेट कार्य मंत्रालय विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं
- आईसीएआई की परिषद् और एक्सबीआरएल इंडिया की वर्गीकरण, विकास और पुनर्विलोकन समिति द्वारा यथा अनुमोदित पुनरीक्षित इंड एस एक्सबीआरएल वर्गीकरण को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।
- कंपनियों के चुने हुए वर्ग द्वारा वित्तीय विवरणों की वार्षिक फाइलिंग हेतु वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण : लेखांकन मानकों में किए गए नवीनतम संशोधनों के अनुसार हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण, 2016 का संशोधन किया गया है और एक्सबीआरएल फाइलिंग हेतु उसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को प्रस्तुत किया गया है। यह अद्यतन वर्गीकरण कंपनियों के चुने हुए वर्ग द्वारा वित्तीय विवरणों की एक्सबीआरएल फाइलिंग हेतु उपलब्ध होगा।

7.8 आईसीएआई – एआरएफ

लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 है) के अधीन जनवरी, 1999 में लेखांकन, संपरीक्षा, पूंजी बाजारों, राजकोषीय और धनीय नीतियों के क्षेत्रों में मूल अनुसंधान करने के लिए आईसीएआई द्वारा स्थापित किया गया था। गत वर्ष के दौरान, आईसीएआई एआरएफ द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

- भारतीय रेल – वर्ष के दौरान आईसीएआई एआरएफ द्वारा, “सभी ज़ोनल रेलों, उत्पादन इकाइयों और भारतीय रेल के अन्य कार्यालयों में प्रोदभवन लेखांकन को लागू करने” की परियोजना का निष्पादन करते समय, आईसीएआई एआरएफ ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए भारतीय रेल और साथ ही 17 ज़ोनल रेल और 8 उत्पादन इकाइयों के प्रोदभवन आधारित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया था। लेखांकन सुधार संबंधी दल, क्रिस और रेल बोर्ड के विभिन्न पदधारियों के साथ अनेक चरणों में विचार-विमर्श करने के पश्चात् अंतिम रूप प्रदान किए गए वित्त संहिता – 2 की कार्ययोजना संबंधी अवधारणा पत्रों को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वयं संव्यवहार स्तर पर प्रोदभवन आधारित लेखांकन को सुकर बनाने हेतु 2 दृष्टिकोणों का प्रस्ताव किया गया था, जो प्रोदभवन लेखांकन से भिन्न विद्यमान प्रणाली की अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा।
- आईसीएआई एआरएफ ने भारतीय रेल – रेल मंत्रालय, भारत सरकार के लिए सेवानिवृत्ति फायदा निधि की योजना और उसके लेखांकन संबंधी अवधारणा पत्र को प्रस्तुत किया था।
- तमिलनाडु सिविल आपूर्ति निगम : आईसीएआई एआरएफ ने इस परियोजना को पूरा किया था और तमिलनाडु सिविल आपूर्ति निगम के लिए एक संपूर्ण आईटी समर्थ प्रबंध सूचना प्रणाली को सम्मिलित करते हुए एकीकृत लेखांकन प्रणाली के विकास संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

- भारतीय समर्पित माल भाड़ा कारीडोर निगम लिमिटेड : आईसीएआई एआरएफ ने, संविदाकारों को कीमत में अंतर के संदाय के लिए डब्ल्यूपीआई (शृंखला – 2004-05) को डब्ल्यूपीआई (शृंखला 2011-12) के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए पद्धति का सुझाव देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

7.9 आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सृजित एक धारा 8 प्राइवेट कंपनी है, जिसका गठन कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसरण में और उससे आनुषंगिक कृत्यों को करने के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों या मूल्यांकक सदस्यों को उसके सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए किया गया था।

(I) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटें), जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए पूर्व शर्त है :

- आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन ने अपने प्रारंभिक चरण में अपनी सदस्यता के आधार को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया था और इसके साथ ही अपने मूल्यांकक सदस्यों के लिए एक 50 घंटें के शैक्षिक पाठ्यक्रम का संचालन भी किया था, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए एक पूर्व शर्त है तथा संगठन ने शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री को भी तैयार किया था।
- इस दिशा में, जून, 2018 से, आईसीएआई आरवीओ ने देश भर में 50 घंटें के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के 30 बैचों का संचालन किया है।
- अगस्त, 2019 तक आईसीएआई आरवीओ द्वारा उसके 50 घंटें के शैक्षिक पाठ्यक्रम के अधीन 2000 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

(II) आस्ति वर्ग की प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के लिए आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण :

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने आस्ति वर्ग की प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के लिए 31 जुलाई, 2019 तक 662 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण किया है, जिनमें से 396 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक आईसीएआई आरवीओ के सदस्य हैं, जो कुल सदस्यों का लगभग 59% है।

(III) आईसीएआई आरवीओ द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन माड्यूल

ऐसे सदस्यों की सहायता करने के लिए, जो आईसीएआई आरवीओ में इस शैक्षिक पाठ्यक्रम हेतु नामांकन करते हैं, इस विषय के संबंध में बेहतर समझ बनाने के लिए इस शैक्षिक पाठ्यक्रम के 4 अध्ययन माड्यूलों को तैयार किया गया है :

- माड्यूल 1, जो व्यौरवार रूप से मूल्यांकन के पर्यावलोकन और उसकी अवधारणाओं को सम्मिलित करता है।
- माड्यूल 2, जो व्यौरवार रूप से मूल्यांकन संबंधी दृष्टिकोणों और पद्धतियों को सम्मिलित करता है।
- माड्यूल 3, जो न्यायिक उदघोषणाओं को सम्मिलित करता है।
- माड्यूल 4, जो पाठ्यचर्या के अनुसार सुसंगत विधियों और विनियमों को सम्मिलित करता है।

(IV) आईसीएआई आरवीओ द्वारा आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 का अपनाया जाना

आईसीएआई ने अपने मूल्यांकन मानक बोर्ड के माध्यम से आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को तैयार किया है, जो भारत में अपनी किस्म के पहले मानक हैं। आईसीएआई आरवीओ ने कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 8 के अधीन आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अंगीकृत किया है। आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 ऐसे सदस्यों के लिए आज्ञापक है, जिन्होंने स्वयं को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आईसीएआई आरवीओ के साथ नामांकित किया है और वे उस समय तक आज्ञापक बने रहेंगे जब तक कि उक्त नियमों के अनुसार सरकार द्वारा मूल्यांकन मानक जारी नहीं कर दिए जाते। आईसीएआई के ये मानक अन्य कानूनों के अधीन मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु सिफारिशात्मक हैं।

(V) आईसीएआई आरबीओ पठन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ

आईसीएआई आरबीओ ने अपनी पठन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किया है, जो एक ई-पठन मंच है, जो ऐसी अध्ययन सामग्री के रूप में, जो बहु विकल्प वाले प्रश्नोत्तरों को अंतर्विष्ट करने वाली मोक परीक्षा द्वारा सम्पूरित है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विहित पाठ्यचर्या की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करती है। यह पठन प्रबंध प्रणाली ऐसे सदस्यों हेतु, जो आईसीएआई आरबीओ के प्राथमिक सदस्य हैं, आईबीबीआई मूल्यांकक परीक्षा की तैयारी को सुकर बनाती है।

(VI) प्रकाशन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन ने आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :

- मूल्यांकन : वृत्तिक अंतःदृष्टि (शृंखला I, II और III)
- मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड
- मूल्यांकन संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

7.10 आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान

आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई), जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का एक पूर्ण स्वामित्व वाला समनुषंगी है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सृजित एक धारा 8 पब्लिक कंपनी है, जिसका गठन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और उससे संबद्ध विनियमों और कृत्यों के अनुसरण में उसके सदस्यों को नामांकित करने और दिवाला वृत्तिकों का विनियमन करने हेतु किया गया है।

इसे संघ के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा 28 नवंबर, 2016 को दिल्ली में भारत के प्रथम दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। आईआईआईपीआई ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, जिनके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखापाल, अधिवक्ता और प्रबंध संबंधी वृत्तिक भी हैं, सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल 2698 दिवाला वृत्तिकों में से 1679 वृत्तिक आईआईआईपीआई से संबंधित हैं।

सदस्यता अभियान

निम्नलिखित का आईपीए	कुल रजिस्ट्रीकरण (31 मार्च तक)*							
	वि.वर्ष 17	%	वि.वर्ष 18	%	वि.वर्ष 19	%	कुल मार्च, 19 तक	%
आईसीएआई	33	34.4	1067	62.2	418	64.5	1518	61.7
आईसीएसआई	51	53.1	511	29.8	176	27.2	738	30.0
आईसीडब्ल्यूआई	12	12.5	138	8.0	54	8.3	204	8.3
योग	96	100.0	1716	100.0	648	100.0	2460	100.0

* स्रोत : आईबीबीआई डाटा

आईआईआईपीआई के प्रचालनों के प्रारंभिक चरण में सदस्यता आधार को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तथापि, सदस्यता आधार को सुदृढ़ बनाए जाने के पश्चात् क्रियाकलापों को और अधिक व्यापक बनाया गया है।

पहलें

- **विश्व बैंक समूह के साथ सहयोग** – आईआईआईपीआई ने विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) के सहयोग से संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु एक ठहराव किया है।
- **विश्व बैंक समूह के साथ प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यक्रम** – आईबीबीआई के साथ ज्ञान के प्रसार संबंधी एक गहन पहल की गई थी, जिसमें आईबीसी, विनियमों, सीमापार दिवाला और व्यष्टिक दिवाले से संबंधित ज्ञान को दिवाला वृत्तिकों के साथ साझा करने हेतु तीन बैचों का आयोजन किया गया था।

- **सीआईआई के साथ सहयोग** – सीआईआई, डेलो लाइट और एजेडबी पार्टनर्स के सहयोग से मार्च, 2019 से दिल्ली में एक आईबीसी संबंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- **आईएमसी और बीएसई के साथ सहयोग** – आईबीसी – चुनौतियों, अवसरों, पठन और आगे की योजना संबंधी विषय पर आईएमसी और बीएसई के साथ सहयोग से मुंबई में एक संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।
- **पूर्व रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम** – आईआईआईपीआई ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान देश भर में स्थित भिन्न-भिन्न केंद्रों में 16 पूर्व रजिस्ट्रीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया था। आईआईआईपीआई ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में अभी तक ऐसे 4 कार्यक्रमों को पूरा कर लिया है।
- **आईआईआईपीआई द्वारा गोलमेज बैठकों का आयोजन** – सीआईआरपी और परिसमापन की संभाव्य कार्यान्वयन योग्य संभावनाओं का पुनर्विलोकन और उन पर विचार करने के लिए मुंबई, कोलकाता, बंगलौर और दिल्ली में गोलमेज बैठकों का आयोजन, जिससे आईबीबीआई में उपांतरणों हेतु उपयुक्त सुझावों और सिफारिशों को प्राप्त किया जा सके।
- **आईआईआईपीआई द्वारा दिवाला वृत्तिकों के लिए अध्ययन समूह संबंधी बैठकें** – आईआईआईपीआई ने दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चिंताओं का समाधान करने के लिए दिवाला वृत्तिकों संबंधी अध्ययन समूहों की विभिन्न बैठकों में भाग लिया था।
- **आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान की पठन प्रबंध प्रणाली** – आईआईआईपीआई ने आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से आईपी बनने हेतु उत्तीर्ण की जाने वाली सीमित दिवाला परीक्षा के लिए तैयारी करने हेतु वृत्तिकों को समर्थ बनाने के लिए एक पठन प्रबंध प्रणाली को तैयार किया है।
- **आईआईआईपीआई साप्ताहिक न्यूज़ लैटर** – आईआईआईपीआई के साप्ताहिक न्यूज़ लैटर, जो दिवाला वृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और आयोजनों के व्यौरे प्रदान करता है, को वेबसाइट पर नियमित रूप से रखा जा रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** – राष्ट्रीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता परिषद्, एसोचैम भारत, एसआईपीआई, आईएनएसओएल भारत, एडल्वाइज और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग, एएंडएम के सहयोग से “नई निगम दिवाला व्यवस्था” संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- **एसोचैम, पीएचडी चैम्बर्स और आईआईआरसी के साथ सहयोग** – एसोचैम, पीएचडी चैम्बर्स और आईआईआरसी के सहयोग से व्यापक रूप से संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था और इन संगोष्ठियों में आईबीसी से संबंधित भिन्न-भिन्न पहलुओं तथा प्रचालनात्मक तथ्यों और उनकी समझ संबंधी विषयों को सम्मिलित किया गया था।
- **आईपी सभा** – 26 मई, 2018 को मुंबई में आईआईआईपीआई द्वारा आईबीबीआई के सहयोग से दिवाला वृत्तिक सभा का आयोजन किया गया था।
- **बीएफएसआई सेक्टर कौशल परिषद् और एनएसडीसी के साथ सहयोग** – आईआईआईपीआई ने (क) सभी रजिस्ट्रीकृत दिवाला वृत्तिकों (आईपी) हेतु एक दिवसीय कौशल वर्धन कार्यक्रम का संचालन करने, और (ख) आईपी हेतु समर्थन सेवा के रूप में “दिवाला सहबद्ध पाठ्यक्रम” का शुभारंभ करने के लिए बीएफएसआई सेक्टर कौशल परिषद् और एनएसडीसी के साथ सहयोग किया था।
- **वेबीनार और वेब सम्मेलन** – दूरस्थ स्थानों में अवस्थित आईपी के ज्ञान वर्धन हेतु और उन्हें नवीनतम संशोधनों, अधिसूचनाओं या परिपत्रों या आईबीसी के संदर्भ में प्रक्रिया में परिवर्तनों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए बार-बार वेबीनारों और वेब सम्मेलनों की व्यवस्था की गई थी और इसके लिए एक परस्पर क्रियाशील अंतःपृष्ठ को तैयार किया गया था, जिससे समुचित रूप से परस्पर सूचना का आदान-प्रदान करके उनकी शंकाओं का समाधान किया जा सके।
- **आईबीबीआई के सहयोग से कार्यशालाएं** – आईआईआईपीआई, अखिल भारत में आईपी के लिए आईबीबीआई के सहयोग से कार्यशालाओं और अग्रिम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
- **आईपी के लिए प्रस्तावित निरीक्षण मैनुअल संबंधी कार्यशाला** – इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था तथा मैनुअल और

निरीक्षण हांचे के प्रारूप प्ररूप को आईबीबीआई को प्रस्तुत किया गया था ।

- **आनलाइन उपयोगिताएं** – आईआईआईपीआई ने अपनी वेबसाइट www.iiipicai.in पर विभिन्न आनलाइन उपयोगिता कृत्यों को विकसित किया है, जिससे दिवाला और परिसमापन संबंधी समनुदेशनों की प्रास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :

- लोक उदघोषणाओं को अपलोड करना
- नातेदारी संबंधी प्रकटनों को फाइल करना
- फीस और सीआईआरपी तथा परिसमापन में उपगत अन्य व्यय के व्यौरों को अपलोड करना
- आईआईआईपीआई ने नामांकन आवेदन प्ररूप को आनलाइन बनाया था
- आईआईआईपीआई के सदस्यों द्वारा आनलाइन रूप से सभी प्रकार की फीसों के संदाय को सुकर बनाने के लिए संदाय पटल को विकसित किया था ।
- आईआईआईपीआई एक एकीकृत ईआरपी पैकेज को विकसित करने के लिए कार्यवाही कर रहा है, जो उसके सदस्यों के लिए एकल पटल प्रसुविधा होगी ।

8. अन्य मामले

8.1 आईसीएआई द्वारा अपने प्लेटिनम जयंती वार्षिक समारोह का मनाया जाना, स्वयं को राष्ट्र की सेवा हेतु समर्पित करना

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने 4 फरवरी, 2019 को होटल द अशोक, नई दिल्ली में अपने प्लेटिनम जयंती वार्षिक समारोह का आयोजन किया था । यह ऐसा समय था, जब संस्थान ने न केवल पीछे मुड़कर परिषद् वर्ष 2018-19 में अपनी उपलब्धियों और प्राप्त किए गए मील के पथरों को स्मरण कर गर्व का अनुभव किया था अपितु उसने एक स्वर्णिम भविष्य का भी स्वप्न देखा था । इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी आफ इंडिया) श्री राजीव महर्षि ने आईसीएआई और भारतीय सीए को राष्ट्र और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अस्तित्वों के रूप में घोषित किया था । इस अवसर पर, ऐसे केंद्रीय परिषद् सदस्यों, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, को सम्मानित किया गया था और योग्य सीए छात्रों और उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं और विदेशी चैप्टरों को भी उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया था । यह संस्थान का एक ऐसा महान प्लेटिनम जयंती वार्षिक समारोह था, जिसमें 1400 से अधिक पणधारियों ने भाग लिया था और इस समारोह में आईसीएआई के अनेक प्रकाशनों का भी विमोचन किया गया था ।

8.2 प्लेटिनम जयंती चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए दिवस) 1 जुलाई, 2019

इस वर्ष, 1 जुलाई के समारोह विशेष थे, क्योंकि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने अपना प्लेटिनम जयंती सीए दिवस मनाया था । इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वैकेया नायडु ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में समारोह का शुभारंभ किया था । माननीय उप राष्ट्रपति ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों को परिवर्तन लाने वाले अभिकर्ताओं के रूप में संबोधित करते हुए यह कथन किया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वृत्ति के विवेक के रक्षक भी हैं क्योंकि वे ही यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके ग्राहक ईमानदारी से अपने करों का संदाय करें । कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव, श्री इनजेती श्रीनिवास और आईएफएसी के अध्यक्ष डा. इन की जू ने भी विशेष अतिथि के रूप में इस समारोह में भाग लिया था । इससे पूर्व आईएफएसी के अध्यक्ष ने प्लेटिनम जयंती सीए दिवस के औपचारिक शुभारंभ के कुछ घंटों पूर्व उसी स्थल पर आयोजित एक तकनीकी सत्र में भाग लिया था, जिसके दौरान उन्होंने सदस्यों के ज्ञान आधार को अद्यतन बनाया था । वस्तुतः, ये समारोह उस दिन प्रातः ही संस्थान के मुख्यालय में आईसीएआई के झंडे को फहराए जाने के साथ ही आरंभ हो गए थे ।

पूर्व व्यवहार के अनुसार, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के पीआर समूहों द्वारा अग्रेषित संसूचनाओं के आधार पर देश भर से सदस्यों/छात्रों/पदधारियों ने एक होकर इस गौरवान्वित अवसर को सफल बनाने हेतु प्रयास किए थे । इस अवसर पर अनेक सामाजिक क्रियाकलाप और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था ।

8.3 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

संस्थान का केंद्रीय परिषद पुस्तकालय उसके पणधारियों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है । इसका उद्देश्य, आईसीएआई के वर्तमान और भावी सदस्यों/छात्रों, अनुसंधान अध्येताओं और पदधारियों को प्रारंभिक और द्वितीय मुद्रण और गैर-मुद्रण सामग्रियों का

व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय ने समितियों, विभागों में जानकारी प्रदान करने और मूल्यवान सूचना का प्रसार करने के वृहत्तर उत्तरदायित्व को ग्रहण किया है। यह इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पुस्तकों, ई-पुस्तकों, जर्नलों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन डाटाबेसों, मुद्रित समाचारपत्रों और साथ ई-समाचारपत्रों के माध्यम से करता है। केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय विभिन्न समितियों के कार्य के लिए अपेक्षित जर्नलों और पुस्तकों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है।

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है और वह लिबर्टी-एक पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है। पुस्तकालय की सामग्रियों, जिनके अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटा बेस भी है, के लिए विषय, लेखक, शीर्षक, टापिक, कुंजी शब्द और प्रकाशक के माध्यम से खोज की जा सकती है। ये अभिलेख पुस्तकालय में इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस www.ica.org पर "नो युअर इंस्टीट्यूट सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी" पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑनलाइन सर्च ओपीएसी लिबर्टी के अधीन उपलब्ध है।

संस्थान के जर्नल के स्तंभ "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" के अधीन लेखांकन वृत्ति से सुसंगत लेखों की अनुक्रमणिका को प्रत्येक मास प्रकाशित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" पूर्ववर्ती लेखों के अभिलेखागार के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की एक अनुक्रमणिका है। निर्देश सेवा विभिन्न शोधकर्ताओं और विद्वानों, संकाय और छात्रों तथा सदस्यों को प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑन लाईन डाटाबेस भी अर्जित किए गए हैं जिनके ब्यौरे www.ica.org—Central Council Library पर उपलब्ध हैं। पुस्तकालय ने इन आनलाइन ज्ञान डाटाबेसों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों तथा साथ ही आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों के पुस्तकालयों में भी छात्रों, सदस्यों, संकाय और अनुसंधान अध्येताओं के लिए अपेक्षित सामग्री की सर्च को सुकर बनाने के लिए आनलाइन रूप से प्रतिष्ठापित किया है। पुस्तकालय द्वारा अनेक आनलाइन जर्नलों की ग्राहकी भी प्राप्त की गई है। केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय के क्रमशः प्रधान कार्यालय और नोएडा कार्यालय में स्थित पुस्तकालयों में 1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 की अवधि के दौरान जोड़े गए नए संसाधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय (मुख्यालय)

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	37
2.	ग्राहकी प्राप्त किए गए जर्नलों तक ई-पहुंच	7
3.	आनलाइन संसाधन	13
4.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या	643

केंद्रीय परिषद् लाइब्रेरी, सेक्टर 62 नोएडा

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	28
2.	आनलाइन संसाधन	08
3.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या	109

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय नियमित रूप से अपने संसाधनों को अद्यतन बना रहा है ताकि वृत्तिक सदस्यों, छात्रों, संकायों और अन्य पणधारियों को नवीनतम और अद्यतन जानकारी और सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

8.4 संपादक बोर्ड

संपादक बोर्ड भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की एक गैर-स्थायी समिति है जिसका उद्देश्य सदस्यों को नियमित रूप से वृत्तिक ज्ञान, वृत्ति से हितबद्ध अन्य विषयों पर एक संरचित रीति में "दि चार्टर्ड अकाउंटेंट" जर्नल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है। जर्नल की पहुंच और प्रभाव का अनुमान इसके परिचालन से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो आज के दिन 3,00,000 से अधिक है।

यह आईसीएआई का 'ब्रांड अम्बेसेडर' है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज द चार्टर्ड अकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर आईसीएआई के सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों की विभिन्न विषयों और मुद्दों पर जानकारी को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादक बोर्ड निरंतर प्रयासरत है।

आईसीएआई केरल बाढ़ राहत निधि : संस्थान ने, विनाशकारी केरल बाढ़ के पीड़ितों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि को 73,33,927 रुपए का योगदान दिया था।

1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 की अवधि के दौरान संपादक बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी संबंधी पहलें

संपादक बोर्ड ने अपने मासिक जर्नल, द चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ ही अन्य माध्यमों से ज्ञान का उन्नयन और प्रसार करके राष्ट्र निर्माण में भागीदारी संबंधी अनेक पहलों को आरंभ किया है। इस संबंध में, की गई महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :-

(II) राष्ट्रीय/वृत्तिक हित के प्रकाशन :

आईसीएआई के जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट में विभिन्न सरकारी अंगों, आईसीएआई की समितियों, लेखक सदस्यों और अन्य पणधारियों के सहयोग से राष्ट्रीय-वृत्तिक-आर्थिक हित से संबंधित 300 लेखों/फीचरों का प्रकाशन किया गया था।

(III) 'आई गो ग्रीन विद आईसीएआई' पहल

- माइक्रो साइट : आईसीएआई के बहु आयामी हरित अभियान के भागरूप में, हरित क्रांति की सोच रखने वाले सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को हाल ही में एक विकल्प प्रदान किया गया था, जिसके अधीन वे वृक्षों को बचाने के लिए जर्नल की हार्ड प्रति को न लेकर जर्नल के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पाठों का विकल्प ले सकते थे। इस संबंध में प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए एक माइक्रो वेबसाइट को भी स्थापित किया गया था।
- जर्नल की हार्ड प्रति को प्राप्त न करने का विकल्प लेने वाले सदस्यों के लिए ग्रीन छूट : 1 अप्रैल, 2019 से आईसीएआई के ऐसे सदस्यों को, जो जर्नल की हार्ड प्रति को प्राप्त न करने का विकल्प लेते हैं, सदस्यता फीस में 500 रुपए की छूट का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक 25000 से अधिक सदस्यों ने इस विकल्प को चुना है।

(IV) सदस्यों/छात्रों के लिए पहलें

संपादक बोर्ड, अपने मासिक जर्नल, द चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से सदस्यों/छात्रों के ज्ञानवर्धन और वृत्तिक विकास के लिए पहलें करने में सदैव सक्रिय रहा है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :

(V) द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में क्वालिटी और समकालीन अंतर्वस्तु :

- विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित किया जाना : अप्रैल, 2018 से जुलाई, 2019 तक के जर्नल के अंकों में विभिन्न नवीन और समकालीन मुद्दों के अधीन 300 से अधिक लेख/फीचर और विभिन्न विषयों पर रिपोर्टों का प्रकाशन किया गया था।
- नए फीचरों 'अवर अचीवर' और 'वाट द लीजेंड्स सेड' का आरंभ किया जाना : जर्नल के मार्च, 2018 के अंक से 'अवर अचीवर' शीर्षक वाले एक नए फीचर को आरंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत ख्याति प्राप्त आईसीएआई के ऐसे सदस्यों के साक्षात्कारों का प्रकाशन किया जाता है, जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को प्राप्त किया है। मार्च, 2019 के अंक से एक अन्य नए फीचर 'वाट द लीजेंड्स सेड' को आरंभ किया गया था, जिसके अधीन पूर्व अध्यक्षों के सुसंगत कोटों को प्रकाशित किया गया था।
- नए फीचर 'इंड एएस अलर्ट' का आरंभ किया जाना : जर्नल के नवंबर, 2018 के अंक से नए फीचर 'इंड एएस अलर्ट' को आरंभ किया गया था, जिससे सदस्यों/पाठकों को भारतीय लेखांकन मानकों के संबंध में नवीनतम घटनाओं की अद्यतन जानकारी प्रदान की जा सके।

- **जुलाई, 2018 और जुलाई, 2019 के आईसीएआई के जर्नल के अंकों को कलेक्टर्स संस्करणों के रूप में निकाला जाना :** सीए दिवस और आईसीएआई द्वारा उसके प्लेटिनम जयंती वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष में जुलाई, 2018 अंक और प्लेटिनम जयंती सीए दिवस के उपलक्ष्य में जुलाई, 2019 के अंक को कलेक्टर्स संस्करण के रूप में निकाला गया था।

(VI) सदस्यों और छात्रों की सुविधा हेतु द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अंकीय पाठों के अनेक रूपों का उन्नयन

- **ई-जर्नल :** द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल, जो कि इस जर्नल का इलैक्ट्रॉनिक पाठ है, आईसीएआई की वेबसाइट www.icaai.org पर आनलाइन रूप से एक उच्च प्रौद्योगिकी और उपयोक्ता मित्र ई-पत्रिका के रूप में उपलब्ध है, जो और अधिक समुन्नत किया गया था। ई-जर्नल का अद्यतन पाठ, पूर्ववर्ती पाठ की तुलना में तीव्र तथा अधिक क्रियाशील है, जिससे एक बेहतर उपयोक्ता अनुभव प्राप्त होता है तथा यह और अधिक बेहतर मोबाइल अनुरूपता प्रस्थापित करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों की नई पीढ़ी की अपेक्षाओं के अनुरूप है।
- **पीडीएफ प्ररूप में जर्नल :** तथापि, पाठकों के लिए और अधिक तथा वैकल्पिक सुविधाओं को आरंभ करने, विशिष्ट रूप से अंतर्वस्तु-वार पृथक् डाउनलोड के लिए जर्नल को पीडीएफ प्ररूप में वेबसाइट पर रखा जाना और साथ ही इसके लिए अनुक्रमणिका पद्धति को अपनाए जाने को जारी रखा गया है। अंकीय जर्नल के जुलाई, 2002 के आगे से पिछले सार संग्रह आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- **मोबाइल पर जर्नल :** इसके अतिरिक्त, यह ई-जर्नल अब मोबाइल पर भी उपलब्ध है तथा यह आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) और एंड्रयाड युक्तियों के समनुरूप है। इस जर्नल तक पहुंच को <http://www.icaai.org/> के अधीन 'ई-जर्नल' टैब पर सुकर बनाया जा सकता है। यह ई-जर्नल आईसीएआई मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
- **जर्नल हाईलाईट ईमेलर्स :** एक अतिरिक्त सेवा के रूप में जर्नल के प्रत्येक अंक की विशिष्टियों को संक्षिप्त रूप में तथा जर्नल में सम्मिलित अध्यक्ष के संदेश को सभी सदस्यों को ई-मेल किया जाता है।
- **वर्ष 1952 से सभी जर्नलों की डीवीडी :** चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के सभी पाठकों को एकल बिन्दु संदर्भिका उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में तथा उनकी बेहतर रूप से सेवा करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के विचार से, जर्नल के सभी पूर्व अंकों की एक डीवीडी भी पाठकों और अन्य पणधारियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। यद्यपि, दस वर्ष के जर्नलों (जुलाई, 2002 – जून, 2012) की एक डीवीडी पीडीएफ प्ररूप में न्यूनतम लागत पर पाठकों के लिए निकाली गई थी, अभी हाल ही में एक एचटीएमएल कृत डीवीडी, जिसमें द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के 63 वर्षों के सभी अंक (जुलाई, 1952 से जून, 2015) अंतर्विष्ट हैं, भी जारी की गई है। इस एचटीएमएल – पाठ डीवीडी में खोज पद्धति समाविष्ट है, जिससे पाठक अंतर्वस्तु को लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान आदि जैसे कुंजी शब्दों और साथ ही मास, वर्ष, जिल्द, प्रवर्ग (जैसे कि परिपत्र और अधिसूचना, आईसीएआई समाचार, विश्विक निर्णय आदि), लेखक आदि के माध्यम से खोज सकेंगे।

8.5 त्रिवर्षीय चुनाव - ICAI की परिषद / क्षेत्रीय परिषदें

24 वीं परिषद और 23 वीं क्षेत्रीय परिषदों के लिए 2019-22 के लिए त्रिवर्षीय चुनाव दिसंबर, 2018 में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। पहली बार, मतों की गिनती विकेन्द्रीकृत की गई और प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्रों पर अलग-अलग शुरू हुई।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 9,505 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था, जिससे 1 अप्रैल, 2019 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 2,91,698 हो गई है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, पूर्व वर्ष के 3367 के आंकड़ों की संख्या की तुलना में 6752 सहयोजित सदस्यों को प्रविष्ट किया गया था।

1 अप्रैल, 2019 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता	सहयोजित	स्तंभ (1) और (2) का योग
पूर्णकालिक व्यवसाय में	83272	55602	138874
अंशकालिक व्यवसाय में	3558	8278	11836

जो व्यवसाय में नहीं हैं	12011	128977	140988
योग	98841	192857	291698

9.2 दीक्षांत समारोह

संस्थान, नवम्बर, 2008 से अपने नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। पांचों प्रादेशिक कार्यालयों के अधीन निम्नलिखित नौ स्थानों पर दिसंबर, 2018 से अप्रैल, 2019 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए नए नामांकित सदस्यों के लिए "दीक्षांत समारोह 2019" के पहले चरण को 30-31 अगस्त और 1 सितंबर, 2019 के दौरान आयोजित किया गया था :

1. अहमदाबाद	6. कोलकाता
2. मुंबई	7. जयपुर
3. पुणे	8. कानपुर
4. चैन्नई	9. नई दिल्ली
5. हैदराबाद	

9.3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरण पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की उभरती अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31 मार्च, 2018 को कुल आजीवन सदस्य	1,34,596
2.	31 मार्च, 2019 को कुल आजीवन सदस्य	1,36,137
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2019 को यथाविद्यमान)	1,541

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे

	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)	31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)
1. दी गई कुल वित्तीय सहायता	1,12,70,000	92,10,500
2. प्रशासनिक खर्चे	2,014	1,000
3. वर्ष के दौरान निधि में अधिशेष	1,24,95,000	2,04,80,000
4. निधि का अतिशेष	4,93,29,000	3,68,34,000
5. कोरपस का अतिशेष	20,63,28,000	19,86,23,000

9.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

निधि की आजीवन सदस्यता संबंधी आंकड़ों को तैयार किया जा रहा है। निधि के पास 31 मार्च, 2018 को 47,97,000 रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2019 को 52,97,000/- रुपए है।

9.5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ)

आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी। वर्ष 2018-19 के लिए 1073 ऐसे आर्टिकलड सहायकों, जो आईपीसीसी और आईआईपीसीसी के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं, को वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपए प्रति मास की दर पर और 256 ऐसे आर्टिकलड सहायकों, जो फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत

हैं, को वित्तीय सहायता के रूप में 2000 रुपए प्रति मास की दर पर सहायता उपलब्ध कराई गई थी। 31 मार्च, 2018 को 13,91,82,000/- रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2019 को 14,31,53,000/- रुपए साधारण निधि में अतिशेष के रूप में जमा थे।

01.04.2019 को सदस्यों संबंधी आंकड़े

अध्येता :	पूर्णकालिक व्यवसाय में	83272
	अंशकालिक व्यवसाय में	3558
	जो व्यवसाय में नहीं हैं	12011
		98841
सहयोजित :	पूर्णकालिक व्यवसाय में	55602
	अंशकालिक व्यवसाय में	8278
	जो व्यवसाय में नहीं हैं	128977
		192857
कुल सदस्यता :		291698

	अध्येता				सहयोजित				
	व्यवसाय में				व्यवसाय में				
क्षेत्र	पूर्णकालिक	अंशकालिक	जो व्यवसाय में नहीं हैं	योग	पूर्णकालिक	अंशकालिक	जो व्यवसाय में नहीं हैं	योग	कुल योग
पश्चिमी	24186	1075	3486	28747	19691	3256	49349	72296	101043
दक्षिणी	17715	893	2829	21437	8536	1707	24109	34352	55789
पूर्वी	7961	272	1185	9418	4014	528	11005	15547	24965
मध्य	16264	458	1615	18337	11779	1073	20670	33522	51859
उत्तरी	17140	859	2896	20895	11575	1710	23844	37129	58024
योग	83272	3558	12011	98841	55602	8278	128977	192857	291698

10. अध्ययन बोर्ड :

संस्थान का अध्ययन बोर्ड (बीओएस), चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यचर्या के प्रशासन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक अनुदेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस अवधि के दौरान बोर्ड की महत्वपूर्ण पहलों और उपलब्धियों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

(I) शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम :

अध्ययन सामग्री : शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के अधीन सभी विषयों, जिनके अंतर्गत वैकल्पिक विषय भी हैं, के लिए अध्ययन सामग्रियों का मुद्रण किया गया था और उन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। चुने गए विषयों की अध्ययन सामग्रियों के पुनरीक्षित संस्करणों को इस वर्ष जारी किया गया था और साथ ही उन्हें बीओएस ज्ञान पोर्टल पर भी रखा गया था।

अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर और मामला अध्ययन : छात्रों को, उनकी आगामी परीक्षाओं हेतु तैयारी करने में सहायता करने के लिए मूल प्रश्न-

पत्रों के लिए प्रश्नों और वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों के लिए मामला अध्ययनों को भी आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

पुनरीक्षण प्रश्न-पत्र : शिक्षा की पुरानी और नई स्कीम के अंतर्गत सभी प्रश्न-पत्रों के लिए पुनरीक्षण प्रश्न-पत्रों को बीओएस ज्ञान पोर्टल पर अपलोड किया गया है और छात्रों की सुविधा के लिए उन्हें मुद्रित भी किया गया है।

एमसीक्यू आधारित निर्धारण : छात्रों के विक्षेपणात्मक और व्यापक कौशल को और अधिक विकसित करने के लिए और साथ ही परीक्षा में उनके प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ निर्धारण करने हेतु, आईसीएआई ने एक निर्धारण प्रणाली को आरंभ किया है, जिसमें किसी चुने गए प्रश्न-पत्र की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 30 प्रतिशत प्रश्न बहु विकल्पों पर आधारित प्रश्न होंगे, जो एक और दो अंकों के होंगे। यह प्रणाली मई, 2019 की परीक्षाओं से, मध्यवर्ती और फाइनल, दोनों प्रकार के स्तरों पर शिक्षा और प्रशिक्षण की पुरानी और नई दोनों स्कीमों के अधीन स्थापित की गई थी।

मध्यवर्ती (नया पाठ्यक्रम)		आईआईपीसीसी (पुराना पाठ्यक्रम)	
प्रश्नपत्र	विषय	प्रश्नपत्र	विषय
2	निगम और अन्य विधियां	2	कारबार विधियां, आचार और संसूचना
4	कराधान	4	कराधान
6	संपरीक्षा और आश्वासन	6	संपरीक्षा और आश्वासन
7	उद्यम सूचना प्रणाली और रणनीतिगत प्रबंध	7	उद्यम सूचना प्रणाली और रणनीतिगत प्रबंध

फाइनल (नया पाठ्यक्रम)		फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम)	
प्रश्नपत्र	विषय	प्रश्नपत्र	विषय
3	अग्रिम संपरीक्षा और वृत्तिक आचार	3	अग्रिम संपरीक्षा और वृत्तिक आचार
4	निगम और आर्थिक विधियां	4	निगम और आर्थिक विधियां
		6	सूचना प्रणाली नियंत्रण और संपरीक्षा
7	प्रत्यक्ष कर विधि और अंतर्राष्ट्रीय कराधान	7	प्रत्यक्ष कर विधियां
8	अप्रत्यक्ष कर विधियां	8	अप्रत्यक्ष कर विधियां

चुने हुए विषयों में 30 : 70 निर्धारण के लिए एमसीक्यू की वेब होस्टिंग :

एमसीक्यू आधारित वस्तुनिष्ठ निर्धारण (30 अंक) को मध्यवर्ती/आईआईपीसीसी और फाइनल (पुराने) तथा (नए) पाठ्यक्रम के चुने गए विषयों हेतु मई, 2019 की परीक्षाओं से आरंभ किया गया है। तदनुसार, इन विषयों में से प्रत्येक के संबंध में एमसीक्यू को बीओएस ज्ञान पोर्टल पर रखा गया था।

बीओएस ज्ञान पोर्टल पर खंडवार और कौशलवार अधिमानता को रखा जाना

आईआईपीसीसी और फाइनल स्तरों के शिक्षा और प्रशिक्षण की पुरानी स्कीम के अधीन विषयों के लिए खंडवार और कौशलवार अधिमानता, जो मई, 2019 की परीक्षाओं से लागू की गई थी, को बीओएस ज्ञान पोर्टल पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त, शिक्षा और प्रशिक्षण की पुरानी स्कीम के अधीन मध्यवर्ती और फाइनल स्तरों के कतिपय विषयों के लिए खंडवार और कौशलवार अधिमानता, जिसे मई, 2019 की परीक्षाओं से आंशिक वस्तुनिष्ठ प्रकार के निर्धारण के संबंध में आरंभ किया गया है, को पुनरीक्षित किया गया था और पुनरीक्षित अधिमानताओं को बीओएस ज्ञान पोर्टल पर रखा गया था।

ओपन हाऊस प्रश्नोत्तर सत्र

मध्यवर्ती और फाइनल के सभी विषयों (वैकल्पिक विषयों सहित) के लिए ओपन हाऊस प्रश्नोत्तर सत्रों का आयोजन आईआईपीसीसी, मध्यवर्ती, फाइनल (पुराने) और फाइनल (नए) के सभी छात्रों के लिए किया गया था। इन सत्रों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया गया है और उन्हें साधारण रूप से छात्रों के फायदे के लिए बीओएस ज्ञान पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

छात्रों को छात्रवृत्तियां मंजूर करना

अध्ययन बोर्ड वर्ष में दो बार विभिन्न प्रवर्गों अर्थात् मेरिट, मेरिट-सह-आवश्यकता आधारित, आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्गों, वृत्ति दान के अधीन छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान अध्ययन बोर्ड ने उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन चुने गए छात्रों को 1646 छात्रवृत्तियां प्रदान की थी।

(II) व्यवहारिक प्रशिक्षण के निर्धारण के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा

आईसीएआई ने हाल ही में, व्यवहारिक प्रशिक्षण के पहले और दूसरे वर्ष के पूरा हो जाने के पश्चात् छात्रों के लिए आनलाइन एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं का आयोजन करना आरंभ किया है। अभी तक, 23 सितंबर, 21 अक्तूबर, 2 दिसंबर, 30 दिसंबर, 2018, 3 फरवरी, 10 मार्च, 21 अप्रैल और 7 जुलाई, 2019 को ऐसी 7 परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिनमें दोनों स्तरों पर लगभग 80,000 छात्र उपस्थित हुए थे। इन परीक्षाओं का प्रयोजन, प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे वर्ष को पूरा करने वाले छात्रों के बीच गंभीरता का सृजन करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि छात्रों को पठन के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन परीक्षाओं में प्राप्त किए गए ग्रेडों के औसत को छात्र की अंतिम अंक-सूची में उपदर्शित किया जाएगा। छात्र 200 रुपए की फीस का संदाय करके अपने ग्रेडों में सुधार लाने के लिए समान स्तर की परीक्षा में दो बार और बैठ सकते हैं।

(III) लाइव वर्चुअल कक्षाएं

अध्ययन बोर्ड (बीओएस), आईसीएआई ने अगस्त, 2018 में एक अग्रणी परियोजना के रूप में मध्यवर्ती और फाइनल स्तरों के लिए लाइव वर्चुअल कक्षाओं (एलवीसी) को आरंभ किया था। इन कक्षाओं की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

- लाइव व्याख्यान
- कंप्यूटरों और मोबाइल पर उपलब्ध
- रिकार्ड किए गए व्याख्यानों की उपलब्धता
- आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से युक्त स्मार्ट कक्षाएं
- समृद्ध अनुभव वाला विशेषज्ञ संकाय
- लाइव कक्षाओं के दौरान प्रश्न पूछने की सुविधा के साथ परस्पर क्रियाशील कक्षाएं
- परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला दृष्टिकोण
- मामला अध्ययन आधारित वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों के संबंध में पृथक् सत्र
- पृथक् प्रश्नोत्तर सत्र
- कार्यपालन का पुनर्विलोकन करने के लिए आवधिक परीक्षाएं
- संपूर्ण पाठ्यचर्या को सम्मिलित किया जाना
- इन कक्षाओं का आयोजन सप्ताह दिवसों के दौरान कार्य घंटों से परे प्रातः और सायंकाल के दौरान किया गया था (प्रातः 7 से 9.30 बजे) (सायं: 6 से 8.30 बजे)
- लगभग 500 छात्रों ने एलवीसी का फायदा प्राप्त किया था।

नवंबर, 2019 (इंटर) और मई, 2020 (फाइनल) परीक्षाओं के लक्षित लाइव कक्षाओं को क्रमशः 4000 रुपए और 4750 रुपए की सस्ती फीस के साथ आरंभ किया गया है।

(IV) प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं और छात्रों के साथ मासिक परस्पर क्रियाएं

वेबकास्ट के माध्यम से प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं और छात्रों के साथ बीओएस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा निदेशक की मासिक परस्पर क्रियाओं को आरंभ किया गया है, जिससे इस संबंध को सुदृढ़ बनाया जा सके। बीओएस ने विभिन्न शैक्षिक और बीओएस की अन्य पहलों से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का संकलन किया है और उन्हें संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया है।

(V) सोशल मीडिया साइटों के माध्यम से छात्र कनेक्ट

अध्ययन बोर्ड ने संस्थान के फेसबुक पृष्ठ में सुधार किया है और इसे छात्रों के लिए और अधिक सूचना प्रदान करने वाला बनाया गया है, जिससे छात्रों के साथ बेहतर रूप से जुड़ा जा सके, जैसे कि,--

- संस्थान के संबंध में महत्वपूर्ण समाचारों और उद्घोषणाओं तथा उसके क्रियाकलापों की इस चैनल के माध्यम से संसूचना दी जा सके।
- छात्रों के संपर्क में रहा जा सके तथा उन्हें नियोजित और प्रेरित किया जा सके।

- अनेक प्रकार के मुद्दों के संबंध में परिचर्चाओं और वाद-विवाद के लिए छात्रों के एक समुदाय का सृजन किया जा सके।
- छात्रों को दैनिक आधार पर थीम आधारित अंतर्वस्तु (पाठ, चित्र, वीडियो आदि) उपलब्ध कराई जा सके, जिससे उनमें दिलचस्पी का सृजन हो तथा उन्हें सुसंगत जानकारी उपलब्ध हो सके।

(VI) बीओएस : एकल संदर्भिका

बीओएस : एकल संदर्भिका नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन प्रदेशों, शाखाओं, सदस्यों और छात्रों तथा पणधारियों के फायदे के लिए किया गया है। इस पुस्तिका में बीओएस की पहलों और क्रियाकलापों के संबंध में ब्यौरेवार जानकारी और साथ ही क्रियाकलापों के संबंध में कार्यवाही करने वाले संबद्ध पणधारियों के संपर्क ब्यौरे भी अंतर्विष्ट हैं।

(VII) जीएसटी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

बीओएस ने, अप्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से 14 जुलाई से 12 अगस्त, 2018 की अवधि के दौरान 30 घंटे के एक सप्ताहांत जीएसटी संबंधी वर्चुअल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 3000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था।

(VIII) छात्र सम्मेलन संरचना का पूर्ण सुधार करना

बोर्ड ने, छात्र सम्मेलनों की कार्यक्रम संरचना की रूपरेखा को पुनः संरचित किया है, जिससे कि न केवल ऐसे छात्र, जो मंच पर मौजूद हैं, अपितु ऐसे छात्र भी, जो श्रोताओं के रूप में उपस्थित हैं, उसमें भागीदारी कर सकें।

(IX) बीओएस की छात्र समर्थन संबंधी पहल के भागरूप में छात्रों के लिए निःशुल्क सहायता टेलीफोन नंबर

बीओएस, नोएडा में स्थापित निःशुल्क टेलीफोन सहायता नंबर 18001211330 मई, 2017 से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अप्रैल, 2018 और जून, 2019 के बीच देश भर से 72,000 से अधिक छात्रों ने इस सेवा का लाभ उठाया है।

(X) वर्चुअल प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम

ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने 2002 (नवंबर के पश्चात्) से 2018 तक सीए फाइनल को अर्हित किया है किंतु संस्थान की सदस्यता हेतु आवेदन नहीं किया है, 4 फरवरी, 2019 से वर्चुअल प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम (एमसीएस) को आरंभ किया गया है।

ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने सीए फाइनल को अर्हित किया है किंतु संस्थान की सदस्यता हेतु आवेदन नहीं किया है, अब, वर्चुअल प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम को वर्चुअल पद्धति से उत्तीर्ण करके संस्थान की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थी किसी भी समय और कहीं से भी यह पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। 90 घंटे के इस वर्चुअल एमसीएस पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् वे संस्थान की सदस्यता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(XI) वर्चुअल प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम की विशिष्टियां

- इसमें कोई कक्षा अध्यापन सम्मिलित नहीं है। छात्र आनलाइन पद्धति से इस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। इस वर्चुअल एमसीएस पाठ्यक्रम की अवधि 90 घंटे है।
- इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किसी छात्र को अधिकतम 180 दिन की अवधि अनुज्ञात है। उस दशा में, जहां कोई छात्र पूर्वोक्त अवधि के दौरान पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थ रहा है, छात्र को 90 दिन की अवधि का और विस्तारण किया जाएगा। छात्र को पूर्वोक्त पाठ्यक्रम संबंधी रजिस्ट्रीकरण के पुनः विधिमन्यकरण हेतु पाठ्यक्रम फीस के 50 प्रतिशत का संदाय करना होगा।
- एक पृथक् पोर्टल/पठन प्रबंध प्रणाली (एलएमएस) विद्यमान है, जहां छात्र रजिस्टर कर सकते हैं और इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं।
- छात्र दैनिक रूप से सत्रों को देखने में समर्थ होंगे।
- प्रत्येक सत्र के अंत में, एक वस्तुनिष्ठ किस्म की आनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। छात्र द्वारा सभी परीक्षाओं को

उत्तीर्ण करने के पश्चात् उसे प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उस दशा में, जहां छात्र आनलाइन परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहा है वहां छात्र उस परीक्षा में पुनः बैठेगा।

(XII) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के साथ कार्यक्रम

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

परस्पर सहयोग के भागरूप में आईआईएम वल्लपुर, अहमदाबाद में 24-28 दिसंबर, 2018 के दौरान "चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अग्रिम नेतृत्व संबंधी कार्यक्रम" नामक एक पांच दिवसीय आवासीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नए परिप्रेक्ष्यों, आयामों और रणनीतियों के संबंध में विचार करने का एक अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपने संगठनों को उनके उद्देश्यों की ओर अग्रसर कर सकें। यह कार्यक्रम, उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों में नेतृत्व संबंधी कौशलों का संचार करेगा, जैसे कि स्पष्टता, बातचीत, विरोध का समाधान, दल का निर्माण और परिवर्तन प्रबंध।

(XIII) छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल

अध्ययन बोर्ड ने, अपने छात्रों को, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न छात्र संबंधी कार्यक्रमों हेतु कहीं से भी और किसी भी समय स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करने में सहायता करने हेतु एक छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल को विकसित किया है। छात्र इस पोर्टल पर समय-समय पर लॉगिन करके छात्र संगोष्ठियों, छात्र सम्मेलनों, मोक परीक्षाओं, कार्यशालाओं, सीए छात्रों के लिए विशेष परामर्शी कार्यक्रमों, सीए छात्रों में योग्यता की खोज, सीए छात्र समारोह, खेल-कूद प्रतियोगिताओं आदि जैसे आयोजनों के लिए स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कर सकते हैं।

यह पोर्टल कार्यक्रम आयोजक इकाईयों और अध्ययन बोर्ड के स्तर पर छात्र क्रियाकलापों के प्रणालीगत प्रबंध में सहायता करता है।

(XIV) आर्टिकल नियोजन पोर्टल

आर्टिकलशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण नियोजन पोर्टल – यह सदस्यों, संगठनों और छात्रों के लिए एक-दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने और सदस्यों/संगठनों को दिलचस्पी रखने वाले छात्रों की खोज करने, उन्हें सूचीबद्ध करने तथा उनके साथ साक्षात्कारों का समय तय करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक सामान्य मंच है। छात्र स्थान और क्षेत्रों से संबंधित अपनी अधिमानताओं को उपदर्शित करते हुए रिक्तियों की खोज/उनके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यह पोर्टल उपयोक्ता मित्र है और यह सदस्यों/उद्योगों तथा आर्टिकलशिप/औद्योगिक प्रशिक्षण की वांछा करने वाले छात्रों के बीच दूरी को कम करने में सहायता करेगा।

(XV) पठन कक्ष पोर्टल

देश भर में सीए छात्रों को उनके पठन हेतु अनुकूल प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए 174 पुस्तकालय/पठन कक्ष/अतिरिक्त पठन कक्ष कार्य कर रहे हैं। छात्र अपने उपयोक्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करते हुए इस पठन कक्ष पोर्टल पर लागिन कर सकते हैं तथा किसी भी समय और कहीं से भी स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। पठन कक्ष पोर्टल की अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

- मासिक फीस का अग्रिम में संदाय करके अपने लिए स्थान सुरक्षित करना
- छात्रों द्वारा एकदिवस/एक मास के लिए नमनीय रजिस्ट्रीकरण
- 20 रुपए प्रति दिवस की निम्न फीस
- 24X7 आनलाइन सेवाओं का उपलब्ध होना
- संदाय के 24 घंटों के भीतर स्थान की पुष्टि
- रजिस्टर करने हेतु छात्रों की सहायता करने हेतु पोर्टल पर ही अद्यतन जानकारी का उपलब्ध होना

(XVI) सीए पाठ्यक्रम के लिए दूरस्थ शिक्षा

छात्रों के लिए ई-पठन पहलें : चार्टर्ड अकाउंटेंटसी पाठ्यक्रम के लिए दूरस्थ शिक्षा को आईसीएआई द्वारा वीडियो व्याख्यानों और ई-पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जो सीए पाठ्यक्रम के तीन स्तरों के लिए आईसीएआई क्लाउड कैम्पस के माध्यम से <http://cloudcampus.icaai.org> पर उपलब्ध हैं। दूरस्थ शिक्षा संबंधी पहल छात्रों को उनकी सुविधानुसार, अर्थात् उनके घर/कार्यालय से किसी भी समय और कहीं से भी पठन करने में समर्थ बनाती है।

वीडियो व्याख्यान : सीए पाठ्यक्रम के सभी स्तरों के सभी विषयों के लिए वीडियो व्याख्यान उपलब्ध कराए गए हैं, जो विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं तथा कदम-दर-कदम व्यावहारिक समस्या समाधान प्रक्रिया को ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं – जो कि एक परीक्षा परिप्रेक्ष्य से प्रमुख कौशल संबंधी अपेक्षा है। वर्तमान में, शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के लिए 590 घंटों के 347 व्याख्यानों और पुरानी स्कीम के लिए 559 घंटों के 664 व्याख्यानों को क्लाउड परिसर पर रख दिया गया है।

डिजिटल पठन केंद्र संबंधी ई-पुस्तकें : शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के सभी विषयों के लिए अध्यायवार ई-पुस्तकें डिजिटल पठन केंद्र के माध्यम से आईसीआईटी क्लाउड कैम्पस पर उपलब्ध हैं। फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए वीडियो व्याख्यानों और स्वनिर्धारण क्विजों को भी इन ई-पुस्तकों में समाविष्ट किया गया है।

(XVII) छात्रों के लिए आयोजित साफ्ट कौशल संबंधी पाठ्यक्रम

1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2019 की अवधि के दौरान प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा छात्रों के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

पाठ्यक्रम	बैचों की संख्या	प्रशिक्षित छात्रों की संख्या
आईसीआईटीएसएस-आईटी	2023	59722
एआईसीआईटीएसएस-अग्रिम आईटी	1762	58709
योग	3785	118431

सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशल संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम (एआईसीआईटीएसएस) के परिणामों की घोषणा की प्रास्थिति – अग्रिम सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परीक्षा। कार्यालय द्वारा पृथक् प्रयासों के पश्चात्, निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई एआईसीआईटीएसएस – अग्रिम आईटी परीक्षा की वर्तमान प्रास्थिति नीचे दी गई है :

क्रम सं.	परीक्षा की तारीख	परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या	परीक्षा अर्हित करने वाले छात्रों की संख्या
1	21 जनवरी, 2018	2,956	2,843
2	18 फरवरी, 2018	5,070	4,890
3	18 मार्च, 2018	5,183	5,121
4	22 अप्रैल, 2018	2,373	2329
5	08 जुलाई, 2018	8,239	8,097
6	19 अगस्त, 2018	6169	5920
7	16 सितंबर, 2018	3336	3213
8	07 अक्तूबर, 2018	2112	2054
9	06 जनवरी, 2019	9969	9330
10	03 मार्च, 2019	10105	9767
11	27 अप्रैल, 2019	11030	10614
12	17 मई, 2019	3573	3436
	योग	70,115	67,614

परिषद् ने 17 दिसंबर, 2018 को आयोजित अपनी 379वीं बैठक में यह विनिश्चय किया था कि साफ्ट कौशल और आईटी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों की उपस्थिति बायोमीट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज की जाएगी।

इसे ध्यान में रखते हुए 18 अवस्थानों पर बायोमीट्रिक मशीनों को प्रतिष्ठापित किया गया है और उन्हें आनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया है।

आईसीआईटीएसएस – अनुकूलन पाठ्यक्रम : प्रादेशिक कार्यालयों/शाखाओं/भारत से बाहर स्थित चैप्टरों द्वारा इस पाठ्यक्रम के 1423 बैचों

का आयोजन किया गया था और 63242 छात्रों ने इस पाठ्यक्रम को पूरा किया है।

एआईसीआईटीएसएस – प्रबंध और संसूचना कौशल संबंधी पाठ्यक्रम : प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं/भारत से बाहर स्थित चैप्टरों द्वारा इस पाठ्यक्रम के 1417 बैचों का आयोजन किया गया था और 64616 छात्रों ने इस पाठ्यक्रम को पूरा किया है।

एमसीएस पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए प्रोत्साहन : एमसीएस पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने और उनके वाक कौशल में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार स्कीम को आरंभ किया गया है। इस स्कीम को बैच के सर्वोत्तम प्रस्तुतीकर्ता का नाम दिया गया है। बैच के प्रत्येक छात्र को सत्र के अंतिम दो से तीन दिनों में अपना प्रस्तुतीकरण करना होता है। सर्वोत्तम प्रस्तुतीकर्ता को एक सराहना पत्र के साथ 1100 रुपए का नकद इनाम प्रदान किया जाता है जबकि दूसरे और तीसरे सर्वोत्तम प्रस्तुतीकर्ता को सराहना पत्र प्रदान किए जाते हैं।

(XVIII) संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीआई ने दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और मुंबई में एआईसीआईटीएसएस (प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम) संबंधी संकाय विकास कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया था, जिसमें 549 संकाय सदस्यों ने भाग लिया था, जो वर्तमान में अध्ययन बोर्ड द्वारा आयोजित एआईसीआईटीएसएस – एमसीएस पाठ्यक्रम की कक्षाएं ले रहे हैं/लेने के इच्छुक हैं। एफडीपी का उद्देश्य, सभी पीओयू के बीच सत्रों के एकसमान परिदान को सुनिश्चित करना तथा उनका मानकीकरण करना है।

(XIX) महत्वपूर्ण घटनाएं

सम्मेलन/सभाएं/संगोष्ठियां और छात्र सम्मेलनों से संबंधित अन्य क्रियाकलाप : राष्ट्रीय सम्मेलन, सीए छात्र सम्मेलन और सीए छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन : 2018-19 की अवधि के दौरान अध्ययन बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित 35 सीए छात्र सम्मेलनों के अलावा जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, कोलकाता, नई दिल्ली और मुंबई में 5 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया था और इसके साथ ही अहमदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इन छात्र सम्मेलनों में लगभग 26,000 छात्रों ने भाग लिया था।

अहमदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन : अध्ययन बोर्ड ने 5 और 6 जनवरी, 2019 के दौरान अहमदाबाद में एक दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन की मेजबानी आईसीआई की डब्ल्यूआईआरसी और डब्ल्यूसीएसए की अहमदाबाद शाखाओं द्वारा की गई थी और यह अत्यधिक सफल सिद्ध हुआ था, जिसमें 3200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का प्रमुख विषय "नैतिक दृष्टिकोण के साथ ज्ञान और प्रशिक्षण – वृत्तिक उत्कृष्टता की ओर प्रस्थान" था। श्री सुरेश पी. प्रभु, संघ के माननीय वाणिज्य और उद्योग और सिविल विमानन मंत्री ने इस कार्यक्रम के उदघाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ाई थी। माननीय न्यायमूर्ति श्री मुकेश कुमार रसिक भाई शाह, भारत का उच्चतम न्यायालय और श्री पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आय-कर अपील अधिकरण (आईटीएटी) इस समारोह के विशेष अतिथि थे। इस कार्यक्रम के उदघाटन सत्र में आईसीआई के माननीय अध्यक्ष सीए नवीन एन.डी. गुप्ता, माननीय उपाध्यक्ष सीए प्रफुल प्रेमसुख छाजेड़, सीए धीनल अश्विनभाई शाह, अध्यक्ष, बीओएस ने अनेक केंद्रीय परिषद सदस्यों के साथ भाग लिया था। इस कार्यक्रम में विदेशी छात्रों द्वारा भी प्रस्तुतीकरण किए गए थे और यह सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा था।

सीए छात्र टैलेंट सर्च, 2018 : अध्ययन बोर्ड ने 28 जून, 2018 को एनडीएमसी कन्वेंशन केंद्र, दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर के "सीए छात्र टैलेंट सर्च" का आयोजन किया था, जिसमें देश भर से आए 69 अंतिम प्रतिस्पर्धियों ने क्विज, वक्तृता, वाद्य संगीत और नुक्कड़ ड्रामा में भाग लिया था। इस आयोजन के दौरान सुश्री रेचल ग्रिम्स, (अध्यक्ष, आईएफएसी) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई थी। आईसीआई के माननीय अध्यक्ष सीए नवीन एन.डी. गुप्ता, माननीय उपाध्यक्ष सीए प्रफुल प्रेमसुख छाजेड़, सीए धीनल अश्विनभाई शाह, अध्यक्ष, बीओएस, सीए विजय कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष, बीओएस, सीए अतुल गुप्ता, केंद्रीय परिषद् के सदस्यों और साफा प्रतिनिधियों ने भी इस आयोजन में भाग लिया था।

वक्तृता प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले छात्रों के वाक कौशल और प्रस्तुतीकरण संबंधी कौशलों में सुधार करने के लिए 27 जून, 2018 को अनुकूलन सत्रों का आयोजन किया गया था। डा. पी.सी. जैन, सरकार के नामनिर्देशिनी, सीए भावना सिंघल, सीए अरुण गर्ग और सीए मनप्रीत सिंह उपरोक्त प्रतिस्पर्धाओं की ज्यूरी के सदस्य थे। यह आयोजन अत्यधिक सफल रहा था और इसके विजेताओं के व्यौरे नीचे दिए गए हैं :

विजेताओं के ब्यौरे			
	प्रथम पुरस्कार विजेता	द्वितीय पुरस्कार विजेता	तृतीय पुरस्कार विजेता
	नाम	नाम	नाम
क्रिज प्रतिस्पर्धा	श्री पलाश महेश्वरी	सुश्री पुष्पा पालीवाल	
	श्री मयूर राजपूत	सुश्री रेवती नायडू	
वक्तृता	सुश्री श्रीनिधि यू	श्री आकाश गंगोपाध्याय	श्री निखिल सचदेवा
वाद्य संगीत	श्री चिराग जैन	श्री अतुल डांग	श्री मुदित भट्टर
नुक़्क़ड़ ड्रामा	श्री निखिल सचदेवा [टीम लीडर]	सुश्री साक्षी प्रजापति [टीम लीडर]	श्री राहुल अग्रवाल [टीम लीडर]
	सुश्री शिवम	सुश्री स्वाति सरथे	श्री पुलकित अग्रवाल
	सुश्री सुरभि गुप्ता	सुश्री परिधि भटनागर	सुश्री दर्शना मालपानी
	सुश्री कुंजम	सुश्री नेहल शर्मा	श्री सुमित गोयल
	श्री पीयूष गोयल	सुश्री शर्मिष्ठा दाना	श्री अमन अग्रवाल
	सुश्री पूर्णिमा बारिक	सुश्री चारु आहूजा	

5 सितंबर, 2018 को शिक्षक दिवस : अध्ययन बोर्ड ने 5 सितंबर, 2018 को अपनी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से देश भर में शिक्षक दिवस संबंधी समारोह का आयोजन किया था, जिससे प्रिंसिपल और उनके आर्टिकलों के बीच एक सुदृढ़ अध्यापक और छात्र संबंध स्थापित हो सके। इस कार्यक्रम के दौरान प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं ने निबंध और कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था।

बोर्ड ने छात्रों के बीच उनके शिक्षकों के प्रति आदर और आभार की भावना का सृजन करने के लिए कुछ ई-कार्डों को छात्रों को उपलब्ध कराया था और आईसीएआई के दिल्ली कार्यालय से प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक एक वेबकास्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें सीए एन.डी. गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और राज्य सभा सदस्य, सीए प्रफुल प्रेमसुख छाजेड, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, डा. पी.सी. जैन, केंद्रीय परिषद् सदस्य, सीए. जवारे शिवाजी भीकाजी, केंद्रीय परिषद् सदस्य ने अपने-अपने संबोधन प्रस्तुत किए थे।

संयुक्त संगोष्ठी

- 6 और 7 अप्रैल, 2018 के दौरान पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी में एक दो दिवसीय संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में वृत्तिक कौशल विकास संबंधी आवासीय कार्यक्रम :

वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के चार बैचों (उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में दो बैचों और उत्कृष्टता केंद्र, जयपुर में दो बैचों) का आयोजन किया गया था, जिनमें 145 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था।

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों द्वारा पीएचडी करने हेतु सीए अर्हता को मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्यवाही करने के पश्चात् अध्ययन बोर्ड 103 विश्वविद्यालयों, 6 आईआईएम और 2 आईआईटी, बंबई और मद्रास, (कुल 111) संस्थाओं से पीएचडी/अध्येता कार्यक्रम करने के प्रयोजन के लिए सीए पाठ्यक्रम की मान्यता अभिप्राप्त करने में सफल रहा था।

11. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्, जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर

और नई दिल्ली में स्थित हैं। इस समय इसके पास पूरे भारत में 164 शाखाएं और भारत से बाहर 34 विदेशी चैप्टर तथा 15 प्रादेशिक पुस्तकालय हैं।

11.1 सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा, सर्वोत्तम छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वोत्तम शाखा के लिए पुरस्कार :

ये पुरस्कार आईसीएआई द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सकल कार्यपालन और स्थापित संनियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2018 के लिए ये शील्डें 4 फरवरी, 2019 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी।

1. सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्

प्रथम पुरस्कार: पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्

दूसरा पुरस्कार: पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्

2. प्रादेशिक परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा :-

1. बृहत्त श्रेणी

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की इंदौर शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की पुणे शाखा

2. बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की बड़ौदा शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एनकुलम शाखा

3. मध्यम शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की औरंगाबाद शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की ईआईआरसी की सिलिगुड़ी शाखा

4. लघु शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की सीआईआरसी की भिलाई शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की सेलम शाखा

5. सूक्ष्म शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की शिवकाशी शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी के तूतीकोरन शाखा

3. सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ

प्रथम पुरस्कार: पश्चिमी भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ

दूसरा पुरस्कार: पूर्वी भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ

4. छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा

क. बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएसए की पुणे शाखा और आईसीएआई की

डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएसए की औरंगाबाद शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी के डब्ल्यूआईसीएसए की बड़ौदा शाखा

ख. मध्यम शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एसआईसीएसए की शिवकाशी शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएसए की नांदेड शाखा

11.2 विकेन्द्रीकृत कार्यालय

आईसीएआई की परिषद् ने, त्वरित और व्यक्तिगत सेवा के मूल्य को मान्यता प्रदान करते हुए, जिन्हें विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, निम्नानुसार रूप से 18 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों की स्थापना की है :

मुंबई	चेन्नई	कोलकाता	कानपुर	नई दिल्ली	अहमदाबाद
बैंगलोर	हैदराबाद	पुणे	जयपुर	नागपुर	सूरत
वदोदरा	ठाणे	एनकुलम	कोयंबटूर	इंदौर	चंडीगढ़

12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2019 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो संपरीक्षकों द्वारा सम्यक्तः संपरीक्षित है, इसमें इसके पश्चात् प्रकाशित किए गए हैं।

13. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे, प्रादेशिक परिषदों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों तथा गैर-सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने वर्ष 2018-19 के दौरान परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में परिषद् की सहायता की, के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2018-2019 के दौरान केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद्, भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वैकेया नायडू, श्री राजीव महर्षि, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, श्री इनजेती श्रीनिवास, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, डा. इन की जू, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन (आईएफएसी) और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, दिल से आभार व्यक्त करती है।

परिषद् राज्य स्तर पर विभिन्न कृत्यकारियों की भी, जिन्होंने आईसीएआई के विभिन्न अंगों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, सराहना करती है।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक पहलों में केन्द्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रुचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

परिषद्, आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2018-2019 के दौरान और उसके पश्चात् उनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी अनुशंसा करती है।

सांख्यिकी एक दृष्टि में
सदस्य रजिस्ट्रीकरण
(1 अप्रैल, 2007 से)

सारणी 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त अध्येता योग	31159 16896 48055	18237 13646 31883	7829 6488 14317	9642 8882 18524	14182 12880 27062	81049 58792 139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त अध्येता योग	32364 17646 50010	19203 14034 33237	7939 6738 14677	10045 9472 19517	14642 13398 28040	84193 61288 145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त अध्येता योग	34294 18442 52736	20666 14516 35182	8193 7002 15195	10578 10007 20585	15951 13951 29902	89682 63918 153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त अध्येता योग	36390 19181 55571	21733 15076 36809	8512 7192 15704	11252 10615 21867	17104 14461 31565	94991 66525 161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त अध्येता योग	38608 19831 58439	22998 15612 38610	9154 7406 16560	12329 11182 23511	18547 14943 33490	101636 68974 170610

1 अप्रैल, 2012	सहयुक्त अध्येता योग	45273 20510 65783	25505 16132 41637	11069 7578 18647	15963 11720 27683	23332 15431 38763	121142 71371 192513
1 अप्रैल, 2013	सहयुक्त अध्येता योग	52846 21522 74368	28020 16918 44938	13258 7815 21073	20606 12327 32933	27743 16051 43794	142473 74633 217106
1 अप्रैल, 2014	सहयुक्त अध्येता योग	56595 22313 78908	29401 17460 46861	14035 8007 22042	22978 12915 35893	29467 16508 45975	152476 77203 229679
1 अप्रैल, 2015	सहयुक्त अध्येता योग	60229 22838 83067	30126 17864 47990	14514 8137 22651	24702 13441 38143	31137 16986 48123	160708 79266 239974
1 अप्रैल, 2016	सहयुक्त अध्येता योग	64235 23700 87935	31919 18495 50414	15046 8223 23269	27353 14071 41424	32774 17521 50295	171327 82010 253337
1 अप्रैल, 2017	सहयुक्त अध्येता योग	67746 25742 93488	33591 19711 53302	15580 8718 24298	30036 15618 45654	34632 18933 53565	181585 88722 270307
1 अप्रैल, 2018	सहयुक्त अध्येता योग	70683 26736 97419	34733 20280 55013	15606 8912 24518	32094 16494 48588	36988 19667 56655	190104 92089 282193
1 अप्रैल, 2019	सहयुक्त अध्येता योग	72296 28747 101043	34352 21437 55789	15547 9418 24965	33522 18337 51859	37129 20895 58024	192857 98841 291698

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

	सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841

1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 को	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 को	1,42,473	74,633	2,17,106
1 अप्रैल, 2014 को	1,52,476	77,203	2,29,679
1 अप्रैल, 2015 को	1,60,708	79,266	2,39,974
1 अप्रैल, 2016 को	1,71,327	82,010	2,53,337
1 अप्रैल, 2017 को	1,81,585	88,722	2,70,307
1 अप्रैल, 2018 को	1,90,104	92,089	2,82,193
1 अप्रैल, 2019 को	1,92,857	98,841	2,91,698

रजिस्ट्रीकृत छात्र

(31 मार्च, 2009 से)

वर्ष के दौरान	नए सीआरईटी के अनुसार फाउंडेशन	फाइनल	नया फाइनल	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी एवं आईआईपी सीसी	मध्यवर्ती	एटीसी	योग
2009-10	-	24,172	-	1,67,073	1,860	80,745	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	57,175	-	1,55,217	329	67,984	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	47,515	-	1,61,712	-	85,053	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	45,102	-	1,61,084	-	1,02,406	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	39,348	-	1,54,742	-	96,285	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	36,950	-	1,41,241	-	66,570	-	881	2,45,642
2015-16	-	31,669	-	1,25,140	-	77,962	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	27,611	-	1,07,392	-	81,886	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	26,291	14,056	73,804	-	22,657	63,693	-	2,10,289
2018-19	45048	-	27,966	-	-	-	53,654	-	126,668

परिषद् की संरचना

परिषद् के सदस्य (2019-20)		
अध्यक्ष	निर्वाचित सदस्य	
सी.ए. प्रफुल प्रेमसुख छाजेड	सी.ए. अनिल सत्यनारायण भंडारी	मुंबई
	सी.ए. जय छैयरा	सूरत
	सी.ए. प्रफुल प्रेमसुख छाजेड	मुंबई
उपाध्यक्ष	सी.ए. चंद्रशेखर वसंत चिताले	पुणे
सी.ए. अतुल कुमार गुप्ता	सी.ए. तरुण जमनादास धिया	मुंबई
	सी.ए. नंदकिशोर चिदम्बर हेगडे	मुंबई
	सी.ए. निहार निरंजन जम्बुसरिया	मुंबई
	सी.ए. श्रीनिवास यशवंत जोशी	मुंबई

अवधि	सीए. दुर्गेश कुमार काबरा	मुंबई
	सीए. धीरज कुमार खंडेलवाल	मुंबई
12 फरवरी, 2019 से आगे	सीए. अनिकेत सुनील तलाती	अहमदाबाद
	सीए. बाबु अब्राहम कल्लीवयालिल	कोच्ची
परिषद् के सचिव	सीए. दयानिवास शर्मा	हैदराबाद
	सीए. प्रसन्ना कुमार डी.	विशाखापट्टनम
श्री राकेश सहगल कार्यकारी सचिव	सीए. राजेन्द्र कुमार पी.	चेन्नई
	सीए. जी. शेखर	चेन्नई
	सीए. एम.पी. विजय कुमार	चेन्नई
	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल	कोलकाता
	सीए. सुशील कुमार गोयल	कोलकाता
	सीए. (डा.) देवाशीष मित्रा	गुवाहाटी
	सीए. मनु अग्रवाल	कानपुर
	सीए. प्रमोद कुमार बूब	जयपुर
	सीए. अनुज गोयल	गाजियाबाद
	सीए. सतीश कुमार गुप्ता	जयपुर
	सीए. प्रकाश शर्मा	जयपुर
	सीए. केमिशा सोनी	इंदौर
	सीए. हंसराज चुघ	नई दिल्ली
	सीए. अतुल कुमार गुप्ता	गुडगांव
	सीए. प्रमोद जैन	नई दिल्ली
	सीए. चरणजोत सिंह नंदा	नई दिल्ली
	सीए. राजेश शर्मा	नई दिल्ली
	सीए. (डा.) संजीव कुमार सिंघल	नई दिल्ली
सरकार के नामनिर्देशिती	श्री अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (12 फरवरी, 2019 से 14 अगस्त, 2019 तक)	नई दिल्ली
	श्री मनोज पांडे, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (14 अगस्त, 2019 से)	नई दिल्ली
	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	नई दिल्ली
	सुश्री रितिका भाटिया, प्रधान निदेशक (वाणिज्य-2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय	नई दिल्ली
	डा. रवि गुप्ता, सहबद्ध प्रोफेसर, श्रीराम कालेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय	नई दिल्ली
	श्री सुनील कनोरिया	नई दिल्ली
	श्री चन्द्र वाधवा	नई दिल्ली
	डा. पी.सी. जैन	नई दिल्ली
	श्री विजय कुमार झालानी	नई दिल्ली

शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

खन्ना एंड अन्नाधानम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

परिषद्, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2019 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संक्षिप्त विवरण को सम्मिलित करने वाले वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणों की संपरीक्षा की है।

हमारी राय में, 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूर्वोक्त वित्तीय विवरण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार सभी सारवान अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, तैयार किए गए हैं और वे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान के मामलों की स्थिति और उसके नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अपनी संपरीक्षा को आईसीएआई द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार पूरा किया है, उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक के उत्तरदायित्वों संबंधी खंड में वर्णित किया गया है। हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी संपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमारी राय का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधमंडल चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अनुसार, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे आंतरिक नियंत्रण आवश्यक हैं, जिन्हें प्रबंधमंडल अवधारित करे, जिससे ऐसे वित्तीय विवरणों के तैयार किए जाने को समर्थ बनाया जा सके, जो सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे किसी कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधमंडल, एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने संबंधी संस्थान के सामर्थ्य का निर्धारण करने, यथा लागू प्रकटन करने, गोईंग कर्न्सन से संबंधित विषयों का निर्धारण करने और लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधमंडल का आशय या तो संस्थान का परिसमापन करना है या उसके प्रचालनों को बंद करना है या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है।

प्रबंधमंडल संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यावलोकन करने के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासनों को प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सकल रूप से सारवान मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण और ऐसी संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट को जारी करना है, जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं करता है कि एसए के अनुसार की गई संपरीक्षा सदैव सारवान कथनों का उस समय पता लगाने में समर्थ होगी, जब वे विद्यमान होते हैं। मिथ्या कथन, कपट या त्रुटि, किसी भी कारण से उद्भूत हो सकते हैं और उन्हें उस समय सारवान समझा जाता है, यदि व्यक्ति रूप से या सकल रूप से उनसे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए जाने वाले उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे।

एसए के अनुसार की जाने वाली संपरीक्षा के भागरूप में, हम अपने वृत्तिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूर्ण संपरीक्षा के दौरान वृत्तिक संदेहों को भी बनाए रखते हैं। हम :

- कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों की पहचान करते हैं और उनसे संबंधी जोखिमों का निर्धारण करते हैं, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में संपरीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को तैयार और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त करते हैं, जो हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी कपट के परिणामस्वरूप होने वाले किसी सारवान मिथ्या कथन की पहचान न करने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप आए सारवान मिथ्या कथन से कहीं अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, अथर्थात् विवरण या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना अंतर्बलित हो सकती है।
- संपरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ को प्राप्त करते हैं, जिससे ऐसी संपरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके, जो मामले की

परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, किंतु जो संस्थान के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता के संबंध में राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं है।

- प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और प्रबंधमंडल द्वारा दिए गए लेखांकन प्राकृत्यों और संबद्ध प्रकटनों के औचित्य का भी मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधमंडल द्वारा लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तथा प्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या किन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है, जो एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने के संस्थान के सामर्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है तो हम से यह अपेक्षा की जाती है कि हम हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को उपांतरित करें। हमारे निष्कर्ष, हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक हमारे द्वारा प्राप्त किए गए संपरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां यह प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं कि संस्थान एक गोईंग कर्न्सन के रूप में अपना कार्यकरण जारी रखना बंद कर दे।

हम ऐसे व्यक्तियों से परस्पर संपर्क करते हैं, जिन्हें अन्य विषयों के साथ संपरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार क्षेत्र, समय और महत्वपूर्ण संपरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित विषयों को शासित करने का प्रभार सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमियां भी हैं, जिनकी हम हमारी संपरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

अन्य विषय

- (क) संस्थान ने भारत में और विदेशों में बड़ी संख्या में चैप्टरों को प्राधिकृत किया है। संस्थान ने हमें यह निवेदन किया है कि चूंकि यह चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं इसलिए उनके लेखाओं को समेकित किया जाना अपेक्षित नहीं है।
- (ख) हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से जात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण कुल 94,467 लाख रुपए की कुल आस्तियों, 18,903 लाख रुपए का कुल राजस्व और 84 लाख रुपए की रकम का शुद्ध नकद प्रवाह/(बर्हिगामी) उपदर्शित करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा अन्य संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधमंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।
- (ग) उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की गई है और प्रबंधमंडल द्वारा उन्हें हमें प्रस्तुत किया गया है और उन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इस शाखा के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन असंपरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधमंडल द्वारा हमें दी गई जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण संस्थान के सकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सारवान नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय और नीचे दी गई विनियामक अपेक्षाओं को, अन्य संपरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टें तथा प्रबंधमंडल द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विश्वास के आधार पर अन्य मामलों के संबंध में उपांतरित नहीं किया गया है।

अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :

- (क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;
- (ख) हमारी राय में, जहां तक लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं से समुचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;
- (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित संस्थान का तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है।

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574डब्ल्यू

ह/

सी.ए. राजीव बसल

भागीदार, सदस्यता सं. 088598

UDIN : 19088598AAAAABR8508

नई दिल्ली

24 सितंबर, 2019

खन्ना एंड अन्नाधानम

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म रजि. सं. 001297एन

ह/

सी.ए. वी.जे. सिंह

भागीदार, सदस्यता सं. 007884

UDIN : 19007884AAAAAD9018

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002
31 मार्च, 2019 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

	विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, को यथा विद्यमान	
			2019	2018
I	निधियों के स्रोत :		(रुपए लाख में)	
	i. अधिशेष और उद्दिष्ट निधियां			
क	आरक्षितियां और अधिशेष	3	127,756	128,239
ख	उद्दिष्ट निधियां	4	68,591	39,370
	ii. गैर चालू दायित्व			
क	अन्य दीर्घकालिक दायित्व	5	1,591	1,219
ख	दीर्घकालिक प्रावधान	6	25,291	22,941
	iii. चालू दायित्व			
क	व्यापार संबंधी देय	7	4,132	3,677
ख	अन्य चालू दायित्व	8	24,042	24,274
ग	अल्पकालिक प्रावधान	6	1,628	1,307
			253,031	221,027
II	निधियों का उपयोग			
	i. गैर चालू आस्तियां			
क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9	61,006	54,363
ख	अमूर्त आस्तियां	10	34	55
ग	चालू पूंजी संकर्म	11	5,555	10,877
घ	गैर-चालू निवेश	12	118,177	76,535
ङ	उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	13	5,176	5,229
च	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	14	3,433	3,397
छ	अन्य गैर चालू आस्तियां	15	330	678
	ii. चालू आस्तियां			
क.	चालू निवेश	12	4,917	2,506
ख.	उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	13	37,992	54,704
ग.	वस्तु-सूचियां	16	479	1,080
घ.	नकद और बैंक अतिशेष	17	8,712	6,824
ङ.	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	14	3,295	2,714
च.	अन्य चालू आस्तियां	15	3,925	2,065
	योग		253,031	221,027

संलग्न टिप्पण 1 से 28 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

ह./-
राकेश सहगल
कार्यकारी सचिव

ह./-
सी.ए. अतुल कुमार गुप्ता
उपाध्यक्ष

ह./-
सी.ए. प्रफुल पी. छाजेड
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

खन्ना एंड अन्नाधानम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म रजि. सं. 109574डब्ल्यू

फर्म रजि. सं. 001297एन

ह/

सीए. राजीव बसल

भागीदार, सदस्यता सं. 088598

नई दिल्ली

24 सितंबर, 2019

ह/

सीए. बी.जे. सिंह

भागीदार, सदस्यता सं. 007884

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

विवरण		टिप्पण सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
			2019	2018
I	आय		(रुपए लाख में)	
	(क) फीस	18	70,467	62,526
	(ख) संगोष्ठियां	19	4,312	5,761
	(ग) अन्य आय	20	14,597	12,322
	कुल आय		89,376	80,609
II	व्यय			
	(क) संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम	21	4,505	6,036
	(ख) कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	22	14,695	16,872
	(ग) मुद्रण और लेखन सामग्री		5,517	5,810
	(घ) परीक्षकों और परामर्शियों को संदत्त वृत्तिक फीस		9,557	8,005
	(ङ) अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	9-10	2,688	2,257
	(च) अन्य व्यय	23	24,075	22,770
	कुल व्यय		61,037	61,750
III	शुद्ध अधिशेष (I-II)		28,339	18,859
IV	निधियों/आरक्षितियों को विनियोग:			
	(क) शिक्षा निधि [टिप्पण 2.6(iii) देखें]		5,818	5,073
	(ख) कर्मचारी कल्याण निधि [टिप्पण 2.6(iv) देखें]		80	78
	(ग) सदस्य कल्याण निधि [टिप्पण 25.24 देखें]		2,138	-
	(घ) उद्दिष्ट निधियां और अन्य निधियां		2,831	2,296
	(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरक्षितियां [टिप्पण 2.6(vii) देखें]		1,780	1,001
	(च) सिंकिंग निधि [टिप्पण 2.6(viii) देखें]		276	-
	(छ) अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए), 2022 [टिप्पण 25.19 देखें]		1,500	-
	(ज) साधारण आरक्षिती		13,916	10,411
	योग		28,339	18,859

संलग्न टिप्पण 1 से 28 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

ह./-
राकेश सहगल
कार्यकारी सचिव

ह./-
सीए. अतुल कुमार गुप्ता
उपाध्यक्ष

ह./-
सीए. प्रफुल पी. छाजेड
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574डब्ल्यू

खन्ना एंड अन्नाधानम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001297एन

ह/
सीए. राजीव वसंत
भागीदार, सदस्यता सं. 088598
नई दिल्ली
24 सितंबर, 2019

ह/
सीए. बी.जे. सिंह
भागीदार, सदस्यता सं. 007884

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

विवरण		31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
		2019	2018
		(रुपए लाख में)	
I.	प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
	पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष	28,339	18,859
	<u>निम्नलिखित के लिए समायोजन :</u>		
	- अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	2,688	2,540
	- ऐसे प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित	(445)	(193)
	- संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	4	229
	- व्याज संबंधी आय	(11,332)	(8,743)
	- सदस्यों से प्रवेश फीस, जिसे सीधे आरक्षिती को आबंटित किया गया है	387	367
	कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	19,641	13,059
	कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन :		
	प्रचालन संबंधी वास्तवों में (वृद्धि/कमी) के लिए समायोजन :		
	- वस्तु सूचियां	601	(79)
	- दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	216	(8)
	- अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(585)	(691)
	प्रचालन संबंधी दायित्वों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
	- अन्य दीर्घकालिक दायित्व	372	488
	- दीर्घकालिक प्रावधान	2,350	6,603
	- व्यापार संबंधी देय	900	679
	- अन्य चालू दायित्व	(218)	4,904
	- अल्पकालिक प्रावधान	321	370
		23,598	25,325
	आय-कर (संदत्त)/प्राप्त (शुद्ध)	(252)	(402)
	प्रचालन क्रियाकलापों से हुई आय (अ)	23,346	24,923

II.	निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
	- गैर-चालू निवेशों का क्रय	(41,642)	(51,904)
	- चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	(2,411)	5,585
	- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संबंधी पूंजी व्यय	(4,273)	(2,104)
	- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विक्रय से आगम	271	(197)
	- उद्दिष्ट और अन्य निधियों में कमी	16,765	14,085
	- प्राप्त व्याज आय	9,820	11,288
	निवेश संबंधी क्रियाकलापों में (प्रयुक्त) नकद (आ)	(21,470)	(23,247)
III.	वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
	- भवन के लिए प्राप्त संदान	-	11
	- प्राप्त अभिदाय	27	83
	- पर्याप्त/(प्रयुक्त) अन्य निधि	(15)	19
	वित्तीय क्रियाकलापों से नकद (इ)	12	113
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)	1,888	1,789
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	6,824	5,035
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	8,712	6,824

संलग्न टिप्पण 1 से 28 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

ह./-
राकेश सहगल
कार्यकारी सचिव

ह./-
सी.ए. अतुल कुमार गुप्ता
उपाध्यक्ष

ह./-
सी.ए. प्रफुल पी. छाजेड
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574-डब्ल्यू

खन्ना एंड अन्नाधानम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001297एन

ह/
सी.ए. राजीव वसंत
भागीदार, सदस्यता सं. 088598
नई दिल्ली
24 सितंबर, 2019

ह/
सी.ए. बी.जे. सिंह
भागीदार, सदस्यता सं. 007884

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान या आईसीएआई") जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने अभी तक मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली प्रत्येक में एक और कुल पांच प्रादेशिक परिषदों, 18 प्रादेशिक कार्यालयों और 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 13 उप विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 164 शाखाओं और दुबई में एक विदेशी कार्यालय का भी गठन किया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

2.1 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण, टिप्पणों के साथ सम्मिलित हैं, संस्थान द्वारा जारी और लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किया जाता है। यहां भारतीय जीएएपी में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक और अन्य उद्घोषणाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन सतत आधार पर तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, सिवाय सेवानिवृत्ति फायदों से संबंधित मामलों के, जहां पूर्व वर्ष तक, भविष्य निधि स्कीम में संस्थान के अभिदाय को एक परिभाषित अभिदाय योजना के रूप में विचार में लिया जाता था और चालू वर्ष में इसे एक परिभाषित फायदा योजना के रूप में विचार में लिया गया है।

2.2 प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंध मंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वर्ष के दौरान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई रकमों (जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं) और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई रकमों हेतु विचार में लिए जाते हैं। प्रबंध मंडल यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच अंतर को ऐसी अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है, जिनमें परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है/ वे कार्यान्वित किए जाते हैं।

2.3 वस्तु-सूचियां

वस्तु-सूचियों में प्रकाशनों, अध्ययन सामग्रियों, लेखन सामग्रियों और अन्य भंडारों की वस्तु-सूचियां सम्मिलित होती हैं। इन वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन प्रथम आगम, प्रथम जावक ("एफआईएफओ") पद्धति के आधार पर, जिसके दौरान जहां आवश्यक समझा जाए, अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए उपबंध करने के पश्चात् संगणित निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है।

लागत में माल को विक्रय के बिन्दु पर लाने संबंधी सभी प्रभार सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत चुंगी, अन्य उदग्रहण, प्रवहन बीमा और अनुपंगी प्रभार भी हैं।

2.4 नकद और नकद समतुल्य (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

नकद में, हाथ में नकदी और बैंकों में मानदेय निक्षेप अंतर्विष्ट हैं। नकद समतुल्य ऐसे अल्पकालिक अतिशेष हैं (जिनकी मूल परिपक्वता, उनके अर्जन की तारीख से तीन मास या उससे कम की अवधि है), जो अत्यधिक रूप से चल निवेश हैं, जिन्हें सुगम रूप से नकद की जात रकमों में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.5 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है। संस्थान के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

2.6 आरक्षितियों में विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

(i) संस्थान के अध्येता के रूप में प्रवेश हेतु सदस्यों से प्राप्त फीस को अवसंरचना संबंधी आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

(ii) भवनों और अनुसंधान के लिए प्राप्त संदानों को सीधे संबंधित आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

(iii) दुरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है।

(iv) वर्ष के दौरान प्राप्त सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।

(v) उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षित खाते को निम्नलिखित अंतरण किए जाते हैं :

(क) अनुसंधान भवन निधि
लेखांकन से

लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से, भवन से संबंधित अभिवृद्धियों की
लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 100 प्रतिशत

(ख) शिक्षा निधि से

नियत आस्तियों से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत

(vi) उद्दिष्ट निधियों के निवेश से होने वाली आय को उद्दिष्ट निधियों में जोड़ा जाता है। इस आय को, संबद्ध उद्दिष्ट निधियों के प्रारंभिक अतिशेष के आधार पर, भारित औसत का आधार बनाते हुए आवंटित किया जाता है।

(vii) वर्ष के दौरान प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी)/आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फीस के 25 प्रतिशत को कंप्यूटरों तथा अन्य आईटीटी केंद्र अवसंरचना के प्रतिस्थापन हेतु अन्य आरक्षितियों में अंतरित किया जाता है।

(viii) वर्ष के लिए अवक्षयण के समतुल्य राशि (आईटीटी आरक्षिती को अंतरित रकम को छोड़कर) को आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन हेतु सिंकिंग निधि में अंतरित किया जाता है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब यह संभावना हो कि मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदों संस्थान को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को संचयी अवक्षयण और संचयी हानिकरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर अग्रणीत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में उसकी क्रय कीमत, किन्हीं व्यापार बट्टों और छूटों के शुद्ध, आयात शुल्कों और अन्य करों (कर प्राधिकारियों से तत्पश्चात् वसूलनीय से भिन्न) सहित सम्मिलित होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाले व्यय से प्रत्यक्षतः जोड़ा जा सकता है। आशयित उपयोग हेतु आस्ति को तैयार किए जाने की तारीख तक अर्हित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अर्जन के संबंध में होने वाले अन्य आनुषंगी व्ययों और उसके संबंध में लिए गए उधारों पर ब्याज का भी पूंजीकरण किया जाता है।

2.8 अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, संचयी परिशोधन और संचयी हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत (छूट और बट्टों का शुद्ध) सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चात्तवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है। किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य आनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर ब्याज भी है। अमूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चात्तवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

2.9 चालू पूंजी संकर्म

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है। इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं।

2.10 अवक्षयण और परिशोधन

(क) मूर्त नियत आस्तियों के संबंध में अवक्षयण को संस्थान की परिषद् द्वारा अनुमोदित उपयोगी जीवन के अनुसार अपलिखित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है। आस्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण, तकनीकी सलाह के आधार पर आस्ति की प्रकृति, आस्ति के प्राक्कलित उपयोग, आस्ति के प्रचालन की परिस्थितियों, प्रतिस्थापन के पूर्व ईतिवृत्त, अनुमानिक प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तनों, विनिर्माताओं की वारंटियों और अनुरक्षण समर्थन आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

नियत आस्तियों के परिशोधन के लिए प्रयुक्त परिशोधन दरें निम्नानुसार हैं :-

	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वर्ग	अवक्षयण की दर
(i)	भवन	5%
(ii)	लिफ्ट, इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग	10%
(iii)	कंप्यूटर	60%
(iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	10%
(v)	वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%

(vi)	वाहन	20%
(vii)	पुस्तकालय की पुस्तकें	100%

(ख) पट्टाधृत भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या उसके उपयोगी जीवन, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

(ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अमूर्त आस्तियों का परिशोधन उनकी प्राक्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती पद्धति के अनुसार निम्नलिखित रूप में किया जाता है :

अमूर्त आस्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवन और परिशोधन अवधि का पुनर्विलोकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पर किया जाता है और परिवर्तित पैटर्न, यदि कोई हो, उपदर्शित करने के लिए हानिकरण की अवधि का पुनरीक्षण किया जाता है।

2.11 राजस्व मान्यता

राजस्व को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

- (i) छात्रों से प्राप्त दूरस्थ शिक्षा फीस को संबद्ध पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।
- (ii) कक्षा प्रशिक्षण फीस में प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम ("एमसीएस"), सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्ट कौशल संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("आईसीआईटीएसएस"), अग्रिम सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्ट कौशल संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("एआईसीआईटीएसएस") और अनुकूलन कार्यक्रम ("ओपी") के लिए प्राप्त फीस सम्मिलित होती है। कक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग कक्षाओं संबंधी आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, जब सेवाओं को प्रदान किया जाता है और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।
- (iii) परीक्षा फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।
- (iv) संगोष्ठी फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।
- (v) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण-पत्र और उसे पुनः स्थापित करने की फीस भी सम्मिलित है) और प्रवेश फीस से मिलकर बनने वाली सदस्यता फीस को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

(क) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए फीस भी है) को उस समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब वह वर्ष के दौरान शोध्य हो जाती है। सदस्य के नाम को पुनः प्रविष्ट करने संबंधी फीस को, उसके प्राप्त होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) प्रवेश फीस :

- सहबद्ध सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस के एक-तिहाई भाग को उस वर्ष की प्रवेश संबंधी आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और शेष भाग को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।
 - अध्येता सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।
- (vi) छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस को उस समय मान्यता दी जाती है, जब छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जाता है।
 - (vii) छात्र संगमों संबंधी आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब छात्रों को पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रदान किया जाता है।
 - (viii) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के राजस्वों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं।
 - (ix) प्रमाणपत्र/अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व प्रवेश रद्द किए जाने की दशा में फीस के 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है और उस दशा में, जब पाठ्यक्रम आरंभ हो गया हो, फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाता है किंतु सदस्य को भविष्य में आयोजित किए जाने वाले वैचों में पाठ्यक्रम के शेष भाग को पूरा करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

2.12 अन्य आय

(क) प्रकाशन के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कारों को क्रेता को अंतरित किया जाता है, जो सामान्यतः माल के परिदान के समय होता है। इस आय में, प्राप्त हुआ यह प्राप्य प्रतिफल, बट्टों का शुद्ध और अन्य विक्रय संबंधी कर (यदि कोई हों) सम्मिलित हैं।

(ख) छात्र न्यूज लैटर और जर्नल के अभिदाय से होने वाली आय को अभिदाय की अवधि के अनुसार अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।

(ग) कैम्पस साक्षात्कार और विशेषज्ञ सलाहकार फीस से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।

(घ) व्याज संबंधी आय को, खातों में जमा निक्षेपों और लागू दर पर व्याज को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

2.13 निवेश

(क) संस्थान के निवेशों में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में लिखतें, भारत में अधिवासी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि निक्षेप और लाभ न कमाने वाले अस्तित्वों के शेयर सम्मिलित होते हैं।

(ख) निवेशों को एएस 13, निवेशों के अनुसार चालू और दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश वे हैं, जिन्हें सुगमता से वसूल किया जा सकता है और उन्हें, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि तक धारित करने का आशय रखा जाता है। कोई दीर्घकालिक निवेश कोई ऐसा निवेश है, जो चालू निवेश से भिन्न है।

(ग) निवेशों को प्रारंभिक रूप से लागत पर लेखबद्ध किया जाता है और इस लागत में अर्जन की लागतें, जैसे दलाली, फीस और शुल्क सम्मिलित होते हैं। क्रय के समय संदत्त प्रोदभूत व्याज का मुजरा व्याज की प्रथम प्राप्ति के विरुद्ध किया जाता है।

(घ) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को चालू निवेशों को लागत और उचित मूल्य के निम्नतर पर अग्रणीत किया जाता है। उचित मूल्य का अवधारण व्यष्टिक आधार पर किया जाता है। दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर अग्रणीत किया जाता है। तथापि, मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को सम्मिलित किया जाता है, जिससे निवेशों के मूल्य में अस्थायी से भिन्न किसी कमी को मान्यता प्रदान की जा सके। क्रय के समय संदत्त प्रीमियम का परिशोधन निवेशों की शेष परिपक्वता की अवधि हेतु किया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों से व्याज' शीर्ष के अधीन आय के प्रति समायोजित किया जाता है।

2.14 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

तुलन-पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा धनीय मदों को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर पुनः कथित किया जाता है। संस्थान की गैर-धनीय मदों का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

विदेशी मुद्रा धनीय आस्तियों और दायित्वों के समाधान/पुनर्कथन पर उदभूत होने वाले विनिमय संबंधी अंतरों को आय और व्यय के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.15 कर्मचारी फायदे

कर्मचारी फायदों में भविष्य निधि, उपदान निधि, प्रतिपूरित अनुपस्थिति, दीर्घ सेवा पुरस्कार, पेंशन स्कीम और सेवा-पश्च चिकित्सीय फायदें सम्मिलित हैं।

(i) अल्पकालिक कर्मचारी फायदे

अल्पकालिक कर्मचारी फायदों (जैसे कि वेतन, भत्ते, अनुग्रह आदि) की बढ़ा रहित रकम को, कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले संदत्त किए जाने की आशा की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। अल्पकालिक कर्मचारी फायदे संभावी रूप से उस अवधि के अंत के 12 मास के पश्चात् उत्पन्न होते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति की लागत को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है :

(क) एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उनकी भावी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की हकदारी में वृद्धि करती हैं; और

(ख) गैर-एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब अनुपस्थितियां दर्ज की जाती हैं।

(ii) नियोजन पत्र फायदें

नियोजन पत्र फायदें कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे फायदें हैं, जो सेवा समापन फायदों से भिन्न हैं और जो नियोजन के पूरा होने के पश्चात् संदेय होते हैं। नियोजन पत्र फायदों का लेखांकन, सुसंगत योजनाओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसे कि उन्हें या तो परिभाषित फायदा योजना (डीबीएफ) या परिभाषित अभिदाय योजना (डीसीपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नियोजन पत्र फायदा योजनाएं, जहां संस्थान किसी पृथक् अस्तित्व या निधि को कोई नियत संदाय करता है और वह उस दशा में किन्हीं अन्य अभिदायों को करने की बाध्यताओं के अधीन नहीं होगा यदि पृथक् अस्तित्व या निधि के पास चालू और पूर्व अवधि में कर्मचारी की सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी फायदों का संदाय करने के लिए पर्याप्त अस्तित्वा विद्यमान नहीं है। दूसरी ओर, डीसीपी के रूप में वर्गीकृत योजनाओं से भिन्न नियोजन पत्र फायदा योजनाओं को डीबीपी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(क) परिभाषित फायदा योजनाएं

उपदान और सेवानिवृत्ति पत्र पेंशन के रूप में परिभाषित फायदा योजनाओं के लिए, फायदे उपलब्ध कराने की लागत का अवधारण प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसके दौरान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभों और हानियों को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे उद्भूत होते हैं। पूर्व सेवा संबंधी लागत को, फायदों के पहले से ही निहित किए जाने की सीमा तक तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें अन्यथा फायदों के निहित हो जाने तक की औसत अवधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। तुलन-पत्र में मान्य ठहराई गई सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी बाध्यता, गैर-मान्यताप्राप्त पूर्व सेवा लागत के लिए यथा समायोजित परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उपदर्शित करती है, जिसमें से स्कीम संबंधी अस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो। इस परिगणना के पारिणामिक कोई अस्ति, पूर्व सेवा लागत धन उपलब्ध प्रतिदायों और स्कीमों में भावी अभिदायों में कमी के वर्तमान मूल्य तक सीमित है। उपदान संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान भविष्य निधि न्यास ('न्यास') को भविष्य निधि स्कीम के मद्दे किए गए अभिदाय को चालू वर्ष के लिए परिभाषित फायदा योजना के रूप में विचार में लिया जाता है और उसे एक ऐसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जो किए जाने के लिए अपेक्षित अभिदाय की रकम पर आधारित है, जब कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस न्यास का प्रबंध संस्थान द्वारा निर्वाचित शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

इन परिभाषित फायदा बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को लेखांकन मानक (एएस) - 15, कर्मचारी फायदे के अनुसार एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा अभिनिश्चित किया जाता है।

(ख) पेंशन स्कीम

संस्थान अपने कर्मचारियों को पेंशन के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(ग) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति-पत्नी को सेवानिवृत्ति पत्र चिकित्सा स्कीम फायदा

संस्थान अपने कर्मचारियों को चिकित्सा स्कीम के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(III) दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे

ऐसी प्रतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जिनकी उस अवधि के अंत के पश्चात् 12 मास के भीतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, जिसमें कर्मचारी द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य पर एक ऐसे दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें से योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो और जिसमें से बाध्यताओं के समाधान होने की आशा की जाती है।

2.16 पट्टे

संस्थान पट्टों को लेखांकन और प्रकटन प्रयोजनों के लिए वित्त और प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करता है। ऐसे पट्टों को, जहाँ संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टों को, जहाँ पट्टाकर्ता और न कि संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन पट्टों के अधीन पट्टा किरायों को पट्टे की अवधि के अनुसार सीधे कटौती पद्धति के आधार पर आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। वित्तीय पट्टे की दशा में, आस्तियों को पट्टाकृत आस्ति के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा संदाय के वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा संबंधी संदायों को वित्तीय प्रभार और पट्टा दायित्व के पुनः संदाय के बीच परिशोधित किया जाता है। पट्टाधृत आस्तियों का अवक्षयण पट्टे की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन के निम्नतर पर किया जाता है।

2.17 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों के अग्रेषण मूल्य को हानिकरण हेतु पुनर्विलोकित किया जाता है। यदि हानिकरण का कोई संकेत विद्यमान होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम को प्राक्कलित किया जाता है और हानिकरण को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, यदि इन आस्तियों की अग्रणीत रकम उनकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। वसूलनीय रकम, वह शुद्ध विक्रय कीमत और उनके उपयोग मूल्य दोनों में से उच्चतर है। उपयोग मूल्य की गणना, भावी नकद प्रवाहों को एक समुचित बट्टा कारक के आधार पर बट्टा देते हुए उनके वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। जब इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि किसी आस्ति के लिए पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों के दौरान मान्यता प्रदान किया गया हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कोई कमी आई है तो ऐसे हानिकरण की वापसी को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.18 आय पर कर

संस्थान को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) और धारा 11 के अधीन आय-कर से छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार, आय-कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और आस्थगित कर आस्ति और दायित्व के लिए किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है।

2.19 उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियाँ

उद्दिष्ट निधियों और बैंकों में निक्षेपों के रूप में धारित ऐसी अन्य निधियों को, जो तुलन-पत्र की तारीख से 12 मास की अवधि के पश्चात् परिपक्व हो रहे हैं, गैर-चालू और अन्य निधियों को चालू निधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये निधियाँ संस्थान की परिपक्व के विवेकानुसार उपयोग के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध हैं, सिवाय उद्दिष्ट और कर्मचारी फायदा निधियों की कुल योग की सीमा तक।

2.20 प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप संस्थान की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर निर्भर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उद्भूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण # 3. आरक्षितियां और अधिशेष

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	साधारण		शिक्षा		अवसंरचना		अन्य*		कुल	
	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	82,207	71,796	38,343	35,854	5,700	5,304	1,989	987	128,239	113,941
जोड़ें: आय और व्यय विवरण से विनियोग	13,916	10,411	-	-	-	-	1,780	1,001	15,696	11,412
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षिती से/(को) अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उद्धिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	(20,890)	-	4,339	2,489	-	-	-	-	(16,551)	2,489
दाखिला फीस और आवंटित प्रवेश फीस	-	-	-	-	387	367	-	-	387	367
भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11
(उपयोग)/परिवृद्धियां	-	-	-	-	(15)	18	-	1	(15)	19
वर्ष के अंत में अतिशेष	75,233	82,207	42,682	38,343	6,072	5,700	3,769	1,989	127,756	128,239

* अन्य आरक्षितियों में, पुस्तकालय आरक्षितियों, कक्षा प्रशिक्षण आरक्षितियों और विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिती (दुबई शाखा) आदि जैसी आरक्षितियों सम्मिलित हैं।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

टिप्पण : #4. उद्दिष्ट निधियां

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	अनुसंधान		लेखांकन अनुसंधान भवन निधि		शिक्षा निधि		मेडल और पुरस्कार निधि		छात्रों की छात्रवृत्ति निधि		सदस्य कल्याण निधि		कर्मचारी कल्याण निधि		आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए सिंकिंग निधि(*)		अन्य निधि		योग	
	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	2,479	2,282	854	793	29,713	25,204	265	236	167	127	-	-	789	661	-	-	5,103	5,026	39,370	34,329
आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	-	-	5,818	5,073	-	-	-	-	2,138	-	80	78	276	-	1,500	-	9,812	5,151
आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण	-	-	-	-	(4,339)	(2,489)	-	-	-	-	-	-	-	-	20,890	-	-	-	16,551	(2,489)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां	-	24	-	-	-	-	15	23	12	36	-	-	-	-	-	-	-	-	27	83
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई व्याज आय	198	173	70	61	2,416	1,925	19	15	11	10	-	-	64	50	-	-	88	83	2,866	2,317
वर्ष के दौरान उपयोजित	-	-	-	-	-	-	(19)	(9)	(4)	(6)	-	-	(10)	-	-	-	(2)	(6)	(35)	(21)
वर्ष के अंत में अतिशेष	2,677	2,479	924	854	33,808	29,713	280	265	186	167	2,138	-	923	789	21,166	-	6,689	5,103	68,591	39,370

टिप्पण : 1. 68,591 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 39,370 लाख रुपए) की उद्दिष्ट निधियों को सावधि निक्षेपों और सरकारी प्रतिभूतियों में धारित किया गया है (टिप्पण 12 और 13 देखें)

2. 31 मार्च, 2018 तक आईटीटी आरक्षिती को घटाकर संचयी अवक्षयण की सीमा तक 20,890 लाख रुपए की सीमा तक की सिंकिंग निधि को वर्ष के दौरान साधारण आरक्षिती से सिंकिंग निधि में स्थानांतरित किया गया था। वर्ष के लिए आईटीटी आरक्षिती के संबंध में वर्ष के शुद्ध आरक्षण के मद्दे 276 लाख रुपए की राशि को सिंकिंग निधि के मद्दे विनियोजित किया गया है।

3. 1500 लाख रुपए को, अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस, जिसका आयोजन 2022 में किया जाना है, के लिए 4500 लाख रुपए के प्राक्कलित व्यय के वित्तपोषण हेतु विनियोजित किया गया है। (टिप्पण 25.19 देखें)

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

टिप्पण #5 : अन्य दीर्घकालिक दायित्व		31 मार्च को यथा विद्यमान	
		2019	2018
अग्रिम में प्राप्त फीस			
(i)	शिक्षा फीस	1,579	1,206
(ii)	जर्नल का अभिदाय	12	13
योग		1,591	1,219
टिप्पण #6 : प्रावधान		31 मार्च को यथा विद्यमान	
		2019	2018
		दीर्घकालिक	अल्पकालिक
कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान			
(क) नियोजन पश्च फायदे			
(i)	उपदान	-	567
(ii)	पेंशन	11,861	11,426
(iii)	भविष्य निधि		-
(ख) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान		4,570	3,748
(ग) शाखा कर्मचारियों के लिए प्रावधान (टिप्पण 25.15)		3,500	2,800
(घ) वेतन पुनरीक्षण के लिए प्रावधान (टिप्पण 25.16)		5,360	4,400
योग		25,291	22,941
टिप्पण #7 : व्यापार संबंधी देय		31 मार्च को यथा विद्यमान	
		2019	2018
व्यापार संबंधी देय		4,132	3,677
योग		4,132	3,677

(रुपए लाख में)

टिप्पण #8 : अन्य चालू दायित्व		31 मार्च को यथा विद्यमान	
		2019	2018
(क)	अग्रिम में प्राप्त फीस		
(i)	परीक्षा फीस	7,046	7,231
(ii)	जर्नल अभिदाय	25	21
(iii)	सदस्यता फीस	3,112	2,876
(iv)	शिक्षा फीस	9,471	9,060
(v)	अर्हता पश्च पाठ्यक्रम फीस	256	111
(vi)	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम फीस	171	118
(vii)	संगोष्ठी फीस :		
	(क) संगोष्ठी सदस्य	110	105
	(ख) संगोष्ठी छात्र	-	2
(viii)	कक्षा प्रशिक्षण फीस	937	1,325
(ix)	कोचिंग कक्षा फीस	105	84
(x)	अन्य फीस	63	64
	योग (क)	21,296	20,997
(ख)	अन्य दायित्व		
(i)	पूँजी ऋणदाता	15	29
(ii)	संदेय भविष्य निधि, ईएसआईसी और वृत्तिक कर	109	96
(iii)	प्रतिधारण कर	540	317
(iv)	जीएसटी देय	784	1,389
(v)	प्रतिभूति और जमा किया गया बयाना धन	816	832
(vi)	अन्य	482	614
	कुल योग (ख)	2,746	3,277
	योग (क+ख)	24,042	24,274

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

टिप्पण 9. # संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर		सकल ब्लॉक				अवक्षयण				
	31 मार्च को यथाविद्यमान	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान अंतरण/विलोपन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ के संचयी अवक्षयण	वर्ष के लिए प्रभारित	वर्ष के दौरान अंतरण/विलोपन	वर्ष के अंत में संचयी अवक्षयण	वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2019	17,663	356	292	18,311	-	-	-	-	18,311
	2018	19,214	270	(1,821)	17,663	-	-	-	-	17,663
पट्टाश्रुत भूमि	2019	7,549	1,033	(792)	7,790	824	92	(76)	840	6,950
	2018	5,879	112	1,558	7,549	668	107	49	824	6,725
भवन	2019	31,800	7,005	(70)	38,735	7,766	1,584	(348)	9,002	29,733
	2018	28,441	3,096	263	31,800	6,600	1,449	(283)	7,766	24,034
लिफ्ट, इलेक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स	2019	2,183	118	11	2,312	1,157	115	(5)	1,267	1,045
	2018	1,863	342	(22)	2,183	1,063	106	(12)	1,157	1,026
कंप्यूटर	2019	5,233	260	(76)	5,417	4,948	239	(85)	5,102	315
	2018	5,129	178	(74)	5,233	4,767	242	(61)	4,948	285
फर्नीचर और फिक्सचर	2019	4,572	455	(192)	4,835	2,221	244	(48)	2,417	2,418
	2018	4,192	401	(21)	4,572	1,990	241	(10)	2,221	2,351
वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	2019	5,387	322	(83)	5,626	3,135	354	(77)	3,412	2,214
	2018	4,801	634	(48)	5,387	2,850	325	(40)	3,135	2,252
वाहन	2019	135	2	(1)	136	108	6	-	114	22
	2018	135	-	-	135	101	7	-	108	27
पुस्तकालय की पुस्तकें	2019	1,041	25	(7)	1,059	1,041	26	(6)	1,061	(2)
	2018	1,009	32	-	1,041	1,009	32	-	1,041	-
योग	2019	75,563	9,576	(918)	84,221	21,200	2,660	(645)	23,215	61,006
	2018	70,663	5,065	(165)	75,563	19,048	2,509	(357)	21,200	54,363

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

टिप्पण 10. # अमूर्त आस्तियां	31 मार्च को यथाविद्यमान	
कंप्यूटर साफ्टवेयर	2019	2018
वर्ष के प्रारंभ में लागत	746	663
परिवृद्धियां	5	62
अंतरण/विलोपन	15	21
वर्ष के अंत में लागत	766	746
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन	691	644
वर्ष के लिए प्रभार	28	31
अंतरण/विलोपन	13	16
वर्ष के अंत में परिशोधन	732	691
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	34	55
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	55	19
टिप्पण 11. #: चालू पूंजी संकर्म		
प्रारंभिक अतिशेष	10,877	13,875
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	1,292	561
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत/ समायोजित रकम	(6,614)	(3,559)
अंतिम अतिशेष	5,555	10,877

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

टिप्पण : 12. # निवेश (लागत पर, मूल्य में हास को घटाकर)		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2019	2018	2019	2018
		गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
क. केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां					
कोट की गई प्रतिभूतियां					
1	8.27% भारत सरकार 2020	2,548	2,588	-	-
2	7.80% भारत सरकार 2021	2,559	2,588	-	-
3	6.35% भारत सरकार 2020	998	995	-	-
		6,105	6,171	-	-
कोट न की गई प्रतिभूतियां					
4	8.00% भारत सरकार कराधेय बंधपत्र - संचयी	11,200	11,200	-	-
5	8% बचत (कराधेय) बंधपत्र 2003-गैर संचयी	44,000	44,000	-	-
		55,200	55,200	-	-
बही मूल्य		61,305	61,371	-	-
बाजार मूल्य					
कोट किया गया		6,109	6,112	-	-
कोट न किया गया (बही मूल्य)		55,200	55,200	-	-
		61,309	61,312	-	-
ख. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां					
कोट की गई प्रतिभूतियां:					
1	7.75% राजस्थान उदय एसडीएल 2018	-	-	-	2,506
2	8.45% पंजाब एसडीएल 2023	2,557	2,572	-	-
3	8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	3,058	3,068	-	-
4	8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	2,038	2,045	-	-
5	8.62% महाराष्ट्र एसडीएल 2023	511	514	-	-
6	8.75% पश्चिमी बंगाल जीएस 2022	510	514	-	-
7	8.39% राजस्थान उदय एसडीएल 2022	1,527	1,537	-	-
8	8.39% राजस्थान उदय बंधपत्र 2021	3,870	3,904	-	-
9	8.49% आंध्र प्रदेश पीएसडीएल 2020	1,510	-	-	-
10	8.18% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2020	1,506	-	-	-
11	8.20% पंजाब एसडीएल 2019	-	-	1,003	-
12	8.85% पंजाब एसडीएल 2019	-	-	1,004	-
13	07.86 राजस्थान उदय 2019	-	-	2,910	-
14	8.44% उत्तर प्रदेश उदय 2023	1,004	-	-	-
15	8.01% राजस्थान उदय एसडीएल 2020	2,497	-	-	-
एसजीएस (क)		20,588	14,154	4,917	2,506

(रुपए लाख में)

		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2019	2018	2019	2018
		गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
16	7.56% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2021	2,478	-	-	-
17	7.64% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2021	2,976	-	-	-
18	8.37% ओडिशा एसडीएल 2022	1,003	-	-	-
19	07.79% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2022	990	-	-	-
20	7.62% महाराष्ट्र एसडीएल 2021	1,984	-	-	-
21	6.90% पंजाब एसडीएल 2021	2,452	-	-	-
22	8.39% राजस्थान उदय बंधपत्र 2021	3,016	-	-	-
23	6.94% ओडिशा एसडीएल 2021	1,464	-	-	-
24	8.21% हरियाणा उदय 2022	1,487	-	-	-
25	9.04% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2021	509	-	-	-
26	9.18% पंजाब एसडीएल 2021	511	-	-	-
27	9.13% गुजरात एसडीएल 9/5/2022	2,434	-	-	-
28	8.90% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2022	2,525	-	-	-
29	9.01% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2022	508	-	-	-
30	8.86% पंजाब एसडीएल 2022	1,014	-	-	-
31	8.97% बिहार एसडीएल 2022	509	-	-	-
32	8.95% असम एसडीएल 2022	1,524	-	-	-
33	8.92% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2022	1,015	-	-	-
34	9.01% कर्नाटक एसडीएल 2024	528	-	-	-
35	7.93% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2024	1,520	-	-	-
36	8.45% गुजरात एसडीएल 2023	2,582	-	-	-
37	8.25% उत्तर प्रदेश उदय बंधपत्र 2023	509	-	-	-
38	8.39% राजस्थान उदय 2022	1,494	-	-	-
39	8.27% राजस्थान एसडीएल एसपीएल 2023	196	-	-	-
40	8.18% हरियाणा एसडीएल उदय 2024	46	-	-	-
एसजीएस (ख)		35,274	-	-	-
बही मूल्य (क+ख)		55,862	14,154	4,917	2,506
बाजार मूल्य		57,263	14,209	4,928	2,506
कुल योग		117,167	75,525	4,917	2,506

		(रुपए लाख में)			
		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2019	2018	2019	2018
		गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
ग.	समनुषंगियों की साम्या लिखतों में निवेश (पूर्ण समादत्त)				
i.	आईसीएआई का दिवाला वृत्तिक संस्थान 100 रुपए प्रत्येक के 10,00,000 सामान्य शेयर	1,000	1,000	-	-
ii.	आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन निवेश	10	10	-	-
कुल योग	वही मूल्य	1,010	1,010	-	-
योग (क+ख+ग)		118,177	76,535	4,917	2,506
टिप्पण : # 13 उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां		31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2019	2018	2019	2018
		गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
बैंकों में सावधि निक्षेप		5,176	5,229	37,992	54,704
योग		5,176	5,229	37,992	54,704

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

टिप्पण : # 14 ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत, उत्तम माने गए)	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2019	2018	2019	2018
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
(क) प्रतिभूति निक्षेप	81	190	352	362
(ख) स्रोत पर कर कटौती	2,508	2,256	-	-
(ग) इनपुट कर प्रत्यय	-	-	1,230	966
(घ) सदस्यों से प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी	-	-	521	366
(ङ) अन्य ऋण और अग्रिम				
(i) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	600	660	900	551
(ii) अन्य प्राप्य	244	291	296	698
घटाएं : संहितास्पद प्राप्यों के लिए प्रावधान	-	-	(4)	(229)
योग	3,433	3,397	3,295	2,714

टिप्पण # 15 : अन्य आस्तियां	31 मार्च को यथाविद्यमान		31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2019	2018	2019	2018
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
(क) प्रोदभूत ब्याज				
(i) बैंक के साथ सावधि जमा पर	44	28	960	1,045
(ii) निवेश पर	132	506	2,925	981
(iii) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	154	144	40	39
योग	330	678	3,925	2,065

टिप्पण # 16 : वस्तु-सूचियां (निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर)	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2019	2018
(क) प्रकाशन और अध्ययन सामग्रियां	434	1,038
(ख) लेखन सामग्रियां और भंडार	45	42
योग	479	1,080

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 17 : नकद और बैंक अतिशेष		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2019	2018
(क)	हाथ में नकदी	42	43
(ख)	बैंकों में बचत और चालू खातों में अतिशेष	8,670	6,781
	योग	8,712	6,824

टिप्पण # 18 : फीसें		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2019	2018
(क)	दूरस्थ शिक्षा	23,910	21,654
(ख)	कक्षा प्रशिक्षण आय	15,182	9,209
(ग)	कोचिंग	1,160	1,285
(घ)	परीक्षा	16,867	16,870
(ङ)	सदस्यता	10,870	10,830
(च)	प्रवेश	116	106
(छ)	अर्हतापश्च पाठ्यक्रम	976	747
(ज)	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1,386	1,825
	योग	70,467	62,526

टिप्पण # 19: संगोष्ठी आय		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2019	2018
(क)	सदस्य	2,889	3,555
(ख)	छात्र	695	834
(ग)	गैर-सदस्य	711	1,328
(घ)	ई-पठन आय	17	44
	योग	4,312	5,761

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 20 : अन्य आय	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2019	2018
क) व्याज आय		
i. साधारण निधियों में धारित बैंक निक्षेप पर	2,783	3,234
ii. निवेशों से	5,613	3,114
iii. उद्दिष्ट निधियों के लिए धारित बैंक निक्षेपों पर	2,866	2,317
iv. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	70	78
ख) प्रकाशनों का विक्रय	933	1,568
ग) न्यूजलेटर	106	187
घ) जर्नल अभिदाय	277	113
ङ) कैम्पस साक्षात्कार	970	782
च) विशेषज्ञ सलाहकार फीस	53	23
छ) अनापेक्षित प्रावधानों का अपलेखन	445	193
ज) प्रकीर्ण आय	481	713
योग	14,597	12,322

टिप्पण # 21: संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2019	2018
क) सदस्य	3441	4867
ख) छात्र	943	973
ग) छात्र क्रियाकलाप व्यय	83	155
घ) ई-पठन आय	38	41
योग	4505	6036

टिप्पण # 22 : कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2019	2018
क) वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते	12,912	14,612
ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय	1,616	2,113
ग) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	167	147
	14,695	16,872

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 23. अन्य व्यय		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2019	2018
क)	डाक और टेलीफोन	2,743	2,869
ख)	किराया, दरें और कर	5,542	5,242
ग)	घरेलू यात्रा	2,212	1,761
घ)	विदेशों से संबद्ध व्यय		
	i) विदेश यात्रा	110	133
	ii) विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	573	503
	iii) अन्य	160	180
ङ)	मरम्मत और अनुरक्षण	2,589	2,301
च)	कक्षा प्रशिक्षण व्यय	5,187	3,835
छ)	विज्ञापन और प्रचार	278	170
ज)	बैठक व्यय	1,182	895
झ)	योग्यता द्वावृत्ति	189	176
ञ)	संपरीक्षा फीस : प्रधान कार्यालय	11	11
	अन्य कार्यालय	39	35
ट)	उद्दिष्ट निधियों से संदाय	35	21
ठ)	पूर्वाविधि समायोजन (शुद्ध) (टिप्पण 24)	115	748
ड)	जीएसटी व्यय	1213	2,059
ढ)	अग्रिमों के लिए प्रावधान	4	229
ण)	निवेशों के विक्रय पर हानि	-	285
त)	अन्य व्यय	1,893	1,317
योग		24,075	22,770

टिप्पण # 24: पूर्वाविधि समायोजन (शुद्ध)		31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2019	2018
i)	आय *	(969)	(116)
ii)	व्यय *	1,084	864
	योग	115	748
* पूर्वाविधि आय और व्यय के ब्यौरे			
i)	कक्षा प्रशिक्षण आय	796	-
ii)	अन्य	173	116
	पूर्वाविधि आय का योग	969	116
i)	कक्षा प्रशिक्षण संबंधी व्यय	308	-
ii)	भवनो पर अवक्षयण	415	284
iii)	मुद्रण और लेखन सामग्री संबंधी व्यय	-	218
iv)	अन्य	361	362
	पूर्वाविधि व्ययों का योग	1,084	864

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

25. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण

25.01 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :

	<i>(रुपए लाख में)</i>	
	2018-19	2017-18
क. आकस्मिक दायित्व		
i) संस्थान के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है	2,603	1,830
ii) आयकर की मांग (टिप्पण #25.03 देखें)	4,142	4,142

iii) संस्थान को अपर महानिदेशक, माल और सेवाकर सतर्कता से वार्षिक फीस, व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस, प्रवेश फीस, संगोष्ठी फीस और कोचिंग कक्षा फीस आदि के संबंध में सेवाकर के संदाय के लिए 15,797 लाख रुपए की मांग संबंधी दो कारण बताओं सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। संस्थान की यह राय है कि वह कारण बताओं सूचना में उल्लेख किए गए अनुसार सेवाकर का दायी नहीं है। इस संबंध में 8.4.2019 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ, विभाग द्वारा तारीख 9.8.2018 और 3.10.2018 को जारी की गई कारण बताओं सूचनाओं के अनुसरण में कार्यवाहियों को आस्थगित करने का अनुरोध किया गया था। यह रिट याचिका 16.04.2019 को फाइल की गई थी और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और संस्थान को यह सलाह दी है कि वह पूर्वोक्त कारण बताओं सूचनाओं का उत्तर दे और उसने आगे और यह आदेश दिया था कि रिट याचिका का निर्णय दिए जाने तक विभाग द्वारा इस संबंध में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। अगली सुनवाई 13 दिसंबर, 2019 को की जानी है।

ख. पूंजी प्रतिबद्धताएं :

	2018-19	2017-18
पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	2,716	3,654

25.02 टिप्पण # 14 दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के अधीन अन्य प्राप्यों में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 243.75 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं, जिसे संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (जेडीआर), नागपुर द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। संस्थान ने, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे के समक्ष महाराष्ट्र स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा 53 के अधीन, जेडीआर, नागपुर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दो अपील फाइल की हैं, जो अंतिम अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं। संस्थान को यह सलाह दी गई है कि स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए उनके पास उत्तम विधिक मामला है।

25.03 निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विभाग से एक मांग सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 4,142 लाख रुपए के आयकर की मांग रखी गई है। आईटीएटी ने इस मामले को, 19.03.2016 को जारी आदेश की धारा 143(1) के अधीन संसूचना में आवश्यक सुधारों के लिए माननीय आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करने, कराधेय आय की रकम को निर्धारित करने और दावा किए गए टीडीएस का प्रत्यय देने और पूर्वोक्त मांग को समाप्त करने तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 234क के अधीन व्याज के साथ 452 लाख रुपए का प्रतिदाय जारी करने के लिए 10.10.2018 को एक पत्र फाइल किया गया था।

आय-कर विभाग ने, माननीय आईटीएटी के पूर्वोक्त आदेश को निरस्त करने के लिए धारा 260क के अधीन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील फाइल की है। यह मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है। संस्थान को यह विधिक सलाह दी गई है कि इस बात का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और यह आशा की जाती है कि वह विभाग द्वारा फाइल की गई अपील को खारिज कर देगा।

- 25.04 संगोष्ठियों संबंधी क्रियाकलापों के मद्दे प्रत्यक्ष रूप से होने वाले व्ययों को संगोष्ठी संबंधी व्ययों के अधीन प्रभारित किया गया है और इससे संबंधित अप्रत्यक्ष व्ययों को व्यय के कार्यकरण शीर्षों के अधीन प्रभारित किया गया है।
- 25.05 छात्रों से, छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है।
- 25.06 पट्टाधृत भूमि के मूल्य में 6.17 लाख रुपए सम्मिलित हैं, जो भूमि और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली से इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में विद्यमान (प्रधान कार्यालय के साथ लगी) भूमि से संबंधित हैं, जिसके लिए करार और पट्टाभिलेख के ज्ञापन के निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।
- 25.07 संस्थान ने, “परिवर्तन परियोजना” के रूप में निर्दिष्ट एक परियोजना को आरंभ करके अपने संपूर्ण गतिविधियों के अंकीकरण के लिए एक प्रक्रिया को आरंभ किया है। इस प्रयोजन के लिए, संस्थान ने एक वैश्विक रूप से ख्यातिप्राप्त परियोजना प्रबंध परामर्शी के द्वारा पर्यवेक्षित एक वैश्विक एकीकृत सेवा प्रदाता (विक्रेता) को नियुक्त किया था, जिसकी कुल लागत 3,981 लाख रुपए है। 31 मार्च, 2015 तक 867 लाख रुपए की राशि उपगत की गई है।

चूंकि एकीकृत सेवा प्रदाता ने, उसे विस्तारित समय सीमाएं प्रदान करने के पश्चात् भी अपेक्षा के अनुसार विकास कार्य नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने संविदा को रद्द कर दिया था और जून, 2015 मास में 295 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति का प्रत्याह्वान और नकदीकरण किया था तथा 572 लाख रुपए की शेष रकम को 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष में बढ़े खाते में डाल दिया गया था।

विक्रेता ने फरवरी, 2017 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा संस्थान से 807 लाख रुपए के संदाय की अपेक्षा की गई थी, जिसके अंतर्गत नकदीकरण की गई बैंक गारंटी की रकम भी सम्मिलित थी, जिसे संस्थान द्वारा नामंजूर कर दिया गया है और सेवा प्रदाता के साथ करार को समाप्त कर दिया गया है। संविदा को समाप्त करने के पश्चात् से विक्रेता से किसी प्रकार की कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष के दौरान, संस्थान ने विक्रेता को तारीख 31.10.2018 की एक विधिक सूचना भेजी है, जिसमें उससे, परियोजना का निष्पादन न किए जाने के मद्दे संस्थान को हुई हानि के प्रति लागू ब्याज सहित 2140.79 लाख रुपए की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई थी। विक्रेता ने अपने तारीख 20.03.2019 के प्रत्युत्तर द्वारा यह दावा किया है कि संस्थान का दावा समय द्वारा वर्जित है। इस मामले में, विधिक सलाहकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

- 25.08 आईसीएआई भवन, फरीदाबाद से 225 वर्ग मीटर के मापमान वाली भूमि को जनवरी, 2013 में डीएमआरसी द्वारा अधिगृहीत किया गया था, जिसके लिए फरीदाबाद शाखा ने डीएमआरसी द्वारा किए गए अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में शाखा के आसपास और अधिक भूमि के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर वर्तमान में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकार द्वारा विचार किया जा रहा है।
- 25.09 अन्य व्यय में 114 लाख रुपए (262 लाख रुपए) सम्मिलित हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28क के अधीन गठित क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा उपगत लागतों की प्रतिपूर्ति है। अन्य व्ययों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन गठित अपील प्राधिकरण को दिया गया 60 लाख रुपए (67.50 लाख रुपए) का अभिदाय भी सम्मिलित है। क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड और अपील प्राधिकरण के व्ययों का वहन संस्थान द्वारा किया जाना अपेक्षित है। अन्य व्ययों के अंतर्गत एक्सटेन्सिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) को दिया गया 15 लाख रुपए (10 लाख रुपए) का अनुदान और निवेश आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन को 15 लाख रुपए (शून्य) का एकबारगी व्यय समर्थन भी है।

- 25.10 पूर्व वर्षों में सृजित विभिन्न आरक्षित निधियों और उद्दिष्ट निधियों का और संबद्ध उद्दिष्ट निवेशों का ब्यौरेवार पुनर्विलोकन आरंभ किया गया है ताकि संस्थान की वर्तमान अपेक्षाओं और कार्यकरण के अनुसार इन निधियों को पुनः संरचित किया जा सके।

संस्थान पूर्व वर्षों से लेखा बहियों में, बिना किसी उपयोग के निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों को सम्मिलित कर रहा है :

विशिष्टियां	(लाख रुपए में)
शिक्षा आरक्षिती	42,682
शिक्षा निधि	33,608
अनुसंधान भवन निधि	924

- 25.11 आय और व्यय शीर्षों से संबंधित अंतःयूनिट लेखाओं की दशा में, ऐसे अंतरों का, जिनका सुमेलन नहीं किया गया है, नामे में उनका योग 552.62 लाख रुपए तथा जमा में उनका कुल योग 546.59 लाख रुपए हो गया है। इसका शुद्ध अंतर नामे में 6.03 लाख रुपए है। सुमेलन के पूरा होने के लंबित रहने के दौरान 6.03 लाख रुपए के शुद्ध अंतर को 'अंतःशाखा सुमेलन लेखा' के लिए प्रावधान के अधीन सम्मिलित किया गया है और उसके लिए प्रावधान किया गया है।

आस्तियों और दायित्वों से संबंधित अंतःयूनिट लेखाओं की दशा में, आमेलित अंतरों का कुल योग नामे में 3814.52 लाख रुपए और जमा में 4029.70 लाख रुपए है। 215.18 लाख रुपए के शुद्ध अंतर को 'अग्रिम में प्राप्त फीस' में सम्मिलित किया गया है।

- 25.12 यद्यपि, संस्थान की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन पूर्णतया छूट प्राप्त है, फिर भी कुछ विक्रेताओं ने संस्थान को किए गए संदायों पर स्रोत पर कर की कटौती की है। ऊपर टिप्पण सं. 25.03 में निर्दिष्ट लंबित अपीलों के निपटारे के पश्चात् प्राप्त होने वाले संभावित अंतिम परिणाम के फलस्वरूप स्रोत पर कटौती किए गए कर के संबंध में 2508 लाख रुपए (2256 लाख रुपए) का प्रतिदाय प्राप्त होने की संभावना है। शून्य आय के साथ 31.03.2016 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर, संस्थान ने 221 लाख रुपए के टीडीएस दावे के प्रति 9.13 लाख रुपए के व्याज और 55.37 लाख रुपए के प्रतिदाय को प्राप्त किया है। 165.63 लाख रुपए की शेष रकम के प्रतिदाय के लिए कर विभाग के साथ इस मामले को उठाया गया है।

- 25.13 प्रबंध मंडल के मतानुसार, अध्ययन सर्कल, अध्ययन चैप्टर और विदेशी चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और उनके लेखाओं का समेकन नहीं किया जाता है।

- 25.14 प्रधान कार्यालय और शाखाओं में नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन और बही अतिशेषों के साथ उनके सुमेलन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

- 25.15 शाखा कर्मचारी स्कीम 2006 को नई शाखा कर्मचारी स्कीम 2014 से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे केंद्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है किंतु अभी उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया है। वर्ष 2014-15 से, इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष 700 लाख रुपए का प्रावधान लेखाओं में किया जा रहा है, जिनका योग 31 मार्च 2019 को 3500 लाख रुपए हो गया है। इस प्रावधान में कमी/आधिक्य का अवधारण उस समय किया जाएगा जब पुनरीक्षित स्कीम को पूर्णतया कार्यान्वित किया जाएगा।

- 25.16 क्रमशः 1.1.2016 और 1.7.2017 से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 में 960 लाख रुपए (4400 लाख रुपए) का प्रावधान किया गया था। इस मामले के अंतिम पुनर्विलोकन और निर्णय के लंबित रहने के दौरान 1071 लाख रुपए का संदाय अग्रिम के रूप में कर्मचारियों को किया गया है।

- 25.17 संस्थान की 189 इकाईयों में से, जो समेकन का एक भाग हैं, उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषदों के लेखाओं की

संपरीक्षा नहीं की गई है।

- 25.18 संदत्त किए गए और संदेय जीएसटी और जीएसटी इनपुट के सुमेलन संबंधी कार्यवाही की जा रही है। 1213 लाख रुपए (2059 लाख रुपए) की रकम को, जिसके अंतर्गत अपात्र इनपुट कर प्रत्यय और छूट प्राप्त पूर्तियों के मद्दे इनपुट प्रत्यय भी है, 'जीएसटी व्ययों' के रूप में आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है। वर्ष के अंत में संदेय 784 लाख रुपए (1389 लाख रुपए) के जीएसटी को अन्य दायित्वों (टिप्पण सं. 8) के अधीन सम्मिलित किया गया है और 1230 लाख रुपए (966 लाख रुपए) की जीएसटी इनपुट प्रत्यय के रूप में वसूलनीय रकम को 'ऋणों और अग्रिमों (टिप्पण सं. 14)' के अधीन दर्शित किया गया है। प्रबंध मंडल की यह राय है कि सुमेलन के पूरा हो जाने के पश्चात् किसी सारवान समायोजन की संभावना नहीं होगी।
- 25.19 वर्तमान प्राक्कलनों के अनुसार यह संभावना है कि संस्थान भारत में वर्ष 2022 में अकाउंटेंटों के विश्व कांग्रेस का आयोजन करने के लिए 4500 लाख रुपए के प्राक्कलित व्यय को उपगत करेगा। यह विनिश्चय किया गया है कि वर्ष 2018-19 और आगामी दो वर्षों के अतिशेष में से 1500 लाख रुपए की रकमों को एक पृथक् क्लोज एंडेड निधि में विनियोग किया जाएगा, जिससे सम्मेलन के आयोजन संबंधी वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। प्रत्येक वर्ष में उपगत व्यय को एक अभिहित खाते "डब्ल्यूसीओए – 2022 संबंधी व्यय" से निकाला जाएगा और एक समतुल्य रकम को प्रत्येक वर्ष उक्त निधि से उपयुक्त खाते को अंतरित किया जाएगा।
- 25.20 वर्ष 2018-19 के दौरान, संस्थान ने भवनों की मरम्मत और आस्तियों के प्रतिस्थापन के लिए एक सिकिंग निधि का सृजन किया है, जिससे भविष्य में ऐसे व्ययों का वित्तपोषण किया जा सके। वर्ष के दौरान, 31 मार्च 2018 तक आईटीटी आरक्षिती को घटाकर संचयी अवक्षयण की सीमा तक 20,890 लाख रुपए की रकम को साधारण आरक्षिती से सिकिंग निधि में अंतरित किया गया है। 276 लाख रुपए की रकम का, जो आईटीटी आरक्षिती का वर्ष के लिए शुद्ध अवक्षयण था, सिकिंग निधि के प्रति विनियोग किया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में उद्दिष्ट निवेश किए जाएं और इन प्रतिभूतियों से उदभूत होने वाली आय का इस निधि में विनियोग किया जाएगा।
- 25.21 पुराने पैकेज से नए पैकेज में डाटा संपरिवर्तन से संबंधित कतिपय समस्याओं के कारण, सदस्यों से प्राप्त अग्रिम फीस, जिसकी रकम 3112 लाख रुपए थी और छात्रों से प्राप्त दूरस्थ शिक्षा की फीस की रकम, जिसका मूल्य 9471 लाख रुपए था, के ब्यौरेवार सूचीकरण को 31.03.2019 तक उपदर्शित नहीं किया जा सका था तथा सत्यापन हेतु संपरीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका था।
- 25.22 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम 1988 के विनियम 197 के अनुसार, परिषद् के संपरीक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे वास्तविक आय और व्यय की तुलना परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट प्राक्कलनों के साथ करें तथा सारवान विचलनों के संबंध में परिषद् को रिपोर्ट करें। निकट भविष्य में इस अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
- 25.23 संस्थान अनुपालन और प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा किए जाने को सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक तंत्र को स्थापित करने और साथ ही माल और सेवाओं के ऐसे विक्रेताओं की पहचान करने के लिए कार्यवाही कर रहा है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- 25.24 वर्ष के दौरान, प्राप्त सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस) में से 2138 लाख रुपए की रकम को सदस्य कल्याण निधि को अंतरित किया गया है। प्रथम वर्ष होने के कारण, परिषद् ने चालू वर्ष के लिए सदस्यता फीस के 20 प्रतिशत का अनुमोदन किया है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

26. कर्मचारी फायदे

परिभाषित अभिदाय योजनाएं

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 858.14 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 597.36 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

वर्ष के दौरान, संस्थान ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ने भविष्य निधि न्यास का बीमांकिक मूल्यांकन करवाया है। यह सलाह दी गई है कि भविष्य निधि स्कीम एक परिभाषित फायदा योजना है न कि कोई परिभाषित अभिदाय योजना। 200.15 लाख रुपए (शून्य रुपए) की शुद्ध कमी हेतु लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है। 31.03.2018 तक भविष्य निधि स्कीम को परिभाषित फायदा योजना के रूप में माना जाता था और उसका बीमांकिक मूल्यांकन नहीं कराया जाता था।

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

उपदान	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन	गैर-वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति	गैर-वित्तपोषित

26.01 उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(रुपए लाख में)

वर्णन		2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
1.	बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान				
	क. वर्ष के आरंभ में बाध्यता	3,298	2,510	2,358	2,213
	ख. चालू सेवा लागत	266	1,102	202	184
	ग. ब्याज लागत	239	176	166	169
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	442	(204)	44	(53)
	ङ. संदत्त फायदे	(340)	(286)	(260)	(155)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यता	3,905	3,298	2,510	2,358
2.	योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
	क. वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,277	2,325	2,292	2,232
	ख. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	188	165	183	191
	ग. बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	4	6	2	6
	घ. संस्थान द्वारा किया गया अभिदाय	1,045	84	132	78
	ङ. संदत्त फायदे	(1)	(303)	(284)	(215)
	च. वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,513	2,277	2,325	2,292
3.	योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान				
	क. बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य	3,905	3,298	2,510	2,358
	ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,513	2,277	2,325	2,292
	ग. तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	(392)	(1,021)	(185)	(66)

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
4.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
	क. चालू सेवा लागत	266	1,102	202	184
	ख. व्याज लागत	239	176	166	169
	ग. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	(188)	(165)	(183)	(191)
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	438	(210)	42	(59)
	ङ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	755	903	227	103
5.	निवेशों के ब्यौरे	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत
	क. अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां	100.00	100.00	100.00	100.00
6.	पूर्वानुमान				
	क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)	7.62%	7.65%	7.45%	7.92%
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)	7.65%	7.45%	7.45%	8.85%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	घ. संनिघर्षण दर	2%	2%	5%	5%
	ङ नश्वरता सूची	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा	आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा	आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा

26.02 सेवानिवृत्ति पञ्च पेंशन योजनाओं के ब्यौरे					
	वर्णन	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
1.	बाध्यता के प्रारम्भिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	11,890	11,115	5,086	2,684
	ख. व्याज लागत	874	813	357	211
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	79	378	6,063	2,210
	घ. संदत्त फायदे	(480)	(416)	(391)	(19)
	ङ वर्ष के अंत में बाध्यताएं	12,363	11,890	11,115	5,086
	वर्णन	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
2.	योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	12,363	11,890	11,115	5,086
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकम	(12,363)	(11,890)	(11,115)	(5,086)

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

	वर्णन	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
3.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
	क. व्याज लागत	874	813	357	211
	ख. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	79	378	6,063	2,210
	ग. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	953	1,191	6,420	2,421
4.	पूर्वानुमान				
	क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)	7.60%	7.50%	7.30%	7.90%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	ग. संनिघर्षण दर	2%	2%	5%	5%
	घ. नश्वरता सूची	आईएएल 1996-98 अंततोगत्वा	आईएएल 1996-98 अंततोगत्वा	आईएएल 1996-98 अंततोगत्वा	आईएएल 1996-98 अंततोगत्वा

छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरे

1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	4,137	3,873	3,468	3,097
	ख. चालू सेवा लागत	221	182	399	291
	ग. व्याज लागत	301	274	227	216
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	851	188	127	115
	ङ संदत्त फायदे	(406)	(380)	(348)	(251)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	5,104	4,137	3,873	3,468
2.	योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5,104	4,137	3,873	3,468
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमे	(5,104)	(4,137)	(3,873)	(3,468)
3.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय				
	क. चालू सेवा लागत	221	182	399	291
	ख. व्याज लागत	301	274	227	216
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	851	188	127	115
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	1,373	644	753	622

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

वर्णन	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
4. पूर्वानुमान				
क. बढ़ा दर (प्रतिवर्ष)	7.62%	7.65%	7.45%	7.92%
ख. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
ग. संनिघर्षण दर	2%	2%	5%	5%
घ. नश्वरता सूची	आईएएल 2012-14	आईएएल 2006- 08	आईएएल 2006-08	आईएएल 2006-08
	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा	अंततोगत्वा
27. खंड रिपोर्टिंग				
संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति के विनियमन" तक सीमित हैं और यह मुख्यतः भारत में प्रचालन करता है। अतः, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस) - 17 खंड रिपोर्टिंग के अर्थातगत एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।				
28. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तत्समान बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।				

ह./-
सी.ए. सुदीप श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

ह./-
राकेश सहगल
कार्यकारी सचिव

ह./-
सी.ए. अतुल कुमार गुप्ता
उपाध्यक्ष

ह./-
सी.ए. प्रफुल पी. छाजेड
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574 डबल्यू

खन्ना एंड अन्नाश्रानम
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 001297 एन

ह/
सी.ए. राजीव बसंल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598

ह/
सी.ए. बी.जे. सिंह
भागीदार, सदस्यता सं. 007884

नई दिल्ली
24 सितंबर, 2019

राकेश सहगल, कार्यवाहक सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./233/19]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2019

No. 1-CA(5)/70/2019.—In pursuance of sub-Section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the audited accounts and the Report of Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year ended 31st March 2019 is hereby published for general information.

70th Annual Report

The Council of ICAI takes immense pleasure in presenting its 70th Annual Report for the year ended 31st March 2019. Since the inception of the Institute on 1st July 1949 by an Act of Parliament, the chartered accountancy profession has grown tremendously. Founded with about 1,700 members, the Institute has today 2,91,698 members as on 31st March, 2019. The Report highlights the important activities of the Council and its various Committees during the year 2018-2019, besides the accounts of the Institute for the year ended on 31st March 2019. The Council also takes this opportunity to submit in this Report major initiatives, important events, statistical data relating to members, students, details of seminars, conference, workshop, training programmes organised during the period upto early July 2019. The Council acclaims its members and students for the respect which the Chartered Accountancy profession commands today in the society. This has been achieved through excellence, independence and integrity displayed by the members and students all along.

1. THE COUNCIL

The twenty-fourth Council was constituted on 12th February 2019 for a period of three years. It comprises of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government. Composition of the 24th Council is shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted, on 12th February 2019, various Standing and Non-Standing Committees/Boards and Groups to deal with the matters concerning the profession of Chartered Accountancy. During the year ended 31st March 2019, 236 meetings of various Standing and Non-Standing Committees / Boards and Groups of the Council were held.

3. AUDITORS

M/s. Shah Gupta & Co. and M/s. Khanna & Annadhanam were the joint auditors of ICAI for the financial year 2018-19.

4. STANDING COMMITTEE**4.1 Executive Committee**

Executive Committee is one of the Standing Committees of the Council of ICAI. The functions of this Committee have been prescribed in the Regulation 175 of Chartered Accountants Regulations, 1988. Some of these functions are relating to articulated and audit assistants and enrolment, removal, restoration of members from the Register, cancellation of certificate of practice, permission to engage in any other business or occupation other than profession of accountancy. Executive Committee is also the custodian of the property, assets and funds of the Institute beside maintenance of the Institute's offices.

4.2 Finance Committee

Finance Committee introduced vide the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both revenue and capital.

4.3 Examination Committee

Examination Committee performs all functions of the Council relating to examinations. The Committee conducted the Chartered Accountants Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Existing and Revised) Examinations smoothly all over the country and abroad. Details of the examinations conducted during the period under report are given below:

May 2018 Examinations – conducted in 475 centres from 2nd May to 17th May, 2018. The total numbers of candidates,

who appeared in the said Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Existing and Revised) and passed, were as follows:

	Appeared and Passed Group I only		Appeared and Passed Group II only		Appeared and Passed Both Groups/ Either of the Groups	
	Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed
Intermediate (IPC)	53149	5392	72146	10861	32878	6671
Intermediate	13135	3026	445	18	19108	8369
Final (Existing)	38696	6195	37350	5075	27727	6871
Final (Revised)	2289	260	1208	96	936	266

November 2018 Examinations - conducted all over the country and abroad in 470 centres from 1st to 18th November, 2018. The total numbers of candidates, who appeared in the said Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Existing and Revised) and passed, were as follows:

	Appeared and Passed Group I only		Appeared and Passed Group II only		Appeared and Passed Both Groups/ Either of the Groups	
	Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed
Intermediate (IPC)	40157	5051	68888	21708	25375	5577
Intermediate	24411	4525	8652	3724	21909	8095
Final (Existing)	32633	9934	35655	8348	22514	9466
Final (Revised)	6181	884	3307	894	4075	1505

	Appeared	Passed
Foundation Examination, May 2018	6315	1215
Foundation Examination, November 2018	48702	21488

Besides the above, the Common Proficiency Test [CPT] was held successfully on June 17th, 2018 and on December 16th 2018 across the country and abroad at 332 and 248 examination centres respectively. The total numbers of candidates who appeared and passed in the CPT are as under:

	Appeared	Passed
CPT held on June 17th, 2018	54474	15284
CPT held on December 16th, 2018	25037	9038

During the year, Post Qualification Course on Information Systems Audit – Assessment Test (ISA –AT) was held successfully on June 23rd, 2018 all over the country in 54 Examination centres. Another Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on December 22nd, 2018 all over the country in 62 examination centres.

The total numbers of candidates, who appeared in these examinations and passed, were as follows:

	Appeared	Passed
ISA – AT held on June 23rd, 2018	2768	1020
ISA – AT held on December 22nd, 2018	3211	1160

Insurance and Risk Management Technical Examination was held successfully in November, 2018 all over the country. The total numbers of candidates, who appeared in these examinations and passed, were as follows:

	Appeared	Passed
IRM – Technical Examination	47	25

International Taxation-Assessment Test (INTT-AT) for members was held successfully in May and November, 2018. The total numbers of candidates, who appeared and passed in this examination, were as follows:

	Appeared	Passed
INTT – AT held in May, 2018	176	13
INTT – AT held in November, 2018	193	51

The examinations of Post Qualification Courses in Management Accountancy Course (MAC) (Part-1), Corporate

Management Course (CMC) (Part-1), Tax Management Course (TMC) (Part-1), and International Trade Laws and World Trade Organization (ITL & WTO) (Part-1), were also conducted in November, 2018.

The Institute has continuously been improving its Examination Process right from the question paper setting up to declaration of results so that the integrity and sanctity of the examination system which is well known for around seven decades, are maintained and further strengthened and developed.

The Institute's examinations test the conceptual understanding as well as practical application of each of the topics covered in the CA curriculum so that the students could meet the expectations of the stakeholders of the profession. By focusing on analytical abilities of the students and by avoiding predictability of questions, Institute's examinations continue to ensure that those qualifying are well groomed professionals.

Special Examination: Arising out of the Mutual Recognition Agreement / Memorandum of Understanding entered with the foreign professional accounting body, the Special Examination for the members of CPA Australia, desirous of membership of ICAI, were successfully conducted from June 18th to 20th, 2018 in New Delhi.

E-Evaluation System: In another major first this year towards upgrading our examination system and making it more transparent, the project of Digital evaluation of answer booklets (started as Pilot Project in November 2017) was eventually rolled out in respect of two papers in May 2018 examinations and later rolled out for five papers in November 2018 examinations.

Centralised Evaluation: Centralised Evaluation as a pilot project of one paper in November 2018 examinations undertaken. Similar evaluation for Paper 6, Final (Existing Scheme) held in Hyderabad and Noida in December 2018/ January 2019.

Open Book methodology: Examinations under Revised Scheme of Education held concurrently with exams under Existing Scheme in May 2018. Foundation Examination held for the first time in May 2018. Paper 6 (Elective Paper) of Final (Revised Scheme) held on open book methodology for the first time in May 2018. All these were continued in November 2018 examinations also.

Web-Interface on Students Exam Life Cycle Management:-

ICAI embarked on an integrated web-interface called Student Exam Life Cycle Management Project, where CA students using a single user ID and password; can access various examination related services, including application for duplicate marksheets / pass certificates/transcripts, change of centre/medium/group, downloading admit cards, checking results, and applying for verification/seeking certified copies of answer books post result etc. from exam to exam.

New Examination Centres:- With a view to facilitate students to appear in the examination centres as nearer to their place of residence/ articulated training as possible, new examination Centres were opened as follows:

New examination centres for CA Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Existing and Revised) opened:

With effect from May 2018 examination onwards: Junagadh, Badlapur, Chandrapur, Palghar, Ratnagiri, Gondia, Yavatmal, Jalna, Parbhani, Haldwani, Banswara, Mandsaur, Muzaffarpur, Bhagalpur, Burhanpur, Chhindwara, Rewa, Satna and Sirohi

With effect from November 2018 examination onwards: Doha (Qatar).

New centres for CPT opened With effect from June 2018: Ambikapur, Raigarh, Balotra, Port Blair and Kalaburagi

4.4 Disciplinary Committee

The Disciplinary Directorate deals with cases of professional and/or other misconduct against its members, received either in the form of a formal complaint or through the "Information" route as provided under the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases), Rules, 2007.

As part of ICAI's continuous drive to uphold the credibility, integrity and image of the accountancy profession in India, the regulatory framework of ICAI has put in place a strong and vibrant disciplinary mechanism wherein proceedings are initiated and conducted through a well-defined procedure which consistently strives to ensure the principles of natural justice ensuring that the guilty of misconduct are punished.

ICAI not only performs its statutory duties as a regulator of the profession of Chartered Accountancy in India but had also enforced the ethical values as enshrined in Code of Ethics and proactively taken action against its erring members, found guilty of professional misconduct through its well-defined disciplinary mechanism as provided under the Chartered Accountants Act, 1949 and the Rules framed thereunder.

The disciplinary mechanism and the processes involved are designed in such a manner which enhances the confidence in the stakeholders and the public at large and at the same time give fair and equitable justice to the members involved in allegations of professionals and/or other misconduct.

(I) Salient initiatives/achievements during the current year:

- Five benches i.e. TWO benches of Board of Discipline and THREE benches of Disciplinary Committee have been constituted for expeditious disposal of pending disciplinary cases under enquiry.
- A separate and exclusive Bench for hearing cases of Public Interest matters as well as cases referred by the various regulators viz SEBI, RBI, SFIO, CBI has also been constituted. This Bench is headed by President, ICAI and two Government Nominees specifically nominated by Ministry of Corporate Affairs in this year as its member. Considering the principles of natural justice and fairness, the Bench maintained momentum in disposal of cases. The Disciplinary proceedings were promptly and suo moto initiated in case of PNB and IL&FS. In fact in case of IL&FS the preliminary findings of Director (Discipline) was one of the basis used by Ministry of Corporate Affairs before NCLT to seek its approval to recast the books of accounts of IL&FS as well as that of its other two group companies.
- A High Powered Group was constituted to look into the Punjab National Bank scam *vis-à-vis* role of allegedly erring members. Later, the Group submitted a well-received confidential report with regard to financial irregularities in PNB. Further, representations were also made to other regulatory agencies.
- A High-Powered Group was also formed to study the systemic issues in IL&FS matter and suggest remedial measures.
- The amendments relating to appearance through video conferencing before the Disciplinary Committee/Board of Discipline have been made in the Chartered Accountants (Procedures of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007. The modalities to this effect have been formulated.
- Filing of disciplinary complaint through online mode has been made live on the official website of ICAI by clicking the link – <https://icai.org/disciplinarydirectorate/>
- Process initiated for automation of entire disciplinary process and the said task is expected to be completed in coming 4-5 months.
- A group has been constituted for finalization of draft amendments to suggest the amendments in Chartered Accountants Act, 1949 and Chartered Accountants (Procedures of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007 so as to do away the major impediments in the expeditious disposal of disciplinary cases.
- With a view to conclude the residual cases pending under the Old Disciplinary Mechanism, the Disciplinary Committee (Under Section 21D), met frequently. As a result all residual cases were heard and concluded during the Year which also includes matters relating to audit of e-GTB for the financial year 2001-02 and 2002-03.
- The Reports related to e-GTB have been considered by the Council in May 2019. Upon consideration, the Council decided to accept the reports of Disciplinary Committee and also decided to recommend the same to the concerned Hon'ble High Court.

(II) Board of Discipline (under Section 21A) of the Chartered Accountants Act, 1949

The Board of Discipline has been constituted by the Council of ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of professional and other misconduct by members falling under First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and/or cases wherein the members are held prima facie NOT guilty of any misconduct by Director (Discipline).

During the year under review, the Board of Discipline held **20 meetings** (Bench I : 6 Meetings and Bench II : 14 Meetings) at various places across the country. In these meetings, the Board concluded its enquiry in **88 cases**, including

cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Board of Discipline is given below :

Board of Discipline (under Section 21A)–Period from 1st April, 2018 to 30th June, 2019

Sl. No.	Particulars	No. of cases
a)	No. of meetings of the Board of Discipline held during the aforesaid period	20
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.*	292
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years).	88
d)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years).	32

**including cases dealt with under Rule 6/12 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of cases) Rule, 2007.*

(III) Disciplinary Committee (under Section 21B) of the Chartered Accountants Act, 1949

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of professional misconduct by members which fall within the purview of Second Schedule or both First and Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949.

During the year 2018-19, three Benches of the Disciplinary Committee (under Section 21B) had been constituted i.e Bench I, II & III where Bench III is looking exclusively into cases of Govt./Regulators/Public Interest etc.

During the year under review, this Committee held 39 meetings (Bench I : 6 meetings, Bench II : 14 meetings & Bench III: 19 meeting) at venues in different parts across the country. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 153 cases, which included cases, referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Disciplinary Committee is given below:

Disciplinary Committee (under Section 21B) – Period from 1st April, 2018 to 30th June, 2019

Sl. No.	Particulars	No. of cases
a)	No. of meetings of the Disciplinary Committee held during the aforesaid period	39
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.	274
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years). <i>*including cases which have been referred</i>	153
d)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years). <i>*including cases which have been referred</i>	49

(IV) Disciplinary Committee under Section (21D)

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 conducts enquiry and submits its report to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the aforesaid Act in 2006. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary enquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon prima facie opinion, during the year under review, this Committee held 4 meetings and dealt with cases under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21(D)]

Statistics of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1st April, 2018 to 30th June, 2019.

Sl. No.	Particulars	No. of cases
---------	-------------	--------------

1.	(i) Number of cases concluded by the Disciplinary Committee during the above period	05
	(ii) Meetings of the Disciplinary Committee under Section 21D held during the aforesaid period	04
2.	Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council (including reports of those cases in which hearings were concluding by the Disciplinary Committee during the earlier years).	03
	Out of the above	
	a) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule for affording an opportunity of hearing before the Council before passing an order under Section 21(4) of the Chartered Accountants Act, 1949.	NIL
3.	b) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the Second Schedule and/or other misconduct to be referred to High Courts under Section 21(5) of the Chartered Accountants Act, 1949.	02
	c) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule and the Second Schedule/other misconduct	NIL
	d) Number of cases referred back to the Disciplinary Committee for further enquiry.	NIL
	e) Number of cases in which Respondents have been found not guilty of any misconduct.	01
4.	Number of cases in which Orders passed under Section 21(4) in respect of the Respondents who were found guilty under the First Schedule.	NIL
5.	Number of cases disposed of by the High Court under Section 21(6)	04

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board (ASB)

(I) Upgrading Financial Reporting Standards:

➤ In March, 2019, Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2019 notified Ind AS 116, Leases replacing Ind AS 17 and Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rules, 2019 and issued certain amendments to Ind AS *related to following areas*:

- Appendix B, Uncertainty over Income Tax Treatment to Ind AS 12
- Annual Improvements to Ind AS (2018) (Corresponding to Annual Improvements to IFRS Standards 2015–2017 Cycle issued by the IASB)
- Plan Amendment, Curtailment or Settlement (Amendments to Ind AS 19, Employee Benefits)
- Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to Ind AS 109, Financial Instruments)
- Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to Ind AS 28)

➤ Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rules, 2018 were notified on September 20, 2018. These Rules contain limited amendments to Ind AS 20 to allow entities the option of recording non-monetary government grants at a nominal amount and presenting government grants related to assets by deducting the grant from the carrying amount of the asset.

➤ Schedule III- Division III to the Companies Act, 2013 for presentation of financial statements of Non-Banking Financial Company (NBFC) notified by Ministry of Corporate Affairs in October, 2018.

➤ In addition to the above, following amendments were cleared by the Council of ICAI:

- Definition of Business (Amendments to Ind AS 103)
- Definition of Material (Amendments to Ind AS 1 and Ind AS 8)
- Amendment to Ind AS 40, Investment Property

ASB continued its efforts to upgrade the existing Accounting Standards to bring them nearer to Ind ASs and in this regard following exposure drafts of upgraded Accounting Standards were issued by ASB:

- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 34, Interim Financial Reporting
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 17, Leases
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 41, Agriculture

- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 11, Construction Contracts
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 18, Revenue
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 1, Presentation of Financial Statements
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 40, Investment Property
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 19, Employee Benefits
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 109, Financial Instruments

(II) Implementation Support

Following Guidance Note/ FAQs/Announcement were issued:

- FAQ on accounting treatment of increase in liability due to enhancement of the gratuity ceiling
- Announcement for withdrawal of the Guidance Note on Accounting for Real Estate Transactions (for entities to whom Ind AS is applicable)

(III) International initiatives: Forging long lasting partnership

Comments submitted on the following Exposure Drafts/Discussion Papers issued by the International Accounting Standards Board (IASB) were submitted to the IASB:

- Exposure Draft on Accounting Policy Changes Proposed amendments to IAS 8
- IASB's Discussion Paper on 'Financial Instruments with Characteristics of Equity'
- Exposure Draft 'Onerous Contracts- Cost of fulfilling a contract - Proposed amendments to IAS 37
- Exposure Draft "Interest Rate Benchmark Reform (Proposed amendments to IFRS 9 and IAS 39)"
- Tentative Agenda Decisions (TAD) issued by the IFRS Interpretations Committee
- **Global Collaborations/MoUs/MRAs:** India, being a member of AOSSG Financial Instruments Working Group, received an accounting issue regarding interests in an Associate held via instruments other than ordinary shares and ICAI inputs on the same were provided to the Working Group.
- On the historic day 2nd October, 2018; being birth anniversary of the Father of our Nation, Mahatma Gandhi, ICAI on behalf of Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India signed a Memorandum of Understanding (MOU) and Licence Agreements with IFRS Foundation in London. This MoU formalises the mutual understanding and acceptance about the rights of each of the parties in the copyrights in IFRS Standards and Indian Accounting Standards (Ind AS).
- A Week of Global Partnership:
 - A series of interactive meetings and conferences were organized to bring together the Indian stakeholders and the international bodies. "Interaction of IASB official with National Regulators" was organised on 10th April, 2018,
 - "IFRS – 17 (Ind AS 117, Insurance Contracts) Insurance Industry Outreach" and ICAI – IASB Joint Stakeholders' Seminar on "IFRS 9 (Ind AS 109) ECL Model Challenges in Banking Industry were organised on 11th April, 2018, which were attended by relevant stakeholders.
 - A meeting of International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) was held on April 12-13, 2018 at Mumbai. Over 60 delegates from more than 25 jurisdictions, including prominent ones i.e. US, Europe, Japan, Australia etc, took part in the event where at an issue regarding 'Consolidation of Not-for-profit entities under IFRS 10' was presented by India
- CA. S.B. Zaware, Past-Chairman, ASB, (year 2016-19) being Vice Chair, Asian Oceanian Standard Setters Group (AOSSG), was nominated to represent AOSSG at Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) for a period of 3 years from 1.12.2018 to 30.11.2021. ASAF is a critical consultative body of IASB & IFRS Foundation.
- IFRS Foundation Trustees appointed CA. M P Vijaykumar, Chairman, ASB, as a member of IFRS Advisory Council representing SAFA with effect from January 1, 2019. The IFRS Advisory Council advises the IFRS Foundation Trustees and the IASB on both strategic and technical matters.

ASB continued its contribution and collaboration with International Accounting Standards Board for developing high quality global accounting standards. ICAI representatives participated in the meetings of various international forum, viz. World Standards-Setters (WSS), Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG), Emerging Economies Group (EEG)

and International Forum of Accounting Standards Setters (IFASS) as follows:

- 17th Emerging Economies Group (EEG) meeting held from March 25–27, 2019 & International Forum of Accounting Standards Setters (IFASS) held from March 28–29, at Buenos Aires, Argentina. The ICAI had sent the papers on following two topics for discussion:
 - At EEG – Paper on IAS 20: Government Grants Receivables
 - At IFASS –Presentation of an item on Finance Costs - IAS 1, IFRS 7 & IAS 23.
- Meeting of Chair's Advisory Committee (CAC) held on 29th January 2019 at Kuala Lumpur, Malaysia
- Joint Meeting of CAC Members of AOSSG and the Trustees of IFRS Foundation held on 30th January 2019 at Kuala Lumpur, Malaysia
- Chair and Advisory Committee (CAC) meeting with IFRS Foundation trustees held on September 30, 2018 at London and November 20, 2018, at Singapore.
- Chair and Vice Chair (CVC) teleconference meetings were held on July 19, 2018, and September 14, 2018, and Chair's Advisory Committee (CAC) teleconference meetings were held on July 26, 2018.
- IFASS meeting was held on October 2-3, 2018 at London, UK, whereat a paper on "Treatment of stamp duty on acquisition of Property in Business Combinations" was presented.
- 10th Annual AOSSG meeting was held on November 22-24, 2018 at Singapore whereat issues on 'Accounting Issues involved in Bullion (Gold) Lending and Borrowing' was presented and AOSSG Interim Meeting held on 30th September, 2018, London.
- 16th Emerging Economies Group (EEG) meeting was held on October 29-31, 2018 at Seoul, South Korea, whereat various technical matters, for e.g., Discussion Paper on Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE) issued by IASB, Goodwill and Impairment etc., were discussed.
- World Standard-Setters (WSS) Conference was held on October 1-2 2018 at London.
- 15th Emerging Economies Group (EEG) meeting was held on May 17-18, 2018, at Kuala Lumpur, Malaysia whereat following 2 papers were presented by the ICAI representatives:
 - Consolidation of not-for-profit entities
 - Presentation of current/non-current assets
- The quarterly ASAF meeting was held on 1-2 April 2019 at London whereat ASB had submitted its views to the AOSSG Secretariat, China on the following agenda items post which the Working Group Leaders had consolidated the comments and shared the same at the Forum:
 - SMEs that are subsidiaries
 - Accounting Policy Changes (Proposed amendments to IAS 8)
 - Onerous Contracts - Cost of fulfilling a Contract
- IFRS Advisory Council (IFRS AC): The ICAI representative attended the meeting of IFRS AC which was held on March 19-20, 2019 at London, UK which dealt with Disclosure of Sensitive information, Comprehensive Review of the IFRS for SMEs Standard— Scope of the IFRS for SMEs Standard. The ICAI representative participated in a breakout session on Disclosure of Sensitive information.

(IV) Building robust relationship with Regulatory Bodies:

ASB submitted views on the accounting issues referred by various Regulators and, wherever felt appropriate, various accounting issues were taken up with the relevant Regulators, namely:

- Ministry of Corporate Affairs :
 - Ind AS Core Group meeting was held at Ministry of Corporate Affairs on May 25, 2018, ASB described the provisions relating to Revenue recognition with reference to real estate sector. Apart from this,

- NBFCs' request for deferment of Ind AS to April 2019 was also discussed.
 - On request of Ministry of Corporate Affairs (MCA), ASB has undertaken to facilitate drafting of new Rules under Companies Act, 2013 mirroring existing Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 for submission to NFRA.
 - 1st meeting of National Financial Reporting Authority (NFRA) was held on March 14, 2019, at New Delhi which was attended by ICAI Officials. Ind AS 116, Leases and other amendments to Ind AS recommended by the ICAI were presented to NFRA in the said meeting.
 - Meeting of Core Group of Ministry of Corporate Affairs - Ind AS implementation, was held on April 24, 2019 at New Delhi whereat discussion on Ind AS implementation Roadmap of Banking Sector and Insurance Sector, formulating multifaceted threshold criteria for all the entities for implementation of Ind AS based on key parameters of Paid-up share capital, Net Worth, Turnover and Profit After Tax (PAT) etc were held.
- With a view to ensure smooth implementation of Ind AS, various outreach programmes and workshops were organised with Regulators, Industry Associations and other stakeholders. During last year, numerous outreach meetings on some of the standards such as Ind AS 109 Financial Instruments, Ind AS 115 Revenue from Contracts with Customers, Ind AS 116 Leases and Ind AS 117 Insurance Contracts were organised as a proactive measure, before finalisation of new Ind AS at various locations in India, namely; New Delhi, Mumbai and Pune.

(V) Other Initiatives:

Publications issues: The Board issued the following publications for the benefit of the Institute's members at large:

- Released First set of Compendium of Indian Accounting Standards effective as on April 1, 2018 along with E-version of Ind AS guidance Material of IFRS Standards comprising IFRS Part B (Illustrative Examples and Implementation Guidance) and IFRS Part C (Basis for Conclusions).
- Indian Accounting Standards (IFRS converged) - Successful Implementation Impact Analysis and Industry Experience
- Indian Accounting Standards : Disclosure Checklist
- E-version of second edition of *Compendium of Indian Accounting Standards (Ind AS)* as on April 1, 2019 was released on May 1, 2019. Promptly thereafter, background material of IFRS Standards comprising IFRS Part B (Illustrative Examples and Implementation Guidance) and IFRS Part C (Basis for Conclusions) was also released on May 7, 2019.
- Third edition of *Indian Accounting Standards: An Overview* was released in July 2018 jointly with Ind AS Implementation Committee which captures all the recent amendments to Ind AS notified by the Ministry of Corporate Affairs till March 2018 specifically issuance of revenue standard (Ind AS 115) and other consequential amendments thereto.
- On July 1st, 2019 on the occasion of Platinum Jubilee Celebrations; following publications were also released:
 - Accounting Standards: Quick referencer
 - Compendium of Accounting Standards
 - IFRS 9 Financial Instruments, A Study: Transition Impact on Banks Across the Globe
 - Technical Guide on Accounting treatment of Bullion (Gold) Lending and Borrowing Transactions.
 - Compendium of Ind AS (print version).
 - Forth edition of *Indian Accounting Standards: An Overview* jointly with Ind AS Implementation Committee capturing the recent amendments to Ind AS notified by the Ministry of Corporate Affairs till March 2019

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB)

The erstwhile Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB) of ICAI had worked in the direction of prescribing high quality Accrual Accounting Framework for third tier of government (Local-self Government), i.e., Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) since 2005. CASLB was also involved in providing technical inputs on the documents/ drafts of Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB)/International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB). CASLB was also imparting trainings to Local Bodies and various stakeholders such as end users and citizens about the benefits of the accounting reform process in Government and Local Bodies.

During 2019, the Committee on Accounting Standards for Local Bodies was renamed as Committee on Public Finance and Accounting Standards for Local Bodies in the year 2019-20 continuing further with the task being performed by the erstwhile Committee on Public Finance and Government Accounting in 2018.

Important activities undertaken from April 1, 2018 to February 11, 2019:**(I) Formulation of Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) and other projects:**

- ASLBs issued: ASLB 2, 'Cash Flow Statements' and ASLB 20, 'Related Party Disclosures'
- The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Local Bodies submitted to the Council for its final approval.

(II) Seminars/Conferences/ programmes

- One day seminar on '*Issues under Direct Taxes (Trusts & Local Bodies)*' jointly with Direct Tax Committee (DTC) held on May 19, 2018 at Jodhpur (Rajasthan) hosted by the Jodhpur Branch of ICAI.
- Two days National Conference on '*PRAVAAH*' jointly with Corporate Laws & Corporate Governance Committee (CL&CGC) held on August 24-25, 2018 at Jaipur (Rajasthan) hosted by the Jaipur DCO.
- One day seminar on '*Income Tax*' held on September 1, 2018 at Bhilai hosted by the Bhilai Branch of CIRC of ICAI.
- Two days National Conference on '*Srijan : Vikash Ki Or*' held on November 17 – 18, 2018 at Ranchi hosted by the Ranchi Branch of CIRC of ICAI
- Three Days Residential Refresher Course jointly with Banking, Financial Services and Insurance Committee held on November 24 – 26, 2018 at Salasar Balaji, (Churu, Rajasthan) hosted by the Sikar Branch of CIRC of ICAI
- Two days National Conference on "*Gyanoday*" - Spectrum of Professional Excellence jointly with Banking, Financial Services and Insurance Committee held on January 5 – 6, 2019 at Udaipur hosted by the Udaipur Branch of CIRC of ICAI

(III) Technical Comments submitted:

- The comments submitted to International Public Sector Accounting Standards Board's (IPSASB) on the documents/Consultation Papers/Exposure Drafts : Document on 'Strategy and Work Plan 2019-2023' & Exposure Draft (ED) 64 of IPSASB on 'Leases'.
- The comments submitted to Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB)'s documents on the Agenda of 32nd board meeting of GASAB held on May 17, 2018, "Due process" and "Preface to Indian Government Accounting Standards & Indian Government Financial Reporting Standards" of GASAB, Modified Indian Government Accounting Standard (IGAS) 2, 'Accounting of Grants-in-Aid', Modified IGAS 3, 'Accounting of Loans & Advances', and Agenda of 33rd board meeting of GASAB held on October 30, 2018.
- The inputs submitted on agenda papers of meeting of Public Sector Financial Management Committee (PSFMC) of CAPA held on August 16 & 18, 2018 at Vietnam.

5.3 Auditing & Assurance Standards Board (AASB)**(I) Representations/suggestions**

During the period under report, the Board submitted the following representations/suggestions to various Ministries and Regulators:

- The Board submitted "Suggestions on New Indicators of Early Warning Signals for inclusion in the RBI's Master Directions on Frauds – Classification and Reporting by commercial banks and select FIs" to Shri Y. H. Malegam, Chairman of Expert Committee on NPAs and Frauds constituted by RBI.
- Chairman, AASB attended a meeting with the NFRA Chairman and members held on 26th October 2018 at NFRA Office, New Delhi. At the meeting, Chairman, AASB made a presentation about the activities of AASB and the standard setting process followed by AASB for formulation and issue of auditing standards.
- SEBI constituted a Group to prepare Guidelines on new Regulation 33(8) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended. Inputs of ICAI were sought on the draft Guidelines prepared by the Group. The Board considered the draft Guidelines and submitted its views thereon to SEBI.

(II) Publications Issued

The Board issued the following publications for the benefit of the Institute's members at large:

- Handbook of Auditing Pronouncements 2019 Edition.
- Guidance Note on Audit of Banks 2019 Edition.
- Guidance Note on Reports in Company Prospectuses (Revised 2019).
- Implementation Guide to SA 230, Audit Documentation (Revised 2018).

- Implementation Guide on Resignation/ Withdrawal from an Engagement to Perform Audit of Financial Statements.
- Implementation Guide to SA 610(Revised), Using the Work of Internal Auditors.
- Technical Guide on Audit of Urban Improvement Trusts and Development Authorities.

(III) Other Technical Accomplishments

- The Board developed the Auditor's Report Formats for Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs) and submitted the same to the Accounting Standards Board for onward submission to SEBI.
- The Board issued the Illustrative Auditor's Certificate on Return of Deposits pursuant to Rule 16 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, as amended.
- The Board submitted its comments on the Exposure Draft of ISA 315 (Revised), "Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement" issued by the International Auditing and Assurance Standards Board for public comments.

(IV) Initiatives for Members

- The Board organized various seminars, workshops and awareness programmes on auditing standards, bank audit and other auditing aspects for awareness and professional enhancement of the members. Programmes were held in Kolkata, Indore, Mumbai, Jaipur, Bangalore, Chennai, Coimbatore, Visakhapatnam, Bilaspur, Bhopal, Siliguri, Dibrugarh, Guwahati, Asansol, Bhilai and Raipur during the year.
- The Board jointly with the Professional Development Committee of ICAI, organized series of interactive seminars for central statutory auditors of banks held in January & February, 2019 at Kolkata, Delhi, Chennai and Mumbai.
- The Board organized Two Days National Conference on "Auditing & Beyond" at Jaipur in November 2018 which was attended by more than 2000 participants.
- The Board organized Two Days National Conference on Bank Audit, Companies Act & GST at Bhopal in March 2019. The conference was attended by more than 500 participants.
- The Board organized live webcast on "Commonly found Non-Compliances of SAs and Revised Reporting Standards" at Mumbai on September 4, 2018.
- The Board organized live webcast on SA 701, "Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report" at Mumbai on April 8, 2019 & April 11, 2019.
- Like earlier years, the Board constituted an online panel of experts to address the members' queries regarding bank branch audits for the financial year 2018-19. The panel resolved members' queries from April 1, 2019 till April 15, 2019.
- The Board issued the announcements/clarifications for guidance of the members:
 - Clarification on Auditor's Certificate on Return of Deposits pursuant to Rule 16 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.
 - Requirement of Mentioning UDIN while Signing Audit Reports.
 - Using Information Available at Information Utility (IU) Platform for External Confirmations.
- The Board provided replies/clarifications to various queries on auditing aspects received from the members from time to time.

(V) Contribution at International Platform

- Chairman, AASB represented ICAI at the meeting of the International Auditing and Assurance Standards Board held in September 2018 at New York.
- Chairman, AASB and Vice-Chairman, AASB represented ICAI at the meeting of the International Auditing and Assurance Standards Board held in December 2018 at New York.
- Chairman, AASB represented ICAI at the meeting with Audit and Assurance team of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) held in September 2018 at London.
- Chairman, AASB represented ICAI at the IAASB-NSS Meeting held in November 2018 at Sydney.
- Vice-Chairman, AASB represented ICAI at the IAASB-NSS Meeting held in May 2019 at Paris.

5.4 Banking, Financial Services and Insurance Committee

The Committee organized the following activities during the year:

The Committee presented its views on "The Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill, 2017" at the Meeting of the Joint Parliamentary Committee at its meeting held on 14th May 2018.

- The Committee had organised Two Days Workshop on Blockchain for Financial World on 22nd -23rd June 2019 at Mumbai.
- The Committee supported IMC Chamber of Commerce and Industry for conducting 10th Banking & Finance Conference -“India a Ten Trillion Dollar Economy by 2030: Role of Banks” organized on 14th June 2019 at Mumbai.
- With the support of the Committee, eight programmes on banking and financial services were organised by the Branches of ICAI for the benefit of members and public at large.
- The Committee had organised two Webcasts on the topics having professional relevance and interest during the period.
- Three batches of the Orientation Programmes for the DIRM Technical Examination passed members of ICAI were organised during the period.

There were 5244 registrations to the DIRM Course as on 30th June 2019.

5.5 Committee for Capacity Building of Members in Practice (CCBMP)

The Committee for Capacity Building of Members in Practice (CCBMP) is a non-standing Committee which was formed in February, 2010. Objective of the Committee is to strengthen CA firms as well as Small & Medium Practitioners to rejuvenate their practice portfolio. The Committee works to create awareness amongst CA firms on capacity building through consolidation by networking, merger & setting up management consultancy services firm and popularizing the concept of union through arranging workshops, symposia and summit on the benefits of consolidation and endurance to better accounting, auditing and ethical standards. The Committee assists Small & Medium Practitioners in improving their visibility amongst the business community and also attempts to create additional professional opportunities for them.

The Committee for Capacity Building of Members in Practice (CCBMP) performed following activities during the year.

(I) Office Management

The Committee has arranged the ‘Tax Cloud’ software on Web based ITR & TDS Return Preparation for practicing Chartered Accountants & CA Firms of ICAI. The aforesaid software is free of cost for 2 financial years to the Practitioners & CA Firms. The aforesaid software enables Income Tax Return and TDS Return preparation, provides all types of assesses support including Individuals, HUFs, Firms and Companies, calculates Income Tax under all heads such as Salary, House Property, Capital Gain, Business and Profession, Other and Exempt Income Heads, generates detailed computation of Income Tax Returns, PDF for paper filing and XML for e-Filing, automatic data backup every night for CAs for cloud servers.

- In order to enable members to have access to antivirus software; institution tie up has been made with a leading antivirus software provider for providing access to Antivirus Software at a special discounted price from March, 2018 to March, 2020 for single user for a period of 3 years for the Members & students of ICAI. Details of above are available at www.icai.org or https://icai.org/post.html?post_id=11505.
- The Committee has arranged the practice management software for members in practice / firms, in form of cloud software designed for managing the Professional Practice in an effective way. The scope and function of aforesaid software Assignment management – Long duration, Assignment Management - Short duration, Work allocation and tracking, Timesheet recording, Variance and Profitability analysis, Leave management, Expense management, Meeting management, Mobile based GPRS based attendance management, Mobile app and portal based system, Customer Relationship Management (CRM), Invoicing, Collection Management, BI and Analytics tool. https://www.icai.org/new_post.html?post_id=15286.

(II) Insurance Schemes

- *LIC Group term Insurance:* specially designed Group Term Insurance through the LIC for Members of ICAI. The Term Insurance policy will cover death due to any reason. Details are available at https://www.icai.org/new_post.html?post_id=15416
- *Motor Vehicle Insurance for Members, Students of ICAI:* A MOU with New India Assurance Co. Ltd for Motor Vehicle Insurance was arranged by the Committee. The Motor Vehicle Insurance is basically designed for the members but also has been extended to the students and employees of ICAI. The Motor Vehicle Insurance for which MOU is being executed has value added features such as Unique Offer of 65% discount (on erstwhile Tariff Rate) for both Private car and two Wheeler etc. Members and students may purchase the Motor Vehicle Insurance Policy online at the website <http://icai.newindia.co.in>.

- *Arrangement for Office Protection Shield Insurance at special premium for the Members in Practice/CA Firms:* The Committee has arranged Office Protection Shield Insurance at special premium for members of ICAI. Members and CA firms desirous to avail the benefits of the aforesaid scheme may please visit <http://icai.newindia.co.in> & online solution for the same.
- *Professional Indemnity Insurance for Members & CA Firms of ICAI:* The Committee has arranged insurance protection for members in practice/firms in the form of specially designed professional indemnity insurance at a reasonable premium i.e. 85% discount in market rate. The scheme is for the Members in practice/ Firms of the ICAI. Members and CA firms desirous to avail the benefits of the aforesaid scheme may please visit <http://icai.newindia.co.in> & online solution for the same.
- *Personal Accident Insurance for Members of ICAI:* The Committee arranged specially designed Personal Accident Insurance through the New India Assurance Company Limited, Mumbai for Members & Students of ICAI. The Personal Accident Insurance policy will cover Death/Permanent Total Disability, loss of Limb(s) & Permanent Partial Disability including reimbursement of hospitalization expense. Members desirous to avail the benefits of the aforesaid scheme may please visit <http://icai.newindia.co.in> & online solution for the same.
- *Householder's Insurance for Members of ICAI:* The Committee arranged specially designed Householder's Insurance through the New India Assurance Company Limited, New Delhi for Members of ICAI. The Householder's Insurance policy covers insurance of building and contents against fire & allied perils inclusive STFI & EQ, housebreaking including larceny & theft, jewellery & valuables, employers liability (WC) on annual wages etc. Members desirous to avail the benefits of the aforesaid scheme may please visit <http://icai.newindia.co.in> & online solution for the same.

(III) Capacity Building Measures

- *MOU with World Bank for Procurement Audit:* The Committee entered a MoU with the World Bank for the arrangement of Knowledge enhancement of the Members of ICAI in Procurement Audit & thereof. This arrangement with the World Bank offers procurement training with the Joint Certification basis to the participants of the training programme. These trainings are meant to enhance the capacity of ICAI members to participate in procurement opportunities in Bank funded Projects for various assignments including external/internal audits; procurement audits/post reviews, and other consultancy assignments for firms and individual members of ICAI.
- *Certificate Course on Preparation of Appeals, Drafting of Deed & Documents and Representation before Appellate Authorities and Statutory Bodies:* The certificate course on Preparation of appeals, Drafting of Deed & Documents and Representation before Appellate Authorities and statutory bodies is developed for the knowledge enhancement of the effective drafting skills of members and acquaints the members with the legal provision pertaining to appearances before various authorities. As Chartered Accountant has been recognized under various Acts to appear as an authorized representative before various tribunals/quasi judicial bodies, therefore it is essential for members to demeanour professional and proficient image in the corporate world as well as while appearing before the tribunals and other quasi judicial bodies. Every efforts has been made to designed the full fledged certificate course so that members may enhance necessary acumen in drafting documents and appearances before Statutory bodies .
- *Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning (WMFP):* This course has been launched for enhancing new career opportunities for the members. The objective of this Course is to equip the members knowledge in principles of Financial Planning and Management of Wealth through guidance on Investments and Retirement Benefits by effective Investment Strategy. The course elaborates practical procedural aspects of Wealth Management in order to build the core competency of the members for their enhanced career opportunity in financial services. For course details please visit <https://resource.cdn.icai.org/35876ccbcaf25359-wmfp-details.pdf>
- *Revised Minimum Recommended Scale of the fees for the Professional Assignments done by the Chartered Accountants for Class 'A' & Class 'B' cities:* The Committee has issued Revised Minimum Recommended Scale of the fees for the Professional Assignments done by the Chartered Accountants for Class 'A' & Class 'B' cities.
- *Quick Insight 2018:* The Committee released Quick Insight 2018 for the CA fraternity, highlighting latest developments in the profession. The Quick Insight contains important information on tax, accounting & auditing standards, limited liability partnership, Management consultancy services, statements and standards and standards on audit as well as information on important forms related to CA students https://www.icai.org/post.html?post_id=14719
- *Publication of E-Book on "Ready Reckoner on Regulatory Aspects of ICAI for Members & CA Firms":* publication of E-book on "Ready Reckoner on Regulatory Aspects of ICAI for Members & CA Firms" is a reference book which will provide the practitioners with all requisite information to comply with the various regulatory aspects of ICAI. It compiles the information on all important areas of the profession like Enrolment, registration and other regulatory aspects of ICAI for the Members & CA Firms and will be of great benefit to the practitioners and is available at https://www.icai.org/post.html?post_id=14807

- *Publication of E-Book on “Ready Reckoner on Regulatory Aspects of Articled/Audit Assistants:* A reference book which will provide the practitioners & CA Firms with all requisite information to comply with the various regulatory aspects of Articled/Audit Assistants. It compiles the information on all important areas of the Articled/Audit Assistants like Engagement, Stipend/Remuneration, Working Hours and other regulatory aspects with respect to CA Firms/Practitioners and is available at https://www.icaai.org/new_post.html?post_id=15063&c_id=240
- *Networking of CA firms:* Networking of Firms is a facility provided to CA Firms for collective association to share collective resources for providing better professional services making it available at multi location places. The Committee has considered practical difficulties in consolidation of CA Firms – formation of Networking. Various impediments have been examined and to address these issues, the Committee has appropriately finalized the revised Guidelines of Networking facilitating members and firms for its easy adoption.

(IV) Knowledge sharing & Enhancement

- *ICAI Learning Curve–Consolidation of Queries and Solution for Queries by FAQs and Live Webcast:* The Committee arranged a portal; ICAI Learning Curve for Consolidating the Query on Various Professional Issues and answers these queries in multiple phases for enhancement of the Practice portfolio and other aspects. The Committee captures the queries of Members in Practice, Women Members & Senior Members by means of the aforesaid portal. The Queries will be reproduced by means of the Frequently Asked Questions and the answers. The answer of the queries will be covered along with other professional aspects in live webcast organised by the Committee.
- *Portal <http://kb.icaai.org/>: a gateway to ICAI Knowledge Bank – Consolidation of ICAI Publications:* The Committee arranged the portal kb.icaai.org gateway to ICAI Knowledge Bank for Consolidation of all the Publications of ICAI. The portal is designed for search/Advance search facility and management of publications and user will be able to search uploaded documents with a key phrase. System will show list of documents showing each results along with page numbers, keyword sentence, and link to download & view the pdf document, user will also have functionality to share this document link through email, advanced search interface that will provide user access to search limited to category, section, publication date and result sorting and there will also be display of related searches for keywords that have been searched by other users in the past. The said portal includes the Publications of ICAI, ICAI Journal & Newsletter of the Committees, Branches & Regional Councils and the other publications consolidated in the portal.
- *ICAI Connect – A self-service portal (<http://ssp.icaai.org/>) for members of ICAI:* The Committee has launched the ICAI Connect, a self-service portal for the members of ICAI. The features of the aforesaid single window self-service portal includes viewing personal Profile and firms constitution, Announcements of ICAI, details of payments of fees and regulatory charges, My Articles details, tracking regulatory forms and application status, e-Services, My Firms, My Software(s), Letters & Certificates, CPE Hours credited, Guidelines of Networking, Merger & Demerger etc.
- *Committee’s exclusive website www.icaai.org.in:* The website provides a platform for the CA Firms to upload their firms’ details and gives them an opportunity to reach out to the members and CA firms practicing worldwide. The website also acts as a forum for consolidation of the members and CA Firms by providing for consolidation measures like Networking, Merger and Corporate Form of Practice.
- *A portal for Senior Members of ICAI www.seniormembers.icaai.org:* The Committee has developed a website namely www.seniormembers.icaai.org which provides a platform for senior members of ICAI for getting flexi working hours assignment as well as fulltime assignment after their retirement. At the same time it also helps industry to tap experienced talent pool which might not be accessible otherwise in normal course. The said portal would be useful & handy to all the senior members of ICAI.
- *LEAD - A Diversity Support for Women CAs through <https://www.cpeicai.org/cpe-qna/> :* An Initiative by the Committee for Capacity Building of Members in Practice ((CCBMP) & CPE Committee: The Committee for Capacity Building for Members in Practice (CCBMP) & Continuing Professional Education Committee (CPEC) present LEAD – A Diversity Support Initiative where Women CA’s in any stream can ask questions on Personal development, Professional Enhancement and strategies to stay empowered and be leaders. Questions will be answered by a Panel of Experts in a few days time. Queries are enabled through a platform i.e. Samadhan link - <https://www.cpeicai.org/cpe-qna/>. It may be mentioned that the below should be kept in mind while asking queries:
 - Querist can ask a query only on the topic Personal development, Professional Enhancement and strategies to stay empowered and be leaders that has been opened for the QnA Session.
 - Queries outside of the session topic is not addressed.
 - It will be the endeavour of ICAI to enable the responses within a reasonable time frame having regard to the number of questions received.
 - Only one question per querist is permitted in the present session.

- *SETU*-Bridging the Gap between Women Members & CA Firms: The Committee is organizing regular Programmes/ Seminars of Women Empowerment, along with the SETU Programme i.e. bridging between Women Members of ICAI and Practicing CA Firms all across India.
- E-Booklet on Sample Checklist on SAs: Ready Reference for the Practitioner & CA Firms: The Committee comes up with a publication on E-Booklet on Sample Checklist on SAs: Ready Reference for the Practitioner & CA Firms. The same is used for day to day work of the Practitioners & CA Firms.

(V) Publications of the Committee

- Publication of E-Book on Roadmap to Income Tax Practice : A Practitioner Perspective
- “Practiquer”- Quarterly e-Newsletter for the Chartered Accountants
- Publication of E-Book on Companies Act, 2013: A Practitioner Perspective
- Publication of E-Book on Roadmap to GST: A Practitioner Perspective

(VI) Live Webcast, Conference, Seminars and residential programmes

CCBMP organized 11 live webcasts for the capacity –building measures of practitioners on practice Management, Appellate Procedures under Income Tax, professional opportunities in International Arena & RERA, on Benami Law and Insolvency & Bankruptcy Code, Common Mistakes in GST Returns & Audit, Drafting, Pleading and conveyance, Tax Audit, GST Audit, special reference to Recent Changes in ITR Forms and Fair Value Measurement Under Ind AS at the ICAI Bhawan, Mumbai Delhi Indore and Bangalore. The Committee organized 56 national conferences, seminars and residential programmes on the similar topics at Bhubaneswar, Munnar, Kollam, Shirdi, Mussoorie, Tirupati, Ranchi, Goad, Jodhpur, Ernakulam, etc. during the year wherein many members were participated in the programmes.

5.6 Continuing Professional Education Committee (CPE Committee)

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through its Continuing Professional Education (CPE) Committee (now CPE Directorate from Council year 2019-20) has been working very hard and takes number of initiatives to keep its Members updated with the recent advancements in existing and emerging areas.

The profession of Chartered Accountancy has always been recognised for the quality of education, training and strong grip over technical standards. Thus, not only the Chartered Accountants are required to keep themselves up to date but also there is a need to acquire new knowledge in response to the challenges of new business requirements and professional environment. Continuing Professional Education is the forum by which these professionals maintain, improve and broaden their knowledge and skills and develop the inter-personal qualities required in their professional lives.

(I) Robust Members’ Learning & Development Mechanism

To monitor, supervise and oversee the functioning of various POU’s and their Compliance with Directions of the CPE Directorate/Council. Also, the CPE guidelines are being updated from time to time.

Contemporary with Global requirements & Practices, the CPE Credit Hours requirements for various categories of members as applicable from the current block of 3 years (1-1-2017 to 31-12-2019) are as under:-

Category of Members	CPE Hours requirement
Members (aged less than 60 years) who are holding Certificate of Practice (except all those members who are residing abroad)	120 (out of which minimum 60 CPE hours should be of Structured learning) -minimum 20 CPE credit hours of structured learning in each calendar year
Members (aged 60 years & above) who are holding Certificate of Practice	90 (either structured or unstructured learning) - minimum of 20 CPE credit hours either Structured or Unstructured Learning in each calendar year
Members (aged less than 60 years) who are not holding Certificate of Practice; and all the members who are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not)	60 (either structured or unstructured learning) -minimum 15 CPE credit hours either structured or unstructured learning in each calendar year

Exemptions to Members:

- A member is exempted only for the particular calendar year during which he gets his membership for the first time.
- **The following class of members are exempted from CPE credit hours requirement:**
 - All the members (aged 60 years and above) who are not holding Certificate of Practice.
 - Judges of Supreme Court, High Court, District Courts and Tribunal
 - Members of Parliament/MLAs/MLCs
 - Governors of States
 - Centre and State Civil Services
 - Entrepreneurs (owners of Business (manufacturing) organizations other than professional services)
 - Judicial officers
 - Members in Military Service

Temporary Exemptions

- Female members for one Calendar year on the grounds of pregnancy.
- Physically disabled members on case to case basis having permanent disability of not less than 40% and above (Supported with medical certificates from any doctor registered with Indian Medical Council with relevant specialisation as evidenced by Post Qualifications (M.D., M.S. etc.).
- Members suffering from prolonged critical diseases/illnesses or other disability as may be specified or approved by the CPEC/CPED. (Supported with medical certificates from any doctor registered with Indian Medical Council with relevant specialisation as evidenced by Post Qualifications (M.D., M.S. etc.).
- A member or class of members to whom the CPEC/CPED may in their absolute discretion grant full/partial exemption specifically or generally on account of facts and circumstances of the case which in their opinion prevent such person(s) from compliance with the requirements of CPE as specified in the Statement.

(II) IT Initiatives

- *E-Learning* platform - Digital Learning Hub (<https://icai.org/elearning>): the Committee has developed an e-Learning platform – Digital Learning Hub which can be accessed by members with their SSP Login credentials through the link (<https://icai.org/elearning>). Members can earn their professional learning credits (Unstructured CPE hours) through this platform where the learning is facilitated with videos, presentations, reference material, guidance notes etc in both desktop and mobile device modes. In days to come, this portal will facilitate to earn CPE Credit Hours under Structured Learning as well.
- Samadhan: a CPE – QnA e-Solution Forum: Samadhan is a CPE – QnA e-Solution Forum through which the members can reach out to experts and seek guidance for seamless information and query resolution experiences in the select areas of practice.
- My CPE - CPE Programs of Your Choice: The concept seeks a bottom up approach for Members to update their preference for My CPE - CPE Programs of their Choice at Google form for the programs that they are interested in, and the total aggregate interest from the members can be intimated to the respective Program Organising Units (POUs) to organise these programs during the course of the year.
- ICAI-ICE: ICAI Interactive CPE Enabler (www.ice.icai.org): It is developed for questions and polls ahead of and during CPE programs. A full-fledged version of ICAI – ICE has been enabled for all the CPE Programmes organised by various POUs to ask queries from speakers before and during the programme many of which would be answered by the Speakers, according to the availability of time.
- Development and implementation of Online Feedback Mechanisms (www.cpeicai.org): The Committee has developed various online feedback forms namely Quick feedback form, detailed feedback form and monitor feedback form for strengthening the feedback mechanism and overall CPE monitoring framework.
- Strengthening and updation of CPE Portal with new features: A dedicated CPE Portal (www.cpeicai.org) is in place to facilitate our members and POUs. Through this Portal the members can search CPE events POU-wise, City-wise and Subject-wise, manage their preferences regarding receiving alerts. The Portal is having facility for e-mail alerts before the programme and after crediting of CPE Hours.
- The above activities can also be accessed through “CPE Programs” segment on ICAI Mobile app through both Android and iOS platforms on just a click of the button.

(III) Other activities

- *E-newsletter*: 20th edition of the quarterly e-newsletter was brought out to share recent initiatives taken by the CPE Directorate.

- Spreading Wings Globally: 14 CPE International Study Tours were organised internationally by the CPE Programme Organising Units (POUs) at Australia, Kandy & Colombo (Sri Lanka), Bali (Indonesia), Bangkok (Thailand), Langkawi (Malaysia), Kazakhstan, Beijing (China), Singapore, Phuket (Thailand), Dubai, Muscat (Oman).
- Brand and Capacity Building: The ICAI has all along endeavoured to keep its members aware of and abreast with the professional and technological changes that are taking place, around the globe through the process of continuous skill honing by way of classroom teaching, e-Learning mode, In-house Executive Development Programmes, Webcasts, Awareness programmes, Seminars, Conferences etc. Few of the milestones are as follows:
 - 66 Live Webcasts were organised by CPE Committee/Central Committees/Boards of ICAI on various topics of professional interest. The recordings of webcasts are available at www.icaity.com.
 - 41 CPE Programmes were organised by the CPE Committee at National level etc. and hosted by Regional Councils/Branches of ICAI in different parts of the Country.
 - 9109 CPE Programmes were organised for the Members across the country, by the CPE Programme Organising Units of ICAI on various topics of professional interests.
 - 224 Programmes on Certificate Courses of ICAI on GST, Anti Money laundering Laws, Wealth Management and Financial Planning, Concurrent Audit of Banks, IndAS, Forensic Accounting and Fraud Detection, Preparation of appeals, Drafting of Deeds & Documents and Representation before Appellate Authorities and statutory bodies etc. were organised for Members through Central Committees of ICAI.
 - 26 batches of Pre-registration Education Course organised by ICAI RVO.
 - 18 batches of Pre-registration Education Course organised by IIIPI.
 - 133 Post Qualification Courses on Information Systems Audit (ISA), Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM) and International Taxation etc. were organised through Central Committees of ICAI.
 - 30 more CPE POUs were opened for helping the members in mofussil/remote areas of the country to undergo CPE activities in their nearby places, reaching to a strong network base of 610 CPE POUs in India and abroad.

(IV) Supporting Society – Commitment to Nation

ICAI organises various other programmes supporting the initiatives of the Government for effective implementation of the same in various parts of Country through its strong Network base of CPE Program Organising Units.

- 113 programmes have been organised by the CPE POUs on Demonetization, Black Money, Benami Transactions and Undisclosed Income.
- 2703 programmes on GST were organised by the CPE POUs in various parts of the Country including 657 programmes specifically on GST Audit were organised by the CPE POUs in various parts of the Country.
- 291 programmes on RERA (Real Estate Regulatory Act)
- 129 programmes on ICDS (Income Computation and Disclosure Standards)
- 203 programmes on Insolvency and Bankruptcy Code
- 256 programmes on Companies Act
- 35 programmes on Investor Awareness
- 21 programmes on Professional Ethics
- 52 CPE Programmes were organised on Stress Management, Lifestyle Management where Yoga is way of life, Work Life Balance etc. on 21st June celebrated as International Yoga Day.
- 9 programmes on Corporate Social Responsibility (CSR) were organised by CPE POUs at various parts of the country.

5.7 Corporate Laws & Corporate Governance Committee (CL&CGC) & Insolvency and Bankruptcy Laws Group of CL&CGC

A. Corporate Laws and Corporate Governance Committee

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee aims to facilitate a fair corporate regime with the best global practices. The Committee has been making collaborative efforts with the government to strengthen the regulatory framework i.e. being part of the Rule making process of the Companies Act, 2013 and also regularly interacting with the Ministry of Corporate Affairs and submitting representation/ providing suggestions/ giving inputs regularly on various issues concerning the Companies Act 2013.

(I) Representation to Ministry of Corporate Affairs (MCA)

The Committee regularly interacts with the Ministry of Corporate Affairs for smooth implementation of the Companies Act 2013. The Committee submitted the following representations to the Ministry of Corporate Affairs:

During the year 2019-2020:

- ICAI Recommendations on what shall/ shall not constitute Management Services under Section 144 of the Companies Act 2013 were submitted to Ministry of Corporate Affairs in June, 2019.
- ICAI Suggestions on the Recommendations of the Committee on Corporate Governance under Uday Kotak Committee on the following issues submitted to Ministry of Corporate Affairs in June, 2019.
 - Strengthening role of ICAI – Recommendations w.r.t enforcement/disciplinary process of the ICAI.
 - Strengthening of reporting on Internal Financial Controls
 - Greater transparency on audit quality indicators
 - Strengthening the independent functioning of the Quality Review Board (QRB) Current Regulatory Provisions.
- ICAI suggestions on the practices followed by UK, US, Australia and Singapore for appointment of Internal auditor as external auditor and vice-versa after cessation of the tenure were submitted to Ministry of Corporate Affairs in June, 2019.
- ICAI Comments/ Suggestions on the provisions of CSR in the Companies Act 2013, Companies (CSR Policy) Rules, 2014 and Circulars issued concerning CSR submitted to High Level Committee on CSR constituted by Ministry of Corporate Affairs in May, 2019.
- Request to waive off additional fee for filing ADT- 1 where Form GNL- 2 has already been filed by the companies for the period 1st April, 2014 to 19th October, 2014, with respect to filing of the ACTIVE form submitted to Ministry of Corporate Affairs in April, 2019.
- Ministry of Corporate Affairs issued clarification and waived off fee for filing Form ADT- 1 till 15.06.2019.

During the year 2018-2019:

- Suggestions on the proposed amendments in the Companies Act, 2013.
- ICAI Suggestions regarding Audit Rotation under Companies Act 2013 and Practice Adopted by select CA Firms for appointment of Internal Auditor as statutory Auditor or vice-versa.
- Request to extend due date for filing DIR 3 KYC by 15 days, i.e., upto 30th September, 2018.
- ICAI Suggestions on the Comments/suggestions on Draft notification of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2018 were submitted in July, 2018.
- Key Issues in Draft National Financial Reporting Authority Rules June, 2018 submitted on 18th July, 2018.
- ICAI Concerns on Draft NFRA Rules June 2018 were submitted in July, 2018.
- Suggestions on the Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2018 were submitted in May, 2018.
- Regarding Procedure for dealing with applications for removal of auditors under Section 140 of the Companies Act 2013 by the Regional Directors were submitted in May, 2018.
- ICAI suggestions on Draft National Financial Reporting Authority Rules issued in 2013 for public comments by the Ministry Corporate Affairs were submitted in May, 2018.
- ICAI Suggestions on Draft Companies (Beneficial Interest and Significant Beneficial Interest) Rules, 2018 were submitted in April, 2018.
- The Ministry of Corporate Affairs had issued notice inviting comments/ suggestions on the proposed amendments to the Companies Act 2013 by 20th November, 2018 and ICAI had submitted its suggestions on the proposed amendments in the Companies Act 2013 to the Ministry of Corporate Affairs.
- The Ministry of Corporate Affairs had requested ICAI to give comments/ suggestions on Draft Notification of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014. The Corporate Laws & Corporate Governance Committee discussed the Draft Notification of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 regarding maintenance of Databank of Independent Directors as per Section 150 of the Companies Act, 2013 and qualification of Independent Directors. ICAI had submitted its suggestions to Ministry of Corporate Affairs in July, 2018 mentioning the following points:
 - Since the Databank u/s 150 of the Companies Act, 2013 has already been developed in 2014 by three Institutes jointly with the Ministry of Corporate Affairs, the same may be adopted and considered instead of developing a new portal.
 - The Draft Rules mentions about the Certification Course to be conducted by IICA to become Independent Directors and also lays down criteria for exemption. ICAI suggests that the Chartered Accountants should

be exempted from undertaking this Certification Course by virtue of their professional qualification.

- The Ministry of Corporate Affairs has requested ICAI to formulate and issue detailed guidelines to the Regional Directors dealing with the cases related to Removal of Auditors under section 140 of the Companies Act, 2013. The Removal of Auditors once appointed by the shareholders normally should be allowed only when there is a full justification with proper reasoning. In this regard, the Committee has prepared a detailed checklist which has been submitted to Ministry of Corporate Affairs.

(II) Representation to Securities and Exchange Board of India (SEBI)

During the year 2018-2019:

ICAI Suggestions on the Consultative Paper on Proposed SEBI (Fiduciaries in the Securities Market) (Amendment) Regulations were submitted in July, 2018.

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) had issued a consultative paper proposing draft regulations to regulate 'fiduciaries' in the capital market like Chartered Accountants, Company Secretaries, Valuers & Cost Accountants, who issue various certificates in the process of fund raising by companies, Mutual Funds and others. SEBI had invited public comments on the draft regulations. In this regard, ICAI suggestions/objections on the Consultative Paper have been submitted to SEBI in August, 2018.

(III) Relating to the Constitution of National Financial Reporting Authority (NFRA)

- The Ministry of Corporate Affairs has notified the National Financial Reporting Authority (NFRA), 2018 Rules as per Section 132 of Companies Act, 2013 on 13th November, 2018.
- ICAI regularly submits its concerns on the Constitution of NFRA and Draft Rules pertaining to NFRA.

Since 1st March, 2018, when the Union Cabinet had taken a decision for establishment of NFRA, the following steps were taken by ICAI:

- 14th March, 2018 – Submitted representation to Secretary, Ministry of Corporate Affairs to review the decision to notify Section 132.
- 17th March, 2018 – Submitted letter to Principal Secretary to PMO seeking appointment to discuss Cabinet decision dated 1st March, 2018 regarding Establishment of NFRA.
- On 8th May, 2018 - Submitted ICAI Concerns on the Draft Rules 2018 on the basis of request from Secretary Ministry of Corporate Affairs.
- On 5th June, 2018 - Draft Rules, 2018 were sent by the Ministry of Corporate Affairs to ICAI for comments/suggestions.
- On 18th June, 2018- Letter to Secretary, Ministry of Corporate Affairs informing that the Draft NFRA Rules, 2018 overreach beyond what is contained in the substantive provisions of the Companies Act 2013.
- On 5th July, 2018 - ICAI Suggestions on the Draft Rules, 2018 were submitted to the Ministry of Corporate Affairs.
- On 18th July, 2018 - Made presentation on the Concerns in Draft NFRA Rules 2018 to Secretary, Ministry of Corporate Affairs.
- On 30th July, 2018 - Appeal to Hon'ble Prime Minister of India requesting to consider non notification of NFRA.
- On 30th September, 2018 – Letter to Secretary, Ministry of Corporate Affairs mentioning that the Draft Rules should be prepared in consultation with ICAI.
- In October, 2018, two writ petitions have been filed in Madras High Court and Delhi High Court challenging the constitutional validity of Section 132 of the Companies Act, 2013. In both the writ petitions, ICAI is one of the Respondents.
- ICAI sought opinion of Mr Mukul Rohatgi, Senior Advocate and Past Attorney General of India on the Constitutional validity of Section 132 of the Companies Act, 2013.

In his legal opinion, the learned Senior Advocate has opined that the "constitution of National Financial Reporting Authority is not constitutionally valid and it does encroach on the powers of ICAI and CA Act does have precedence over the provisions of the Companies Act 2013". The learned Senior Advocate has further opined that "I have no hesitation in concluding that the restriction sought to be placed by section 132 of the Companies Act 2013 on the exercise of profession of Chartered Accountancy, is not permissible under Art 19(6). The restriction would be illegal, arbitrary and also be hit by Article 14 of the Constitution of the India as well".

He also stated that “petitions challenging various provisions of S.132 of the Companies Act, 2013 are already pending in the Chennai High Court as well as the Delhi High Court. I am informed that the Hon’ble Delhi High Court has passed on order of stay dated 3.10.2018 of S.132 of the Companies Act 2013, presumably on the ground that you cannot have an alternative disciplinary authority apart from that under the CA act and that too in a separate act wherein the authority so constituted consists of non professionals. The Querist is already a party in the said petition, the Querist may support the same and make its submissions therein.”

- On 3rd October, 2018, the Hon’ble High Court of Delhi heard the petition filed and the following is the Order “For the Writ Petition No W.P.(C) 10537/2018 & CM. Nos. 41116/2018 has W.P.(C) 10537/2018 & CM. Nos. 41116/2018 (for stay) Issue notice to show cause as to why rule nisi be not issued, returnable on 16th January, 2019.
Let the affidavits be filed within four weeks from today.
In the meanwhile no disciplinary action against the members of the petitioner’s association and respondent no.3/Institute shall be initiated by the National Financial Reporting Authority (NFRA) by virtue of powers conferred upon it under Section under Section 132 (2) and 132(4) of the Companies Act, 2013. List on 16th January, 2019.”
- On 12th October, 2018- Letter submitted to Ministry of Corporate Affairs wherein it has been mentioned that the Council of the Institute had considered the matter of constitution of National Financial Reporting Authority under section 132 of the Companies Act, 2013 and was of the prima facie opinion that it is unconstitutional and ultra-vires of the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949 and therefore decided to constitute a group of its members to further examine the matter and larger stakeholder consultations.
- On 13th November, 2018, the Central Government notified NFRA Rules, 2018.

(IV) Interaction with the Ministry of Corporate Affairs

ICAI has been regularly interacting with the Ministry of Corporate Affairs and submitting representation/ providing suggestions/ giving inputs regularly on various issues right from the bill stage for addressing the issues and smooth implementation of the Companies Act 2013.

ICAI was part of the consultative process adopted by the Companies Law Committee constituted by the Government of India for proposing these major amendments to the Companies Act, 2013. Also, ICAI represented before the Hon’ble Parliamentary Standing Committee on Finance, on the issues in the Companies Act, 2013.

(V) Facilitating in the Law making process in the Companies Act, 2013

- ICAI is a member of the Task Force on ‘Ease of Doing businesses for the indicators “Starting a Business”, “Resolving Insolvency” and “Protecting Minority Investors”.
- ICAI is a member of Strategic Advisory Group of Ministry of Corporate Affairs to design MCA-21 Version III.
- ICAI is a member of the working Committee for streamlining working under the Companies Act 2013.
- ICAI is a member of Sub Group (2) to examine the suggestions pertaining to streamlining the Companies Act 2013.
- ICAI is contributing as a member of the Insolvency Law Committee to identify and suggest ways to address issues faced in implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
- ICAI is a member of the Group to examine the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014 as formed by Ministry of Corporate Affairs.
- ICAI is a member of the Company Law & Corporate Governance Committee of PHD Chamber of Commerce and Industry.
- ICAI is a member of the Committee for drafting appendix to the Investigating manual of Serious Fraud Investigation Office.
- ICAI is a member of Governing Council of National Foundation for Corporate Governance.

(VI) ICAI Recommendations on what shall/ shall not constitute Management Services as per Section 144 of the Companies Act 2013 submitted to Ministry of Corporate Affairs in June, 2019

As per Section 144 (h) of the Companies Act, 2013 (the ‘Act’), Management Services cannot be rendered by an auditor to that company. However, the Act, does not define the term “Management Services”. On the other hand, the ICAI Code of Ethics 2009 and Revised ICAI Code of Ethics 2019 issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) contain principles regarding the services which may be rendered by a Chartered Accountant in practice.

Accordingly, a Concept Paper has been prepared by the ICAI wherein the provisions of ICAI Code of Ethics, 2009, ICAI

Revised Code of Ethics, 2019, Revised IESBA Code of Ethics 2018 and Practices in U.S.A, Australia, Canada and European Union have been considered.

ICAI Recommendations of the Services that may be considered as Management Services under Section 144 (h) of the Act alongwith ICAI Recommendations of the Illustrative Services that may not be Management Services as per Section 144 of the Act have been submitted to Ministry of Corporate Affairs.

(VII) Guidance Note on Division I – Non Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013 (Revised July, 2019 Edition)

To facilitate the exercise of preparation of financial statements by companies which are required to prepare its financial statements as per Accounting Standards, the Committee has issued the revised Guidance Note on Division I- Non Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013 as per the amendments brought in by the Ministry of Corporate Affairs.

(VIII) Guidance Note on Division II – Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013 (Revised July, 2019 Edition)

To facilitate the exercise of preparation of financial statements by companies which are required to prepare its financial statements as per Ind AS Schedule III, the Committee has revised the Guidance Note on Division II- Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013 as per the amendments brought in by the Ministry of Corporate Affairs. The Revised Guidance Note has been issued.

(IX) Frequently Asked Questions on the Companies Act, 2013- Revised July, 2019 Edition

Consequent to the amendments, during the last few years including notification of the Companies (Amendment) Act, 2017, wherein major amendments took place, the Committee undertook the exercise of revision of the publication, “Frequently Asked Questions on the Companies Act, 2013”. The Revised publication has been issued recently.

(X) Guidance Note on Division III to Schedule III to the Companies Act 2013 for NBFC that is required to comply with Indian Accounting Standards (Ind AS)

The Ministry of Corporate Affairs has notified “Division III Financial Statements for a Non-Banking Financial Company (NBFC) whose financial statements are drawn up in compliance of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

In this regard, the Committee is in the process of preparing the Guidance Note on Division III to Schedule III to the Companies Act 2013.

(XI) Other initiatives

- The Committee prepared Frequently Asked Questions were prepared by the office on the queries received from participants during the webcast to give more clarity on the issues and submitted the same to the Ministry of Corporate Affairs. The Ministry of Corporate Affairs has issued the FAQ's on eForm INC 22 A as prepared on the basis of FAQs submitted by the Committee. FAQs are hosted on Ministry of Corporate Affairs website at the following link: <http://mca.gov.in/MinistryV2/active.html>
- In order to support the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in their initiatives, the Committee had organised a webcast on MCA E- Form DPT- 3 -Compliance and other aspects. The Webcast was addressed by the officials of the Ministry. The Webcast was viewed by more than 8000 members and around 550 questions were received and addressed by the speakers. The Webcast has been well received by the Ministry of Corporate Affairs
- In order to support the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in their initiatives and as desired by MCA, the Committee had organised a webcast on MCA E- Form Active (Active Company Tagging Identities and Verification) INC-22A - Compliance and other aspects. The Webcast was addressed by the officials of the Ministry. The Webcast was viewed by more than 25000 members and around 500 questions were received and addressed by the speakers. The Webcast has been well received by the Ministry of Corporate Affairs.

(XII) Conference/Training Programme

- The Committee has organized National Conference and training programme for the IAS Officials of the

Government of Tami Nadu on various legislations and Companies Act, 2013 at various part of countries during the year. In the Conference the participants were addressed by His Excellency Prof. Ganeshi Lal , Hon'ble Governor of Odisha.

- The Institute of Chartered Accountants of India has supported the Government in its initiatives to update its registry wherein Ministry of Corporate Affairs would be conducting KYC of all Directors of all companies annually through a new eform viz. DIR-3 KYC. With a view to create awareness and popularise, ICAI has conducted various Seminars, webcasts, sent mass mail to the members and hosted Announcement on ICAI website as well as in ICAI Journal. Information has been spread through Twitter, Facebook and other Social media platforms.

(XIII) Updates for professional development of members relating to Corporate Laws

The Committee regularly issues series of update for members towards professional development which includes updates on the Corporate Laws. Further, various Announcements/ analysis done by the Committee have been uploaded on ICAI website on the followings subject matters:

- Analysis of Ministry of Corporate Affairs Notification regarding filing of E Form DIR-3 KYC upto 30th June every year.
- Analysis of Ministry of Corporate Affairs Notification regarding filing of DPT- 3 Form upto 29th June, 2019- One time Return.
- Announcement regarding extension of date for filing E-Active Form to 15th June 2019
- Summary of Provisions of The Companies (Second Amendment) Ordinance 2019.
- Summary of the Notification dated 2nd November, 2018 regarding Provisions of The Companies (Amendment) Ordinance 2018.

(XIV) Learning Management System to prepare for IBBI Limited Insolvency Examination

The Institute has launched a Learning Management System to enable the professionals to prepare for IBBI Limited Insolvency Examination. This knowledge initiative is an easy to use platform which delivers the concepts across the entire syllabus in the form of presentations and supplemented by mock tests in each component of the syllabus. A unique feature is that it enables the professionals to do the practice at a modular level and prepare for the examination. The module comprises of three parts - Literature on the entire syllabus, Video lectures on the above content and over 500+ Multiple Choice Question mock exam with additions to the question bank on short intervals. Regular updations are being made in the presentations and new case laws are uploaded as per the Syllabus applicable. Updations were made in 42 PPTs and new Case Laws (37 in number), Bare Act, Rule and Regulations (17 in number), IBBI Sample test Paper pertaining to LMS as per the Syllabus applicable from 1st November, 2018 were uploaded on LMS.

(XV) Meeting with Dignitaries

- A meeting was held with Secretary, Ministry of Corporate Affairs regarding dissemination of salient features of MCA E- Form Active (Active Company Tagging Identities and Verification) INC-22A on 15th March, 2019, wherein it was discussed that for good corporate Governance it is required to make these kind of schemes mandatory. The Secretary, Ministry of Corporate Affairs appreciated the efforts put in by ICAI for conducting the webcasts which received overwhelming response.
- A Meeting was held with Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs on 28th June, 2018, where Ministry of Corporate Affairs has requested ICAI to help them identify young professionals (Chartered Accountants) to work on contract basis, under various provisions of the Companies Act, 2013 like inspection, investigation, at various locations all over India. In this regard ICAI has invited applications from Chartered Accountants (CAs) having 2 years plus of post-qualification experience at various locations.
- The Ministry of Corporate Affairs has formed a Task Force on 'Ease of Doing Business' for the indicators "Starting a Business", "Resolving Insolvency" and "Protecting Minority Investors". The third meeting was held on 11th April, 2018. In that meeting it was discussed to create awareness of the initiatives taken by the Government towards 'Ease of Doing Business' especially in Starting a Business and Resolving Insolvency. In this regard, the Committee had conducted 3 Programmes at Mumbai, Delhi and Kolkata. The details of the same are given below:
 - The Programme was attended by CA. Man Mohan Juneja, Regional Director (Western Zone) Ministry of Corporate Affairs, CA. R. K. Dalmia, Dy. Regional Director, (Western Zone) Ministry of Corporate Affairs and Shri Vinod Sharma, Registrar of Companies, MCA, Mumbai as Guest Speakers. We had received overwhelming response and it was attended by more than 70 members.
 - The Programme was attended by Shri Alok Samantarai Regional Director, Ministry of Corporate Affairs

- Eastern Region Shri. K G Joseph Jackson (ROC Kolkata), Ministry of Corporate Affairs as the Guest speakers.
- A Live webcast was held at ICAI Delhi on 20th April, 2018 where Shri D. Bandopadhyay Regional Director, Ministry of Corporate Affairs (North), was the guest speaker alongwith Government Nominee of ICAI.

B. Insolvency and Bankruptcy Laws Group under CL&CGC for the year 2018-2019

(I) Publications

The Insolvency and Bankruptcy Laws Group under CLCGC, jointly with Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI) has released two Series of the publication “Judicial Pronouncements under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016” Series 1 and 2 during the year. The publication covers important Case Analysis based on the decisions by Supreme Court, High Courts, NCLAT and NCLT on issues under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC).

(II) Programmes

- The Insolvency and Bankruptcy Laws Group, CLCGC, ICAI organized the Mega IBC Conclave on 21st July, 2018 at Delhi and on 11th August, 2018 at Mumbai. A Mega IBC Event was also organized on 10th November, 2018 at Kolkata. The Conclave/Event was attended by large number of delegates from different profession and from across the Country. Dr. M.S. Sahoo, Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India addressed the gathering at the Inaugural session at Delhi as well as in Kolkata and also took questions at the Panel Discussion. Dr. Navrang Saini, Whole Time Member, IBBI addressed the delegates at the Mumbai Conclave.
- Three Days Intensive Training Programme for preparation of IBBI Limited Insolvency Examination was conducted at 9 places - Ongole, Guntur, Kanchipuram, Hubli, Tirupati, Sivakasi, Varanasi, Kolkata and Belgaum.
- Various Training Programme/seminars/workshops for preparation of IBBI Limited Insolvency Examination and on IBC were conducted at Pune, Nagpur, Nashik, Kota, Bhilai, Ahmedabad, Rajkot and Jamnagar.
- Seminar/Training Programme/Workshop on IBC were conducted at 4 places- Bhilai, Ahmedabad, Rajkot, Jamnagar.

5.8 Direct Taxes Committee (DTC)

(I) Representations/interactions with CBDT

- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to consider issue(s) faced by assesseees w.r.t. application of Rule 115 & 115A of the Income-tax Rules, 1962.
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to increase number of benches of CIT (Exemptions) in the state of Uttar Pradesh.
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to amend CBDT instruction (F.No. DGIT(vig.)/HQ/SI/Appeals/2017-18/9959) dated 8th March, 2018 with respect to power of CCIT to monitor orders issued being issued by the CIT (A).
- Submission of representation to representation to Chairman, CBDT regarding Submission of Suggestions on forms 3CA/ 3CB/ 3CD.
- Submission of Letter F. No. 225/53/2018/ ITA.II dated 28.3.2018 to Chairman, CBDT regarding processing of returns which are pushed to Assessing Officers by CPC.
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to expedite the release of ITR utilities for AY 2018-19 (only relating to ITR 1 and 4 released so far).
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to Request to expedite release of new tax audit forms (3CA, 3CB & 3CD) and its utilities for AY 2018-19.
- Submission of various representations to Chairman, CBDT regarding Notification No 23/2018, dated 24th May, 2018 amending Rule 11UA omitting reference to term “accountant”, thereby making Chartered Accountants ineligible to determine the FMV of unquoted equity shares as per the Discounted Free Cash Flow Method.
- Submission of representation regarding Concerns of ICAI in reference to the ICAI letter No. G:142:05:2018 dated 23.05.2018 submitted by the Institute of Cost Accountants of India to amend the definition of “Accountant” in the Explanation appended to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961.
- Submission of representation requesting to issue clarification regarding taxation of interest on Provident Fund balance – Removal of Disparities.
- Submission of representation requesting to rectify issues faced by taxpayers while filing ITR forms for AY

2018-19.

- Submission of representation requesting to allow taxpayers to file time barred returns even after expiry of time allowed u/s 139(4).
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to provide relevant details regarding the article published in The Economic Times newspaper dated 19th July, 2018 and suggestion of ICAI in this regard.
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to extend due date of filing Income-tax returns for the AY 2018-19.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding submission of suggestions on Form No. 3CD revised vide Notification No. 33/2018, dated 20th July, 2018
- Submission of representation requesting to resolve the concern pertaining to delay in updation of TDS data in Form No. 26AS after filing of TDS return by deductors and other related issues.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding request to postpone the applicability of section 12A(1)(ba) of Income-tax Act, 1961 in the case of Charitable & Religious Institutions based in Kerala and to extend the due date of filing Income Tax Returns and Tax Audit Reports for assesseees in Kerala due to unprecedented floods and derailment of life.
- Submission of various representations to Chairman, CBDT requesting for extension of time for submission of Tax Audit Reports and related returns.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding Suggestions on draft notification proposing amendments in Form No. 13, and Rules 28, 28AA, 28AB, 37G and 37H of the Income-tax Rules, 1962.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding Concerns of the taxpayers on the instructions issued by the CBDT to CIT(A) via Para (3) of the Action Items dealing with 'Incentive for quality orders' under Part A - 'Targets for CIT(Appeals)' of Chapter III dealing with Litigation Management of the Central Action Plan 2018-19.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding Concerns of ICAI with regard to 'Minimum Eligibility Criteria' – Invitation for Empanelment of Chartered Accountancy Firms for Special Audit u/s 142(2A) of the Income-tax Act, 1961.
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to rectify ITR-5 utility released on 01.09.2018.
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to rectify Form No. 3CB utility released on 01.09.2018.
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to remove a specific FAQ hosted on the Income Tax Department Website pertaining to provisions of Section 44AD of the Income-tax Act, 1961.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding Submissions of Suggestions for Designing of Phase-2 (2019-2024) of CPC (TDS).
- Submission of representation requesting to remove the specific divergence in utility of Form No. 3CD and notified Form No. 3CD.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding Submission of Suggestions for consideration in drafting of New Direct Tax Legislation.
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to rectify the defect in the utility of ITR Form No. 7.
- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to issue a clarification or notify challan for payment of TDS under section 194-IC (Payment under specified agreement) of the Income-tax Act, 1961.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding:
 - Request to amend Rule 18BBB of the Income-tax Rules, 1962.
 - Request to amend Form No. 10CCB w.r.t. section 80-IE of the Income-tax Act, 1961 and to provide java utility of the said form.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding request to consider modification in 'Guidelines for Compounding of Offences under Direct Tax Laws, 2014' dated 23.12.2014.
- Submission of Preliminary Inputs of ICAI in respect of forms 3CA/3CB/3CD.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding Request to issue clarification or consider recommending amendments on tax issues relating to internal reorganization of business.
- Representation w.r.t. proposals in the Finance Bill, 2019.
- Submission of ICAI's Inputs on Draft Form No. 3CD.
- Request regarding amendment in Rule 11UA with reference to determination of FMV of unquoted equity shares as per the Discounted Free Cash Flow Method.
- Concerns of ICAI in respect of newly notified ITR Forms for AY 2019-20.

(II) Activities Relating to Union Budget

- Submission of Post-Budget Memoranda, 2018.
- Submission of Pre-Budget Memorandum, 2019.

(III) Other Initiatives:

- Release of Technical Guide on Understanding Income Tax Return Forms for AY 2018-19
- Release of "Implementation Guide w.r.t. Notification No. 33/2018 dated 20.07.2018 effective from 20.08.2018"
- Arrangement with vendors for online Subscription on Direct Taxes for members.
- 5 LIVE Webcasts have been organized by the Committee during the year on the various topics such as E and other issues in TDS and TCS Compliances & Understanding and filling new Forms of Income Tax Returns, Recent Developments in Electronic Systems, E-compliances - Issues and Way Forward, Clause wise Analysis and New Requirements in Revised Form 3CD of Tax Audit Report, and Capacity building for TDS deductors filing TDS Statement in form 24Q & Recent changes in Part B of Form 16.
- The Committee organized 25 seminars/conferences/tax awareness programmes/workshops/ lecture meeting during the year.

5.9 Committee on Economic, Commercial Laws & Economic Advisory (CECL&EA)

(I) Representations to various Government Authorities/ Regulators

Committee on Economic & Commercial, Laws & Economic Advisory made various representations to the Government Authorities/Regulators:

- Representation regarding recognizing the Chartered Accountants as authorised representatives under Section 26 and 48 of the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 for appearance before the Adjudicating Authority and Appellate Tribunal under the Act submitted to Ministry of Law and Justice;
- Representation regarding the issues being faced by the Chartered Accountants at RoF, while registering the firms, changes in constitution and other related matters submitted to Registrar of Firms, Maharashtra;
- Representation submitted to the Law Commission of India regarding Abolition of Hindu Undivided Family (HUF) suggested in the Consultation Paper on Reform of Family Law dated 31st August, 2018 presented by the Law Commission of India;
- Representation submitted to Ministry of Housing and Urban Affairs and various RERA Authorities in the matter regarding extension of date for submission of Audit Reports under the Real Estate Regulation and Development Act, 2016, views/suggestions on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 submitted to Hon'ble Chairman, Rajya Sabha, Parliament of India;
- Circulated the views of MahaRERA to various RERA Authorities and Trade Bodies regarding the need to compile the views of RERA Authorities across the country for more enlightenment and for uniformity in implementation of the statute and
- Representation on the matters related to recently pronounced landmark verdicts of the Supreme Court of India which may impact the calculation of Provident Fund deduction and EPS Pension submitted to Central P. F. Commissioner.

(II) Guidance Notes/ Technical Guides/ Publications etc.,

- With the objective to recommend the parameters to be followed by the Chartered Accountants for Certifications and Audit under RERA, a publication titled "Certifications and Audit under Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA)" was released on 11th February 2019 through the august hands of Shri Vijay Goel, Hon'ble Minister of State for Parliamentary Affairs; ICAI's past President, CA. N. D. Gupta and Member of Parliament, Rajya Sabha.
- In an endeavor to broaden the scope of expertise of members on the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019', the Committee brought the E-publication titled "Frequently Asked Questions on The Banning of Unregulated Deposits Ordinance, 2019' under the aegis of the Committee.

(III) Seminars/ Conferences/ Workshops/ Webcast

Awareness programmes were organized on various Economic & Commercial laws including the Role of Chartered Accountants in Business Transformation, Innovation & Technological Development; GST Annual Return, RERA Certificates & Reports and Private Trusts; FEMA etc. by way of Webcasts, Workshops, Seminars, Conferences and program during the period.

(IV) Certificate Course on Anti Money Laundering Laws

The Committee has successfully conducted the 5 batches of the Certificate Course on Anti Money Laundering Laws (Anti- Money Laundering Specialist) during 2018-19 in Pune, Solapur, Mumbai, Bengaluru & Chandigarh. Eminent faculties from the Government Departments, Banks, Legal Fraternity and members from industry & practice addressed the participants.

(V) Roadshows - Competition Commission of India

ICAI provided support and co-operation in the various Roadshows organized by Competition Commission of India (CCI) and Institute of Corporate Affairs at different locations in the year 2018-19 at Mumbai, Delhi, Ahmedabad and Hyderabad with a view to step up competition advocacy and reach out to a greater number of stakeholders in newer and better ways.

Study Groups: Study groups were constituted Study Group for revising Publication “Referencer on FEMA- Foreign Exchange Management Act, 1999” and Study Group for development of Technical Guide and FAQs on Provident Fund.

5.10 Digital Accounting and Assurance Board

Strengthening the role of Chartered Accountants by building digital competencies to ensure that Chartered Accountants meet challenges and leverage opportunities of digital era, ICAI in the year 2018 merged Committee on Information Technology (CIT) with Digital Accounting and Assurance Board (DAAB). DAAB is developing knowledge base through position papers and articles on issues related to impact of technology on accounting and assurance. Research on potential impact of Artificial Intelligence, Robotics Process Automation, Blockchain, Cloud Computing and Big Data on accounting and assurance is being undertaken to develop concept papers. The purpose is to help chartered accountants expand their knowledge and enhance their skills in new areas of digital era.

The Board performed the following major activities during this year:

(I) Publications

- Concept Paper on “*Blockchain Technology – Adoption Trends and Implications for Accountancy Profession*” briefly explains fundamental concepts and unique features of blockchain technology, highlighting current usage of this novel technology. It throws light on accounting and assurance of blockchain based systems/ processes, and also adoption and development phases by accounting firms. Case studies have been included for explaining practical aspects to the readers.
- Keeping pace with dynamic digital landscape, the Board has released this Concept Paper which briefly provides an overview of Robotic Process Automation and focuses on role of chartered accountants in adoption of this evolving technology by organizations. This document highlights key objectives of RPA, Triggers for Use of RPA, Target Areas for RPA, Critical Success Factors for RPA, Robotic tools and vendor landscape, RPA Future – Towards Intelligent Automation, etc. Case studies also have been included on accounting function, tax function, management reporting and analysis, etc.
- The Board has brought out revised and updated publication “Early Signals of Fraud in Banking Sector” which would guide members to be instrumental in timely detecting fraud and also suggesting controls for prevention. Apart from incorporating impact of revised circular, this revised edition also includes fraud risks involving information technology covering Core Banking Solutions (CBS), Digital Payment System, Internet Banking, etc.

(II) Data Analytics (DA)/ Forensic Labs

The Board had launched DA Lab at Kolkata, Chennai and Hyderabad. Total Six Data Analytics/ Forensic Labs has been launched by the board where Hands on Training is given to the members on advance Excel and GAS (Generalized Audit Software) tool (IDEA) functionalities for assurance analytics (i.e., data analytics from an audit perspective), reporting, interpreting results and decision making. The Certificate Course on Forensic Accounting & Fraud Detection is also being organized in the labs for the Members to provide hands on experience trainings on the Forensic Tools.

(III) Executive Development Program on Blockchain

The Board has launched Executive Development Program on “Blockchain Technology – Driver of Digital Era” which would provide introduction to blockchain technology and develop use cases in different industries. The course also covers future of blockchain technology in terms of innovation in enabling transparent accounting ecosystem, and its potential to transform current auditing practices. The board had successfully conducted 9 Programs at various places in the country and at Dubai and Bahrain.

(IV) Post Qualification Course on Information Systems Audit

Post Qualification Course on Information System Audit (DISA), conducted by the Board, was started in the year 2001 to upskill chartered accountants in Information Systems Audit which was in increasing demand. DISA course combined technology, information assurance and information management expertise that enabled a DISA qualified chartered accountant to become trusted Information Technology advisor and provider of Information Security Assurance services. From 2001 till date more than 25,500 members have qualified this Course. DISA was also conducted at Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka in July, 2018. With a view to benchmark DISA qualification to international standards, the Board is in the process of taking American National Standards Institute (ANSI) Certification. Digital Accounting and Assurance Board had also updated the syllabus for the Post Qualification Course on Information Systems Audit. Total 91 batches were held during the year 2018-19.

(V) Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection

The Board conducts “Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection”, and till date around 4,500 members have qualified this Course. The objective of this specialized Course is to help the chartered accountants attain skill of utilizing accounting, auditing, CAATs/ Data Mining Tools, and investigative skills to detect fraud/ mistakes. Total 48 batches held during the Council year 2018-19

(VI) ICAI Startup Summit 2018 – Palette of Innovation” at New Delhi in June, 2018

The Board had organized the Startup Summit for encouraging entrepreneurship in Chartered Accountants and aimed to provide adequate mentoring.

(VII) ICAI Blockchain Summit 2018

The Board conducted the Blockchain Summit on 23rd August 2018 with an objective to provide conceptual and practical understanding of Blockchain Technology & Implementation in various industries from Accounting, Assurance and Compliance perspective to empower Chartered Accountants to provide relevant advisory/ Assurance Services.

(VIII) Data Analytics Conference 2018 -Transformation Of Assurance Services

The Board conducted the Data Analytics Conference on 20th October 2018. The Conference focused on the application of Data Analytics to audit procedures - Risk Assessment, Analytical Review, Substantive Testing, Advances analytics to gain greater awareness and deeper insights into business operations.

(IX) ICAI 3rd Annual Conference On Disruptive Innovation For Transformation – Digital & Forensics

- DAAB of ICAI started an initiative to organize an Annual Conference on Digital and Forensic to cover emerging technology trends impacting profession, recent trends of fraud and strategy to mitigate the risk of frauds. The 3rd edition of the Conference with the theme of Disruptive Innovation for Transformation was organized on 18-19 January, 2019 by the Board. The theme of the conference was ABCD of technology i.e. the sessions were based on the emerging technologies like Artificial Intelligence and Machine Learning, Blockchain Technology Trends, Cyber Security and Data Analytics.
- Digital Practice Webinar Series is conducted by the Board and webinar on "Cybersecurity for Accountants – Concepts and Tools" was conducted in April, 2019.
- Technology Summits for Empowering Chartered Accountants to meet Challenges of Digital Transformation were organised at Coimbatore, Belgaum, Bhopal, Warangal, Indore, Kanpur and Lucknow.

European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) has adopted Digital Competency Maturity Model (DCMM) Version 1.0 released by DAAB in June, 2019.

Collaboration with the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

Joint research by ICAEW and ICAI into leading examples of automation in finance and accounting to learn more about:

- How automation is being deployed and its practical benefits
- The elements that underpin successful automation, such as process change and change Management
- The impact on staff working in transactional parts of finance and accounting

The research will focus on interviews with a number of people in the companies, including finance leaders, staff involved

in the delivery of automation projects and IT or other technical functions. In addition, review of relevant documents that are provided by companies will also be done.

5.11 Ethical Standards Board (ESB)

The momentum with which the ethics and probity has been highlighted in recent years throws light on how much the society attaches importance to these attributes. Those abiding with ethical principles are able to muster credibility that others can't. Given that the ethical conduct is a highly sought after trait from everybody in general, it would naturally imply that level of expectation of ethics from professionals is way ahead. This expectation is the highest level when it comes to chartered accountants, as they are the pillars of financial propriety in the country and beyond.

Though the relationship of ethics with the profession of accountancy is as old as the profession itself, the Ethical Standards Board (hereinafter referred to as "Board") of the Institute was formed in 1976 with the primary responsibility to formulate principles of Ethics for its members that are stringent enough to guarantee the confidence building in the public.

The mission of the Board is "To work towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of 'excellence, independence, integrity' as also to protect the dignity and interests of the members".

Besides formulating ethical principles for members, the Board also examines and renders advice on ethical issues referred to it. It reviews the 'Code of Ethics' for members from time to time, and publishes the revised editions. The other publications of the Board, namely, 'FAQ on Ethical Issues', and 'Guidance Note on Independence of Auditors' are revised from time to time. The Board promotes public awareness and confidence in the integrity, objectivity, competence and professionalism of members. It also examines and deals with the complaints of members against their unjustified removal as auditors of an entity, as per procedure evolved, and takes necessary steps to protect the interest of its members

(I) Significant Achievements

- "Code of Ethics" has been revised as per International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), 2018 edition. It is thus the revised counterpart of Part- A of Code of Ethics, 2009 edition. The revised Code will be effective from 1st April, 2020. The existing (2009) edition of Code of Ethics will remain effective till then. The revised Code was released at the Annual Function of the Institute held on 4th February, 2019.
- "Frequently Asked Questions on Ethical Issues" has also been revised. The revised edition was released at the Chartered Accountants Day on 1st July, 2018. The earlier edition of publication was issued in 2012. The new edition contains revised guidance, and contemporary issues useful for the members of the Institute.
- CA. Sanjiv Kumar Chaudhary, Past Council Member and Past, Chairman, Ethical Standards Board, has been nominated as member in International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) 2019 – 2022.

(II) Some important clarifications by Ethical Standards Board

- There is no conflict of interest where the current asset auditor of borrower accounts of a branch of a bank is the statutory auditor of another branch of the bank.
- An auditor would not be exempt from sharing the working papers if any law or regulation specifically requires auditor to share his working papers.
- A Chartered Accountant, being partner in a firm, can accept position as Director of an overseas subsidiary of the said company (where the said firm has been appointed a Tax Auditor of the parent company in India) if he ascertains that he will not be able to exert direct and significant influence over the subject matter information of the tax audit engagement.
- A commercial transaction in the ordinary course of business of a company at arm's length price will not result in indebtedness (as per provisions of Companies Act, 2013) if the outstanding amount is settled in accordance with the terms same as offered to other customers, and also subject to safeguards provided in ICAI Code of Ethics, if applicable.
- Chartered Accountants Firms can be registered under the MSME category, as there is no prohibition of the same under The Chartered Accountants Act, 1949, Chartered Accountants Regulations, 1988 or Code of Ethics.
- From the point of view of ICAI Code of Ethics, 2009, there is no prohibition for internal auditor of a company to acquire/purchase shares of the said Company.
- It is permissible for a member in practice to become an arbitrator, as per Chartered Accountants Regulations, 1988. Empanelling with Indian Council of Arbitration (ICA) would be deemed as ancillary to becoming arbitrator, and the same is therefore permissible.

- A member may hold shares of a company as an investment only. However, in view of Clause (11) of Part-I of First Schedule to The Chartered Accountants Act, 1949, it is not permissible for him to be engaged in the business of buying and selling shares, and will have to seek prior and specific permission for carrying out such business.
- A member holding Certificate of practice and in salaried employment abroad will be deemed to be in part time practice. He can continue to be partner in a CA Firm, since the only prohibition on a member in part-time practice is on doing attest functions. Thus, there is no prohibition on a member in part time practice to be a partner in a CA Firm. However, he will not be reckoned for the purpose of number of Audits for which the CA Firm is entitled to.
- As per Entry (xv) of Guidelines of Management Consultancy and other Services, Valuation of shares and business and amalgamation, merger and acquisition are permissible to members in practice. Accordingly, only these valuations would be deemed permissible from the point of view of a member in practice. It is not permissible for a member in practice to carry out any other kind of valuation.
- The requirement of communication under Clause (8) of Part-I of First Schedule to The Chartered Accountants Act, 1949 cannot be applied to a situation where a Chartered Accountants Firm, which was previous Auditor, does no longer exist. The incoming Auditor will however be required to confirm this fact from the Institute.
- A member cannot *inter alia* mention the services provided by the Firm on sign board of the Firm. However, a sign board mentioning services provided by the Firm can be put inside the premises of the Firm, since it will not be advertisement to the world at large, but only depiction of services provided by the Firm, and accessible only to the clients/persons who are already voluntarily present inside the premises of the Firm.
- It is not permissible for a member to allow his name to be appear on the visiting card of a Law Firm.
- It is not permissible for a member in practice to host a conclave or seminar, and collect delegate fees, and sponsorship fees.
- The role of “Scrutinizer” is within the purview of a member in practice.
- It is not permissible for a member in practice to have his office premise (of CA Firm) and Coaching Centre at the same place.
- A member in practice contemplating to start an education institution abroad would be representing him as a member in one or more ways while proceeding with the establishment of institution. Accordingly, the provisions of Clause (11) of Part-I of First Schedule to The Chartered Accountants Act, 1949, read with Entry (5) of “Permission to be granted specifically” of Appendix (9) of Chartered Accountants Regulations, 1988 will apply to such member. He should therefore seek specific and prior approval of the Council before starting such educational institution.

5.12 Expert Advisory Committee (EAC)

(I) Opinion

The fast changing economic environment often requires organisations to undertake complex business transactions. Financial reporting for such transactions sometimes poses interpretation and implementation issues. Moreover, with a comprehensive change in accounting principles for some companies in terms of Indian Accounting Standards (Ind ASs), financial reporting also poses certain challenges to the accounting professionals in discharging their duties. This gives rise to the need for an authoritative expert guidance on such matters. Here comes the role of the Expert Advisory Committee (EAC) of the ICAI, of giving such guidance to the members of the ICAI on specific issues relating to accounting and/or auditing principles under specific situations/circumstances. The EAC gives this guidance in the form of Opinions on specific queries raised by the members, relating to application and implementation of accounting and/or auditing principles, in accordance with Advisory Service Rules framed and revised from time to time by the Council of the Institute. As per these Rules, the Committee does not answer queries which involve only legal interpretation of various enactments. Further, it does not answer queries which concern a matter which is pending before the Disciplinary Committee of the Institute, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the Government. The said Rules are available on the web-site of the ICAI, at its hyperlink, http://www.icaai.org/new_category.html?c_id=142 or can be obtained from the Institute’s Head Office at New Delhi.

Over a period of time, EAC’s role has also been acknowledged by various Government and Regulatory bodies, such as, Ministry of Corporate Affairs (MCA), Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Securities and Exchange Board of India (SEBI) etc. who approach EAC from time to time for seeking opinion on accounting queries/issues faced by them. The opinions expressed by the Expert Advisory Committee are based on the facts and circumstances of the query as supplied by the querist, considering the relevant legal position and the accounting/auditing principles prevailing on the date the Committee finalises the particular opinion. The date of finalisation of the opinion is also indicated with each opinion. The opinion, therefore, must be read and applied in the light of any subsequent developments and/or amendments in the relevant legal position and accounting/auditing principles that may affect the opinion.

During the period from 01.04.2018 to 30.06.2019, the Committee finalized 50 opinions received from the members of the Institute and 3 opinions on different accounting issues received from the Regulators/ Government authorities.

For the benefit of the members, EAC also regularly publishes Compendium of Opinions where the opinions finalised during a year are published in a volume of the Compendium. Till now, thirty-five volumes of the Compendium have been released for sale which have enjoyed extensive readership. An advanced and user friendly search facility in the form of a CD containing around 1400 opinions contained in all the thirty-five volumes of Compendium of Opinions has also been released, which is available with Volume XXXV of the Compendium of Opinions. The next Volume in series, viz., Volume XXXVI of the Compendium of Opinions is under compilation and is expected to be released very shortly.

Some of the opinions finalised by the Committee which are of general professional interest, are published in every issue of the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also hosted on the knowledge sharing page of the Committee on the website of the Institute.

(II) Opinions issued during the year

The Committee issued the various opinions to members during the year such as netting of trade Netting off of trade receivable and advances received from customers, Disclosure of impairment loss on long-term investments as exceptional item, Disclosure in standalone financial statements of contingent liability in respect of Corporate Guarantee (Deed of Guarantee) issued by the parent company to the bank for furnishing Performance Bank Guarantee on behalf of wholly owned subsidiary company towards its performance obligation, Accounting treatment to recognise interest earned on advance fee as its income is correct as per the provisions of Ind AS 18, etc.

5.13 Financial Reporting Review Board (FRRB)

In its endeavor to improve financial reporting practices, the ICAI through FRRB reviews the General Purpose Financial Statements of various enterprises and the auditors' report thereon. The Board aims to maintain an environment of sound financial reporting and also to improve transparency in financial reporting and good governance, which is important to promote investor confidence in audited financial statements. The Board also supports various regulators viz MCA, SEBI, ECI and other regulators by undertaking review of cases as referred by them time to time. During this period, the Board has completed the review of 65 cases selected on suo motto basis or as special case.

As suo moto proactive measure and in view of public interest involved, ICAI set up Shell Companies Review Group (SCRG) under Financial Reporting Review Board (FRRB). The SCRG undertakes review of shell companies on references received from Regulatory / Government bodies like 'Task Force on Shell Companies' etc.

(I) Contribution to Society – Commitment to Nation

In its endeavour to support regulators, the following significant assignments were performed by the Board during the period:

- *Status of review of cases referred by Regulators:* Election Commission of India has appreciated the role played by FRRB in previous years for reviewing annual audited accounts of various political parties and also holding a workshop for auditors of political parties. It has again requested FRRB to undertake review of the annual audited accounts of at least six National political parties and recognized parties with income/ expenditure exceeding Rs. 10 Crore. Accordingly, the Board has undertaken the review of 18 annual audited accounts of political parties, pertaining to financial year 2016-17 and 2017-18. During the year, the Board has also undertaken (as special cases) review of 13 general purpose financial statement and auditor's reports thereon of various enterprises as referred by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, based on media reports and other references received.
- *Meeting with Chairperson, National Financial Reporting Authority (NFRA):* To understand the scope and procedure of FRRB, NFRA had requested ICAI for a meeting. A meeting was held with Shri R. Sridharan, Chairperson NFRA and Shri Prasenjit Mukherjee, member NFRA. The Chairman, FRRB gave a presentation about the overview of FRRB, outlining its scope, procedure, contribution as well as the ways in which FRRB has supported various regulators from time to time. Also, informed the number of instances where irregularity/ non-compliances observed by the FRRB has been sent to the regulatory body (MCA/ SEBI/ ECI) relevant to the enterprise.
- The FRRB conducted its 100th meeting on January 23, 2019 at ICAI Bhawan, New Delhi. On this occasion, the Board organised a webcast for the Technical Reviewers and Group members. The Chairman, FRRB and Vice Chairman, FRRB acknowledged their contribution as well as appraised them about critical aspects in the review process and with the way forward of the Board. Some of the Central Council Members, Technical Reviewers and Group members from across the country attended the webcast. The webcast received wide appreciation from the attendees.

Further, in order to acknowledge the contribution and efforts of past as well as present Board members, a felicitation event was also organised. CA. Naveen N. D. Gupta, President, ICAI, CA. Prafulla P. Chhajed, Vice President, ICAI, CA. T. S. Vishwanath, Former President, ICAI, CA. N.D. Gupta, Former President, ICAI and Honourable member of Rajya Sabha, CA. Amarjit Chopra, Former President, ICAI, CA. Jayant P. Gokhale, CA. Vinod Jain, CA. Babu Abraham Kallivayalil, Former Chairmen of the Board graced the event alongwith council member, Technical Reviewers and the members of the Financial Reporting Review Groups .

(II) Publication: Article in Journal

With a view to apprise the members of the Institute and others concerned about the non-compliances observed during the review, the Board initiated a series of articles in journal regarding 'Non-Compliance with Reporting Obligations' pertaining to various Accounting Standards. In this direction, 4 articles on 'Non-Compliance with Reporting Obligations' pertaining to AS 1: Disclosure of Accounting Policies, AS 15: Employee Benefits, AS 3: Cash Flow Statement, AS 2: Inventories and AS 18: Related Party Disclosures have been published in the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant', in the issue of November, 2018, April, 2019, May 2019 and June 2019 respectively.

(III) Empowering Members and Capacity Building

- To enhance the knowledge of members with the changes made in financial reporting framework as well as to apprise them about the common non-compliances observed by the Board during review of various financial statements, following activities were undertaken during this period:
- 4 Live Webcast have been organized on Commonly Found Non-compliances on AS 15, AS 3, AS 2, AS 18 and Companies Act, 2013 in the month of March, April, May, June 2019 and were well attended by members.
- Awareness Programmes on "Financial Reporting Practices" have been organized by FRRB at Gurugram, Kolkata, Ludhiana, Chandigarh. In Gurugram and Kolkata, it was attended by 156 members and 113 members respectively and in Ludhiana-Chandigarh, it was well attendant by 150 members in each city.
- *2 Day Training Programme for Technical Reviewers and FRRG Members:* To update the Technical Reviewers (TRs) and members of Financial Reporting review Group (FRRGs) on Ind ASs and equip them with the necessary skills required to review the Ind AS based financial statements a '2 Day Residential Workshop for Technical Reviewers and FRRG Members' was organized by FRRB.
- The Board also organised a 'Seminar for Preparers and Auditors of the Financial Statements' on July 14, 2018 at New Delhi, which was hosted by NIRC of ICAI. The Programme was inaugurated by President, ICAI and Shri V. Kurian, Ex- DG (Commercial) C&AG, who enlightened the participants by sharing their enriching experience with them. With the view to identify the issues and challenges pertaining to financial reporting, a panel discussion was also held, wherein CFOs of renowned corporates as well as experienced members in practice were invited to share their views on the subject. The programme was well attended by 176 members and was highly appreciated by the participants and faculties.

5.14 Indirect Taxes Committee (IDTC)

(I) **Input/support to the Government:** The Committee has submitted following inputs/ suggestions to the Government:

- Suggestion on Annual Return Form GSTR -9 on 26th Sept, 2018
- Suggestion on GST Audit Form GSTR -9C on 11th Dec, 2018.
- Suggestions on draft return formats on GST on 31st August, 2018
- Suggestions on GST Law on 12th July, 2018
- Suggestions on proposed amendments in GST Law on 18th July, 2018
- Alternative workable Reverse Charge Mechanism under GST on 17th July, 2018
- Post Budget Memorandum, 2018
- Nomination of members at GSTN for testing of GST Accounting, Billing and Return filing software

(II) **Representation/presentation to/before the Government:** The Committee submitted representation to the Government on the following matters:

- Consultation meeting on GST Return filing with Group of Ministers (GoM) on April 17, 2018
- Meeting with Senior Officers in CBIC and GSTN on 8th Oct, 2018
- Representation for extending due date of filing Form GSTR 9 & 9C on 4th Dec, 2018
- Representation for permitting availment of input tax credit under GST pertaining to Financial Year 2017-18 till 31st December, 2018 on 15th Oct, 2018

- Representation suggesting non-deduction of TDS under MVAT Act after implementation of GST on 4th October, 2018
- Representation for hosting Judgement of Advance Ruling on the Website on 29th May, 2018

(III) Publication – A research Initiatives: The Committee brought out/revised following publications on GST/Service Tax/CST/Customs/FTP:

- Technical Guide on Annual Return & GST Audit – 2nd Edition – May, 2019 (New & revised once)
- Handbook on GST Annual Return – 1st Edition – May, 2019
- Background Material on GST– 7th Edition – March, 2019
- E-Publication on E-way bill – 4th Edition – February, 2019
- E-Publication on supplies by/to Government under GST– 1st Edition – Jan, 2019
- E-Publication on Exempted Supplies under GST– 1st Edition – Jan, 2019
- Background Material on GST Law for Commerce Students – 1st Edition – Jan, 2019
- Background Material on Customs and FTP– 3rd Edition – January, 2019
- E-Publication on Refund under GST– 1st Edition – Dec, 2018
- Bare Law on GST- 3rd Edition -Nov, 2018
- Handbook on classification under GST– 1st Edition – July, 2018
- E-Handbook on GST Amendments – 1st Edition – June, 2018
- E-Handbook on Job-work under GST – 2nd Edition – June, 2018
- Compliances of GST in Banking Sector – 6th Edition – April, 2019

(IV) Initiatives for VAT in Dubai: VAT has been implemented in UAE from 1st January, 2018. With a view to support the members, the Committee has taken following initiatives:

- Revision of BGM on UAE VAT – 3rd editions – June, 2018
- Organising Certificate Course on UAE VAT
- Organising a series of LIVE Webcasts on UAE VAT

(V) E-initiatives

- E-learning on GST Audit: Committee launched E-learning on GST through recorded video sessions covering almost the entire topics of GST. This was subscribed by 1160 stakeholders and benefited out of this initiative.
- E-learning on Litigation Management: To build further capacity of the members in indirect taxes, the Committee recorded 13 sessions on litigation management and converted into e-learning.
- LIVE Webcasts series on GST Audit: The Committee organised 3 series of live webcasts on GST Audit in July, October and November, 2018.
- Live webcast Series on Customs and FTP: To build overall indirect tax capabilities, the Committee is organising a series of live webcast on Customs and FTP containing 10 session from 2nd to 9th February, 2019.
- Live Webcast Series on GST for Student: The Committee jointly with Board of Studies has been organising a Live Webcast Series on GST for Student on 14th, 15th, 21st, 22nd, 28th, 29th July, 2018 4th, 5th, 11th and 12th August, 2018.
- Short Video on various concepts of GST: The Committee has recorded 70 short videos on various concepts of GST which have been hosted on YouTube free of charge.
- ICAI E-Newsletter on GST: ICAI has been issuing its newsletter on GST from April, 2017. 23rd issues of the same have been released till June, 2019.
- Standardised PPT on GST: The Committee has developed Standardized PPT on GST and hosted on the website with a view to provide guidance to the faculty members and bring uniformity in the session of GST in the programme as well as proving a tool to members to learn GST through PPT.
- Training Programme for the Government: With a view to help the Government in capacity building and partner them in Nation Building, the Committee organised 7 training programmes on GST at various Commissionerates across the Country.

(VI) Awareness programme for members through Course, programme, workshop, conferences etc.

- **Certificate Course on GST:** With a view to facilitate the members with the specialized knowledge in the area of GST in a systematic manner and enhancing their skills, the Committee has organised 25 batches of Certificate Course on GST during the year which have been attended by 1227 members.
- **Programmes, Seminars and Conferences:** During the period, 61 programmes, seminars, conferences and workshops etc. have been organised by the Committee, which were attended by more than 12000 members.

- **Formation of Study Group for helping State Government in smooth implementation of GST:** Committee has formed nineteen (16) State level Study Group on GST for extending its support to the State Government in smooth implementation of GST.
- **Indirect Taxes Updates including legal update-** With a view to update the members, summary of significant notifications, circulars and other important development in the area of Indirect Taxes, including GST are regularly been circulated among the IDT NET registered members on the website of the Committee www.idtc.icai.org Further, the Committee has recently started sending Legal Update on Indirect Taxes to the members registered on its website.

Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi acknowledged ICAI's GST endeavours when he said in his CA Day message "A year ago, when the nation had just begun heading towards the One-Nation-One-Tax goal, I had the opportunity to address your (CA) fraternity. Today, we have all ushered in a new era in history of Indian economy making the goods and services tax come out with flying colours... Such a feat could not have been achieved without your (CAs') vital contribution in not only helping businesses adapt to the new tax regime but also in coming up with innovative ways to simplify the system..."

5.15 Internal Audit Standards Board

In this era of globalization, deregulation, increasing complexity of business, maturity of IT systems and increasing expectations from stakeholders, role of Chartered Accountants as internal auditors in facilitating these changes has occupied center-stage attention. Hence, there is a growing need to better equip members of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to enable them in discharging these onerous duties. The ICAI has been proactive in these areas and come up with several landmark initiatives in providing cutting-edge technical guidelines to Chartered Accountants through its Internal Audit Standards Board. A comprehensive overview of the important initiatives of the Board during the year is as follows:

(I) Standards on Internal Audit

The Board has been bringing out Standards on Internal Audit which, in addition to outlining fundamental principles for the guidance of the members, also serve as their performance benchmarks. The Board has initiated the process of revising the Standards to make them principles based and making them mandatory for certain class of companies in a phased manner. Revised Standards have been re-numbered and classified in the categories: Standards on Key Concepts (100 series), Standards on Internal Audit Management (200 series), Standards on the Conduct of Audit Assignments (300-400 series), Standards on Specialized Areas (500 series), Standards on Quality Control (600 series) and Standards on Miscellaneous Matters (700 series). These principle-based Standards provide a framework for internal audit activities, establish the basis for evaluation of internal audit performance, and foster improved organizational processes and operations. The Internal Audit Standards Board has issued following revised Standards on Internal Audit during this period:

- Preface to the Framework and Standards on Internal Audit
- Framework Governing Internal Audits
- Basic Principles of Internal Audit
- Standard on Internal Audit (SIA) 210, Managing the Internal Audit Function
- Standard on Internal Audit (SIA) 220, Conducting Overall Internal Audit Planning
- Standard on Internal Audit (SIA) 310, Planning the Internal Audit Assignment
- Standard on Internal Audit (SIA) 320, Internal Audit Evidence
- Standard on Internal Audit (SIA) 330, Internal Audit Documentation
- Standard on Internal Audit (SIA) 110, Nature of Assurance
- Standard on Internal Audit (SIA) 230, Objectives of Internal Audit
- Standard on Internal Audit (SIA) 240, Using the Work of an Expert
- Standard on Internal Audit (SIA) 360, Communication with Management
- Standard on Internal Audit (SIA) 370, Reporting Results
- In order to provide one stop reference of the existing suite of Standards to the members, the Board has issued Compendium of Standards on Internal Audit (As on February 1, 2019).

(II) Industry Specific and Generic Internal Audit Guides

The Board has constituted study group for various projects i.e., Revision of Manual on Concurrent Audit of Banks (2016 edition), Technical Guide on Internal Audit of FMCG Sector, Technical Guide on Risk Based Internal Audit in Banks, Technical Guide on Internal Audit of Cement Industry, Technical Guide on Internal Audit of Pharmaceutical

Industry, Technical Guide on Internal Audit of Tyre Industry, Revision of Technical Guide on Internal Audit of Stock Brokers.

(III) Certificate Course on Concurrent Audit of Banks

The Internal Audit Standards Board of the ICAI is conducting Certificate Course on “Concurrent Audit of Banks” to enable members to understand the intricacies of concurrent audit of banks. The Board has successfully completed 61 batches of the Certificate Course on Concurrent Audit of Banks at various places and around 1780 members have successfully qualified the Course during this period. Online examination for around 1150 candidates is scheduled to be held in August 2019.

(IV) Certificate Course on Internal Audit

The Board has revised Course Structure for "Certificate Course on Internal Audit", which has been completely revamped with new topics and heavy dose of information technology. The main thrust of the course is to educate the participants on the theory and concepts of internal audit, especially its linkage with risk management and governance concepts, provide practical exposure to the design and conduct of internal audit, especially through the deployment of information technology and specialized tools, understand the current best practices and the way to deploy these to mitigate risks and address business challenges, and help the members acquire all the skills and knowledge required to conduct highly professional, best-in-class internal audit, which not just provides basic assurance but seeks to add tangible value to their organizations.

The Council has approved the revised curriculum of Certificate Course on Internal Audit recently and the Board has finalized the modalities. It is proposed to launch the batches of the said Certificate Course in the metro cities of India. Further, videos recordings of all the modules of E-learning of Certificate Course on Internal Audit have been done and is being uploaded on E-learning platform of the Institute.

(V) Virtual Certificate Course on Concurrent Audit of Banks

The Board has taken this new initiative in year 2018 in which classes would be conducted through blue jeans link as provided to Participants by the Board. Participants would login with their own laptops/ computer system. There is no such need to visit the venue or Branch premises to attend the class. Through BlueJeans, participants and speakers would be connected face-to-face from anywhere. The Board had successfully conducted first batch of virtual Course at Anantapur in December 2018.

(VI) E-learning on Concurrent Audit of Banks

With a view to provide easy access to the members, the Board has also taken up the project of development of e-learning modules of "Certificate Course on Concurrent Audit of Banks" which would include quizzes and case studies on practical aspects of concurrent audit.

Videos recordings of all the modules of E-learning of Certificate Course on Concurrent Audit of Banks have been done and is being uploaded on E-learning platform of the Institute.

(VIII) Programmes, Seminars, Conferences and Webinars on Awareness on Internal Audit

With a view to provide platform of dissemination of knowledge among members, the Board has organized 8 programs on Internal Audit at various places during this period. The Board has also organized Twenty Ninth webcast on “Making Concurrent Audit More Effective and Relevant” on April 27, 2018.

(IX) Survey Report on State of Internal Audit Profession in 2019

This is one of the first comprehensive surveys commissioned by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) on the Internal Audit professions in India and conducted under the aegis of the Internal Audit Standards Board. The survey polled 406 participants, members- both from the industry (44%) and in practice (56%) and others, covering a broad range of topics using 27 questions, during November and December 2018. This report is an outcome of this exercise and is designed to gauge the current pulse, and future prospects, of the Internal Audit profession in India based on inputs of the participants.

5.16 Committee on International Taxation

(I) Representations/ interactions with Government

- Request to CBDT for establishing a Transfer Pricing Unit in Bhubaneswar
- Representation regarding difficulties and challenges in filing Form No. 67 for claiming foreign tax credit in income-tax return and reporting of Indian bank account in the income-tax return
- Submission of Pre Budget Memoranda pertaining to International Taxation
- Request made to CBDT for Public Consultation on the proposal for amendment of Rules for Profit attribution to Permanent Establishments (PE)

(II) Conferences/Seminars/Workshops/Webcasts on International Taxation

- A seminar on International Taxation was organized by the Committee which was hosted by Hyderabad Branch of SIRC of ICAI on 14th July 2018 containing technical sessions on Non Resident Taxation - Key Issues, Permanent Establishment - Current Legal Trends, BEPS Action Plans and Multilateral Instrument (MLI), General Anti Avoidance Rule (GAAR) and Section 195-Withholding Taxes.
- LIVE WEBCAST - “*An Overview of Hong Kong transfer pricing legislation – The BEPS Bill*” organized by Committee on International Taxation of ICAI on 04.09.2018.
- LIVE WEBCAST - “GAAR- Issues and Case Studies” organized by Committee on International Taxation of ICAI on 25.04.2019.
- LIVE WEBCAST - “*Royalties and Fees for Technical Services – Case Studies*” organized by Committee on International Taxation of ICAI on 30.5.2019.

(III) Post Qualification Diploma in International Taxation

The Committee has conducted 14 batches of Diploma Course in International Taxation during the period at New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Ghaziabad, Pune, Trivandrum, Ernakulam and Kolkata.

(IV) Other initiatives:

- The Committee had released 9th edition of e-Newsletter on International taxation during the above mentioned period.
- Two attempts of assessment tests for Certificate course in International taxation were held in April, 2018 and October, 2018.
- The Committee has added a few e-learning modules on some of the important topics as per following details:
 - Base Erosion and Profit Shifting (excluding Action Plans 8-10 and 13) and Multilateral Instruments
 - Base Erosion and Profit Shifting -Action Plans 8-10
 - Transfer Pricing Documentation and Drafting (including BEPS Action plan 13)
- Revision of the Background Material of Diploma in International Taxation Course and Taxation of Non-Residents.
- Contribution of articles on International taxation in CA Journal.
- Regular updates to the members on the subject of International taxation to domestic as well as overseas members.

5.17 Committee for Members in Industry & Business

The Committee serves as a platform to facilitate synchronization between individual and organizational goals, create an interface between ICAI and industry, and recognize/ project Chartered Accountants beyond the traditional fields and as skilled and knowledgeable professionals on all aspects of functioning in company, business and commerce. The Committee seeks to encourage and enhance the close links between CAs in industry and business, and the Institute. To support this endeavour, the CMI&B has been organizing various knowledge-enriching conferences, industry meets and outreach programmes for the benefit of the members. Other important activities of CMI&B include providing placement opportunities to both young and experienced Chartered Accountants through campus placement programmes and ICAI job portal, organizing the prestigious ICAI Awards to recognize exemplary achievements of Chartered Accountants in business and industry, releasing general publications on the matters of professional interest, formation of CPE study circles, e-newsletter, etc., in the interests of members. Major activities that took place during 2018-19 are:

(I) Campus Placement Programme for newly qualified CAs

- *August-September 2018:* These were held at 17 centres wherein 5822 candidates registered, out of which 3530 appeared for interview. 111 organisations participated and offered jobs to 1600 candidates. Highest

salary (cost to company) offered was Rs. 22.62 lakh per annum for domestic posting and 35 lakh per annum for international posting.

- *February-March 2019:* These were held at 17 centres wherein 9011 candidates registered, out of which 6646 appeared for interview. 139 organisations participated and offered job to 3815 candidates. Highest salary (cost to company) offered was Rs. 22.50 lakh per annum for domestic posting and 36 lakh per annum for international posting.

(II) Overseas Campus Placement programme

ICAI in line with its mission to partner with the Government of India champion sector initiative for increased export of accounting services, organised Overseas Campus Placement drive between 14th -16th September 2018 under the aegis of CESWTO, CMII and IA Committees. While these were conducted through videoconferencing mode at Jaipur, Kolkata, Hyderabad and Bangalore; both physical interactions and videoconferencing were made available at Mumbai, Delhi and Chennai centres.

Total companies Registered	Total companies Participated from Middle East and Africa	Registered Members	Shortlisted Members	Appeared Members	Offered
42	29	6428	1527	544	66

Being the maiden initiative; this drive had many a positives; despite slump and slowdown in Middle East, with limited efforts ICAI had drawn interest of 42 companies and that too only Middle East with one company from Africa.

(III) **Job Fair:** Job Fair for ICAI CA Inter/IPCC/PE II Candidates at Mumbai on 19th January, 2019.

(IV) Placement for experienced CAs

- *Snapshot of Career Ascent Programme:* CMI&B organized Career Ascent programme on 29th June 2018 in Mumbai and in Chennai and New Delhi on 30th June 2018. This provided platform for placement opportunities to experienced Chartered Accountants to secure career advancement in leading organizations. It was a customized campus placement programme for the chartered accountants who have three-year-plus experience of working in industry. 17 organisations (22 interview teams) participated creating 291 vacancies and more than 1000 candidates registered for this programme.
- *Lateral Placement:* Lateral Placement was organised successfully from 25th to 28th June 2019 in Chennai, Kolkata, Mumbai and New Delhi to provide a platform for placement opportunities to experienced Chartered Accountants to secure career advancement in leading organizations. 14 companies (17 interview teams) with 226 vacancies participated in the placement drive.

(V) Awards

- *SME Leader Awards:* The Committee had organized “SME Leaders Awards” successfully on 26th October, 2018 at Mumbai to honor imagination, commitment & success of members who have made valuable contributions to the SME’s activities and growth. The Jury panel headed by Shri Manohar Kumar, CMD, National Projects Construction Corporation Ltd. selected eleven awardees who were felicitated during the gala night.
- *International Leader Awards:* The Committee had successfully organized International Leader Awards, hosted by Abu Dhabi Chapter of ICAI, for the members who are based outside India to recognize their achievements as a result of which they have attained the heights in their career on 15th November, 2018 at Abu Dhabi. Seven awardees who were selected by the Jury Panel chaired by Dr. Subhash Chandra Khuntia, Chairman, IRDAI were felicitated during the award ceremony.
- *12th ICAI and Business Excellence Awards:* The Committee had successfully organized 12th ICAI and Business Excellence Awards at Hotel Grand Hyatt, Mumbai. 29 Awardees were felicitated by the august hands of Shri Vijay Goel, Hon’ble Minister of State for Parliamentary Affairs and Statistics and Programme Implementation. Jury panel under the chairmanship of CA. Keki Mistry, Vice-Chairman & CEO, HDFC selected the awardees.

(VI) Programmes Organised

Various programmes, including seminars, live webcasts, interactive meets, CFO Meets, etc., were organized on recent laws with special focus on GST, merger & acquisition, construction industry, food processing industry, healthcare industry, blockchain, fintech, accounting & financial reporting, building start-ups, etc., during this period.

(VII) New CPE Study Circles for Members in Industry

The Committee has formed CPE Study Circles for Members in Industry of ICAI: J. K Gram CPE Study Circle of Raymond Ltd, Faridabad CPE Study Circle of L& T- MHPS Boilers Private Limited(LMB), Brook Field CPE Study Circle of DXC Technology, Haddows Road CPE Study Circle of Sundaram Clayton Limited, Grande Palladium CPE Study Circle of Marico Limited, Ramanujan ITP CPE Study Circle of Philips Global Services LLP, Ghaziabad CPE Study Circle of Bharat Electronics Limited, INOX Noida CPE Study Circle of HPCL Mittal Energy Ltd(HMEL) , Moti Nagar CPE Study Circle of Jindal Saw Ltd, Mumbai CPE Study Circle of Cipla Ltd.

(VIII) Launching of CA Job Portal:

The Committee had launched CA Job Portal which is one stop solution for all job requirements of CAs where recruiters can choose from the huge no. of relevant job options available at one place. In order to further expand the reach of the CA Job Portal platform, the Committee had launched mobile applications of CA Job Portal which are having features that interacts with, and often integrates, with camera, contact list, calendar, etc. so that user can easily perform various tasks in just a click. 3614 Companies are registered on CA Job Portal with 1110 vacancies for members and 71 for CA Inter.

(IX) Setting up of Helpdesk:

The Committee has set up a helpdesk within the committee for disposal of all the queries and concerns of the members in industry. Members in industry can submit their queries pertaining to ICAI through any of the below mentioned channels:

- Fill the form in help desk at <https://cmib.icaai.org> or
- Drop an email to helpdesk.cmib@icaai.in or
- Call at 844851274

5.18 Peer Review Board (PRB)

The Peer Review Board was established in 2002, recognizing the need to ensure the quality of services provided by practicing Chartered Accountants.

The Peer Review is aimed to ensure that in carrying out the assurance service assignment, the members of the Institute (a) comply with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable including other regulatory requirements thereto and (b) have in place proper systems including documentation thereof, to amply demonstrate the quality of the assurance services. The Peer Review is conducted of a Practice Unit by an independent evaluator known as a Peer Reviewer.

The requirements of two regulators - SEBI and C&AG, in recognition of the Board's endeavor are stated below:-

- SEBI with effect from April 1, 2010, has made it mandatory for the listed entities, that limited review/statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the Institute.
- C&AG has recognized Board's work; as it seeks details from the CA firms about their Peer Review Status in the application form for allotment of audit for Public Sector Undertakings. Furthermore, from last few years, the C&AG annually seek details from ICAI of those firms which have been issued certificate by the Board.

Coverage of more firms under Peer Review process

The Board as a regulator for review of assurance services of CA firms in India has increased its scope of assurance services by coverage of more firms for peer review. Cases of non-compliances observed in the Financial Statements which may not affect the True and Fair view but indicates negligence on the part of the auditor, are forwarded by the FRRB so that the quality control framework applied by the member may be ascertained. Also, Peer Reviewers are now required to report on the coverage of the practice unit under Quality Review and the necessary compliance as regards submission of Compliance Report to Quality Review Board. Also, resources and investments made by PU for

development and communication to its personnel in support of its QC system is also to be reported by the Practice Unit. The summary report is forwarded to QRB periodically, for its review and necessary action. Such efforts will make the regulatory mechanism of the Institute more effective.

The Peer Review Board has considered and issued 11,411 Peer Review Certificates till June 30, 2019.

5.19 Professional Development Committee (PDC)

Since its establishment in 1962, Professional Development Committee (PDC) has been making vigorous efforts towards exploring ample opportunities for the members of the Institute in different sectors of the economy. Apart from exploring uncharted territories in the professional development, the Committee strives to strengthen the communication process with multitude of users across the different sections of the society and educate them about the role of Chartered Accountants. In the year 2019, the Committee is also looking after the various tasks being performed by the Committee on Co-operatives and NPO Sectors in the year 2018-19. With a view to enhance skill sets of Chartered Accountants in the existing and new areas, it also organizes seminars, workshops on contemporary areas of interest.

(I) Development of Software for Allotment of Bank Branch Audit by all PSBs

The Institute has over the years expressed its concerns on the issue of appointment of auditors of Public Sector Banks by the Banks' Board themselves. The Management of Public Sector Banks do not have any major ownership interest, this autonomy of appointment of auditors by management is fraught with risk in a very important and sensitive sector like banking.

To address the issue, PDC has developed the automated application for selection of Bank Branch Auditors without any manual intervention. With the usage of software so developed by large number/ all banks the process of allotment will become uniform apart from fair, transparent and equitable. Accordingly, PDC had demonstrated the software to most of the banks and as a result of continuous persuasion for utilization of the software, for last year, the Software was used by 7 Banks namely Punjab National Bank, Central Bank of India, Bank of Baroda, Dena Bank, United Bank of India, Punjab & Sind Bank, Oriental Bank of Commerce, Public Sector Banks.

(II) Panel to Various Authorities

Bank Branch Auditor's Panel to RBI and NABARD: PDC in its endeavour to explore equitable professional opportunities for CA members, for the year 2018-19, hosted the MEF application which contained pre-populated data of applicants' from ICAI's records for the case of their filing the form. Members were also facilitated in uploading the Financial Documents online in addition to submission of Declaration digitally signed or Scanned Declaration.

As per the applications received, the Bank Branch Auditors' Panel 2018-19 was prepared as per RBI norms and was submitted to RBI, NABARD etc.

Panel to Security Exchange Board of India (SEBI): Every year, SEBI conducts inspection of mutual funds under Section 61 (1) of the SEBI (Mutual Fund) Regulations, 1996. Till now, CA firms which were interested in conducting the inspection on behalf of SEBI, used to apply as per the eligibility norms regarding their empanelment with SEBI. Last year, for the first time, SEBI approached ICAI asking for a panel of Chartered Accountant firms/ LLPs. Accordingly, a panel has been submitted to the SEBI and this will pave the way for more professional opportunities for our members. Professional Development Committee has also submitted the panel to the following authorities:

- Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi
- Serious Fraud Investigation Office (SFIO)
- State Express Transport Corporation, Tamil Nadu
- Indian Institute of Bank Management, Guwahati
- Finance Department, Government of Gujarat
- The Financial Advisor and Chief Accounts Officer, Indian Institute of Management Tiruchirappalli
- Central Warehouse Corporation(CWC), Delhi etc.

(III) Unique Document Identification Number (UDIN)

To curb the malpractices of misrepresentation of Chartered Accountants' services and forgeries of signatures of CA's by Non CAs, ICAI has taken the initiative of UDIN by creating a platform namely "UDIN portal" wherein any Regulator/Stakeholder can visit and verify the authenticity of Report/Certificates/Documents certified by Practicing Chartered Accountants in real time without any manual intervention.

Henceforth, every Practicing Chartered Accountant has to generate an 18 Digit system driven random number to put on every Certificates/Reports/Documents and Regulators/Stakeholders can visit the UDIN portal and verify the credentials of Chartered Accountant who has certified that Reports/Certificates/Document.

As per the decision of the Council of ICAI, UDIN has been made mandatory for all Chartered Accountants who are in Full-time Practice in a phased manner as following:

- From 1st Feb. 2019 onwards, for all certifications.
- From 1st April 2019 onwards, for all GST and Tax Audit Reports.
- From 1st July 2019, for all Assurance/Attest functions.

ICAI has taken up the matter with various Regulators and Authorities to accept the documents certified by CAs with UDIN only and also to include a mandatory column for mentioning UDIN in all the Forms/Reports certified by CAs.

The UDIN Portal so developed by ICAI allows only full-time Chartered Accountants to generate UDIN. Using this UDIN system, regulators having UDIN number, on a single click, can verify the credentials of Chartered Accountant and the authenticity of the document.

The UDIN operates on secured platform as it does not require uploading of any document or sharing of any confidential details.

UDIN is one of the landmark reforms of the year 2018-19 and ICAI is the pioneer in the world to conceptualize the concept of UDIN. With this concept, frauds and forgery of CAs signature by unscrupulous elements will now be a thing of past. Many member bodies of the South Asian Federation of Accountants (SAFA) has shown interest in this unique initiative of the ICAI and a SAFA Task Force under the convenorship of ICAI has been formed at the SAFA Level.

(IV) Tendering

The Tendering of Professional Services has always been an area of concern. PDC has taken up the various issues including the evaluation criteria in Tendering with CVC at various point of time.

It has been observed that sometimes organizations float the tenders without mentioning any Minimum Fees or quote very low minimum fees. On the other hand, Members of ICAI are also responding to the tenders which do not mention of any Minimum Fees which is violating Council Guidelines. To address such issues related to Tendering, a Group for "Monitoring the Tendering issues" has been formed. It will also monitor the tenders floated and their standardization, taking up with CVC for determining the manner of evaluation of tenders related to professional services, to develop a mechanism for monitoring and analyzing the responses of the members and referring the deviations at appropriate level.

Further during the year various representations were sent to various authorities on various issues such as quoting the minimum fee of the assignment in the tender document, for stringent / restrictive eligibility conditions, to make it equitable etc.

(V) Certificate Courses conducted:

The Committee for Co-operatives and NPO Sectors of ICAI conducts two Certificate Courses ON Cooperatives and NPO. During the year, the Committee conducted 2 batches of Certificate Course on Cooperatives at Gwalior and Kolkata and 2 batch of Certificate Course on NPO at Noida and Siliguri.

(VI) Consideration of Tie ups with Educational Institutes like IIMs.

ICAI has entered into a MOU with IIMA wherein it was agreed to partner in co-hosting of customized training programmes exclusively designed, developed and delivered for Chartered Accountants by IIMA. The two batches of the said course were conducted by the Young Members Skill & Innovation Development Committee wherein 35 Chartered Accountants have attended the Programme and was a huge success and to take the initiative further, the Professional Development Committee is conducting the course from 7th to 11th October, 2019, exclusively designed for Chartered Accountants to acquire managerial excellence in functional and operational areas.

(VII) CA Directors Interactive Meet

- With the intent to have continued dialogues with the Chartered Accountant Directors on the Board of Banks & Public Sector Entities, Professional Development Committee organized yearly interactive meet of CA Directors on 14th June, 2018 at New Delhi in the presence of Shri Dr. Navrang Saini, Whole-Time Member, Insolvency and Bankruptcy Board of India as Chief Guest, the then President & Vice-President, Past Presidents.
- This year, the scope of the meet was widened by including the CA Directors of Asset Management Companies, Insurance Companies & Public Sector Undertakings in addition to Banks and was jointly organized with Corporate Laws Corporate Governance Committee.
- More than 40 CA Directors participated and the meet was highly appreciated which covered the Technical sessions on contemporary topics such as Corporate Governance, Internal Financial Control, Risk Management in Banks, Cyber Security etc.

(VIII) Series of Seminars for Central Statutory Auditors at various locations

A series of interactive seminars with the CSAs were organised by PDC jointly with AASB to discuss about revised directions/circulars by RBI and recent developments in Standards on Auditing such as SA 700, SA 570, SA 26,, SA 299. These seminars aim to familiarize Central Statutory Auditors (CSAs) of the recent regulatory developments pertaining to banks.

Under above series, four seminars were held at Mumbai, Delhi, Kolkata & Chennai on 19th January, 23rd January, 30th January and 7th February, 2019 respectively.

(IX) State Level Co-ordination Committee (SLCC) Meeting on the working of Non-Banking Financial Companies & Unincorporated Bodies

ICAI has represented Chartered Accountants community as they serve as the auditor of the NBFCs Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India normally holds State Level Coordination Committee\meeting (once in a every quarter) to regulate Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and deposit accepted activities of incorporated bodies (UIBs) at each of their regional offices. Such meetings is conveyed by Regional Director of respective regional office of RBI and attended by Principal Secretary/Secretaries of various departments such as Finance, Home, Law etc. of respective states, National Housing Board (NHB), Securities Exchange Board of India (SEBI), Registrar of Companies (RoC), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA), Registrar of Chit Fund, Department of Chit Fund and The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

(X) Inputs sought by C&AG on their draft revised norms for Empanelment

ICAI offers its inputs to C&AG as and when sought to review the present arrangement for empanelment of CA firms and to fine tune the allotment of PSEs audits to the empanelled CA firms.

(XI) Other activities

- *Meeting with RBI, NABARD & IBA:* ICAI representatives met RBI, NABARD and IBA on 3rd June, 2019 and several concerns relating to the profession like gaps in audit, divergence in Audit and Inspection Report, LFAR and Auditors' Qualification and adherence to Accounting Standards etc. were discussed. Various other matters such as upward revision in audit fee, separate fee for tax audit, the issues faced by various Auditors while conducting Bank Audits, limited number of branches to be allotted to one auditor and consideration of Sole Proprietorship firm for the allotment of audit of RRBs etc. were also discussed. *Meeting with RBI on "Cyber Security Framework":* ICAI representatives met the team of CSITE Cell of Department of Banking Supervision, RBI on 18th April, 2019 at Mumbai for additional certification to be done Statutory Central Auditors on "Cyber Security Framework". On acceding to the request of ICAI, RBI has advised SCAs the methodology to be followed by them to assess the level of compliance by banks in this regard. Further, RBI advised that the Certificate in this regard may be submitted by SCAs along with the Long Form Audit Report (LFAR).
- *Exploring Professional Opportunities at Indian Post Payment Banks (IPPBs):* A communication has been written to Shri Ananta Narayan Nanda, Secretary, Department of Posts & Chairperson for exploring the utilization of the professional skills of Chartered Accountants in various areas at IPPBs.
- *Appointment of Statutory Auditor of Jammu and Kashmir Bank:* ICAI being conscious about the autonomy given to Banks for the appointment of auditors, the matter for maintaining the past practice of the appointment of Statutory Auditor of Jammu and Kashmir Bank Ltd for the year 2018-19 by the office of C & AG was taken up vigorously with RBI. Accordingly, for this year, the appointment of auditors was done by C & AG only.

- *Technical support to Reserve Bank of India (Department of Cooperative Bank Supervision):* The Committee provided technical support to Reserve Bank of India (Department of Cooperative Bank Supervision) in terms of providing faculties for their Workshop for Statutory Auditors of Urban Co-operative Banks held in June, 2018 at RBI, New Delhi.

(XII) Representations submitted

- *Representation to State Bank of India:* Representation was sent to State Bank of India for not treating the declaration taken by them from the statutory branch auditors/audit firms for not having been appointed as statutory central/branch auditors of any private sector/foreign bank during the current year as the Auditor/Audit Firm can do Branch Statutory Audit of a Public Sector Bank simultaneously with Statutory Audits of 4 Private Sector Banks and 4 Foreign Banks. SBI acceded to our request.
- Two Representations submitted in March, 2018 to Secretary cum Registrar, Office of the Registrar Cooperative Societies, Government of National Capital Territory of Delhi regarding extension of last date for submission of application form by CA/CA firms for empanelment of their names as Auditor in the Office of Registrar Cooperative Societies, for conducting the Audit of the Societies registered with the Department, Govt. of N.C.T. of Delhi.
- Representation submitted in April, 2018 to Commissioner for Cooperation and Registrar of Cooperative Societies, State of Maharashtra, Pune regarding extension of time period for cooperative society's auditors to submit refund application for seeking refund of 20% of audit fees as deposited over the years with the concerned District Deputy Registrar and District Special Auditor in Maharashtra.
- Representation submitted in January, 2019 to Registrar of Co-operative Societies, Gujarat State regarding empanelment of auditors for Cooperative Societies in Gujarat and related issues/concerns.
- *Representation submitted to Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare:* Representation submitted in January, 2019 to Joint Secretary (Coop.) & Central Registrar, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, regarding audit provisions in various State Cooperative Societies Act
- *Bank Branch Audit allotment in IDBI Bank:* Pursuant to the re-categorization of IDBI as Private Sector Bank with effect from January 21, 2019, ICAI represented to RBI and IDBI for continuing the Branch Audit of IDBI for this year in the manner to accommodate all continuing auditors and accordingly IDBI continued with the continuing auditors.

(XIII) Publication released during the year:

- *Quick Insights on Professional Opportunities for Chartered Accountants:* With an aim to provide heightened focus of Chartered Accountants who are in Practice on various emerging Professional Opportunities such as RERA, Ind AS, Companies Act, 2013, Artificial Intelligence, Blockchain, Cyber Security and Data Analytics (ABCD of Technology), GST, Registered Valuers, Forensic Audit, International Taxation, Insolvency Practice, PSU & Bank Audit etc. PDC has brought out the publication 'Quick Insights on Professional Opportunities for Chartered Accountants' as an e-book. It contains information about empanelment opportunities and other professional opportunities available at trending areas along with important contact web-links.
- *"Frequently Asked Questions for NPOs on GST":* The Committee has released the publication in a Question and Answer format to bring conceptual clarity on various issues related to GST for NPOs for the benefit of members and stakeholders at large.

5.20 Committee on Public Finance & Government Accounting (CPF&GA)

A. CPF&GA

Publications released by the Committee

- The Committee has revised its publication "Commonly Used Terms in Public Finance & Government Accounting" which shall be useful in understanding the terminology/economic terms related to public finance & economics.
- Research Study on "Accounting & Audit Reforms in Urban Local Bodies in India" and released brochure on "Quick Insight on Accrual Accounting".

Training Programmes/Workshops

The Committee organized number of programmes with Government Departments/PSUs at various places including Gangtok, Mumbai, Shimla, New Delhi Chhatisgarh, Jim Corbett, etc.

B. Committee on Public Finance & Accounting Standards for Local Bodies (CPF&ASLB)

In the year, 2019-20, a new Committee i.e. Committee on Public Finance & Accounting Standards for Local Bodies (CPF&ASLB) has been constituted which strives to assist Central & State Governments and Local Bodies in successful implementation of the accounting reforms and public finance management. The Committee primarily focuses on capacity building of the finance officials of various tiers of Government in India by various means such as organizing workshops, developing relevant e-training modules and formulating Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) etc.

5.21 Public Relations and CSR Activities

The PR & CSR Committee was reconstituted this year as “Public Relations Group”. The mission of the Public Relations Group is to develop, strengthen and enhance the image of the ICAI as a premier accountancy body and the sole regulatory authority for the profession of Chartered Accountancy in India through various ways and means, as considered appropriate within framework of the CA Act.

The PR Group further endeavors to foster good relations and aims to bridge the perception gap with internal & external publics and to provide better networking opportunities and to enhance visibility of ICAI. The Group regularly undertakes various initiatives and help Media houses / stakeholders/ Chambers of Commerce / Trade bodies and others to understand & acknowledge the contribution of ICAI & CA profession in economic growth of the nation & society at large.

The PR Group also focuses on Corporate Social Responsibility (CSR) that captures the true essence of social responsibility through a myriad of activities that leads to welfare of the society and promotes sustainable environment.

(I) Activities held during the year

- *Workshop for Media:* With an aim to bridge the perception gap and help media understand & acknowledge the contribution of ICAI & CA profession in economic growth of the nation & society at large, PR Group decided to undertake a series of Workshops for Media all across the country. In this series, the first media workshop was organised in New Delhi with an endeavor to make the media fraternity aware of various important and technical issues being dealt by ICAI. The workshop witnessed overwhelming response from the media, where senior media persons interacted with the expert speakers from ICAI to understand the topics and clear their doubts. Wide media coverage was given to the issues raised during the workshop.
- *CA Day 2018 & Platinum Jubilee Celebrations:* The Group requested all Regional Councils & branches of ICAI to celebrate “CA Day or CA Day week (July 1st - July 7th)” in a structured manner by undertaking mandatory and specified activities throughout the country in order to make collective impact. The launch of Platinum Jubilee celebrations of ICAI & CA Day 2018 was widely publicized by PR Group by undertaking the below mentioned initiatives.
- *Special Mnemonic for ICAI Platinum Jubilee Year:* A special Mnemonic was developed and officially launched on July 1, 2018 by Hon’ble President of India at function organized at New Delhi. The Mnemonic is being used in all communication of ICAI during the year.
- *Publications:* Coinciding with launch of Platinum Jubilee Celebrations, important publications were developed & released in the august presence of eminent dignitaries.
- *History of Accountancy Profession in India-Volume III:* A Group was constituted to bring out Volume III of the publication “History of Accountancy Profession in India” under the aegis of PR Group. This publication is a humble attempt to portray the efforts made by ICAI for the development of Indian accountancy profession and highlights the contribution of our forefathers, Past Presidents and the Central Council.
- *Treasure Trove of Wisdom from Visionaries-Speeches of Past Presidents, ICAI-Volume II:* In an attempt to express sincere gratitude to our Hon’ble Past Presidents for their tireless efforts, commitment & strong perseverance in the interest of the profession, the Group released the publication “Treasure Trove of Wisdom from Visionaries-Speeches of Past President’s-Volume II”. This distinctive publication communicates the significant journey of the Institute in last seven decades through the compilation of speeches of Past President’s delivered during the Annual Function of the Institute.
- *Audio Visual (AV) Films:* In order to showcase the important role played by the Institute in its last 7 decades before the important guests / Dignitaries / Stakeholders, few AV films were developed by PR Group and played to mark the CA Day at New Delhi.

- *AV on Platinum Jubilee of ICAI:* The AV traces the history of Accountancy Profession and milestones achieved by ICAI over last 7 decades, well narrated by Bollywood actor Boman Irani.
- *ICAI- A Treasure Trove:* Our predecessors, the Hon'ble Past Presidents left no stone unturned to pave the way for a bright future & have dedicatedly guided the profession to reach this exemplary position. The AV on Treasure Trove is a tribute to our forefathers.
- *AV about the publication "History of Accountancy Profession in India-Volume III":* The AV was conceptualized to display before the audience the importance of bringing out 3rd Volume of the publication that captures major changes, milestones and achievements of ICAI during last 20 years.
- *Video bytes of President & Vice-President on the occasion of CA Day:* On the occasion of CA Day, a video clip with messages from President and Vice-President addressing the CA Fraternity was prepared and uploaded on ICAI website. The same was also played during the CA Day function. The link of the same was forwarded to all concerned for reference.
- *Special Video Messages of eminent dignitaries:* To encourage and motivate the CA fraternity, the video bytes of eminent dignitaries - CA. Piyush Goyal, CA. Suresh Prabhu and CA. K. Rehman Khan were recorded and played on July 1st during the function held at Vigyan Bhawan.
- *Updation of Corporate Film-2018-19:* The ICAI Corporate Film is played during the various important events, Seminars/Conf. etc. organized by the HO/ DCOs/RCs/Branches. The Group had updated the ICAI Corporate Film for the year 2018-19 and the same was uploaded on ICAI Tv for the reference of all concerned and a link of the same was forwarded to all concerned for reference.

(II) Other Initiatives undertaken during CA Day 2018 Celebrations

- *The Goodwill messages on this occasion were invited from various Dignitaries. Like every year, a special issue of Chartered Accountants Journal was brought out to commemorate CA Day. Total 24 messages were received and published in the July'18 issue of Chartered Accountants Journal.*
- *Advt.s in Magazines: Towards brand building of ICAI and reiterating the significance and contribution of CAs,* advt.s were published in July issue of News / Business magazines i.e. The Week, Business Today, Outlook & Outlook Business.

(III) Promoting ICAI Election 2018 : Audio Visuals & Posters

- *With an aim to create better awareness, drive home the importance of participating in elections & communicating the actual election process to all members, few Audio Visual Films regarding the Voting Process, Inviting Members to Cast Vote, Process of Preferential Voting and Reminder Video were developed to motivate the Members especially new members to vote and also bring clarity about the ICAI Election process. Further, the final AVs were also circulated through Whatsapp groups/ social media to encourage & educate the members to vote.*
- *To publicize triennial elections of ICAI & to bring clarity among the Members about Election process and systems to be followed , a Poster was developed and put across polling booths pan India.*
- *For wider reach the Posters & Audio Visuals were also uploaded on social media and ICAI website.*
- *Letter(s) to Editors in response to misreporting by media: ICAI came across certain media reports projecting the profession and its members in bad light. The PR Group took strong note of the manner in which the news items were printed in leading newspapers bringing disrepute to the profession. Accordingly, Letters were issued to the Editors of newspapers that published adverse reports damaging the reputation and tarnishing the image of the profession of Chartered Accountants in the eyes of public. It was advised to publish suitable corrigendum in the respective matter.*
- *ICAI also filed complaints to The Press Council of India (PCI), against few publications for publishing malicious reports. The matter was followed-up and PCI reprimanded two publications namely Economic Times and Hindustan (Hindi) for misreporting and presenting the Chartered Accountant fraternity in poor light. The Press Council upholding its inquiry reports had issued a strong 'censure' to The Economic Times, while the Hindustan was issued a 'warning' with directions to publish the order passed by the PCI in the newspaper immediately. The matter regarding other publications is also being followed up with PCI.*
- *Important Media Clippings-Communication to all India Members:* It was decided by the PR Group that the important media clippings related to CA profession/ ICAI or any other news of relevance, should be forwarded to all India members on weekly basis to keep members informed of the latest news & updates. The 1st mailer to all India Members was started from May onwards.
- *ICAI Year Book 2018-19:* A comprehensive document capturing significant initiatives undertaken & achievements made by the Institute/Committee's/ Deptt.'s/ Regional offices/ Branches during the year is brought out in the publication-"Year Book". The PR Group collated information from all Committees/Branches/Regional Offices and designed & compiled the document "Year Book: 2018-19: 70 years of Serving, Supporting & Strengthening India's Growth Story."

(IV) Partnering in Initiatives of Government

- During the period Feb-Dec, 2018, Ministry of Corporate Affairs (MCA) had undertaken various activities promoting flagship programmes & campaigns. ICAI as a True Partner in Nation Building & to take forward the initiatives of the Government towards Corporate Social Responsibility (CSR), has actively contributes to the health and welfare of society.
- Following campaigns of the Government were undertaken PAN India by associating all Regional Councils /Branches

Sr. No.	Campaigns
1.	Observed Swachhta Pakhwada (August 1-15, 2018) initiated by Ministry of Drinking Water & Sanitation
2.	Swachhta-hi-Seva (Sept. 15- Oct 2, 2018) initiated by Ministry of Drinking Water & Sanitation
3.	Commemoration of 150 th birth anniversary of Mahatma Gandhi (Oct 2, 2018 to October 2, 2020)
4.	Vigilance Awareness Week (Oct 29, 2018 to Nov 3, 2018) initiated by Central Vigilance Commission
5.	Rashtriya Ekta Diwas/National Unity Day (Oct 31, 2018) initiated by Ministry of Home Affairs
6.	Constitution Day (November 26, 2018) initiated by Ministry of Social Justice & empowerment
7.	Invited Nominations for Prime Minister's Awards of Excellence in Public Administration 2019

- *Swachhta Abhiyaan:* Swachh Bharat Abhiyan (SBA) or Swachh Bharat Mission (SBM) was launched by Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi on October 2, 2014 to take forward Mahatma Gandhi's dream of Clean India through mass awareness campaigns. October 2, 2014 was indeed a moment of pride for ICAI when Hon'ble Prime Minister nominated ICAI along with other personalities and organisations to be associated with this noble campaign. Since the time ICAI was nominated to take forward this societal initiative, the Institute has been undertaking several campaigns and conducting Mass Awareness Programmes through its 5 Regional Councils and 164 Branches.
- This year too, several activities were undertaken like cleanliness drives/ take Swachhta Pledge/Tree Plantation/create awareness about environment conservation through Green Marathon etc. Several initiatives towards realising the vision of the Prime Minister are undertaken on regular basis and especially on important occasions like CA Day, Independence Day, Gandhi Jayanti etc. The aim is to sensitize and raise awareness on need for cleanliness and its associated benefits amongst the members, students and stake holders, officials and staff of ICAI.
- *5th International Day of Yoga:* To commemorate this occasion, ICAI had taken an initiative to encourage all members and students to inculcate Yoga for a healthy body and mind. The Group requested all Regional Councils & Branches of ICAI to celebrate 5th International Day of Yoga throughout the country on June 21, 2019. All concerned were advised to celebrate this day by undertaking specified activities. A good response was received to this initiative.

(V) Other Initiatives

- All major initiatives taken by the Institute were promoted through Social media in addition to print/electronic & online media.
- The Media interactions increased through one to one interviews, constantly apprising the media of the latest developments regarding the curriculum, profession, introduction of new courses, new guidelines for CAs, visit of foreign delegations, other activities and events etc.
- The Group promoted the potential & scope of Chartered Accountancy Profession in today's dynamic context by way of articles as well as through interactive meetings/releases issued to the press at national /regional level and through various TV Channels.
- To create awareness and promote the core domain of ICAI, advts were published in News/Business magazines.
- Provided logistic support to various departments within ICAI, to the regional Offices and Branches with a view to develop communication link between ICAI and its offices/related organizations.
- As part of the PR exercise, organized appropriate coverage in Print and Electronic Media for different Seminars/ Programmes / Events of ICAI.
- Articles on contemporary issues were published in major Business Publications.

5.22 Research Committee

Research Committee is one of the oldest non-standing Committees of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) established in the year 1955. The primary objective of Research Committee is to undertake research in the field of accounting and other affiliated areas with a view to enhance the value of services rendered by the profession. It formulates Guidance Notes on accounting aspects which are issued under the authority of the Council. It also brings out Technical Guides, Studies, Monographs, etc., on generally accepted accounting and/or auditing principles. The Committee, through its sub-committee, the Shield Panel, also conducts an annual competition, 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' with a view to improve the presentation of financial statements.

ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting for Financial Year 2017-18: These awards are being presented annually since 1958. Selection of awardees in specified categories is made through a robust three tier process: first review by Technical Reviewers followed by review of short listed annual reports by Shield Panel and final review by External Jury.

July meeting for the competition year 2017-18 was held on January 19, 2019 at Mumbai and was chaired by Shri U.K. Sinha, former Chairman, Securities and Exchange Board of India (SEBI). Others members of the Jury, who participated in the meeting to select the awardees, were CA. N.P. Sarda, Past President ICAI, Shri T.V. Mohandas Pai, Chairman of Manipal Global Service & Former CFO, Infosys Technologies Ltd., Shri Pravin Kutumbe, Member (Finance and Investment), IRDAI, Shri Nilesh Shah, Managing Director, Kotak Mahindra Asset Management Company Ltd., Shri Sanjay Jhanwar, Managing Partner, M/s Chir Amrit Legal LLP, Shri Anil Bafna, Sr. Partner, A Bafna & Co., Ms. Pinky Mehta, CFO, Aditya Birla Capital Ltd., Shri M. K. Sharma, Non-Executive Chairman and Independent Director of United Spirits Ltd.

As per the scheme of awards, one Gold Shield and one Silver Shield are awarded for the best entry and the next best entry, respectively. Apart from the above-mentioned awards, Plaques are awarded for commendable entries. Hall of Fame award is bestowed on an entity which wins five consecutive Gold Shields in a particular category.

A function to honour the awardees of 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' was held on February 2, 2019, New Delhi, Hon'ble Shri Justice P. P. Bhatt, President, ITAT was the Chief Guest at the occasion. A total of 10 awards – Two Gold Shield, Six Silver Shields and 2 Plaques were given away.

5.23 Committee on Capital Market and Investors' Protection (CCM&IP)

The Committee on Capital Market and Investors Protection was constituted by the Council as a Non Standing Committee of the ICAI in the year 1993-94. Further in the year 1998-99 the name of the Committee was changed to "Committee on Financial Market and Investors Protection". Consequently, in the year 2017-18 the erstwhile Committee on Financial Market and Investors' Protection was merged to the Banking Financial Services and Insurance Committee. Now the committee is reconstituted as Committee on Capital Market and Investors Protection in the year 2018.

The Committee provides suggestions on various Bills/Regulations/Notifications/circulars and other documents relating to Capital Market for submission to the Government/Regulator. Besides this the Committee regularly interacts with Reserve Bank of India (RBI) and Indian Banks Association for example, relating to Depositors, Non-performing Assets Management, Bank operation and supervision, issues relating to securitisation, role played by CAs, Non-Banking Finance companies – NBFCs (Department of Non-Banking Finance companies of RBI), Regulatory authority of Co-operative Banks, Strategies / recommendations relating to their investment patterns, Securities and Exchange Board of India e.g., matters relating to Primary and Secondary Markets, Take-Overs, Amalgamation, Mergers, (tax-havens, Participatory Note, hot-money, corporate governance regulatory compliances etc.), Mutual Funds, Foreign Institutional Investors, Intermediaries, Securities Laws etc, Forward Markets Commission (FMC) including NCDX and MCX, Stock Exchanges on the issues relating to Capital Markets and Investors Protection.

The Committee held the following activities during the year:

- With an aim to emerge as partner in the Nation Building and to spread awareness among the public at large about the do's and do not's of investing their money in financial securities and to promote financial literacy, the Committee organises Investor Awareness Programmes (IAPs) under the aegis of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) of the Ministry of Corporate Affairs. The same are organised through various Resource Persons and Programme Organizing Units (Regional Councils, Branches, Study Circles, Study Chapters and Study Groups) across the length and breadth of the country.
- The Committee has organized 671 Investor Awareness Programmes across India under the aegis of IEPF Authority Ministry of Corporate Affairs Government of India. In line with the speech of the Hon'ble President of India, Shri. Ram Nath Kovind on the occasion of Platinum Jubilee celebrations of the Institute of Chartered Accountants of India on 1st July, 2018 wherein he had requested the ICAI to conduct programmes to create financial literacy among the women of our Country. Accordingly, total of 38322 people were educated including 15372 women participants were educated in the above mentioned IAP's in FY 18-19"

- Presently, the Committee is entrusted with the task of conducting Certificate course for All India Members of ICAI, i.e. "Certificate Course on Forex and Treasury Management".
- The Committee has successfully conducted 51 Batches of Forex and Treasury Management course till date. During the period, committee has successfully completed 7 batches of the Certificate Course on Forex and Treasury Management, wherein total 46 Members of ICAI has enrolled in the course curriculum of the Certificate course on Forex and Treasury Management.
- The Committee has declared the result of an evaluation test held on 24th and 25th November 2018 of past batches of Forex and Treasury Management Certificate Course on 21st January, 2019. The total number of participants appeared for the examination were 69 out of which 63 members have qualified the examination.
- The Committee had successfully organized Certificate Course on Forex and Treasury Management in two phases from 12th -17th March, 2018 and 11th – 16th June, 2018 which was designed for the officials of Hindustan Petroleum Corporation Ltd, Pune, as per the MOU signed with HPCL, Pune wherein 18 members enrolled and qualified the examinations.
- The Committee is increasingly playing a pro-active role in conducting various Seminars, Workshop and Webcast for the professional enhancement of members.
- The second edition of the background material on certificate course on Forex and Treasury Management i.e. "Theory and Practice of Forex and Treasury Management" (Module I, II & III) was released at ICAI Convocation 2019 which was held on 09.02.2019 at, Delhi.

5.24 Ind AS Implementation Committee

Ind AS Implementation Committee was constituted in the year 2011 with the objective to provide guidance for smooth implementation of Ind AS in the country. During the council year 2017-18, the said Committee was reconstituted as Ind AS Implementation Group. However, the purpose and initiatives of the group remained the same. In May 2019, the Council of ICAI reconsidered the status of this Group and decided to reconstitute it as Ind AS Implementation Committee.

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) assumed a crucial role for spurring the need for globally accepted accounting standards and the implementation of the IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS). ICAI strived harder than ever to stress on the implementation of these standards and its adoption throughout the nation bearing in mind the crux and the rationale behind formulation of these standards to ensure they prevail on implementation. On this day, we stand, admiring the progress our nation has made towards such shift as the phaseal adoption of Ind AS has been completed in respect of specified class of companies. Arduous efforts have been made by the Ind AS Implementation Committee for promulgating the need and importance of adoption of Ind AS. It has strived with great determination for the no hiccup transition to Ind AS from the previously used GAAP. Numerous initiatives have undertaken by the Ind AS Implementation Committee to provide guidance to the members and other stakeholders on the notified Ind AS.

In order to ensure implementation of Ind AS in the same spirit in which these have been formulated and to provide appropriate guidance to the members and other stakeholders, the Ind AS Implementation Committee issues Educational Materials on Ind AS, which contains summary of the respective Ind AS and the Frequently Asked Questions (FAQ) covering the issues, which are being faced or are expected to be encountered frequently while implementing the Standard. During the period, six (6) Educational Materials on seven (7) Ind AS have been issued. So far, fifteen (15) Educational Materials on sixteen (16) Ind AS have been issued by the Committee. The Committee is working to bring out Educational Materials on all the Ind AS.

In addition to the above, the Committee has revised its publication titled "Indian Accounting Standards (Ind AS): An Overview (Revised 2019)", which is the fourth edition of the publication containing an overview of various aspects related to IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS) such as roadmap for the applicability of Ind AS, carve-outs from IFRS/IAS, changes in financial reporting under Ind AS compared to financial reporting under accounting standards, summary of all the Ind AS etc. It captures all the recent amendments to Ind AS notified by the Ministry of Corporate Affairs in March 2019 specifically issuance of new leases standard (Ind AS 116) and other consequential amendments thereto.

As the implementation of Ind AS began in the country, a number of issues were being raised by the members, preparers and other stakeholders with regard to applicability/implementation of Ind AS. For addressing transition related queries in a timely and speedy manner, an Ind AS Technical Facilitation Group (ITFG) (formerly known as Ind AS Transition Facilitation Group) was constituted in the year 2016 which issues clarification bulletins addressing implementation issues from time to time. The Group comprises of experts from accountancy firms, industry representatives and other eminent

professionals. During the period, six (6) ITFG Clarification Bulletins have been issued. Till date, the Group has brought out clarifications on 148 issues through its 20 clarification bulletins.

Furthermore, for ease of reference of members, a publication titled 'Compendium of ITFG Clarification bulletins (including clarifications issued till December 2018)' has been brought out which contains a topic-wise compilation of all the issues clarified in the ITFG Clarifications Bulletins at one place.

"Support-desk for Implementation of Ind AS" has also been launched in order to address the difficulties being faced by the members at as early as possible wherein the members can submit their queries, questions, suggestions online by clicking on a link.

This Committee is also taking adequate steps to enhance the knowledge of the members and other stakeholders for proper implementation of Ind AS by conducting workshops, seminars and Certificate Course.

The Committee organises 12-days Certificate Course on Ind AS throughout the country and abroad to impart knowledge about Ind AS. Comprehensive session plan of the course has been designed with a view to make members competent in field of Ind AS. During the period, 29 batches of Ind AS Certificate course have been conducted wherein around 1100 members have been trained. So far, around 9790 members have been successfully trained in the Certificate Course on Ind AS across various locations throughout the country and abroad.

The Committee also organises One/Two days Awareness Programme/ Workshop/Outreach Programme on Ind AS at various locations across the country. In these awareness programmes, training on the basic Standards which form the premise for preparation and presentation of financial statements under Ind AS, difference between Ind AS and existing AS are also specifically covered in order to educate the members and stakeholders about how accounting under Ind AS would be different from existing AS.

In addition to above, the Committee also organises in-house training programmes on Ind AS for officials/employees of various regulators, organisations and corporate houses. During the period, various training programmes on Ind AS have been organised for Allahabad Bank and Aditya Birla Finance Limited.

In addition to above initiatives, the Committee organises webcasts on Ind AS from time-to-time to create awareness on Ind AS. Recently 2 webcasts on the new leases standard Ind AS 116, *Leases* was organised by the Committee and the same are readily available at the icaitv.com.

The Committee is making every possible effort to create knowledge and awareness about Ind AS and to make this transition smooth.

5.25 Audit Committee

The Constitution of Audit Committee of the Institute is governed by the Council. Audit Committee reviews the reporting process and disclosure of financial information of the Institute to ensure that the financial statements are true and fair. It ensures the independence and integrity while appointing auditors at various units of the Institute. The Audit Committee operates through five Regional Audit Committees located at each of its Regional Councils.

5.26 Digital Transformation & Process Re-engineering Group (DT&PRG)

(I) ICAI Mobile App ICAI

Now and ICAI Social Media Platforms have been instrumental in Popularization of various ICAI's events and Key Achievements and Initiatives on no cost basis amongst students, members and other.

ICAI Mobile App ICAI Now and ICAI Social Media Platforms have been instrumental in Popularization of various ICAI's events and Key Achievements and Initiatives on no cost basis amongst students, members and other stakeholders of ICAI.

The app has been downloaded by 5 lakhs of Users. It has been rated as 4.2/5 on App Stores and listed in top 100 Free Education Category.

(II) ICAI Social Networking

ICAI Social Media accounts have been configured on Facebook, Twitter, LinkedIn and YouTube.

ICAI Social Media Networking presence is continuously increasing and total number of Followers has crossed 5,89,000+ users (Facebook 90,000+, Twitter 81,000+, LinkedIn 3,73,000+ and YouTube 45,000+)

5.27 Quality Review Board (QRB)

The Quality Review Board was constituted on 28th June, 2007 by the Central Government pursuant to the powers vested in it under Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 to perform the following functions:

- To make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of ICAI;
- To review the quality of services provided by the members of ICAI including audit services; and
- To guide the members ICAI to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.

One of the functions of the Council under clause (o) of sub-section (2) of Section 15 of the Chartered Accountants Act, 1949 is to consider the recommendations of the Quality Review Board made by it with regard to the quality of services provided by the members of ICAI. The aforesaid clause (o) also provides that the details of action taken on such recommendations shall be published in its Annual Report. In accordance with the aforesaid provisions, during the period under Report, the Council received 1 reference under Section 28B(a) of the Chartered Accountants Act, 1949 from the Quality Review Board with regard to the quality of services provided by the members. The same was considered by the Council at its meeting held during the financial year April 2017 to March, 2018. The following is the details of action taken:

- Number of references referred to the Director (Discipline) for making further investigation under the disciplinary mechanism of ICAI-1.
- Number of references where comments of the Technical Reviewer were decided to be issued as an Advisory to the members / firms – NIL.
- Number of references which were decided to be closed – Nil.
- Number of references pending for consideration of the Council – Nil

5.28 Management Committee

Management Committee, constituted in 2015 as non-standing Committee of the Council, is mandated to consider matters pertaining to formation of Branches, setting up of Chapters abroad, MoUs/ MRAs with national/ international bodies, appointment of central auditors of ICAI, annual accounts of the Institute, matters referred by the Central Government and other regulatory bodies, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949, Rules and Regulations framed thereunder, Regional Councils and Branches matters, Members / CA firms / LLPs / mergers / demergers / networking related matters and proposals received from other committees / departments of the Institute having administrative and policy implications and making its recommendations to the Council wherever required.

5.29 Valuation Standards Board (VSB)

The Valuation Standards Board has been constituted to focus at issuing Valuation Standards from ICAI. The Board also focuses on providing Interpretations, Guidance and Technical Materials from time to time for implementation of the Standards.

Achievements and Initiatives

(I) ICAI Valuation Standards, 2018 were issued, to be followed by Chartered Accountants in their Valuation assignments.

Recognising the need to have the consistent, uniform and transparent valuation approach and harmonise the diverse practices in use in India, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) at its 375th meeting has issued the Valuation Standards. These valuation standards are the first set of standards on valuation in India.

The Standards lay down a framework to ensure uniformity in approach and quality of valuation. The following Valuation Standards have been issued by ICAI:

- ICAI Valuation Standard 101 – Definitions
- ICAI Valuation Standard 102 - Valuation Bases
- ICAI Valuation Standard 103 - Valuation Approaches and Methods
- ICAI Valuation Standard 201 - Scope of Work, Analyses and Evaluation
- ICAI Valuation Standard 202 - Reporting and Documentation
- ICAI Valuation Standard 301 - Business Valuation

- ICAI Valuation Standard 302 - Intangible Assets
- ICAI Valuation Standard 303 - Financial Instruments

These standards have to be applied by reading it together with the Preface to the ICAI Valuation Standards and Framework for the Preparation of Valuation Report in accordance with the ICAI Valuation Standards. The Valuation set up concepts, principles and procedures which are generally accepted internationally having regard to legal framework and practices prevalent in India. These standards are at present recommendatory and are proposed to be made mandatory.

(II) Formation of ICAI Registered Valuers Organisation

The Institute of Chartered Accountants of India has formed ICAI Registered Valuers Organisation which is a Section 8 private Company to enroll and regulate registered valuers or valuer member in accordance with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, and functions incidental thereto. ICAI RVO is registered for Securities or Financial Assets Class.

(III) Representation submitted to Ministry of Corporate Affairs

For the year 2018-2019 the following Representation/ Suggestions were submitted to MCA/IBBI:

- Regarding nomination on “Committee to advise on Valuation Standards” and to recognize ICAI Valuation Standards as National Standards.
- Issues with regard to Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.
- Comments on the Draft Report of the Committee to advise on Valuation matters

(IV) Launch of ICAI RVO Learning Management System

ICAI RVO has launched its Learning Management System which is an e-learning platform which delivers the concepts of the syllabus prescribed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India for the Asset Class- “Securities or Financial assets” in the form of study material and supplemented by mock test in Multiple Choice Questions format. This Learning Management System facilitates the members in preparing for IBBI Valuer Examination.

(V) Study Modules for Educational Course by ICAI RVO:

Four Study Modules for Educational Course have been prepared to help the members in understanding the subject better:

- Module 1 covers in detail Overview and Concepts of Valuation
- Module 2 covers in detail Valuation Approaches and Methods
- Module 3 covers Judicial Pronouncements
- Module 4 covers Relevant laws & Regulations as per the Syllabus

(VI) Series of Publication- Valuation: Professionals' Insight

The Valuation Standards Board has published “Valuation: Professionals' Insight- Series- 1” Series- 2 and Series- 3”. This publication series has now cumulative 61 articles. This publication provides practical insights and case studies on various aspects of Valuation which would be highly useful to valuers, users of valuation reports and learners of valuation.

(VII) Outreach programme of ICAI Valuation Standards with SAFA countries

The ICAI is engaged with SAFA countries, for use of ICAI Valuation as there are no Valuation Standards in these Countries. The Board is beginning the engagement by conducting education programs on valuation in these countries and encouraging use of ICAI Valuation Standards.

(VIII) Meeting of the Committee to advise on Valuation Matters constituted by Ministry of Corporate Affairs under Rule 19 of Companies (Registered Valuers and Valuation Rules), 2017.

ICAI is a member of the Committee to advise on valuation matters under Rule 19 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017. The Committee has been formed to make recommendations to the Central Government on formulation and laying down of valuation standards and policies for compliance by companies and registered valuers. The Advisory Committee has submitted its report to the Ministry of Corporate Affairs which stated that India does not have Valuation Standards and the ICAI Valuation Standards do not have a track record. Therefore, ICAI has submitted its dissent note alongwith the reasons.

(IX) Distinguishing Features of ICAI Valuation Standards vis-à-vis IVSC.

The Ministry of Corporate Affairs had requested ICAI to submit Distinguishing Features of ICAI Valuation Standards 2018 vis-à-vis International Valuation Standards issued by IVSC. In this regard, a detailed document enumerating the distinguishing features of ICAI Valuation Standards 2018 vis-à-vis International Valuation Standards issued by IVSC has been submitted to Ministry of Corporate Affairs.

(X) Awareness programmes on ICAI Valuation Standards 2018 to be conducted by Regional Councils and Branches Webcast

- The Valuation Standards Board is regularly conducting half a day awareness programmes on ICAI Valuation Standards 2018 jointly with the Regional Councils and Branches.
- Valuation Standards Board jointly with ICAI RVO conducted a webcast on “Valuation Standards & Code of Ethics for Registered Valuer” on 18th April, 2019. The purpose of the webcast was to provide knowledge to the large number of audience regarding valuation standards to be followed and the code of ethics to be complied while taking up a specific valuation assignment. The webcast was addressed by Dr. Navrang Saini, Whole time member, Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI). The webcast was viewed by more than 4000 members.

(XI) Amendment in the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017

ICAI regularly submits representations to the Ministry of Corporate Affairs (MCA). On November 13, 2018 the Ministry of Corporate Affairs has made amendments to the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 vide Fourth Amendment Rules. One of the major amendment is that, now a Chartered Accountant having three years of experience who is not a graduate is eligible to become Registered Valuer. Prior to amendment a Chartered Accountant was to be a graduate to become Registered Valuer.

(XII) Publication- Frequently Asked Questions on Valuation

The Valuation Standards Board jointly with ICAI Registered Valuers Organisation has published “Frequently Asked Questions on Valuation” in February, 2019. This publication comprehensively covers questions on Valuation of Financial assets or Securities. The publication has been designed in a question and answer format to assist our members and other stakeholders to enable them to have conceptual clarity on the various Valuation aspects.

(XIII) Technical Guide on Valuation

The Valuation Standards Board has revised and updated the Publication, “Technical Guide on Valuation”. The publication has been designed in a question and answer format to assist our members and other stakeholders to enable them to have conceptual clarity on the various Valuation aspects. This publication comprehensively covers questions that are being asked while undertaking Valuation of Financial assets or Securities.

5.30 Taxation Audits Quality Review Board

In its commitment to serve the nation and in order to improve the reporting of compliances under various taxation laws (both Direct as well as Indirect), the Taxation Audits Quality Review Board for the first time has been constituted by the Council Year in the year 2018-19. It is envisaged that the reviews carried out by the Board, will ensure that the members will exercise greater diligence while certifying the various reports prescribed under direct and indirect taxation and in the long-run would improve the overall reporting and certification done by them.

(I) Selection of Tax Audit Reports: Scope widened

With an objective to widen the scope of review, the Board has modified its terms of reference in the current Council Year to encompass within itself the word ‘persons’ in place of the word ‘entities’ as stated earlier. Accordingly, for the Council Year 2019-20, the Board has decided to review the tax audit reports of top 100 individuals, firms and LLPs each having turnover of more than Rs. 100 crores and top 100 trusts having turnover of more than Rs. 10 crores. In this regard, a letter has been sent to Member (IT&C), CBDT requesting to assist ICAI to provide the Tax Audit Reports along with other attachments as uploaded by the tax auditor in respect of the above mentioned assesseees.

(II) Status of Review of Tax Audit Reports selected during the Council Year 2018-19:

The Board has selected 100 companies during the Council Year 2018-19 for review of their tax audit reports pertaining to Assessment Year 2017-18 on suo motto basis. In this regard, 95 tax audit reports have been received from the tax auditors. Preliminary Review of these reports has been completed by the Technical Reviewers empanelled with the Board. Out of these, 30 preliminary review reports have been assigned to Taxation Audits Quality Review Groups constituted under the convenorship of various Board members for undertaking secondary review of the reports. In respect of the remaining 5 tax audit reports, a letter has been sent to Chairman, CBDT requesting to assist ICAI in providing the tax audit reports of these enterprises so that a detailed review may be undertaken by the Board.

(III) Revision of Publication “ Issues on Tax Audit”

The Board has decided to revise the Publication “ Issues on Tax Audit” as issued by the Direct Taxes Committee of ICAI in the year 2000 and last revised in 2003 to update and guide the members in respect of tax audit reporting requirements incorporating the developments which have taken place in past few years.

5.31 Committee on Insolvency & Bankruptcy Code

This year a new Committee has been constituted Committee on Insolvency & Bankruptcy Code to give specific focus on Insolvency and Bankruptcy Laws. It is an emerging area and it has created a new professional opportunity for the members. This Committee aims to bring in awareness about this new area of practice in the Insolvency Resolution sphere to the members at large and facilitates in educating the members on the practical aspects and procedures of the Law.

(I) Publication on ‘Frequently Asked Questions on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - Revised July, 2019 Edition’:

- The Committee has released the publication ‘Frequently Asked Questions on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - Revised July, 2019 Edition’ incorporating the amendments that have taken place in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

(II) Update on Insolvency & Bankruptcy Code:

- Committee on Insolvency & Bankruptcy Code of ICAI has brought out Update on Insolvency and Bankruptcy Laws for the benefit of members. These Updates which will be brought out on a regular basis will provide Case Updates, News Update as well as give information on the initiatives of the Committee.

(III) Programmes / Workshops organized:

- One day programme was organized on Insolvency and Bankruptcy Code at Nagpur in May, 2019.
- Awareness Programme was conducted on IBC and IBBI Limited Insolvency Examination at Ghaziabad, in June 2019.
- Programmes conducted jointly with Indian Institute of Corporate Affairs under Ministry of Corporate Affairs on Graduate Insolvency Programme for Young Members, as recognised by Insolvency and Bankruptcy Board of India at Jaipur, Mumbai and Noida in April- May, 2019.

(IV) Webcast

- The Committee conducted a Live Webcast on ‘Insolvency : An Emerging Profession with Multifold Opportunities’ in April, 2019.
- Conducted Live Webcast on ‘Graduate Insolvency Programme for Young Members’ in May, 2019, which was addressed by Dr. M. S. Sahoo Chairperson, Insolvency and Bankruptcy Board of India and senior official from Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Ministry of Corporate Affairs.

5.32 Women Members Empowerment Group

Women Members Empowerment group constituted by the Council in the year 2019 to augment the move to recognize the presence of women members in the profession and take initiatives for making them as mainstream performers at all levels; from corporate leadership to academics to practice.

The Group performed the following important activities:

- Women Portal (<https://womenportal.icai.org/>) provides women members a medium through which they can post their requirements and can explore flexi working options available for them based on region/branch. It also aims to provide a common platform to women members to update their knowledge and share their views and concerns.

- To inspire women members to set and achieve higher goals, group has invited success stories from women members and uploaded on Women portal.
- To recognize the presence of women members, group has uploaded details of women members associated with ICAI.
- Group has planned uploading the inspirational videos of eminent women member for inspiring the aspirants and women professionals to be successful in their endeavors, so far pilot video has been uploaded on Motivational video of CA. R M Vishakha, MD & CEO, IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.
- The Group has organized 10 Women Members Empowerment Programmes across India along with the SETU programme, i.e. bridging gap between women Members and practicing CA firms at Gandhinagar, Bhubaneswar, Indore, Bhopal, Chennai, Salem, etc. Over 1100 participants have attended the programmes. The programme structures were formulated in such a manner so as to empower women members in both social as well as professional field.

6. Committee for Export of CA Services & WTO

During the year, Accountancy and Finance Services Sector has been identified as one of the 12 Champion Sectors by Government of India, in order to promote the Chartered Accountancy Services exports in India, and to achieve the mandate of Government of India. During the Council Year 2018-19 Council had newly constituted non-standing Committee for Export of CA Services and WTO to work on the initiatives of Champion Sector and its allied areas.

(I) Joining hands with Government of India to enhance export potential for Accounting and Finance Sector (Champion Sector)

- *Proposal for Champion Sector:* As the Services sector contributes significantly to India's GDP, exports and job creation, increased productivity and competitiveness of the Champion Services Sectors will further boost exports of various services from India, ICAI is working upon various initiatives of Champion Sector under the guidance with Ministry of Corporate Affairs and Ministry of Commerce and Industry. ICAI through CESWTO has submitted its proposal on Action Plan of Champion Sector.



- *GST Account Assistant:* In order to disseminate and promote employability of graduates in India in the areas, this Committee alongwith ICAI ARF, as an initiative of Champion Sector under the guidance of Ministry of Corporate Affairs worked on GST Account Assistant Scheme for Indian graduates. The Screening Committee for Champion Sector had approved amount of Rs. 975 crores for GST Account Assistant Scheme as proposed by ICAI, through ICAI ARF. This scheme would facilitate developing second tier of GST Assistant for

supporting Indian Industry in prompt compliance of GST. The scheme will pave way forward for the graduates in India for their employment generation.

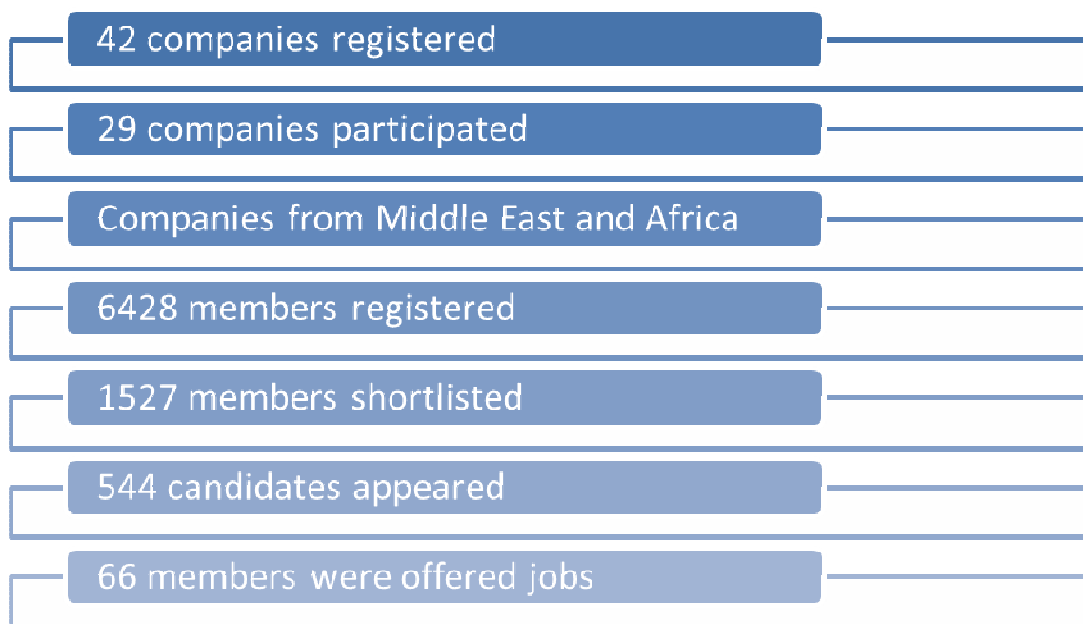
- *MoU signed with Invest India:* Coinciding with the Platinum Jubilee Celebration, ICAI under the aegis of the Committee for Export of CA Services & WTO of ICAI signed an Memorandum of Understanding (MoU) with the Invest India on February, 2019. The objective of the MoU is to collaborate and promote foreign investment in India and Indian investments outside India. The MoU also intends to provide necessary guidance and advice to the potential inbound and outbound investors and to promote the facilitate India as an investment friendly destination.
- *Knowledge Partner:* As a partner in Nation building, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through CESWTO had participated as a “Knowledge partner” at the Global Exhibition on Services (GES) from 15th to 18th May 2018 and had been allotted a Pavillion to showcase ICAI role in ‘Partner in Nation Building’ at the Exhibition. Hon’ble President of India inaugurated the Global Services Exhibition on 15th May 2018 to be followed by launch of 12 Champion Sectors including Accounting and Finance Services Thereafter, the Hon’ble President of India along with CA. Suresh Prabhu also visited the ICAI pavilion. CA. Suresh Prabhu along with Special Secretary Commerce and Shri Sudhanshu Pandey, Joint Secretary made a detailed visit to ICAI pavilion during the day.

(II) Meetings

- Inter-ministerial meeting in connection with 2nd meeting of Joint Administration Committee under expanded India-Chile Preferential Trade Agreement.
- WTO Policy Review Board for Trade & Services wherein request was made for joint collaboration & MRA for promoting Export of CA Services.
- Draft note for Expenditure Finance Committee (EFC) on Champion Services Sector Scheme (CSSS).
- Inter-ministerial stakeholders consultations under India-Peru negotiations.
- Movement of Natural Persons (MoNP) with respect to Trade in Services set up for implementing the provisions of the Chapter on Trade in Services agreed under India-Japan CEPA.
- Issues for 4th Joint Sub-Commission on Trade meeting between India & Vietnam
- India- China 4th meeting on Joint Working Group on Trade in Services
- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Stakeholder Consultations on Trade in Services under RCEP agreement was held on 22nd April, 2019 wherein ICAI expressed its interest in going forward for technical collaborations for capacity building in the mutual interest areas with the 15 countries of RCEP agreement which would be followed by mutual recognition agreements in future.

(III) Overseas Campus Placement of Indian Chartered Accountants abroad in co-ordination with ICAI Chapters Overseas

- ICAI in line with its mission to partner with the Government of India champion sector initiative for increased export of accounting services, organised Overseas Campus Placement drive between 14th -16th September 2018 under the aegis of Committee for Export of CA Services & WTO, Committee for Members in Industry & Business and International Affairs Committees. While these were conducted through videoconferencing mode at Jaipur, Kolkata, Hyderabad and Bangalore; both physical interactions and videoconferencing were made available at Mumbai, Delhi and Chennai centres.
- Being the maiden initiative; this drive had many a positives; despite slump and slowdown in Middle East, with limited efforts ICAI had drawn interest of 42 companies and that too only Middle East with one company from Africa.



(IV) Promoting Foreign Language amongst members

The Institute has a large focus on export of Chartered Accountancy services wherein more than twenty thousand of its members are based overseas. Moreover, with new employment being generated in overseas, the need has been felt that ICAI trains its members and students in language skills pertaining to French, German, Spanish, Japanese, Arabic and Chinese. The same is being mandated by Ministry of Commerce and Industry in its Action Plan for Champion Sector.

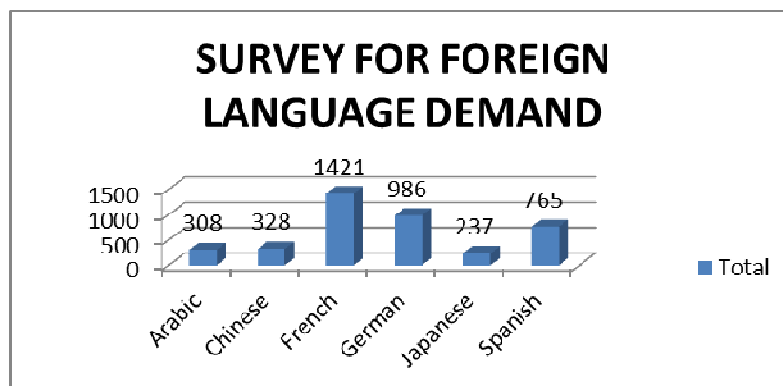
- Spanish Language Learning Courses through Instituto Cervantes, Spanish Embassy Cultural Centre - 9 batches ranging from 45-50 candidates completed & 5 batches in Delhi and 4 batches in Mumbai
- German Language Learning Courses through Goethe Institut Max Mueller Bhavan (official German culture Institute and promotes learning of German language in India) - First batch of German course started in January, 2019
- French Language Learning Course through Alliance Française De Delhi - First batch of French Course to be started in February, 2019
- Awareness Session on Arabic Language: One day session on Arabic Language has been hosted by Overseas office of ICAI in Dubai Knowledge Park in association with Eton Institute in Dubai which was successfully attended by 100 members in order to assess the demand of Arabic language in Dubai on 14th May, 2019. Japanese, Arabic and Chinese language learning course are under active consideration

(V) Survey for ICAI members abroad for boosting export of accounting services from India

- 214 members responded
- Respondents were from Middle East, UK, Canada, Ireland, Asia, Australia and African regions.
- Survey was intended to bridge the expectation gap and to understand the issues of members abroad.
- Their suggestions and inputs were called to assist ICAI in promoting brand Indian CA globally and to address various barriers/limitations which the Indian CAs face overseas.

(VI) Survey for seeking preference for foreign language course from ICAI Members and Students

The Committee has launched the Online Survey for assessing the demand for foreign language. Till date the Committee has received 4045 responses as per detail below :-



(VII) Services to Members

- Launch of Online good standing services - Application and issuance of good standing certificate made online w.e.f. June 2018 and Members can get the certificate in a week's time.
- This initiative is a landmark initiative for our members abroad and for the members aspiring to go abroad. The said e-service would be available for members to facilitate them for easy placements, qualification upgradation abroad.

(VIII) International Capacity building

- Training on Bhutanese Accounting Standards/IFRS organized by Department of Revenue & Customs, Ministry of Finance, Bhutan with the technical support of ICAI from 7th to 9th May, 2019
- A delegation of 21 senior provident fund officers from Nepal visited ICAI on 11th April, 2018
- First Live Webcast on 'Investing Opportunity in India – Professional Opportunities ahead' on 30th January, 2019, New Delhi by Shri Deepak Bagla, MD & CEO, Invest India.
- Webcast on "Opportunities, Modalities & Incentives for Export of Services – Especially for Chartered Accountants" on 19th June, 2019 by CA. Hans Raj Chugh, Central Council Member, ICAI.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Committee on Management Accounting

The Committee on management Accounting provides advanced Knowledge and specialized training on various areas of management Accountancy, including finance and other allied subjects. A specialized Diploma Course on Management and Business Finance has been developed by the Committee. For launching this Post Qualification Course on Management & Business Finance, the Committee is working on the course curriculum and syllabus of the same. The Committee is collaborating with a reputed Business School for jointly conducting one week Residential Programme which will give practical insights to the members on management concepts, leadership skills and decision making for carrying out their management functions more efficiently and effectively.

Initiatives for Members

- Course curriculum and syllabus of the Post qualification course on Management and Business Finance PQC (MBF) which had been notified in the government gazette by Ministry of Corporate Affairs last year, is under preparation. The Committee has conducted meetings with various management institutes to develop one week's residential programme of the Diploma course.
- The Committee conducted one residential programmes for the participants of Certificate Course on Master in Business Finance during the month of Nov-Dec 2018.
- The Committee conducted examination of Certificate Course on Master in Business Finance for the members during the month of May-June, 2018.

Industry/Corporate Initiatives/Programmes

- The Committee organized a One Day Programme on Financial Reporting & GST on 15th Dec, 2018 at Indore branch which was hosted by Indore branch of CIRC of ICAI.

7.2 Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services (CME&PS)

The Committee is to maintain a mutually advantageous live connect between ICAI, members in Entrepreneurship and members in Public Services. Committee also takes up projects which are mutually beneficial. Activities aimed at generating additional opportunities for young Chartered Accountants are also initiated.

(I) Regional Meet of ICAI Members in Public Service in Delhi on May 25, 2018

The Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service organized a Regional Meet of ICAI Members in Public Service at New Delhi on 25th May 2018. The Regional meet was attended amongst other CA Members in Public Service by CA. Anil R. Dave, Hon'ble Retired Judge Supreme Court of India, CA. Vibhu Bakhru, Sitting Judge, Delhi High Court, CA. Deepak Kumar Kedia, Additional Director, Enforcement Directorate, Delhi, CA. Rakesh Rathi, D.I.G. of Police, Central Bureau of Investigation, Delhi, CA. Upender Gupta, IRS, Commissioner (GST) Department of Revenue, Ministry of Finance.

During the Regional meet, ICAI launched a Mobile Application to provide a easy connect of CA Members in Public Service with ICAI and to facilitate updations of their records easily. Important discussions on measures to improve the competencies and skill sets of Professional Accountants were discussed. Further, deliberations on how to meet the expectation gap of the stakeholders and improve the public image of ICAI was also discussed. The Members also discussed the changing needs of the profession arising out of the change in the digital technologies. Further, during the regional meet ICAI felicitated CA. Upendra Gupta, Commissioner, GST for receiving Prime Ministers award for Excellence in Public Administration presented to "Team GST, Department of Revenue, Government of India".

(II) Residential Meet of ICAI Members in Public Service at Tirupati on January 25-27, 2019

The Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service organized a Residential meet of ICAI Members in Public Service from 25th-27th January 2019 under the Chairmanship and Vice-Chairmanship at Tirupati.

The Residential Meet was inaugurated and graced by CA Prafulla Premsukh Chhajed, Vice-President, ICAI. The Meet was attended by Members in Public Service namely CA. Arun Kumar Gujarathi, Hon'ble Ex- Speaker of Maharashtra Legislative Council, CA. Bhanudas K. Murkute, Hon'ble Ex MLA, Maharashtra legislative Council, CA. Deepak Kedia, Additional Director, Enforcement Directorate, CA. Manish Borad, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal, CA. Manoj Kumar Aggarwal, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal, CA. Amit Mittal, IRS, Joint Commissioner of Income Tax CA. Mahesh Kumar, IRS Commissioner of Income Tax (Advance Pricing Agreement) CA. Sarika Jain, IRS Asst CIT, Mumbai CA. Sumit Kumar Agrawal Asst. Commissioner, Central GST & Central Excise, Division-II, Raipur CA. Ajay Agrawal, IRS Raipur Audit Commissioner, Raipur Chhattisgarh, CA Satish Kumar Garg, Principal Director of Audit (Railways), CA Saurabh Deshmukh Director, Ministry of Communications CA. Umesh Kumar Agarwal Joint Commissioner of Income Tax CA. Neha Jain Assistant Director (Cost) Ministry of Commerce and Industry New Delhi CA. Amit Arora, Journalist & Anchor, Doordarshan.

During the Residential Meet, the Committee for Members in Public Service and Entrepreneurship launched a separate website of Committee so as to strengthen the connect between ICAI and Members effectively.

The Meet was graced by Special Address by CA. Arun Kumar Gujarathi, Hon'ble Ex- Speaker of Maharashtra Legislative Council on the topic "How to Enhance Public Trust and Confidence" in which he dwelled upon the issue of the importance of building public trust so as to enhance the credibility of Chartered Accountant Profession and remain of value and utility to the profession. Further, CA Deepak Kedia, Additional Director, Enforcement Directorate addressed on the topic "Anti Money laundering Act- Role of Chartered Accountants" wherein he dwelled upon the issue of enhancing the understanding of Chartered Accountants on the issue of Anti Money laundering Act so that they can be of value addition to the society. Several other issues on the recent developments impacting the accountancy profession and suggestions for communicating the positive strengths of CA profession amongst the Government, Regulators, media, Students and other stakeholders was also discussed. The Members in Public Service also dwelled upon the current issues on recent developments in Electronic Systems, E-Compliances and more effectively on the system as to how to improve the disciplinary mechanism so as to enhance the public confidence in the ICAI regulatory system.

(III) Webcast

Launch of Website for Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service and mobile application for Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service to provide an elective interface of ICAI with members in Public Service and enable them to update their profile with ICAI.

7.3 Legal Advisory Wing

The following important activities were undertaken by the Legal Wing during the period:

- Total number of cases disposed of by the various High Courts under Section 21(6) of the Chartered Accountants Act, 1949 during the period from 1.4.2018 to 31.3.2019 are five.
- Rendering effective legal assistance in the form of legal opinions, studies and reports, as required from time to time by the Council /Executive Committee / various Non Standing Committees and departments of the Institute.
- Providing appropriate legal advice on diverse range of substantive and procedural questions of law arising in administrative functioning of the Institute to firmly secure the interest of ICAI, as required by the operational departments
- Supervising and overseeing the review, negotiations, drafting and vetting of contracts, tender documents and other legal documents, as required by the operational departments and various committees of ICAI.
- Serving on various Standing and non-standing Committees, Study groups and task force, as required, to take care of legal niceties in framing of policies.
- Advising in the matters of taking recourse to legal remedies whenever necessary and assisting the operational departments and committees in preparing reply to legal notices received.

7.4 Infrastructure Development Committee (IDC)

In the year 2014, Infrastructure Development Committee was formed as a non-standing Committee of the Institute. This Committee formulated Infrastructure policy for Branches and Regional Councils/offices. Since 2014, the ICAI has a robust infrastructure policy in place, which ensures financial prudence and discipline. The policy defines what all facilities can be provided, composition of local Infrastructure Committees, policy and procedure for acquisition of land/building, indicative area, permissible grant from Head Office, powers and delegation vested with various authorities within the Institute. Since the policy itself defines the financial powers, all infrastructure projects from the year 2014 onwards are being approved by IDC, instead of the Finance Committee. Since formulation of Infrastructure policy, the ICAI has initiated following projects:

Purchase of new Infrastructure	Construction proposals approved	Gifted Property
Kannur, Jalandhar, Jabalpur, Goa, Gurugram, Moradabad, Pali, Agra, Gorakhpur, Karnal, Kishangarh, Latur, Patiala, Ujjan and Ratlam	Ajmer, Surat, Hubli, Bhopal, Rajamahendravaram, Centre of Excellence Jaipur, Bathinda, Bareilly, Jodhpur, Raipur, Kannur, Ghaziabad, Goa, Moradabad, Raipur and Rohini	Bengaluru Gifted Property

Out of total 164 Branches set up by the ICAI so far, 99 branches are having their own premises which include 14 Branches (presently functioning from Rented Premises) who have procured land on which construction is either commenced or construction is under-way. 16 Branches (functioning from own premises) have procured land where either construction has started or construction is under-way. 51 Branches do not own either land or building. The Region-wise break-up as on 15th July, 2019 is as under:

S.No	Particulars	Remarks					Total
		WIRC	SIRC	EIRC	CIRC	NIRC	
1	Total Nos. of Branches	35	45	13	47	24	164
2	Nos. of Branches having own premises	21	33	6	29	10	99
3	Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started (functioning from rented premises)	1	1	0	7	5	14
4	Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started besides the own premises (functioning from own premises)	5	2	1	7	1	16
5	Total nos. of Branches having neither land or building	13	11	7	11	9	51

7.5 International Affairs Committee

(I) Initiatives of IAC for recognition of professional opportunities abroad

In order to spread its wings internationally, ICAI has been entering into qualification reciprocity agreements with accounting bodies globally to recognize qualification of members at either ends. These agreements foster working relations between the two accounting institutes. During the year qualification reciprocity agreements were signed with different accounting bodies as per details below:-

- The MRA between ICAI & SAICA was formally signed on June 04, 2018 in Johannesburg by CA. Naveen N D Gupta, the then President, ICAI & Ms. Fanisa Lamola, the then CEO, SAICA. CA. Prafulla Chhajed, the then Vice President, ICAI and Dr. K J Srinivasa Hon'ble Consul General, Johannesburg, South Africa were also present at the event. The MRA would facilitate mutual recognition of each other's qualification and admit the members in good standing by prescribing a bridging mechanism between the two Institutes.
- The MoU between ICAI & CPA Canada has been signed on November 17, 2018 in Toronto, Canada. This MoU between ICAI & CPA Canada would facilitate mobility of members across the borders and further strengthen the ties between India and Canada.
- MRA with CPA Ireland was signed on October 05, 2018. This agreement would allow members of ICAI and CPA Ireland to recognize each other's qualification.
- The Union Cabinet chaired by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi on 7th March 2019 has approved the Renewal of the MoU between the ICAI and & Institute of Chartered Accountants in England & Wales ICAEW. The MoU would provide for mutual Recognition and Examination arrangements for the members of the two largest Institutes of the world. The date for signing of the MoU is being worked upon and is expected to be signed soon.

(II) Globalizing ICAI's Brand Equity

ICAI currently has 34 Chapters abroad that promote Brand CA ahead of similarly placed qualifications and act as a gateway to promote career opportunities for the Indian Chartered Accountants. During the period, 3 ICAI Chapters were inaugurated as per details below:-

- The 32nd Malaysia (Kuala Lumpur) Chapter of ICAI was inaugurated on July 06, 2018.
- The 33rd Japan (Tokyo) Chapter of ICAI was inaugurated on September 18, 2018.
- The 34th Ireland (Dublin) Chapter of ICAI was inaugurated on January 17, 2019.
- ICAI to host the World Congress of Accountants on November 18-21, 2022 in Mumbai, India

(III) India Selected to Host WCOA 2022

World Congress of Accountants (WCOA) is held every four years under the auspices of the International Federation of Accountants (IFAC), the worldwide organization for the accountancy profession and is one of the most prestigious global events of Professional accountants where about 6000 delegates gather and exchange views on accounting & allied areas. ICAI, being a member of IFAC, had bid to host the WCOA 2022 and after rigorous assessment regarding the abilities and experience of the member body; suitability of proposed venue; attractiveness to potential delegates, including site visits of IFAC delegation on June 01-02, 2018 at Delhi & Mumbai respectively, ICAI won the bid to host the WCOA 2022 in Mumbai.

The baton of the 21st World Congress of Accountants (WCOA) was formally handed over to CA. Naveen N D Gupta, the then President, ICAI by Dr. In Ki Joo, President, IFAC at the closing ceremony of the 20th WCOA 2018 held in Sydney. H. E. Shri B. Vanlalvawna, Consul General of India in Sydney was also present to witness the historic event.

(IV) Delegations visiting ICAI

- Mr. Abdulwahid Aboo, former Member of IFAC SMP Committee visited India from 13th to 23rd April 2018 and addressed the members in Delhi, Jaipur, and Mumbai for Capacity Building of SMPs in India. The lectures were coordinated by the Committee of Capacity Building of Members in Practice of ICAI.
- A delegation from IFAC comprising of Ms. Rachel Grimes, the then IFAC President, Mr. Fayezul Choudhury, the then CEO, IFAC, and Dr. Gary Pflugrath, the then Senior Director, IFAC Public Policy & Regulation visited Delhi and Mumbai on June 1 and 2, 2018 respectively for site visits for hosting WCOA 2022 in India. The delegation visited the proposed venues International Exhibition cum convention Centre (IECC) at Delhi and met Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister of Delhi, Mr. Injeti Srinivas, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, and Shri Arjun Ram Meghwal, the then Union Minister State, Ministry of Parliamentary Affairs; and Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

- On June 02, 2018, the delegation visited Dhirubhai Ambani International Convention and Exhibition Centre (DAICEC) {JIO World Centre}, the second probable venue as shortlisted by IFAC in India. Further the delegation met with Shri Vinod Tawde, Hon'ble Minister of Education, Govt. of Maharashtra ; Shri Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director, Reliance Industries Limited (RIL).
- The then IFAC President Ms. Rachel Grimes was the Guest of Honour at the launch of the Platinum Jubilee celebrations of ICAI on July 01, 2018 which was inaugurated at the august hands of Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind ji at Vigyan Bhawan, New Delhi. At the occasion, she formally announced that ICAI has won the bid to host WCOA 2022 in Mumbai, India.
- A delegation from CPA Australia comprising Ms. Deborah Leung, Head of International, Mr. Mark Chau, Regional General Manager Business Development International and Mr. Leslie Leow, Regional Manager – MESA, visited ICAI HO on 30th April 2019 to discuss the renewal of Mutual Reciprocity Agreement (MRA) between ICAI and CPA Australia which is getting expired in September 2019. Both the Institutes also discussed other important areas for mutual collaboration.
- Dr. In Ki Joo, President, IFAC and Mr. Russell Guthrie, CFO & Executive Director, IFAC had visited ICAI to be a part of the ICAI Platinum Jubilee celebrations on July 01, 2019. The celebrations were inaugurated by Shri M. Venkaiah Naidu, Hon'ble Vice President of India. Discussions were also held for successful conduct of WCOA 2022 on November 18-21, 2022 in Mumbai, India.

(V) Conferences/Programs

- ICAI and CPA Australia jointly organized a series of workshops in June 2018, September 2018 and June 2019 in Tier I and Tier II cities for creating awareness about the opportunities in Australia after qualifying CPA Australia exams through MRA route.
- ICAI had organized the Meeting of Public Sector Financial Management Committee (PSFMC) of Confederation of Asian & Pacific Accountants (CAPA) on 10th March 2019 at New Delhi. In conjunction to the CAPA PSFMC Meeting, ICAI also organised the ICAI – CAPA Joint Roundtable Stakeholder's Meeting on Public Sector Financial Management on 11th March 2019 at New Delhi. The discussions were aimed to give a brief overview of Public Sector Financial Management in India and the role of the accountancy profession in improving financial management in the public sector. Representatives from over 15 countries attended the event. Mr. Shashi Kant Sharma, Former Comptroller & Auditor General of India graced the occasion as Chief Guest.
- The Stakeholders' Meeting was attended by more than 60 senior officials from CGA, C&AG, Ministry of Railways, Ministry of Finance, Ministry of Communications, Ministry of Housing and Urban Affairs, World Bank, Asian Development Bank, Department of Posts, and representatives from different Municipal Corporations of Delhi.
- ICAI hosted the two days Meeting of International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) on 12th & 13th April, 2018 at Hotel Taj Mahal Palace, Mumbai to deliberate on the emerging paradigm of accounting standards. International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) (formerly known as National Standard-setters, NSS) is a grouping of national accounting standard-setters from around the world, plus other organisations that have a close involvement in financial reporting issues. IASB Vice-Chair. Ms. Sue Lloyd and IFASS Chair Ms. Liesel Knorr along with the representatives from more than 25 countries and various other accounting bodies across the globe participated in the meeting. Shri Vinod Rai, former Comptroller and Auditor General of India and IFRS Foundation Trustee was the Chief Guest at the occasion.

(VI) Technical Co-operation to under developed countries

- ICAI provided technical assistance to ICAN in further strengthening their examination systems wherein officers from ICAN visited ICAI on 8th April, 2019 to peruse the examination system and discuss various activities related to smooth conduct / flow of Examinations. The delegation was very appreciative of the efforts taken by ICAI in this regard.
- ICAI & CPAPNG are going to sign a bilateral co-operation MoU and in pursuance thereof, ICAI has received a request from CPAPNG to improve their course curriculum for their CPA Module. ICAI has undertaken this evaluation/study to improve their modules. ICAI had also supported CPA PNG in attaining full membership of IFAC.
- *Memorandum of Understanding between ICAI and National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tanzania* - ICAI has signed a Technical Memorandum of Understanding (MoU) with the National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tanzania on 6th September 2018 post the approval of Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi on 18th July 2018. The MoU is to establish Mutual Co-operation in the areas of Member Management, Professional Ethics, Technical Research, Continuing Professional Development, Professional Accountancy Training, Audit Quality Monitoring, Advancement of Accounting Knowledge, Professional and Intellectual Development.

- *Memorandum of Understanding (MoU) between ICAI and the Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK)*- ICAI and the Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK) have signed a Memorandum of Understanding on January 21, 2019 to establish Mutual co-operation and collaboration in the areas of Knowledge Sharing through Joint Research, Quality Support, Capability and Capacity Building, Trainee Accountant Exchange Programmes and conducting Continuous Professional Development Courses, Knowledge Sharing Workshops and Conferences.
- *Memorandum of Understanding between ICAI and Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF)*, Bahrain- ICAI has signed the Memorandum of Understanding (MoU) with the Bahrain Institute of Banking and Finance on 30th July 2018 post the Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved MoU on 18th July 2018 to work together to strengthen the accounting, financial and audit knowledge base within Bahrain. Since Bahrain does not have a local professional accountancy Institute and it is the ICAI which has the collaboration with BIBF, this in turn is likely to build positive impact for Indian Chartered Accountants currently working in Bahraini markets and those intending to move to this country relatively easier.
- *Memorandum of Understanding between ICAI and Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA)*- *Memorandum of Understanding (MoU) with Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA)*-The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 4th July 2018 gave approval for the Memorandum of Understanding (MoU) signed in 2014 and approval for renewal of MoU between the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA) in Saudi Arabia. The MoU promotes mutual co-operation framework in the areas of corporate governance, technical research and advice, quality assurance, forensic accounting, issues for Small and Medium-sized Practices (SMPs), Islamic finance, Continuing Professional Development (CPD) and other subjects of mutual interest related to accountancy profession. The MoU is expected to be signed soon.
- *Union Cabinet approval of MoU with Certified Professional Accountants Afghanistan (CPA Afghanistan)* The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the signing of a MoU between the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and Certified Professional Accountants Afghanistan (CPA Afghanistan) on October 24, 2018. The MoU will establish mutual co-operation framework in the areas of Capacity Building of "Afghanistan Accountancy Board (AAB)", strengthening the IT Capacity and Quality Assurance in Afghanistan. The MoU with CPA Afghanistan is expected to be signed soon.

(VII) Working for building blocks

- *Revision of Global E-Kits*: ICAI currently has 34 Chapters abroad that promote Brand Indian CA ahead of similarly placed qualifications and act as a gateway to promote career opportunities for the Indian chartered accountants. ICAI has launched Global Career E-Kits on many countries where it has a Chapter for the benefit of membership community. These Global Career E-Kits covers general information of related jurisdiction such as demographic details, economic environment, useful business information, visa requirements etc. In addition, useful information such as contact details of local chapter, information on MoU/MRA and FAQs for members abroad is also included in these E-Kits. These E-Kits are likely to assist members to establish a preliminary interface with the jurisdiction to serve in times to come. During the period of the report 11 E-Kits covering 14 Chapters of ICAI have been thoroughly revised and updated.
- *ICAI's 1st Overseas Campus Placement Program*: ICAI Committee(s) for Exports of CA services & WTO (CES & WTO), Professional Accountants in Business & Industry (CPABI) and International Affairs Committee together collaborated to organize the first ever Overseas Campus Placement Programme of the Institute on September 14-16, 2018 at various centres all over India. The salient feature of this placement drive is that it is available not only for freshly qualified Chartered Accountants but also to experience Chartered Accountants. Over 6400 members registered for the said Overseas Campus Placement Programme.

7.6 Right to Information Act, 2005

The Right to information Act, 2005 provided the right to information for citizens of India to access the information under the control of Public Authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) a statutory body set up by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under section 2(h) of the RTI Act, 2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, officers of the Institute have been designated as Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority (FAA) and Transparency Officer.

Disclosure under Section 4 (1) (b) of RTI Act, 2005

In terms of the Section 4(1) (b) of the Right to Information Act, 2005, necessary disclosures have been made by the Institute by hosting them on the website of the Institute www.icaai.org and the same are updated from time to time. Total 761 applications have been received and replied in the year 2018-19.

7.7 XBRL

For the effective participation of the regulators, technologists, corporates and academicians in the endeavour of the Institute for the promotion of XBRL in India, the Institute has facilitated the incorporation of XBRL India as a section 25 company with the main objective of promoting and encouraging the adoption of XBRL in India as the standard for electronic business reporting in India through development of taxonomies, facilitation of education and training on XBRL. Also, considering the growing importance of XBRL internationally, XBRL India has taken membership of XBRL International Inc. to facilitate and get updates of XBRL filing globally. XBRL India is an established Indian jurisdiction of XBRL International. Currently, The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) are the members of XBRL India under the category of “Regulators and Stock Exchanges” and “Universities and Educational Institutions” respectively.

XBRL India is developing and maintaining XBRL taxonomies for Ministry of Corporate Affairs (MCA). XBRL India has developed two taxonomies for Ministry of Corporate Affairs, one is Commercial & Industrial (C&I) taxonomy for companies following Accounting Standards and the other one is Ind AS Taxonomy for companies following Ind AS. Through guidance and support provided by XBRL India, Ind AS taxonomy has been successfully implemented and XBRL filing of the financial statements for the financial year 2017-18 has been successfully done.

(I) XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)

- *Amendments in Ind AS taxonomy:* Ind AS taxonomy has been amended in view of the following reasons:
 - Implementation of new Revenue Standard viz Ind AS 115, ‘Revenue from contracts with customers’ and withdrawal of Ind AS 11 & Ind AS 18 for the financial year 2018-19,
 - Amendments in other Ind AS, viz Ind AS 7, ‘Statement of Cash Flows’
 - Amendments in Ind AS compliant Schedule III
 - Ministry of Corporate Affairs specific requirements
- The Revised Ind AS XBRL Taxonomy as approved by the Council of ICAI and Taxonomy Development and Review committee of XBRL India, submitted to Ministry of Corporate Affairs.
- *Commercial & Industrial (C&I) taxonomy:* For annual filings of the financial statements of a selected class of companies, the Commercial & Industrial (C&I) taxonomy 2016 has been amended in view of changes as per latest amendments in Accounting Standards and submitted to the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for XBRL filling. The updated taxonomy shall be available for XBRL filing of financial statements by the selected class of companies.

7.8 ICAI-ARF

ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF) was established in January, 1999 as a Section 25 Company (now Section 8 Company under the Companies Act, 2013) for doing core research in the areas of accounting, auditing, capital markets, fiscal and monetary policies. The following is the detail of projects undertaken by ICAI ARF during the last year:

- *Indian Railways* - During the year, while executing the “Roll out of accrual accounting in all the Zonal Railways, Production Units and other offices across Indian Railways” Project, ICAI ARF submitted accrual based Financial Statements of Indian Railways for the years 2015-16 and 2016-17 along with those of its 17 Zonal Railways and 8 Production Units. The Concept Paper on Mapping of Finance Code-II, as finalized after several rounds of discussion with various officials of the Accounting Reforms team, CRIS, and Railway Board, proposing two approaches to facilitate accrual based accounting at transaction level itself which will fulfill the requirement of existing system apart from those of accrual accounting. Has also been submitted.
- ICAI ARF submitted Concept paper on retirement benefit fund planning and accounting thereof for Indian Railways – Ministry of Railways, Government of India.
- *Tamil Nadu Civil Supplies Corporation* : ICAI ARF completed the project and submitted the Report to Develop Integrated Accounting System including a complete IT enabled Management Information System for Tamil Nadu Civil Supplies Corporation.

- *Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited* :ICAI ARF submitted the report suggesting Methodology for replacement of WPI (Series 2004-05) with WPI (Series 2011-12) for payment of price variation to contactors.

7.9 ICAI Registered Valuers Organisation

ICAI Registered Valuers Organisation is a section 8 Private Company formed by the Institute of Chartered Accountants of India to enrol and regulate Registered Valuers or valuer member as its members in accordance with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, and functions incidental thereto.

(I) Educational Course (50 hours) by ICAI Registered Valuers Organisation which is a precondition to become Registered Valuer:

- The initial phase of ICAI Registered Valuers Organisation has been focused on building its membership base and conducting 50 hours of educational course for its valuer members which is a precondition for becoming Registered Valuers and preparing Educational material for the Educational Course.
- In this direction, from June, 2018 onwards, ICAI RVO has conducted the 30 batches for the 50 hours training across the country.
- As on August, 2019, 2000+ members have been trained by ICAI RVO for its Educational course of 50 hours.

(II) Registration of Registered Valuers with IBBI for the Asset Class Securities or Financial Assets:

The Insolvency and Bankruptcy Board of India under the Asset Class Securities or Financial Assets has registered 662 Registered Valuers as on 31st July, 2019 out of which, 396 Registered Valuers are ICAI RVO members which contributes to 59% of the membership.

(III) Study Modules for Educational Course by ICAI RVO:

Four Study Modules for Educational Course have been prepared to help the members who enrolls with ICAI RVO for the Educational Course, in understanding the subject better

- Module 1 covers in detail Overview and Concepts of Valuation
- Module 2 covers in detail Valuation Approaches and Methods
- Module 3 covers Judicial Pronouncements
- Module 4 covers Relevant laws & Regulations as per the Syllabus

(IV) Adoption of ICAI Valuation Standards 2018 by ICAI RVO

ICAI through its Valuation Standards Board has brought out ICAI Valuation Standards 2018 which are first of its kind in India. ICAI RVO under rule 8 of the Companies (Registered Valuers and valuation) Rules, 2017 has adopted ICAI Valuation Standards 2018. The ICAI Valuation Standards 2018 are Mandatory for the members who are enrolled with ICAI RVO under the Companies Act 2013 till the time the Valuation Standards are issued by the Government as per the said Rules. The ICAI Standards are recommendatory for Chartered Accountants for valuation under other Statutes.

(V) Launch of ICAI RVO Learning Management System

ICAI RVO has launched its Learning Management System which is an e-learning platform which delivers the concepts of the syllabus prescribed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India in the form of study material and supplemented by mock test in Multiple Choice Questions format. This Learning Management System facilitates the members who are primary members of ICAI RVO, in preparing for IBBI Valuer Examination.

(VI) Publications

ICAI Registered Valuers Organisation jointly with the Valuation Standards Board of ICAI has issued the following Publications:

- **Valuation: Professionals' Insight (Series I, II and III)**
- **Technical Guide on Valuation**
- **Frequently Asked Questions on Valuation**

7.10 INDIAN INSTITUTE OF INSOLVENCY PROFESSIONALS OF ICAI

Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIPI), a wholly owned subsidiary of the Institute of Chartered Accountants of India, is a Section 8 Public Company formed by the Institute of Chartered Accountants of India to enroll and regulate insolvency professionals as its members in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and read with regulations and functions incidental thereto.

It has been awarded with the registration certificate as the First Insolvency Professional Agency of India by Hon'ble Union Finance Minister Shri Arun Jaitley on 28th November 2016 at Delhi. IIPI has attracted members from a diverse stream including Chartered Accountant, Company Secretary, Cost Accountant, Advocates and Management Professionals. Out of total 2698 Insolvency Professionals registered with Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI), 1679 i.e. are from IIPI.

Movement of Membership

IPA of	Total Registrations (as on 31 st March)*							
	FY '17	%	FY '18	%	FY '19	%	Total March '19	%
ICAI	33	34.4	1067	62.2	418	64.5	1518	61.7
ICSI	51	53.1	511	29.8	176	27.2	738	30.0
ICWAI	12	12.5	138	8.0	54	8.3	204	8.3
Total	96	100.0	1716	100.0	648	100.0	2460	100.0

* Source: IBBI Data

The initial phase of IIPI's operations have been focused on building its membership base. However, with the strengthening of the same, the activities have become more broad-based.

INITIATIVES

- **Association with World Bank Group** - IIPI entered into an arrangement for conducting joint programmes in association with World Bank Group (WBG).
- **Train the Trainers program with World Bank Group**- An intensive knowledge dissemination initiative was taken with IBBI in three batches to soak the Insolvency Professionals with knowledge of IBC, Regulations, Cross Border Insolvency and Individual Insolvency.
- **Association with CII** – A Conference on IBC was organised at Delhi in association with CII, Deloitte and AZB Partners in March, 2019.
- **Association with IMC and BSE**- A seminar was organised jointly at Mumbai in association with IMC and BSE on IBC- Challenges, Opportunities, Learning and way forward.
- **Pre-Registration Educational Course** – IIPI has Organized 16 Pre-Registration Training Courses at different centers across the country in the Financial Year 2018-19. IIPI have already completed four programs in the Financial Year 2019-20.
- **Round Tables were conducted by IIPI** - To review and discuss the possible implementable prospects of CIRP and Liquidation in Mumbai, Kolkata, Bangalore and Delhi to place suitable suggestions and recommendations for modifications to IBBI.
- **Study Group Meetings for Insolvency Professionals by IIPI** - IIPI has participated in various meetings of Study Groups of Insolvency Professionals to address issues and concerns in the Insolvency Resolution process.
- **Learning Management System of Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI** - IIPI jointly with ICAI, has designed a Learning Management System to enable the professionals to prepare for the Limited Insolvency Examination to become an IP.
- **IIPI Weekly Newsletter** - IIPI Weekly Newsletter, giving the details of important events and developments relating to the Insolvency Profession are being hosted on the website.
- **International Conference** - International Conference on "New Corporate Insolvency Regime" in association with National Council for Insolvency and Bankruptcy Code, ASSOCHAM India, SIPI, INSOL India, Edelweiss, United Nations Commission on International Trade Law, A&M
- **Association with ASSOCHAM, PHD Chambers and EIRC**: Seminars were extensively organized in association with ASSOCHAM, PHD Chambers and EIRC and seminars were conducted to touch the different aspects of IBC and unfold operational facts and understanding.
- **IP Conclave** - IBBI Insolvency Professionals Conclave was organized by IIPI on 26th May 2018 in Mumbai in association with IBBI.
- **Association with BFSI sector Skill council and NSDC** - IIPI has joined hands with BFSI sector Skill council and NSDC to conduct (a) One-Day upskilling program for all the Insolvency Professionals (IPs) registered (b) To commence "Insolvency Associate Course" as a support service for IPs.

- **Webinar & Web conferences**– Frequent Webinars and Web-Conferences were arranged to touch base with the remotest IP and keep them updated with the latest amendment, notification or circular or change in process in context to IBC making the interface interactive to lead to a proper communication and address to their queries.
- **Workshops in association with IBBI**: IIPI frequently organizes workshops and advanced trainings in association with IBBI pan India for the IPs.
- **A Workshop on the proposed Inspection Manual for IPs** was held and the draft format of the Manual and Inspection Framework was submitted to IBBI.
- **Online Utilities** - IIPI has developed various online utilities functional in its website www.iiipicai.in to capture the status of insolvency & liquidation assignments which includes:
 - Uploading of Public Announcements.
 - Filing of relationship disclosures
 - Uploading the details of Fees and other expenses incurred in CIRP and Liquidation
 - IIPI made Enrolment application Form Online
 - Developed payment gateway to facilitate members of IIPI to pay all types of fees online
 - IIPI is in the process of developing an integrated ERP package, a single window facility for its members.

8. OTHER MATTERS

8.1 ICAI Celebrates its Platinum Jubilee Annual Function, Dedicating Itself in Service to the Nation

The Institute of Chartered Accountants of India organised its Platinum Jubilee Annual Function on 4th February 2019 Hotel, The Ashok in New Delhi. It was time not only to look back at the milestones and landmarks that the Institute achieved in the Council Year 2018-19, it was also time to look ahead towards a bright future. Chief Guest on the occasion, Comptroller and Auditor General of India (C&AG of India) Shri Rajiv Mehrishi called ICAI and Indian CAs as of vital importance for the growth of our nation and our economy. On the occasion, outgoing Central Council members were honoured and meritorious CA students and outstanding Regional Councils, Branches and overseas Chapters were felicitated for their outstanding accomplishments. Attended by more than 1400 stakeholders, the successful grand Platinum Jubilee Annual Function of the Institute witnessed the release of various ICAI publications too.

8.2 Platinum Jubilee Chartered Accountants' (CA) Day – 1st July, 2019

This year, celebrations on 1st July were very special one, since The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) celebrated its Platinum Jubilee CA Day. Chief Guest on the occasion, Hon'ble Vice-President of India, Shri M. Venkaiah Naidu launched the celebrations at Vigyan Bhawan in New Delhi. Calling the Chartered Accountants change agents, Hon'ble Vice-President said that the Chartered Accountants are also the conscience keepers of the profession since it is they, who ensure that their clients pay their taxes truthfully. Secretary of the Ministry of Corporate Affairs Shri Injeti Srinivas and IFAC President Dr. In-Ki Joo also joined the celebrations as guests of honour on the occasion. Earlier IFAC President was also part of a technical session, organised hours before the formal launch of Platinum Jubilee CA Day, at the same venue to update our members' knowledge base. In fact, the celebrations had begun in the morning itself with the hoisting of ICAI flag in the Institute's headquarters.

As per the past practice, based on the communication forwarded by the PR Group to the Regional Councils and Branches, the members/ students/ officials across the country got united in their efforts to celebrate this prestigious occasion by undertaking social activities and programmes.

8.3 Central Council Library

The Central Council Library of the Institute caters to the information requirements of its stakeholders. Its aim is to provide comprehensive and upto date collection of primary and secondary print and non-print material to the present and anticipated members/students, research scholars and officials of ICAI. Library has assumed greater responsibilities of serving committees, departments in imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, on-line databases, print newspapers as well as e-newspapers. Central council library is responsible for updating and providing journals and books required for the various committees work.

The Central Council Library is fully computerized and working through Liberty- library management software. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. These records are available on Internet Online Services www.icaai.org under "know your Institute – Central Council Library"-online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library.

Under the Column "Accountants Browser", an index of articles relevant to accounting profession are published every month in the journal "The Chartered Accountant". One may note that The "Accountants Browser" is an index of

important/Professional Articles with archives of past articles. Reference service from library is also provided to the Researchers & Scholars, faculties, students and members.

A number of online databases have been acquired by the Library, details of which are available on www.icai.org – Central Council Library. These On-line knowledge databases have been installed in the Central Council Library premises as well as at various Departments and also installed in Regional Council Libraries of ICAI, to facilitate the search for required material by the students, Members, Faculties and the Research Scholars. Several online journals have also been subscribed in the Library. Details of the new resources added in the Central Council libraries at Head office and Noida office library respectively for the period 1st April-2018 to 30th June, 2019, are as follows:

CENTRAL COUNCIL LIBRARY (H.Q).

S.NO.	Title	Figures
1.	Journals (Print)- national & International	37
2.	E-Access to Journals subscribed	7
3.	Online Resources	13
4.	No. of new arrival Books added during the period	643

CENTRAL COUNCIL LIBRARY SEC.62, NOIDA

S.NO.	Title	Figures
1.	Journals (Print) - national & International	28
2.	Online Resources	08
3.	No. of new arrival Books added during the period	109

Central Council Library is regularly updating its resources to provide the professional Members, students, faculties & other stakeholders with the latest & upto date knowledge and information.

8.4 Editorial Board

The Editorial Board is a non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) with a MISSION to convey regularly to the members the professional knowledge, matters of interest of profession through the journal '*The Chartered Accountant*'. The reach and impact of the Journal can be gauged by its circulation figure which stands at about 3 lakhs today.

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the Institute's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals. The Editorial Board is continuously surging ahead with its mission to keep the ICAI members and other readers of the journal up-to-date on various profession-oriented topics and issues.

ICAI Kerala Flood Relief Fund: The Institute contributed Rs.73,33,927 towards Prime Minister National Relief Fund to help victims of devastating Kerala floods.

Following are the most significant achievements of the Editorial Board during the period 1 April 2018 to 30th June 2019:

(I) Initiatives towards Partner in Nation Building

Editorial Board has undertaken a number of initiatives towards partnering in Nation Building by way of knowledge upgrade and dissemination through its monthly journal, *The Chartered Accountant*, as well as otherwise. Some significant initiatives in this regard are as under:-

(II) Publication of Articles of National/Professional interest:

About 300 articles/features of national-professional-economic interest were published in the ICAI's journal *The Chartered Accountant* in coordination with various government organs, ICAI Committees, Member authors and other stakeholders.

(III) 'I GO GREEN WITH ICAI' Initiative

- **Micro-site:** As part of a multifarious Green Drive of the ICAI, the green-thinking members and other readers of *The Chartered Accountant* journal have been given an option to opt for various electronic versions of *the* journal while discontinuing the hard copy, to save trees. A micro-website has been made live to secure the responses in this regard.

- *Green Discount to Members opting to not receive hard copy of the journal:* With effect from 1st April 2019, the ICAI Members have been offered Rs 500 discount in membership fee if they opt not to receive hard copy of the journal. More than 25000 members have taken this option so far.

(IV) Initiatives for the Members/Students

Editorial Board has always been very active in taking initiatives for the knowledge enhancement and professional development of the Members and Students through its monthly journal, *The Chartered Accountant*. Some significant initiatives in this regard are as under:-

(V) Coverage of Quality and Contemporary Contents in *The Chartered Accountant Journal*:

- **Wide range of topics covered:** From April 2018 and July 2019 issues of the journal, more than 300 articles/features and reports on various topics were published under various innovative and contemporary theme issues.
- **New Features ‘Our Achiever’ and ‘What the Legends Said’ introduced:** A new feature in the name of ‘Our Achiever’ was introduced w.e.f March 2018 issue of the journal under which interviews of outstanding ICAI members, who have excelled in various walks of life, were published. With effect from March 2019 issue, another new feature ‘What the Legends Said’ was introduced as part of which the relevant quotes of Past Presidents are published.
- **New Feature ‘Ind AS Alert’ Introduced:** A new feature ‘Ind AS Alert’ has been introduced with effect from November 2018 issue of the journal to keep the members/readers up-to-date with latest developments vis-à-vis Indian Accounting Standards.
- **July 2018 Issue and July 2019 issues Brought Out as Collector’s Editions:** The July 2018 issue, coinciding with CA Day and ICAI entering Platinum Jubilee year, and the July 2019 issue coinciding with Platinum Jubilee CA Day, were brought out as Collector’s Edition.

(VI) Many Facets of Digital Versions of *The Chartered Accountant Journal* Upgraded for the convenience of Members and Students:

- *eJournal:* The electronic version of *The Chartered Accountant journal*, which is available online on ICAI website www.icai.org hi-tech user-friendly e-magazine, was further upgraded. The updated version of e-Journal is faster and more responsive, carrying better user experience and offering better mobile compatibility, which is in line with the expectations of our new generation of chartered accountant.
- *Journal in PDF format:* However, for the added and alternative convenience of readers, particularly for separate content-wise downloads, the journal continues to be hosted in the PDF format and also in Indexed mode. The archives of digital journal are available on ICAI website from July 2002 onwards.
- *Journal on Mobile:* Further, this eJournal is now also available on mobile, compatible on iOS (IPad/IPhone etc.) and Android devices. It can be accessed at <http://www.icai.org/> under ‘e-journal’ tab. The eJournal is also available on ICAI Mobile App.
- *Journal Highlight emailers:* As an add-on service, the highlights of every issue of journal in capsule form and the President Message in the journal are now mass-emailed to all the members.
- *All Journals since 1952 in DVD:* In an important initiative to provide a single point reference window to the readers of *The Chartered Accountant journal* and leverage the technology to serve them better, a DVD of past issues of the journal is also available for readers and other stakeholders. While a DVD of 10 years of the journal (July 2002-June 2012) in PDF format is already available for members at a nominal cost, an HTML version DVD containing 63 years of *The Chartered Accountant journal* (July 1952 to June 2015) has also been released. In this HTML-version DVD in a searchable mode, readers can global search the contents through key words relating to accounting, auditing, taxation, etc., besides searching by month, year, volume, category (like Circulars & Notifications, ICAI News, Legal Decisions, etc.), author, etc.

8.5 Triennial elections for the term 2019-22 to the 24th Council and 23rd Regional Councils successfully conducted in December, 2018. In a first, the counting of votes was decentralised and commenced at each of Regional centres separately.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2019, 9,505 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 2,91,698 as on 1st April, 2019.

During the year ended 31st March 2019, 6,752 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 3,367 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2019

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	83272	55602	138874
In Part-time Practice	3558	8278	11836
Not in Practice	12011	128977	140988
Total	98841	192857	291698

9.2 Convocation

Since November 2008, the Institute has been organizing Convocation to confer membership certificates to newly enrolled members. ICAI has successfully organized 1st round of “Convocation 2019” for the newly enrolled members covering the period from December, 2018 to April, 2019 on 30th -31st August & 1st September, 2019 at following nine places under five Regional Offices:-

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Ahmedabad | 6. Kolkata |
| 2. Mumbai | 7. Jaipur |
| 3. Pune | 8. Kanpur |
| 4. Chennai | 9. New Delhi |
| 5. Hyderabad | |

9.3 Chartered Accountants’ Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute as well as their dependents, for maintenance, their emergent educational and medical needs etc.

The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1.	Total Life Members as on 31 st March, 2018	1,34,596
2.	Total Life Members as on 31 st March, 2019	1,36,137
3.	Total Additions of New Life Members (as on 31 st March, 2019)	1,541

Details of Financial Particulars

	During the year ended 31 st March, 2019 (Rs.)	During the year ended 31 st March, 2018 (Rs.)
1. Total Assistance provided	1,12,70,000	92,10,500
2. Administrative Expenses	2,014	1,000
3. Surplus of the Fund during the year	1,24,95,000	2,04,80,000
4. Balance of the Fund	4,93,29,000	3,68,34,000
5. Balance of Corpus	20,63,28,000	19,86,23,000

9.4 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

The data of life membership of the Fund is under preparation. The balance in the credit of the Fund was Rs. 52,97,000 as on 31st March, 2019 as against Rs.47,97,000/- as on 31st March, 2018.

9.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. The Scholarships for the year 2018-2019, 1073 articled assistants who are registered for IPCC and IIPCC have been granted assistance @ Rs. 1500 p.m. and 256 articled assistants who are registered for final course granted financial assistance @ Rs. 2000/- p.m. The balance in the credit of the general fund was Rs. 14,31,53,000/- as on 31st March, 2019 as against Rs. 13,91,82,000/- as on 31st March, 2018.

STATISTICS MEMBERS

AS ON 01/04/2019

FELLOWS :	In Full Time Practice	83272
	In Part-time Practice	3558
	Not in Practice	12011
		98841
ASSOCIATES :	In Full Time Practice	55602
	In Part-time Practice	8278
	Not in Practice	128977
		192857
TOTAL MEMBERSHIP :		291698

	FELLOWS				ASSOCIATES				Grand Total
	In Practice				In Practice				
Region	Full Time	Part Time	Not In Practice	Total	Full Time	Part Time	Not In Practice	Total	
Western	24186	1075	3486	28747	19691	3256	49349	72296	
Southern	17715	893	2829	21437	8536	1707	24109	34352	
Eastern	7961	272	1185	9418	4014	528	11005	15547	
Central	16264	458	1615	18337	11779	1073	20670	33522	
Northern	17140	859	2896	20895	11575	1710	23844	37129	
TOTAL	83272	3558	12011	98841	55602	8278	128977	192857	

10. Board of Studies:

Board of Studies (BoS) of the Institute is responsible for the administration of the Chartered Accountancy curriculum and imparting theoretical instruction to students who are undergoing Chartered Accountancy course. Significant initiatives and achievements of the Board during the period are mentioned below:

(I) New Scheme of Education and Training

Study Materials: The Study Materials of all subjects under the New Scheme of Education and Training including Electives have been printed and uploaded on the ICAI's website. The revised edition of the Study Materials of select subjects were released this year and also webhosted at BoS Knowledge Portal.

Questions and Case Studies for Practice: In order to assist students in their preparation for the forthcoming examinations, Questions for Core Papers and Case Studies for Elective Papers have been uploaded on the ICAI's website.

Revision Test Papers: Revision Test Papers for all papers under old and new schemes have been uploaded at the BoS

Knowledge Portal and printed for the convenience of students.

MCQ based Assessment : In order to sharpen the analytical and comprehension skills of students and to have an objective assessment of their performance in the examination, ICAI had introduced an assessment system in which 30% of the questions asked in the examination of Select Papers would be multiple choice based questions of 1 and 2 marks. This system was put in place for May 2019 examination for both Intermediate and Final levels under both the old and new scheme of education and training.

Intermediate (New Course)		IIPCC (Old Course)	
Paper	Subject	Paper	Subject
2	Corporate and Other Laws	2	Business Laws, Ethics & Communication
4	Taxation	4	Taxation
6	Auditing & Assurance	6	Auditing & Assurance
7	Enterprise Information System & Strategic Management	7	Information Technology & Strategic Management

Final (New Course)		Final (Old Course)	
Paper	Subject	Paper	Subject
3	Advanced Auditing and Professional Ethics	3	Advanced Auditing and Professional Ethics
4	Corporate and Economic Laws	4	Corporate and Allied Laws
		6	Information Systems Control and Audit
7	Direct Tax Laws and International Taxation	7	Direct Tax Laws
8	Indirect Tax Laws	8	Indirect Tax Laws

Webhosting of MCQs for 30:70 assessment in select subjects

Objective type assessment (30 Marks) based on MCQs has been introduced in select subjects of Intermediate/IIPCE and Final (Old) & (New) Course from May, 2019 examination. Accordingly, MCQs in each of these subjects are webhosted at the BOS Knowledge Portal.

Section-wise and skill-wise and weightages hosted at the BOS Knowledge Portal

The section-wise and skill-wise weightages for subjects at the IIPCE and Final levels under the old scheme of education and training applicable for May, 2019 examination were webhosted at the BoS Knowledge Portal. Further, section-wise and skill-wise weightages for certain subjects at the Intermediate and Final levels under the new scheme of education and training, in respect of which partial objective type assessment has been introduced from May, 2019 examination were revised and revised weightages were webhosted at the BOS Knowledge Portal.

Open House Question Answer Sessions

Open House Question Answer sessions for all subjects of Intermediate and Final (including Electives) were conducted for all students of IIPCC, Inter, Final (Old) and Final (New). The questions asked in these sessions has been compiled and uploaded at the BOS Knowledge Portal for the benefit of the students at large.

Scholarships granted to students

The Board of Studies awards Scholarships twice a year under various categories, namely Merit, Merit cum need, Need Based and Weaker Sections, Endowment. Accordingly, during the year, the Board of studies awarded 1646 Scholarships to selected students under above categories.

(II) Computer Based Test for Assessment of Practical Training

ICAI has recently started to conduct online MCQ-based tests for students after completion of first and second year of practical training. Seven tests have been conducted so far on September 23, October 21, December 2, December 30, 2018, February 3, March 10, April 21 and July 7, 2019 covering around 80,000 students at both levels. The purpose is to create a seriousness amongst the students for pursuing their 3 years practical training and also to ensure that the training is imparted in all important areas required for a student to learn. The average of the grades assigned in these tests will be reflected in the Final marksheet of the student. Students can appear for the same level test for two more times to improve their grades by paying a fee of Rs.200.

(III) Live Virtual Classes

The Board of Studies (BoS), ICAI started Live Virtual Classes (LVC) in August 2018 for Intermediate and Final levels as pilot project. The classes had the following features:

- Live lectures
- Delivered on computers and mobiles
- Availability of recorded lectures
- Smart classes having the state of art technology
- Expert faculty with rich experience
- Interactive classes with the facility to raise questions during live classes
- Exam focused approach
- Separate sessions on case study based Elective papers
- Separate question answer sessions
- Periodical tests to review performance
- Coverage of entire syllabus
- These classes were held on week days during morning and evening beyond office hours. (Morning: 7 to 9.30 AM) (Evening: 6 to 8.30 PM)
- Around 500 students took the benefit of LVC.

Live Virtual Classes targeting November, 2019 (Inter) and May 2020 (Final) examinations has been launched with economical fee of Rs. 4000/- and Rs. 4750/- respectively.

(IV) Monthly Interaction with Regional Councils, Branches and Students

Monthly interaction of Chairperson, Vice-Chairman and Director, BOS has been initiated with Regional Councils, Branches and students through webcast so that the connect can be strengthened. BoS has compiled and uploaded Frequently Asked Questions (FAQs) on Institute's website relating to various academic and other initiatives of the BoS.

(V) Students' connect through social media sites

The Board of Studies has improved the Face book page of the Institute and made it more informative for students so as to connect with students in a better way, like –

- Communicate important news and announcements about the Institute and its activities through this channel
- Stay in touch with students, engage and inspire them
- Create a community of students for discussion and debate about a variety of issues
- Provide theme-based content (text, images videos etc.) to the students on daily basis to create interest and provide relevant information.

(VI) BoS : One Stop Referencer

A booklet namely **BoS : One Stop Referencer** has been published for the benefit of Regions, Branches, Members, Students and other stakeholders. This booklet contains detailed information about the BOS initiatives and activities, contact details of the respective officials handling the activities.

(VII) Training Course on GST :

The BOS jointly with the Indirect Taxes Committee has organized a 30 Hrs weekend Virtual Training Course on GST from July 14 till Aug 12, 2018 and trained more than 3000 students.

(VIII) Revamping of Students Conference Structure

The Board has restructured the layout of program structure of Students Conferences so as to make it more participative for not only students who are on the dais but for the students who are in the audience.

(IX) Toll-Free helpline for Students as part of Student support initiative BOS

The toll-free helpline 18001211330 established at BOS Noida, has been successfully running since May 2017. Between April 2018 and June 2019, more than seventy two thousand students from across the country have benefited from the

service.

(X) Virtual Management and Communication Skills Course

Virtual Management and Communication Skills (MCS) course has been launched from 4th February, 2019 for the candidates who have qualified CA final w.e.f 2002 (November onwards) till 2018 but have not applied for Membership of the Institute..

The candidates who have qualified CA final but have not applied for Membership of the Institute due to non completion of Management and Communication Skills Course can undergo the Management and Communication Skills through virtual mode. The aforesaid candidates can undergo the course anytime anywhere. After completing the Virtual MCS course of 90 hours they can apply for membership of the Institute.

(XI) Features of Virtual Management and Communication Skills Course-

- No class room teaching. The student will be undergoing the course through online mode. The duration of Virtual MCS course shall be 90 hours.
- Maximum time allowed to the student for completing the course is 180 days. Incase the student is not able to complete the course during the aforesaid period; extension of 90 days shall be given to the student. The student has to pay 50% of the course fee for re-validation of the registration in the aforesaid course.
- Separate portal/Learning Management system (LMS) is there where the student can register and undergo the course.
- The student will be able to view day wise session in seriatim.
- At the end of the each session, there will be an objective type online test. The certificate will be issued after student clears all the test. 50% marks are mandatory for clearing the test. In case, student is not able to clear the online test, the student will appear in re-test.

(XII) Programme with Indian Institute of Management, Ahmedabad:

A Memorandum of Understanding has been signed between the Institute of Chartered Accountants of India and Indian Institute of Management, Ahmedabad.

As a part of mutual cooperation a 5 days Residential Programme - “Advanced leadership programme for Chartered Accountants”, was organised at IIM Vastrapur, Ahmedabad from Dec 24-28, 2018. The programme aims at providing an opportunity for Chartered Accountants to reflect upon new perspectives, dimensions and strategies to steer organizations towards their goals. It would help the participants to imbibe leadership skills such as articulation, negotiation, conflict resolution, teambuilding and change management.

(XIII) Students Activity Portal

The Board of Studies has developed a Student Activity Portal to help its students to get themselves registered from anywhere anytime for various students’ programmes being organised by Regional Councils and Branches. The students can login from time to time to register for events like, Student Seminars, Student Conferences, Mock Tests, Workshop, Special Counselling Programme for CA Students, CA Students Talent Search, CA Students festival, Sports Competition etc.

It helps in the systematic management of student activity at the level of programme organising units and Board of Studies.

(XIV) Article Placement Portal

Articleship and Industrial Training Placement portal - a common platform for members, organisations and students to interact with one another and facilities members/organisations to search, shortlist and schedule interviews with the interested students. Students can also apply / search vacancies indicating their preferences of place and areas. The Portal is user friendly and will help in bridging the requirement gaps between members/industries and students seeking articleship / industrial training.

(XV) Reading Room Portal

174 Libraries/Reading Rooms/Additional Reading Rooms are functional to provide conducive reading atmosphere for CA students across the country. The students can login to the Reading Room Portal by entering with their Username and Password and register anytime anywhere. The other features of the reading room portal are as under:-

- Securing seat by paying monthly fees in advance.
- Flexible registrations by students for a day/ a month.
- Fees as low as Rs. 20 per day.
- 24 x 7 online services available.
- Confirmation of the seat within 24 hrs. of Payment.
- Updated information available on the Portal to help students to register.

(XVI) Distance Education for CA Course

e-Learning Initiatives for Students: The distance education for the Chartered Accountancy Course is provided by ICAI in the form of Video Lectures and e-Books through the ICAI Cloud Campus <http://cloudcampus.icai.org> for all the three levels of CA Course. The Distance Education initiative enables students to learn anytime and from anywhere as per their convenience i.e. from their homes/ offices.

Video Lectures: Video Lectures for all subjects are made available for all levels of CA Course for explaining concepts and step-by-step practical problem-solving process on the blackboard – a key skill requirement from examination perspective. Presently, 664 lectures covering 559 hours for old scheme of education and training are available on the ICAI Cloud Campus and 347 lectures of 590 hours are available for the New Scheme.

e-Books on Digital Learning Hub: Chapter-wise e-Books for all the subjects of the new scheme of education and training are available on the ICAI Cloud Campus through Digital Learning Hub. For Foundation Course, the video lectures and self-assessment quizzes are also embedded in the e-Books.

(XVII) Soft Skill Courses organized for Students

The Regional Offices and Branches have been organized and trained the students since April 01, 2018 to June 30, 2019 is as under:

Course	No. of Batches	No. of students Trained.
ICITSS- IT	2023	59722
AICITSS- Adv. IT	1762	58709
Total	3785	118431

Status of Declaration of results of the Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (AICITSS) - Advanced Information Technology Test. After concerted efforts by the office, the current status of AICITSS - Adv. IT Exam held on following dates is as under:

Sr.	Test Date	Students Appeared in Test	Students Qualified Test
1	January 21, 2018	2,956	2,843
2	February 18, 2018	5,070	4,890
3	March 18, 2018	5,183	5,121
4	April 22, 2018	2,373	2329
5	July 08, 2018	8,239	8,097
6	August 19, 2018	6169	5920
7	September 16, 2018	3336	3213
8	October 07, 2018	2112	2054
9	January 06, 2019	9969	9330
10	March 03, 2019	10105	9767
11	April 27, 2019	11030	10614
12	May 17, 2019	3573	3436
	Total	70,115	67,614

The Council at its 379th meeting held on December 17, 2018 decided the attendance of the students pursuing soft skill and IT courses through biometrics machine.

In the view of above Biometric machines have been installed at 18 locations and mapped with the online portal.

ICITSS- Orientation Course: 1423 batches were organized by the Regional Offices/Branches/chapter outside India and 63242 students have undergone the course.

AICITSS- Management and Communication Skills Course: 1417 batches were organized by the Regional Councils and their Branches/ Chapter outside India and 64616 students have undergone the course.

Motivation to the students undergoing MCS course: In order to motivate and harness the oratory skills of the students undergoing MCS course an incentive/reward scheme has been introduced. The scheme is named as Best Presenter of the Batch. Each student in the batch has to make his/her presentation in the last 2-3 days of the session. The best presenter is awarded with a cash reward of Rs.1100/- along with the letter of appreciation while the 2nd and the 3rd best presenter are being given the letter of appreciation.

(XVIII) Faculty Training Programmes

ICAI successfully organised Faculty Development Programme on AICITSS (Management and Communication Skills Course) course at Delhi, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Ahmedabad, Chandigarh and Mumbai wherein 549 faculty members participated who are presently taking classes/ are willing to take classes of AICITSS- MCS Course organized by Board of Studies. The objective of the FDP is to standardize and ensure uniform delivery of the sessions all across POU's.

(XIX) Important Events

Conferences/ Conventions/ Seminars and other activities Students' Conferences : National Conference, CA Student Conference and International Conference for CA students: During the period 2018-2019, Board of Studies organised 5 National Conferences at Jaipur, Chandigarh, Indore, Kolkata, New Delhi and Mumbai, in addition to 35 CA Student Conference organised at various places all over the India and International Conference at Ahmedabad and around 26,000 students participated in these students conferences.

International Conference for CA Students at Ahmedabad: The Board of Studies has organized a two days International Conference for CA students in Ahmedabad on 5th and 6th January, 2019. The conference, hosted by Ahmedabad Branches of WIRC & WICASA of ICAI, was highly successful with more than 3200 students attending it. The theme of the conference was "Knowledge & Training with Ethical Quotient - Pathway to Professional Excellence". Shri Suresh P. Prabhu, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry and Civil Aviation graced the occasion as Chief Guest in the inaugural session. Hon'ble Justice Shri Mukesh Kumar Rasikbhai Shah, Supreme Court of India and Shri PP Bhat, President, Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) were the Guests of Honour. The inaugural session was attended by Hon'ble President CA. Naveen N. D. Gupta, Hon'ble Vice-President CA. Praffulla Preme Sukh Chhajed, CA. Dhinal Ashvinbhai Shah, Chairman, BOS in the presence of many Central Council Members. There were also presentations from foreign students and the Conference was a grand success.

CA Students Talent Search 2018: Board of Studies has organised the National Level 'CA Students' Talent Search' on 28th June, 2018 at "NDMC Convention Centre, Delhi wherein 69 Final Contestants across the country participated in Quiz, Elocution, Instrumental Music and Nukkad Drama. The event was graced by Ms. Rachel Grimes (President, IFAC) as the Chief Guest. Hon'ble President CA. Naveen N. D. Gupta, Hon'ble Vice-President CA. Praffulla Preme Sukh Chhajed, Chairman, BoS CA. Dhinal Ashvinbhai Shah, Vice-Chairman, BoS, CA. Vijay Kumar Gupta, CA. Atul Gupta, Central Council Member and SAFA delegate also witnessed the event.

To fine-tune the oratory and presentation skills of elocution contestants, grooming sessions were organized on 27th June, 2018. Dr. P. C. Jain, Government Nominee, CA. Bhawana Singhal, CA. Arun Garg, CA. Manpreet Singh were the Jury of above contests. The event was a grand success and the following are the details of winners:-

Winner Details			
	Ist Winner	2nd Winner	3rd Winner
	Name	Name	Name
Quiz Contest	Mr. Palash Maheshwari	Ms. Pushpa Paliwal	
	Mr. Mayur Rajput	Ms. Revati Naidu	
Elocution	Ms. Srinithi U	Mr. Akash Gangopadhyay	Mr. Nikhil Sachedva

Instrumental Music	Mr. Chirag Jain	Mr. Atul Dang	Mr. Mudit Bhattar
Nukkad Drama	Mr. Nikhil Sachdeva [Team Leader]	Ms. Sakshi Prajapati [Team Leader]	Mr. Rahul Agarwal [Team Leader]
	Ms. Shivam	Ms. Swati Sarathe	Mr. Pulkit Agarwal
	Ms. Surbhi Gupta	Ms. Paridhi Bhatnagar	Ms. Darshana Malpani
	Ms. Kunjam	Ms. Nehal Sharma	Mr. Sumit Goyal
	Mr. Piyush Goyal	Ms. Sharmistha Dana	Mr. Aman Agarwal
	Ms. Purnima Barik	Ms. Charu Ahuja	

Teachers' Day on 5th September, 2018: The Board of Studies celebrated Teachers' Day across the country through Regional Councils and Branches on 5th September, 2018 so as to have a strong Teacher and Student relationship amongst the Principal and their Articles.. During the programme, the Regional Council and branches organized Essay and Poem Competitions.

To create a feel of reverence and gratitude in students for their mentor the Board facilitated the students with e-cards and a Webcast was also scheduled from 10.00 am to 11.00 am from ICAI, Delhi Office, which was addressed by CA. N.D. Gupta, Past President, ICAI and Rajya Sabha Member; CA. Prafulla Premeek Chhajer, Vice-President, ICAI; Dr. P.C. Jain, Central Council Member; CA. Zaware Shiwaji Bhikaji, Central Council Member.

Joint Seminar: Two day Joint Seminar was organized with Pondicherry University, Puducherry held on 6th & 7th April 2018.

Residential Programme on Professional Skills Development at Centre of Excellence, Hyderabad

Four batches (Two batches at Centre of Excellence, Hyderabad and Two batches at Centre of Excellence, Jaipur) were held during the year and 145 students were trained.

Recognized CA qualification for pursuing Ph.D. by the following Universities:

With the constant follow up with various Universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 103 Universities, 6 IIMs and 2 IIT Bombay & Madras (Total 111) for the purpose of pursuit of Ph.D./Fellow Programme.

11. Regional Councils and their Branches

The ICAI has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively. Currently it has 164 Branches, 34 Chapters outside India and 15 Regional Libraries all over India.

11.1 Award for Best Regional Council, Best Branch of Regional Council, Best Students' Association and Best Branch of Students' Association.

These awards are given by the ICAI every year. The awards are given on the basis of overall performance and established norms. For the year 2018 these Shields were awarded at the Annual Function held on 4th February, 2019 to the following winners:-

- 1. Best Regional Council**
 - First Prize : Western India Regional Council
 - Second Prize : Eastern India Regional Council
- 2. Best Branch of Regional Councils**
 1. Mega Category
 - First Prize : Indore Branch of CIRC of ICAI
 - Second Prize : Pune Branch of WIRC of ICAI

2. Large Category
 - First Prize : Baroda Branch of WIRC of ICAI
 - Second Prize : Ernakulam Branch of SIRC of ICAI
 3. Medium Category
 - First Prize : Aurangabad Branch of WIRC of ICAI
 - Second Prize : Siliguri Branch of EIRC of ICAI
 4. Small Category
 - First Prize : Bhilai Branch of CIRC of ICAI
 - Second Prize : Salem Branch of SIRC of ICAI
 5. Micro Category
 - First Prize : Sivakasi Branch of SIRC of ICAI
 - Second Prize : Tuticorin Branch of SIRC of ICAI
- 3. Best Students' Association**
- First Prize : Western India Chartered Accountants Students' Association
 - Second Prize : Eastern India Chartered Accountants Students' Association

4. Best Branch of Students' Association

- a. Large Category:
 - First Prize Pune Branch of WICASA of WIRC & Aurangabad Branch of WICASA of WIRC of ICAI
 - Second Prize Baroda Branch of WIRC of ICAI
- b. Medium Category:
 - First Prize Sivakasi Branch of SICASA of SIRC of ICAI
 - Second Prize Nanded Branch of WICASA of WIRC of ICAI

11.2 Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the ICAI has set up eighteen Decentralised Offices as under:-

Mumbai	Chennai	Kolkata	Kanpur	New Delhi	Ahmedabad
Bangalore	Hyderabad	Pune	Jaipur	Nagpur	Surat
Vadodara	Thane	Ernakulam	Coimbatore	Indore	Chandigarh

12. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2019 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date duly audited by the Auditors are published hereinafter.

13. APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/ Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 1949, the Regional Councils, its branches, and their members, and to the non-members who assisted the Council during the year 2018-19 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2018-19.

The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to Hon'ble Vice-President of India, Shri M. Venkaiah Naidu,

Shri Rajiv Mehrishi, Comptroller & Auditor General of India, Shri Injeti Srinivas, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Dr. In-Ki Joo, President, International Federation of Accountants (IFAC), and other dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI.

The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced programmes organised by the organs of the ICAI.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various Central and State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/ being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2018-19 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

STATISTICS AT A GLANCE
MEMBERS REGISTERED
(From 1st April, 2007)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1 st April, 2007	Associate Fellow Total	31159 16896 48055	18237 13646 31883	7829 6488 14317	9642 8882 18524	14182 12880 27062	81049 58792 139841
1 st April, 2008	Associate Fellow Total	32364 17646 50010	19203 14034 33237	7939 6738 14677	10045 9472 19517	14642 13398 28040	84193 61288 145481
1 st April, 2009	Associate Fellow Total	34294 18442 52736	20666 14516 35182	8193 7002 15195	10578 10007 20585	15951 13951 29902	89682 63918 153600
1 st April, 2010	Associate Fellow Total	36390 19181 55571	21733 15076 36809	8512 7192 15704	11252 10615 21867	17104 14461 31565	94991 66525 161516
1 st April, 2011	Associate Fellow Total	38608 19831 58439	22998 15612 38610	9154 7406 16560	12329 11182 23511	18547 14943 33490	101636 68974 170610
1 st April, 2012	Associate Fellow Total	45273 20510 65783	25505 16132 41637	11069 7578 18647	15963 11720 27683	23332 15431 38763	121142 71371 192513
1 st April, 2013	Associate Fellow Total	52846 21522 74368	28020 16918 44938	13258 7815 21073	20606 12327 32933	27743 16051 43794	142473 74633 217106
1 st April, 2014	Associate Fellow Total	56595 22313 78908	29401 17460 46861	14035 8007 22042	22978 12915 35893	29467 16508 45975	152476 77203 229679
1 st April, 2015	Associate Fellow Total	60229 22838 83067	30126 17864 47990	14514 8137 22651	24702 13441 38143	31137 16986 48123	160708 79266 239974
1 st April, 2016	Associate Fellow Total	64235 23700 87935	31919 18495 50414	15046 8223 23269	27353 14071 41424	32774 17521 50295	171327 82010 253337
1 st April, 2017	Associate Fellow Total	67746 25742 93488	33591 19711 53302	15580 8718 24298	30036 15618 45654	34632 18933 53565	181585 88722 270307
1 st April, 2018	Associate	70683	34733	15606	32094	36988	190104

	Fellow	26736	20280	8912	16494	19667	92089
	Total	97419	55013	24518	48588	56655	282193
1 st April 2019	Associate	72296	34352	15547	33522	37129	192857
	Fellow	28747	21437	9418	18337	20895	98841
	Total	101043	55789	24965	51859	58024	291698

MEMBERS*(From 1st April, 1950)***TABLE II**

	Associate	Fellow	Total
As on 1 st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1 st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1 st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1 st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1 st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1 st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1 st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1 st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1 st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1 st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1 st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1 st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1 st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1 st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1 st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1 st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1 st April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610
As on 1 st April, 2012	1,21,142	71,371	1,92,513
As on 1 st April, 2013	1,42,473	74,633	2,17,106
As on 1 st April, 2014	1,52,476	77,203	2,29,679
As on 1 st April, 2015	1,60,708	79,266	2,39,974
As on 1 st April, 2016	1,71,327	82,010	2,53,337
As on 1 st April, 2017	1,81,585	88,722	2,70,307
As on 1 st April, 2018	1,90,104	92,089	2,82,193
As on 1 st April, 2019	1,92,857	98,841	2,91,698

STUDENTS REGISTERED*(From 31st March, 2009)*

During the year	Foundation as per new CRET	Final	New Final	CPT	PCC	IPCC & IIPCC	Intermediate	ATC	Total
2009-10	-	24,172	-	1,67,073	1,860	80,745	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	57,175	-	1,55,217	329	67,984	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	47,515	-	1,61,712	-	85,053	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	45,102	-	1,61,084	-	1,02,406	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	39,348	-	1,54,742	-	96,285	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	36,950	-	1,41,241	-	66,570	-	881	2,45,642
2015-16	-	31,669	-	1,25,140	-	77,962	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	27,611	-	1,07,392	-	81,886	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	26,291	14,056	73,804	-	22,657	63,693	-	2,10,289
2018-19	45,048	-	27,966	-	-	-	53,654	-	126,668

COMPOSITION OF THE COUNCIL - (2019-2020)

President CA. Prafulla Premsukh Chhajed	Members of the Council	
	Elected Members	
Vice-President CA. Atul Kumar Gupta	CA. Anil Satyanarayan Bhandari	Mumbai
	CA. Jay Chhaira	Surat
Period 12 th February 2019 onwards	CA. Prafulla Premsukh Chhajed	Mumbai
	CA. Chandrashekhar Vasant Chitale	Pune
Secretary to the Council Shri Rakesh Sehgal Acting Secretary	CA. Tarun Jamnadas Ghia	Mumbai
	CA. Nandkishore Chidamber Hegde	Mumbai
Government Nominee	CA. Nihar Niranjan Jambusaria	Mumbai
	CA. Shriniwas Yeshwant Joshi	Mumbai
	CA. Durgesh Kumar Kabra	Mumbai
	CA. Dheeraj Kumar Khandelwal	Mumbai
	CA. Aniket Sunil Talati	Ahmedabad
	CA. Babu Abraham Kallivayalil	Kochi
	CA. Dayaniwas Sharma	Hyderabad
	CA. Prasanna Kumar D	Visakhapatnam
	CA. Rajendra Kumar P.	Chennai
	CA. G. Sekar	Chennai
	CA. M.P. Vijay Kumar	Chennai
	CA. Ranjeet Kumar Agarwal	Kolkata
	CA. Sushil Kumar Goyal	Kolkata
	CA. (Dr.) Debashis Mitra	Guwahati
	CA. Manu Agrawal	Kanpur
	CA. Pramod Kumar Boob	Jaipur
	CA. Anuj Goyal	Ghaziabad
	CA. Satish Kumar Gupta	Jaipur
	CA. Prakash Sharma	Jaipur
	CA. Kemisha Soni	Indore
	CA. Hans Raj Chugh	New Delhi
	CA. Atul Kumar Gupta	Gurgaon
	CA. Pramod Jain	New Delhi
	CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
	CA. Rajesh Sharma	New Delhi
	CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal	New Delhi
	Shri. Anurag Agarwal, Jt. Secretary, Ministry of Corporate Affairs	New Delhi
	12 th February 2019 – 14 th August, 2019)	
	Shri Manoj Pandey, Jt. Secretary, Ministry of Corporate Affairs	New Delhi
	(w.e.f. 14 th August, 2019)	
	Shri Gyaneshwar Kumar Singh, Jt. Secretary, Ministry of Corporate Affairs	New Delhi
	Ms. Ritika Bhatia, Principal Director (Commercial-II) O/o Comptroller & Auditor General of India	New Delhi
	Dr. Ravi Gupta, Associate Professor, Sri Ram College of Commerce	New Delhi
	University of Delhi	
	Shri Sunil Kanoria	New Delhi
	Shri Chandra Wadhwa	New Delhi
	Dr. P.C. Jain	New Delhi
	Shri Vijay Kumar Jhalani	New Delhi

Shah Gupta & Co.
Chartered Accountants

Khanna & Annadhanam
Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Council of The Institute of Chartered Accountants of India

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements prepared in all material respects in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949, give a true and fair view of the financial position of the Institute as at March 31, 2019, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949 and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The management is responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Other Matters

- a) The Institute has authorised a large number of Chapters in India and abroad. The Institute has represented to us that since these Chapters are separate entities, their accounts are not required to be consolidated.
- b) We did not audit the financial statements of the Institute's Decentralised offices, Computer Centres, Students Associations, Regional Councils and their Branches (collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of Rs.94467 Lakhs, total revenues of Rs.18903 Lakhs and net cash flows / (outflow) amounting to Rs.84 Lakhs as considered in the financial statements. The financial statements of these branches have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management. Our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Branches is based solely on the reports of the other auditors.
- c) The financial statements of the Northern India Regional Council are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch based is solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material in the context of overall financial statements of the Institute.

Our opinion on the financial statements, and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the management.

Report on Other Regulatory Requirements

Further, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the decentralised offices, computer centres, students associations, Regional Councils and their branches.
- c) The Institute's Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

For Shah Gupta & Co.

Chartered Accountants
Firm Reg. No.109574W

Sd/-

CA. Rajeev Bansal

Partner

Membership No. 088598

UDIN: 19088598AAAABR8508

For Khanna & Annadhanam

Chartered Accountants
Firm Reg. No. 001297N

Sd/-

CA. B.J. Singh

Partner

Membership No. 07884

UDIN: 19007884AAAAAD9018

Place : New Delhi

Date: 24th September, 2019

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019

	Particulars	Note No	As at March 31,	
			2019	2018
I	SOURCES OF FUNDS		(₹ in Lakhs)	
	i SURPLUS AND EARMARKED FUNDS			
	a. Reserves and surplus	3	1,27,756	1,28,239
	b. Earmarked funds	4	68,591	39,370
	ii. NON - CURRENT LIABILITIES			
	a. Other long-term liabilities	5	1,591	1,219
	b. Long-term provisions	6	25,291	22,941
	iii. CURRENT LIABILITIES			
	a. Trade payables	7	4,132	3,677
	b. Other current liabilities	8	24,042	24,274
	c. Short-term provisions	6	1,628	1,307
	TOTAL		2,53,031	2,21,027
II	APPLICATION OF FUNDS			
	i. NON - CURRENT ASSETS			
	a. Property, Plant and Equipment	9	61,006	54,363
	b. Intangible assets	10	34	55
	c. Capital work-in-progress	11	5,555	10,877
	d. Non-current investments	12	1,18,177	76,535
	e. Assets held for Earmarked and other Funds	13	5,176	5,229
	f. Long-term loans and advances	14	3,433	3,397
	g. Other non-current assets	15	330	678
	ii. CURRENT ASSETS			
	a. Current investments	12	4,917	2,506
	b. Assets held for Earmarked and Other Funds	13	37,992	54,704
	c. Inventories	16	479	1,080
	d. Cash and bank balances	17	8,712	6,824
	e. Short-term loans and advances	14	3,295	2,714
	f. Other current assets	15	3,925	2,065
	TOTAL		2,53,031	2,21,027

See accompanying notes 1 to 28 forming part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava
 Joint Secretary

Sd/-
Rakesh Sehgal
 Acting Secretary

Sd/-
CA. Atul Kumar Gupta
 Vice-President

Sd/-
CA. Prafulla P. Chhajed
 President

In our report referred to even date

For Shah Gupta & Co.

Chartered Accountants

Firm registration number:109574W

For Khanna & Annadhanam

Chartered Accountants

Firm registration number:001297N

Sd/-
CA. Rajeev Bansal
 Partner, Membership No. 088598
 New Delhi, 24th September, 2019.

Sd/-
CA. B.J. Singh
 Partner, Membership No. 007884

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

Particulars		Note No.	For the year ended March 31,	
			2019	2018
			(₹ in Lakhs)	
I INCOME				
a) Fees	18		70,467	62,526
b) Seminars	19		4,312	5,761
c) Other income	20		14,597	12,322
Total income			89,376	80,609
II EXPENSES				
a) Seminars and training programmes	21		4,505	6,036
b) Employee benefit expenses	22		14,695	16,872
c) Printing and stationery			5,517	5,810
d) Professional fees paid to examiners and consultants			9,557	8,005
e) Depreciation and amortisation expense	9-10		2,688	2,257
f) Other expenses	23		24,075	22,770
Total expenses			61,037	61,750
III Net surplus (I-II)			28,339	18,859
IV Appropriation to funds / reserves:				
a) Education Fund [See Note 2.6 (iii)]			5,818	5,073
b) Employees Benevolent Fund [See Note 2.6 (iv)]			80	78
c) Members Benevolent Fund [See (Note 25.24)]			2,138	-
d) Earmarked Funds and Other Funds (Net of expenses)			2,831	2,296
e) Information Technology Training Reserves [See Note 2.6 (vii)]			1,780	1,001
f) Sinking Fund [See Note 2.6 (viii)]			276	-
g) World Congress of Accountants (WCOA), 2022 (Note 25.19)			1,500	-
h) General reserve			13,916	10,411
TOTAL			28,339	18,859

See accompanying notes 1 to 28 forming part of the financial statements

Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava
Joint Secretary

Sd/-
Rakesh Sehgal
Acting Secretary

Sd/-
CA. Atul Kumar Gupta
Vice-President

For and on behalf of the Council
Sd/-
CA. Prafulla P. Chhajed
President

In our report referred to even date
For Shah Gupta & Co.
Chartered Accountants
Firm registration number:109574W

For Khanna & Annadhanam
Chartered Accountants
Firm registration number: 001297N

Sd/-
CA. Rajeev Bansal
Partner, Membership No. 088598
New Delhi, 24th September, 2019.

Sd/-
CA. B.J. Singh
Partner, Membership No. 007884

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

	Particulars	For the year ended March 31,	
		2019	2018
		(₹ in Lakhs)	
I	Cash Flow from operating activities		
	Net surplus after prior period adjustments Adjustments for:	28,339	18,859
	-Depreciation and amortisation expense	2,688	2,540
	-Provision no longer required written back	(445)	(193)
	-Provision for doubtful advances	4	229
	-Interest income	(11,332)	(8,743)
	-Admission fees from members directly allocated to reserves	387	367
	Operating surplus before Working Capital changes	19,641	13,059
	Changes in working capital:		
	Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
	-Inventories	601	(79)
	-Long-term loans and advances	216	(8)
	-Short-term loans and advances	(585)	(691)
	Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
	-Other long-term liabilities	372	488
	-Long-term provisions	2,350	6,603
	-Trade payables	900	679
	-Other current liabilities	(218)	4,904
	-Short-term provisions	321	370
	Income tax (paid) / received (net)	23,598	25,325
		(252)	(402)
	Cash generated from operating activities (A)	23,346	24,923
II	Cash Flow from Investing Activities		
	-Purchase of non-current investments	(41,642)	(51,904)
	-Sale / redemption / (purchase) of current investments	(2,411)	5,585
	-Capital expenditure on Property, Plant and Equipment	(4,273)	(2,104)
	-Proceeds from sale of Property, Plant and Equipment	271	(197)
	-Decrease in earmarked and other funds	16,765	14,085
	-Interest income received	9,820	11,288
	Cash (used in) investing activities (B)	(21,470)	(23,247)
III	Cash Flow from financing Activities		
	-Donation received for buildings	-	11
	-Contribution received	27	83
	-Other fund received/(utilisation)	(15)	19
	Cash from financing activities (C)	12	113
	Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C) Cash and	1,888	1,789
	Cash Equivalents at beginning of the year	6,824	5,035
	Cash and Cash Equivalents at closing of the year	8,712	6,824

See accompanying notes 1 to 28 forming part of the financial statements

Notes:

- 1) Cash and Cash Equivalents represent cash on hand and balances with banks (Refer Note. 17).
- 2) Figures in brackets represent outflows.

For and on behalf of the Council

Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava
Joint Secretary
In our report referred to even date
For Shah Gupta & Co.
Chartered Accountants
Firm registration number:109574W
Sd/-
CA. Rajeev Bansal
Partner, Membership No. 088598
New Delhi, 24th September, 2019.

Sd/-
Rakesh Sehgal
Acting Secretary

Sd/-
CA. Atul Kumar Gupta
Vice-President

Sd/-
CA. Prafulla P. Chhajed
President

For Khanna & Annadhanam
Chartered Accountants
Firm registration number: 001297N
Sd/-
CA. B.J. Singh
Partner, Membership No. 007884

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

1. General Information

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute or ICAI"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 under an Act of Parliament viz The Chartered Accountants Act, 1949 for the purpose of regulating the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the institute. For this purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai and New Delhi, 5 Decentralised Offices, 13 Sub-Decentralised Offices, 164 branches and one overseas office in Dubai.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Basis of Preparation

The financial statements comprising Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, Cash Flow Statement and Notes thereon are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) and The Chartered Accountants Act, 1949. Indian GAAP here comprises of the accounting standards and other pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The financial statements are prepared on going concern, under the historical cost convention and on accrual basis unless other wise stated. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year, unless stated otherwise except in the case of retirement benefits where upto the previous year the Institute's contribution to the provident fund scheme was considered as a defined contribution plan and for the current year it has been considered as defined benefit plan.

2.2 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialised.

2.3 Inventories

Inventories comprise publications, study materials, stationery and other stores. Inventories are valued at the lower of cost based on first in first out method ("FIFO") and the net realisable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary.

Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including other levies, transit insurance and incidental charges.

2.4 Cash and cash equivalents (for purposes of Cash Flow Statement)

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.5 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated based on the available information.

2.6 Appropriation to Reserves and Allocation to Earmarked Funds

- i) Fee received from members for admission as fellow of the Institute is credited to Infrastructure Reserve Account.
- ii) Donations received for buildings and for research are credited directly to the respective reserve account.
- iii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.
- iv) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) received during the year is transferred to the Employees' Benevolent Fund.
- v) From the earmarked funds the following transfers are made to Education Reserve Account:
 - a) From Accounting Research Building Fund 100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building Fund relating to Accounting Research Building Fund.
 - b) From Education Fund 50% of cost of additions (net of deductions if any) to Fixed Assets.
- vi) Income from investments of Earmarked Funds is added to Earmarked Funds. The income is allocated based on opening balances of the respective earmarked funds on weighted average basis.
- vii) 25% of the Information Technology Training (ITT)/Advance Information Technology Training course Fee received during the year is transferred to Other Reserves for replacement of computers and other ITT centre infrastructure.
- viii) A sum equal to depreciation for the year (excluding amount transferred to the ITT Reserve) is transferred to Sinking Fund for repair and replacement of assets.

2.7 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment is recognised when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Institute and the cost of the item can be measured reliably. Property, Plant and Equipment are carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost of Property, Plant and Equipment comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use. Other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying Property, Plant and Equipment up to the date the asset is ready for its intended use are also capitalised.

2.8 Intangible Assets

Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if

any. The cost of intangible assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying assets up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on tangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

2.9 Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work-in-Progress. The cost includes the purchase cost including import duties and non-refundable taxes, if any, directly attributable costs.

2.10 Depreciation and amortization

A). Depreciable amount for assets is the cost of an asset, or other amount substituted as cost. Depreciation on Property, Plant and Equipment is calculated on the written down value method as per the useful life as approved by the Council. The useful life of the assets has been assessed based on technical advice, taking into account the nature of the asset, the estimated usage of the asset, the operating conditions of the asset, past history of replacement, anticipated technological changes, manufacturers warranties and maintenance support, etc.

The rates used for the depreciation of Property, Plant and Equipment are as follows:

Class of Property, Plant and Equipment	Rate of Depreciation
i) Buildings	5%
ii) Lifts, electrical installations and fittings	10%
iii) Computers	60%
iv) Furniture and fixtures	10%
v) Air conditioners and office equipments	15%
vi) Vehicles	20%
vii) Library books	100%

B) Carrying amount of Leasehold land is amortised over the shorter of the lease term or its useful life.

C) Intangible assets, consisting of Computer software, is amortised over its estimated useful life on straight line method as follow:

The estimated useful lives of the intangible assets and the amortisation period are reviewed at the end of each financial year and the amortisation period is revised to reflect the changed pattern, if any.

2.11 Revenue recognition

The Revenue is recognised as follows:

- Distance education fee received from the students is recognised pro-rata over the duration of the respective courses.
- Class room training fee comprises fee received for Management Communication Skills Course ("MCS"),

Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("ICITSS"), Advanced Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("AICITSS") and Orientation Programme ("OP"). The income for classroom training and coaching classes is recognised when services are rendered and related costs are incurred.

- iii) Examination fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e when the examinations are conducted.
- iv) Seminar fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e when the seminars are conducted.
- v) Membership fee comprising of annual membership fee (including fee for certificate of practice and restoration fee) and entrance fee is recognised as under:
 - a) Annual membership fee (including fee for certificate of practice) is recognised as income when it becomes due for the year. Restoration of membership fee is recognised when it is received.
 - b) Entrance Fee:
 - One third of entrance fee collected at the time of admission as associate member is recognised as income in the year of admission and the balance is recognised in Infrastructure Reserve.
 - Entrance fee collected at the time of admission of person as fellow member is recognised in Infrastructure Reserve.
- vi) Student registration fees is recognised when student is admitted for the course.
- vii) Student Association income is recognised when student is admitted for the course.
- viii) Revenue from post qualification and certificate course is recognised in the period in which services are rendered.
- ix) In case of cancellation before commencement of the Certificate/ Post Qualification Course/Diploma Course, 10% of the fee is deducted and in case the course has commenced, no fee is refunded but the member will be given an option to attend remaining part of the course in subsequent batches.

2.12 Other income

- a) Income from sale of publications are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincide with delivery of goods. Income includes consideration received or receivable, net of discounts and other related taxes, (if any).
- b) Income from students news letter and journal subscription is recognised on pro-rata basis over the period of subscription.
- c) Income from campus interviews and expert advisory fee are recognised when services are rendered and related costs are incurred.
- d) Interest Income is recognised on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable

2.13 Investment

- a) The Institute's investments comprise of instruments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments, fixed deposits with nationalised banks domiciled in India and shares in Not-for-Profit entities.
- b) Investments are classified as current and long term investments in accordance with AS 13 Investments. Current investments are those that are readily realisable and intended to be held for not more than one year from the date on which such investments are made. A long term investment is an investment other than a current investment.
- c) Investments are initially recorded at cost and the cost includes acquisition costs such as brokerage, fees and duties. Accrued interest paid at the time of purchase is setoff against first receipt of interest.
- d) At each balance sheet date, current investments are carried at lower of cost and fair value. The fair value is determined on an individual basis. The Long term investments are carried at cost. However, the provision for diminution in value is made to recognise the decline in value, other than temporary, of investments. The premium paid at the time of purchase is amortised over the remaining maturity of the investments. Amortisation of premium is adjusted against the income under head 'Interest from Investments.'

2.14 Foreign Currency Transaction

Transactions in foreign currencies are accounted at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Foreign currency monetary items outstanding at the balance sheet date are restated at the year- end rates. Non-monetary items are carried at historical cost.

Exchange differences arising on settlement / restatement of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised as income or expense in the Statement of Income and Expenditure.

2.15 Employee benefits

Employee benefits include provident fund, gratuity fund, compensated absence, long service awards, pension scheme and post-employment medical benefits.

i) Short term employee benefits

The undiscounted amount of short-term employee benefits (ie. salary, allowances, exgratia etc) expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the year when the employees render the service. The short-term employee benefits are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service.

The cost of short-term compensated absences is accounted as under :

- a) in case of accumulated compensated absences, when employees render the service that increase their entitlement of future compensated absences; and

- b) in case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

ii) Post-employment benefits

Post-employment benefits are the benefits to employees, other than termination benefits, which are payable after the completion of employment. Accounting of post-employment benefits depends upon the classification of relevant plans as either defined benefit plan (DBF) or defined contribution plan (DCP). The post-employment benefit plans where the Institute pays fixed contributions into a separate entity or fund and it will have no obligation to pay further contributions if the separate entity or fund does not hold sufficient assets to all employee benefits relating to employee service in the current and prior period. On the other hand, post-employment benefit plans other than those classified as DCP are classified as DBP.

a) Defined Benefits Plans

For defined benefit plans in the form of gratuity and post retirement pension, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in the period in which they occur. Past service cost is recognised immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit obligation recognised represent the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognised past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to past service cost, plus the present value of available refunds and reductions in future contributions to the schemes. Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

The contribution towards provident fund scheme to The Institute of Chartered Accountants of India Provident Fund Trust ('the Trust') is considered as defined benefit plan from the current year and is charged as an expense based on the amount of contribution required to be made and when services are rendered by the employees. The Trust is managed by the governing body elected by the Institute.

The present value of the defined benefit obligations are ascertained by an independent actuary as per the requirements of Accounting Standard (AS) - 15 Employee Benefits.

b) Pension scheme

The Institute offers its employees benefits in the form of pension. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation.

c) Post retirement medical scheme benefit to retired employees and spouse

The Institute offers its employees benefits in the form of medical scheme. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation.

iii) Other Long-term employee benefits

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date less the fair value of the plan assets out of which the obligations are expected to be settled.

2.16 Leases

The Institute classifies the leases as Finance and Operating Lease for accounting and disclosure purposes. The leases where the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as

finance leases. The leases where the lessor and not the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as operating leases.

Lease rental under operating leases are recognised in the statement of income and expenditure on straight-line basis over the lease term. In case of Finance Lease, assets are capitalised at lower of fair value of the leased asset and present value of minimum lease payments. The lease payments are apportioned between the finance charge and repayment of lease liability. Leased assets are depreciated over the shorter of lease term or useful life of the asset.

2.17 Impairment of Property, Plant and Equipment and intangible assets

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure

2.18 Taxes on income

The Institute has been granted exemption from Income Tax under section 10(23C)(iv) and Section 11 of the Income Tax Act, 1961. As such no provision for income tax is made and no provision for deferred tax asset and liability is considered necessary.

2.19 Assets held for Earmarked and Other Funds

Earmarked fund and others funds in the form of deposits with banks maturing after a period of twelve months from the date of balance sheet are classified as non-current and others are classified as current. These are available for use freely at the discretion of the Council except to the extent of total of the earmarked, employee benefit funds.

2.20 Provisions and Contingencies

A provision is recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE # 3 RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Lakhs)

Particulars	General		Education		Infrastructure		Others*		Total	
	As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Balance at the beginning of the year	82,207	71,796	38,343	35,854	5,700	5,304	1,989	987	1,28,239	1,13,941
Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure	13,916	10,411	-	-	-	-	1,780	1,001	15,696	11,412
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer from / (to) Earmarked Funds	(20,890)	-	4,339	2,489	-	-	-	-	(16,551)	2,489
Admission fees and allocated Entrance fees	-	-	-	-	387	367	-	-	387	367
Donation received for buildings	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11
(Utilization)/Addition	-	-	-	-	(15)	18	-	1	(15)	19
Balance at the end of the year	75,233	82,207	42,682	38,343	6,072	5,700	3,769	1,989	1,27,756	1,28,239

* Others comprises Library Reserve, Class Room Training Reserves, Foreign Currency Translation Reserve (Dubai branch) etc.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE # 4 EARMARKED FUNDS**(₹ in Lakhs)**

Particulars	Research Funds		Accounting Research Building Fund		Education Fund		Medals and Prizes Funds		Students Scholarship Funds		Members Benevolent Fund		Employees Benevolent Fund		Sinking Fund for Repair and Replacement of Assets (*)		Other Funds		Total	
	As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,		As at March 31,	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Balance at the beginning of the year	2,479	2,282	854	793	29,713	25,204	265	236	167	127	-	-	789	661	-	-	5,103	5,026	39,370	34,329
Appropriation from Statement of Income and Expenditure	-	-	-	-	5,818	5,073	-	-	-	-	2,138	-	80	78	276	-	1,500	-	9,812	5,151
Transfer from / (to) Reserves and Surplus	-	-	-	-	(4,339)	(2,489)	-	-	-	-	-	-	-	-	20,890	-	-	-	16,551	(2,489)
Contribution received / Addition during the year	-	24	-	-	-	-	15	23	12	36	-	-	-	-	-	-	-	-	27	83
Interest income during the year appropriated through Income and Expenditure	198	173	70	61	2,416	1,925	19	15	11	10	-	-	64	50	-	-	88	83	2,866	2,317
Utilised during the year	-	-	-	-	-	-	(19)	(9)	(4)	(6)	-	-	(10)	-	-	-	(2)	(6)	(35)	(21)
Balance at the end of the year	2,677	2,479	924	854	33,608	29,713	280	265	186	167	2,138	-	923	789	21,166	-	6,689	5,103	68,591	39,370

Note

1. Total earmarked funds of Rs. 68,591 Lakhs (previous year Rs. 39,370 Lakhs) are held in fixed deposits and Government Securities (See Note 12 & 13)

*2. Sinking fund to the extent of accumulated depreciation less ITT Reserve till 31st March 2018 amounting to Rs. 20,890 lakhs has been transferred from General Reserve to Sinking Fund during the year. A sum of Rs. 276 lakhs being depreciation for the year net of ITT reserve for the year has been appropriated towards Sinking Fund.

Rs. 1,500 lakhs have been appropriated to finance estimated expenditure Rs.4,500 Lakhs for the World Congress of Accountants to be held in the year 2022. (See Note No.25.19)

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 5: OTHER LONG-TERM LIABILITIES	As at March 31,	
	2019	2018
Fees received in advance		
i) Education fees	1,579	1,206
ii) Journal subscription	12	13
Total	1,591	1,219

NOTE # 6: PROVISIONS	As at March 31,		As at March 31,	
	2019	2018	2019	2018
	Long-term	Long-term	Short-term	Short-term
Provisions for employee benefits :				
a) Post employment benefits				
i) Gratuity	-	567	392	454
ii) Pension	11,861	11,426	503	464
iii) Provident Fund	-	-	200	-
b) Provision for leave encashment	4,570	3,748	533	389
c) Provision for Branch Employees (Note-25.15)	3,500	2,800	-	-
d) Provision for Pay Revision (Note-25.16)	5,360	4,400	-	-
Total	25,291	22,941	1,628	1,307

NOTE # 7: TRADE PAYABLES	As at March 31,	
	2019	2018
Trade payables	4,132	3,677
Total	4,132	3,677

NOTE # 8: OTHER CURRENT LIABILITIES	As at March 31,	
	2019	2018
a) Fees received in advance		
i) Examination fees	7,046	7,231
ii) Journal subscription	25	21
iii) Membership fees	3,112	2,876
iv) Education fees	9,471	9,060

v) Post qualification courses fees	256	111
vi) Certificate courses fees	171	118
vii) Seminar fees :		
a) Seminar Members	110	105
b) Seminar Students	-	2
viii) Class room training fees	937	1,325
ix) Coaching class fees	105	84
x) other fees	63	64
Sub Total (A)	21,296	20,997
b) Other liabilities		
i) Capital Creditors	15	29
ii) PF, ESIC and Professional tax payable	109	96
iii) Withholding taxes	540	317
iv) GST Payable	784	1,389
v) Security and earnest money deposit	816	832
vi) Others	482	614
Sub Total (B)	2,746	3,277
Total (A+B)	24,042	24,274

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 9:Property,Plant and Equipment						Depreciation				
Particulars	As at March 31,	Cost at the beginning of the year	Additions during the year	Transfers/ Deletions during the year	Cost at the end of the year	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Charged for the year	Transfers/ Deletions during the year	Accumulated depreciation at the end of the year	Net book value at end of the year
Freehold land	2019	17,663	356	292	18,311	-	-	-	-	18,311
	2018	19,214	270	(1,821)	17,663	-	-	-	-	17,663
Leasehold land	2019	7,549	1,033	(792)	7,790	824	92	(76)	840	6,950
	2018	5,879	112	1,558	7,549	668	107	49	824	6,725
Buildings	2019	31,800	7,005	(70)	38,735	7,766	1,584	(348)	9,002	29,733
	2018	28,441	3,096	263	31,800	6,600	1,449	(283)	7,766	24,034
Lifts, electrical installations & fittings	2019	2,183	118	11	2,312	1,157	115	(5)	1,267	1,045
	2018	1,863	342	(22)	2,183	1,063	106	(12)	1,157	1,026
Computers	2019	5,233	260	(76)	5,417	4,948	239	(85)	5,102	315
	2018	5,129	178	(74)	5,233	4,767	242	(61)	4,948	285
Furniture and fixtures	2019	4,572	455	(192)	4,835	2,221	244	(48)	2,417	2,418
	2018	4,192	401	(21)	4,572	1,990	241	(10)	2,221	2,351
Air conditioners and office equipments	2019	5,387	322	(83)	5,626	3,135	354	(77)	3,412	2,214
	2018	4,801	634	(48)	5,387	2,850	325	(40)	3,135	2,252
Vehicles	2019	135	2	(1)	136	108	6	-	114	22
	2018	135	-	-	135	101	7	-	108	27
Library books	2019	1,041	25	(7)	1,059	1,041	26	(6)	1,061	(2)
	2018	1,009	32	-	1,041	1,009	32	-	1,041	-
Total	2019	75,563	9,576	(918)	84,221	21,200	2,660	(645)	23,215	61,006
	2018	70,663	5,065	(165)	75,563	19,048	2,509	(357)	21,200	54,363

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in Lakhs)

NOTE # 10: INTANGIBLE ASSETS	As at March 31,	
	2019	2018
Computer Software		
Cost at the beginning of the year	746	663
Additions Transfers/Deletions	5	62
	15	21
Cost at the end of the year	766	746
Amortisation at the beginning of the year	691	644
Charge for the year Transfers/Deletions	28	31
	13	16
Amortisation at the end of the year	732	691
Net book value at the end of the year	34	55
Net book value at the beginning of the year	55	19

NOTE # 11: CAPITAL WORK IN PROGRESS	As at March 31,	
	2019	2018
Opening balance	10,877	13,875
Add: Addition during the year	1,292	561
Less: Amount capitalised/adjusted during the year	(6,614)	(3,559)
Closing balance	5,555	10,877

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS (at cost less diminution in value)	As at March 31,		As at March 31,	
	2019	2018	2019	2018
	Non-current	Non-current	Current	Current
a. Central Government Securities				
Quoted Securities				
1 8.27% Government of India 2020	2,548	2,588	-	-
2 7.80% Government of India 2021	2,559	2,588	-	-
3 6.35% Government of India 2020	998	995	-	-
	6,105	6,171	-	-
Unquoted Securities				
8.00% Government of India Taxable				
4 Bonds- cumulative	11,200	11,200	-	-
5 8% Saving (Taxable) Bond 2003- non cumulative	44,000	44,000	-	-
	55,200	55,200	-	-
	61,305	61,371	-	-
Book Value				
Market Value				
Quoted Unquoted	6,109	6,112	-	-
(Book value)	55,200	55,200	-	-
	61,309	61,312	-	-
b. State Government Securities				
Quoted Securities :				
1 7.75% Rajasthan UDAY SDL 2018	-	-	-	2,506
2 8.45% Punjab SDL 2023	2,557	2,572	-	-
3 8.45% Karnataka SDL 2024	3,058	3,068	-	-
4 8.45% Karnataka SDL 2024	2,038	2,045	-	-
5 8.62% Maharashtra SDL 2023	511	514	-	-
6 8.75% West Bengal GS 2022	510	514	-	-
7 8.39% Rajasthan Uday SDL 2022	1,527	1,537	-	-
8 8.39% Rajasthan Uday Bond 2021	3,870	3,904	-	-
9 8.49% Andhra Pradesh P SDL 2020	1,510	-	-	-
10 8.18% Andhra Pradesh SDL 2020	1,506	-	-	-
11 8.20% Punjab SDL 2019	-	-	1,003	-
12 8.85% Punjab SDL 2019	-	-	1,004	-
13 07.86 Rajasthan Uday 2019	-	-	2,910	-
14 8.44% Uttar Pradesh Uday 2023	1,004	-	-	-
15 8.01% Rajasthan Uday SDL 2020	2,497	-	-	-
SGS (A)	20,588	14,154	4,917	2,506

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS (at cost less diminution in value)	As at March 31,		As at March 31,	
	2019	2018	2019	2018
	Non-current	Non-current	Current	Current
16 7.56% Andhra Pradesh SDL 2021	2,478	-	-	-
17 7.64% Andhra Pradesh SDL 2021	2,976	-	-	-
18 8.37% Odisha SDL 2022	1,003	-	-	-
19 07.79% Himachal Pradesh SDL 2022	990	-	-	-
20 7.62% Maharashtra SDL 2021	1,984	-	-	-
21 6.90% Punjab SDL 2021	2,452	-	-	-
22 8.39% Rajasthan Uday Bond 2021	3,016	-	-	-
23 6.94% Odisha SDL 2021	1,464	-	-	-
24 8.21% Haryana Uday 2022	1,487	-	-	-
25 9.04% West Bengal SDL 2021	509	-	-	-
26 9.18% Punjab SDL 2021	511	-	-	-
27 9.13% Gujarat SDL 9/5/2022	2,434	-	-	-
28 8.90% Andhra Pradesh SDL 2022	2,525	-	-	-
29 9.01% West Bengal SDL 2022	508	-	-	-
30 8.86% Punjab SDL 2022	1,014	-	-	-
31 8.97% Bihar SDL 2022	509	-	-	-
32 8.95% Assam SDL 2022	1,524	-	-	-
33 8.92% Himachal Pradesh SDL 2022	1,015	-	-	-
34 9.01% Karnataka SDL 2024	528	-	-	-
35 7.93% Chattisgarh SDL 2024	1,520	-	-	-
36 8.45% Gujarat SDL 2023	2,582	-	-	-
37 8.25% Uttar Pradesh UDAY BOND 2023	509	-	-	-
38 8.39 Rajasthan Uday 2022	1,494	-	-	-
39 8.27% Rajasthan SDL SPL 2023	196	-	-	-
40 8.18% Haryana SDL UDAY 2024	46	-	-	-
SGS (B)	35,274	-	-	-
Book Value (A+ B)	55,862	14,154	4,917	2,506
Market Value	57,263	14,209	4,928	2,506
Sub-Total	1,17,167	75,525	4,917	2,506

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS (at cost less diminution in value)	As at March 31,		As at March 31,	
	2019	2018	2019	2018
	Non-current	Non-current	Current	Current
c. Investment in equity instruments of subsidiaries (fully paid up)				
i. Institute of Insolvency Professionals of ICAI 10,00,000 Ordinary shares of Rs. 100 each	1,000	1,000	-	-
ii. Investment ICAI Registered Valuers Organisation	10	10	-	-
Sub-Total Book Value	1,010	1,010	-	-
Total (A+B+C)	1,18,177	76,535	4,917	2,506

NOTE # 13: Assets held for Earmarked and Others Funds	As at March 31,		As at March 31,	
	2019	2018	2019	2018
	Non-current	Non-current	Current	Current
Fixed deposits with banks	5,176	5,229	37,992	54,704
Total	5,176	5,229	37,992	54,704

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in Lakhs)

NOTE # 14: LOANS AND ADVANCES (Unsecured, considered good)	As at March 31,		As at March 31,	
	2019	2018	2019	2018
	Non-current	Non-current	Current	Current
a) Security deposits	81	190	352	362
b) Tax deducted at source	2,508	2,256	-	-
c) Input Tax Credit	-	-	-	-
d) GST on advances received from members	-	-	1,230	966
e) Other loans and advances	-	-	521	366
i) Loans and advances to employees	600	660	900	551
iii) Other receivables	244	291	296	698
Less: Provision for doubtful receivables	-	-	(4)	(229)
Total	3,433	3,397	3,295	2,714

NOTE # 15: OTHER ASSETS	As at March 31,		As at March 31,	
	2019	2018	2019	2018
	Non-current	Non-current	Current	Current
a) Interest accrued				
i. on fixed deposits with banks	44	28	960	1,045
ii. on investments	132	506	2,925	981
iii. on loans to employees	154	144	40	39
Total	330	678	3,925	2,065

NOTE # 16: INVENTORIES (At lower of cost and net realisable value)	As at March 31,	
	2019	2018
a) Publications and study materials	434	1,038
b) Stationery and stores	45	42
Total	479	1,080

NOTE # 17: CASH AND BANK BALANCES	As at March 31,	
	2019	2018
a) Cash on hand	42	43
b) Balances with banks in savings and current accounts	8,670	6,781
Total	8,712	6,824

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 18: FEES	For the year ended March 31,	
	2019	2018
a) Distance education	23,910	21,654
b) Class room training income	15,182	9,209
c) Coaching	1,160	1,285
d) Examination	16,867	16,870
e) Membership	10,870	10,830
f) Entrance	116	106
g) Post qualification courses	976	747
h) Certificate courses	1,386	1,825
Total	70,467	62,526

NOTE # 19: SEMINAR INCOME	For the year ended March 31,	
	2019	2018
a) Members	2,889	3,555
b) Students	695	834
c) Non members	711	1,328
d) E-Learning income	17	44
Total	4,312	5,761

NOTE # 20: OTHER INCOME	For the year ended March 31,	
	2019	2018
a) Interest income		
i. on bank deposit held in general funds	2,783	3,234
ii. from investments	5,613	3,114
iii. on bank deposits held for earmarked funds	2,866	2,317
iv. on loans to employees	70	78
b) Sale of publications	933	1,568
c) News letters	106	187
d) Journal subscription	277	113
e) Campus interview	970	782
f) Expert advisory fee	53	23
g) Provision no longer required written back	445	193
h) Miscellaneous income	481	713
Total	14,597	12,322

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in Lakhs)

NOTE # 21: SEMINARS AND TRAINING PROGRAMMES	For the year ended March 31,	
	2019	2018
a) Members	3441	4867
b) Students	943	973
c) Students Activity Expenses	83	155
d) E-Learning income	38	41
Total	4505	6036

NOTE # 22: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE	For the year ended March 31,	
	2019	2018
a) Salary, pension and other allowances	12,912	14,612
b) Contribution to provident and other funds	1,616	2,113
c) Staff welfare expenses	167	147
Total	14,695	16,872

NOTE # 23: OTHER EXPENSES	For the year ended March 31,	
	2019	2018
a) Postage and telephone	2,743	2,869
b) Rent, rates and taxes	5,542	5,242
c) Domestic Travelling	2,212	1,761
d) Overseas expenses:		
i) Overseas travelling	110	133
ii) Membership fees for foreign professional bodies	573	503
iii) Others	160	180
e) Repairs and maintenance	2,589	2,301
f) Class room training expenses	5,187	3,835
g) Advertisement and publicity	278	170
h) Meeting expenses	1,182	895
i) Merit scholarship	189	176
j) Audit fees : Head office	11	11
: Other offices	39	35
k) Payments from earmarked funds	35	21
l) Prior period adjustments (Net) (Note- 24)	115	748
m) GST expenses	1213	2,059
n) Provision for doubtful advances	4	229
o) Loss on sale of investments	-	285
p) Other expenses	1,893	1,317
Total	24,075	22,770

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in Lakhs)

NOTE # 24: PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET)	For the year ended March 31,	
	2019	2018
i) Income *	(969)	(116)
ii) Expenses*	1,084	864
Total	115	748

* Details of Prior Period Income & Expenses	For the year ended March 31,	
	2019	2018
i) Class room training Income	796	-
ii) Others	173	116
Total of prior period income	969	116
i) Class room training expenditure	308	-
ii) Depreciation on buildings	415	284
iii) Printing & Stationery expenses	-	218
iv) Others	361	362
Total of prior period expenses	1,084	864

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
25 Additional Notes to the Financial Statements

25.01 Contingent liabilities and commitments (₹ in Lakhs)

	2018-19	2017-18
a. Contingent liabilities		
i) Claims against the Institute not acknowledged as debts	2,603	1,830
ii) Income tax demand - (Refer Note # 25.03)	4,142	4,142
iii) The Institute has received two show cause notices of ₹ 15,797 lakhs from the Additional Director General, Goods and Service Tax Intelligence for payment of service tax on annual fee, certificate of practice fee, entrance fee, Seminar Fees and Coaching Class Fees etc. The Institute is of the opinion that it is not liable to service tax as mentioned in show cause notice (SCN). A writ petition was filed with Hon'ble Delhi High Court in this regard, on 08.04.2019 inter alia seeking stay of the proceedings pursuant to the SCN dated 09.08.2018 and 03.10.2018 issued by department. The writ petition was filed on 16.04.2019 and Hon'ble High Court of Delhi has allowed the writ petition and advised the Institute to reply to the aforesaid SCNs and further ordered that no final order shall be passed by the department till the decision of the writ petition. The next hearing is scheduled for 13th December 2019.		

b.	Capital Commitments	2018-19	2017-18
	Capital Commitments (Net of advances)	2,716	3,654

25.02 Other Receivables in Note 14 # under long term loans and advances include ₹ 243.75 Lakh for stamp duty refund receivable on cancellation of principal and supplementary agreements of acquiring property at Nagpur which has been rejected by the Joint District Registrar (JDR), Nagpur. The Institute has filed two appeals before the Chief Controlling Revenue Authority, Pune under section 53 of Maharashtra Stamp Act challenging the orders passed by JDR, Nagpur which are still pending for final adjudication. The Institute has been advised that it has a good legal case to receive the refund of stamp duty.

25.03 For the assessment year 2014-15, a demand of ₹ 4,142 Lakhs was raised by income tax department against the Institute. The ITAT has remanded the case back to the Assessing Officer. Letter to give effect to the order of Hon'ble ITAT for necessary rectification in Intimation u/s 143 (1) of the order issued on 19.03.2016, quantify taxable income and to give credit of TDS claimed and delete the aforesaid demand and issue the refund of ₹ 452 Lakhs along with interest u/s 234A of the Income Tax Act 1961 was filed on 10.10.2018.

The Income Tax Department has filed an appeal u/s 260A in the Hon'ble High Court of Delhi to set aside the aforesaid order of the Hon'ble ITAT. The matter is pending before the Court. The Institute has been legally advised that there is no apparent reason for the Hon'ble High Court to interfere in this matter and is expected to dismiss the appeal filed by the Department.

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

25 Additional Notes to the Financial Statements

- 25.04 Directly attributable expenses on the seminars activity have been charged to seminar expenses and related indirect expenditure is charged to functional heads of expenditure.
- 25.05 Out of the fee received from the students towards Students Registration Fee, a sum of ₹ 250 per student in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.
- 25.06 Leasehold land includes ₹ 6.17 lakhs paid for the plot of land in Indraprastha Estate, New Delhi (adjacent to existing head office) allotted by Land and Development Authority, New Delhi for which execution of Memorandum of Agreement and Lease Deed is in progress.
- 25.07 The Institute had initiated a process for digitization of entire activities by undertaking a project referred as 'Project Parivartan'. For this purpose, Institute had appointed a global integrated service provider (vendor) supervised by a globally reputed project management consultant at a total cost of ₹ 3,981 lakhs. A sum of ₹ 867 lakhs was incurred up to March 31, 2015.

Since the service provider did not carry out the development of digitization as per the requirement even after extended periods, the Institute cancelled the contract and encashed the bank guarantee of ₹ 295 lakhs in the month of June 2015 and the balance amount of ₹ 572 lakhs was written off in the year ended March 31, 2015.

The vendor submitted a proposal requiring the Institute to pay ₹ 807 lakhs including the amount encashed Bank Guarantee which has been rejected by the Institute and the agreement with service providers in February, 2017. No communication has been received from the vendors after contract was terminated.

During the year, Institute has sent a legal notice dated 31.10.2018 to the vendor requiring it to pay an amount of ₹2,140.79 lakhs along with applicable interest towards loss incurred on account of non execution of the project. The vendor in its response dated 20.03.2019 has contested that claim of Institute is time barred. Further action in this matter will be taken as advised by the legal advisor.

- 25.08 Land measuring 225 sq. mtrs area of ICAI Bhawan Faridabad, had been acquired by DMRC in January 2013 for which, Faridabad branch had requested for another piece of land, adjacent to the branch in compensation against the acquisition by DMRC. The matter is currently under consideration by Haryana Urban Development Authority.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

25 Additional Notes to the Financial Statements

25.09 Other expenditure includes ₹ 114 lakhs (₹ 262 lakhs) being the reimbursement of costs incurred by Quality Review Board constituted under section 28-A of The Chartered Accountants Act, 1949. Other expenses also include contribution of ₹ 60 lakhs (₹ 67.50 lakhs) made to the Appellate Authority constituted under Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949. Expenses of the Quality Review Board and the Appellate Tribunal are required to be borne by the Institute. Other expenses also include grant of ₹ 15 lakhs (₹ 10 lakhs) made to Extensible Business Reporting Languages (XBRL) and one time expense support of ₹15 lakhs (₹ Nil) to Investment ICAI Registered Valuers Organization.

25.10 A detailed review of the various reserve funds and earmarked funds created in the earlier years and related earmarked investments has been taken up to restructure these funds as per the present requirements and functioning of the Institute.

The Institute is carrying following earmarked funds in the books of account from earlier years with no utilisation:

Particulars	(₹ in Lakhs)
Education Reserve	42,682
Education Fund	33,608
Research Building Funds	924

25.11 In the case of inter unit accounts relating to income and expenditure heads, the unreconciled differences aggregate to ₹ 552.62 Lakhs in debit and ₹ 546.59 Lakhs in credit. Net difference being ₹ 6.03 Lakhs in debit. Pending completion of reconciliation, the amount of net difference of ₹ 6.03 Lakhs has been included under 'Provision for Inter branch reconciliation account' and provided for. In the case of inter unit accounts relating to assets and liabilities, the unreconciled differences aggregate to ₹ 3,814.52 Lakhs in debit and ₹ 4,029.70 Lakhs in credit. The net difference of ₹215.18 Lakhs has been included in 'Fee Received in Advance'.

25.12 Although the income of the Institute is fully exempt under section 10(23-C)(IV) of the Income Tax Act, 1961, some of the vendors have deducted tax at source on payments made to the Institute. The refund of tax deducted at source is ₹ 2,508 Lakhs (₹ 2,256 Lakhs) is likely to be received on final outcome of the disposal of pending appeals referred to Note No. 25.03 above. On completion of assessment for the year ended 31.3.2016 at ₹ NIL income, the Institute has received a refund of ₹55.37 lakhs plus interest of ₹9.13 lakhs against TDS claim of ₹ 221 lakhs. The matter has been taken up with the tax department for refunding the balance amount of ₹ 165.63 lakhs.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

25 Additional Notes to the Financial Statements

- 25.13 In view of the Management, the study circles, study chapters and overseas chapters are separate entities and their accounts are not consolidated.
- 25.14 Steps have been taken to carry out physical verification of fixed assets and reconciliation with books balances at the Head office and the Branches.
- 25.15 The Branch Employees Scheme 2006 has been replaced by new Branch Employees Scheme 2014 which has been approved by the Central Council but not yet implemented. Since 2014-15, a provision of ₹ 700 lakhs per year is being made in the accounts adding upto ₹3500 lakhs as on March 31, 2019. The shortfall / excess of provision will be determined when the revised scheme is fully implemented.
- 25.16 Consequent to revision of salary and allowances of employees effective 1.1.2016 and 1.7.2017 respectively, a provision of ₹ 960 lakhs (₹ 4,400 lakhs) was made in financial year 2018-19. Pending final review and decision on this matter, ₹ 1,071 lakhs have been paid to the employees as advance.
- 25.17 Out of the 189 units of the Institute that form part of the consolidation, the accounts of Northern India Regional Council are unaudited.
- 25.18 The reconciliation of GST paid, payable and GST input is in progress. An amount of ₹ 1,213 Lakhs (₹ 2,059 Lakhs) including ineligible input tax credit and input credit attributable to exempted supplies, has been charged off to the Income and Expenditure Account as 'GST Expenses'. GST payable at the end of the year of ₹ 784 Lakhs (₹.1389 Lakhs) has been included under other liabilities (Note No.8) and amount of ₹ 1,230 Lakhs (₹ 966 Lakhs) as GST input credit recoverable has been shown under 'Loans and Advances (Note No.14)'. The management is of the opinion that no material adjustments are likely to arise when the reconciliation is completed.
- 25.19 As per the present estimates, the Institute is likely to incur an estimated expenditure of ₹ 4,500 Lakhs for holding World Congress of Accountants in the year 2022 in India. It has been decided that out of surplus of the year 2018-19 and next two years, ₹ 1,500 Lakhs will be appropriated to a separate close ended fund to meet the financial requirements to organize the conference. The expenditure incurred each year will be debited to designated account 'Expenditure on WCOA -2022' and an equivalent amount will be transferred to the appropriation account from the said fund every year.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

25 Additional Notes to the Financial Statements

- 25.20 During the year 2018-19, the Institute has created a sinking fund for Building Repairs and Asset Replacement to fund such expenditure in the future. Sinking fund to the extent of accumulated depreciation less ITT Reserve till 31st March 2018 amounting to ₹ 20,890 lakhs has been transferred from General Reserve to Sinking Fund during the year ₹ 276 lakhs being depreciation for the year net of ITT reserve for the year has been appropriated towards Sinking Fund. It is proposed to earmark investments in Govt. of India securities and income accruing on these securities will be appropriated to the fund.
- 25.21 Due to certain problems relating to data migration from the old package to the new package, the detailed listings of advance fee received from members amounting to ₹ 3,112 Lakhs and fee for distance education ₹ 9,471 Lakhs received from the students could not be extracted as of 31.03.2019 and made available to the auditors for verification.
- 25.22 As per Regulation 197 of The Chartered Accountants Regulations 1988, the auditors of the Council are required to compare the actual income and expenditure with the budget estimates approved by the Council and submit a report to the Council on the material departures. Steps are being taken to comply with this requirement in the near future.
- 25.23 The Institute in the process to setup necessary mechanism to ensure compliance and disclosure requirements and to identify the vendors of goods and services who are covered under The Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.
- 25.24 ₹ 2138 lakhs out of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) received during the year has been transferred to the Members Benevolent Fund. Being the first year, the Council has approved 20% of the Membership Fee for the current year.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Disclosure under Accounting Standards

26 Employee Benefits

Defined Benefit plans

The Institute has recognised an amount of ₹858.14 lakhs for the year ended March 31, 2019 (Previous year ₹ 597.36 lakhs) towards contribution to Provident Fund.

During the year, Institute has got the actuarial valuation done for the Institute of Chartered Accountants of India Provident Fund Trust. It has been advised that provident fund scheme is a defined benefit plan and not a defined contribution plan. The net shortfall of ₹200.15 lakhs (₹ Nil) has been provided for in the books of account. Upto 31.3.2018, Provident fund scheme was treated as a defined benefit plan and no actuarial valuation was carried out.

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees

Gratuity :	Funded
Post retirement Pension :	Non-Funded
Compensated Absence:	Non-Funded

26.1 Details of the Gratuity Plan are as follows

(₹ in Lakhs)

Description	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
1. Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
a. Obligation as at beginning of the year	3,298	2,510	2,358	2,213
b. Current service cost	266	1,102	202	184
c. Interest cost	239	176	166	169
d. Actuarial (gain)/loss	442	(204)	44	(53)
e. Benefits paid	(340)	(286)	(260)	(155)
f. Obligation as at end of the year	3,905	3,298	2,510	2,358
2. Change in fair value of plan assets	2,277	2,325	2,292	2,232
a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	188	165	183	191
b. Expected return on plan assets	4	6	2	6
c. Actuarial gain/(loss)	1,045	84	132	78
d. Contributions made by the Institute	(1)	(303)	(284)	(215)
e. Benefits paid	3,513	2,277	2,325	2,292
f. Fair value of plan assets as at end of the year				
3. Reconciliation of fair value of plan assets and obligations	3,905	3,298	2,510	2,358
a. Present value of obligation	3,513	2,277	2,325	2,292
b. Fair value of plan assets				
c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	(392)	(1,021)	(185)	(66)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Details of the Gratuity Plan (Contd...)**(₹in Lakhs)**

	Description	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
4.	Expenses recognised during the year				
	a. Current service cost	266	1,102	202	184
	b. Interest cost	239	176	166	169
	c. Expected return on plan assets	(188)	(165)	(183)	(191)
	d. Actuarial (gain)/loss	438	(210)	42	(59)
	e. Expenses recognised during the year	755	903	227	103
		% invested	% invested	% invested	% invested
5.	Investment details	100	100	100	100
	a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India				
6.	Assumptions	7.62%	7.65%	7.45%	7.92%
	a. Discount rate (per annum)	7.65%	7.45%	7.45%	8.85%
	b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	Basic 3% :	Basic 3% :	Basic 3% :	Basic 3% :
	c. Rate of escalation in salary	DA 6%	DA 6%	DA 6%	DA 6%
		2%	2%	5%	5%
	d. Attrition rate	IAL 2012-14	IAL 2006-08	IAL 2006-08	IAL 2006-08
	e. Mortality table	Ultimate	Ultimate	Ultimate	Ultimate

26.2 Details of the Post Retirement Pension Plans

	Description	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
1.	Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
	a. Obligation as at beginning of the year	11,890	11,115	5,086	2,684
	b. Interest cost	874	813	357	211
	c. Actuarial (gain)/loss	79	378	6,063	2,210
	d. Benefits paid	(480)	(416)	(391)	(19)
	e. Obligation as at end of the year	12,363	11,890	11,115	5,086
2.	Reconciliation of fair value of plan assets and obligations				
	a. Present value of obligation	12,363	11,890	11,115	5,086
	b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	(12,363)	(11,890)	(11,115)	(5,086)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Details of the Post Retirement Pension Plans (Contd...)

(₹ in Lakhs)

	Description	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
3.	Expenses recognised during the year				
	a. Interest cost	874	813	357	211
	b. Actuarial (gain)/loss	79	378	6,063	2,210
	c. Expenses recognised during the year	953	1,191	6,420	2,421
4.	Assumptions				
	a. Discount rate (per annum)	7.60%	7.50%	7.30%	7.90%
	b. Rate of escalation in salary	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%
	c. Attrition rate	2%	2%	5%	5%
	d. Mortality table	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate

26.3 Employee Benefits (Contd..) Details of Leave Encashment

	Description	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
1.	Reconciliation of opening and closing balances of obligation				
	a. Obligation as at beginning of the year	4,137	3,873	3,468	3,097
	b. Current service cost	221	182	399	291
	c. Interest cost	301	274	227	216
	d. Actuarial (gain)/loss	851	188	127	115
	e. Benefits paid	(406)	(380)	(348)	(251)
	f. Obligation as at end of the year	5,104	4,137	3,873	3,468
2.	Reconciliation of fair value of plan assets and obligations				
	a. Present value of obligation	5,104	4,137	3,873	3,468
	b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	(5,104)	(4,137)	(3,873)	(3,468)
	Expenses recognised during the year				
	a. Current service cost	221	182	399	291
	b. Interest cost	301	274	227	216
3.	c. Actuarial (gain)/loss	851	188	127	115
	d. Expenses recognised during the year	1,373	644	753	622

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Details of Leave Encashment (Contd..)**(₹ in Lakhs)**

	Description	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
4.	Assumptions				
	a. Discount rate (per annum)	7.62%	7.65%	7.45%	7.92%
		Basic 3% :	Basic 3% : DA	Basic 3% : DA	Basic 3% :
	b. Rate of escalation in salary	DA 6%	6%	6%	DA 6%
	c. Attrition rate	2%	2%	5%	5%
	d. Mortality table	IAL 2012-14	IAL 2006-08	IAL 2006-08	IAL 2006-08
		Ultimate	Ultimate	Ultimate	Ultimate

27 Segment Reporting

The Institute's operations are confined to "regulation of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

28 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Sd/- CA. Sudeep Shrivastava Joint Secretary	Sd/- Rakesh Sehgal Acting Secretary	Sd/- CA. Atul Kumar Gupta Vice-President	Sd/- CA. Prafulla P. Chhajed President
--	--	---	---

In our report referred to even date
For Shah Gupta & Co.
Chartered Accountants
Firm registration number: 109574W

For Khanna & Annadhanam
Chartered Accountants
Firm registration number: 001297N

Sd/-
CA. Rajeev Bansa
Partner, Membership No. 088598
New Delhi, 24th September, 2019.

Sd/-
CA. B.J. Singh
Partner, Membership No. 007884

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./233/19]